देशप्राण

सोमवार
रांची, 25 अगस्त, 2025

एआई रोकेगा बुढ़ापा!

एआई को लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोग ई-मेल लिखवा रहा, रिसर्च पेपर लिखवा रहा है, पीपीटी बनवा रहे हैं, जबकि बच्चे होमवर्क में हेल्प रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इंसानी काम को आसान नहीं कर रहा, बल्कि अब एक ऐसी प्रोसेस का हिस्सा भी बन चुका है, जो इंसान को जवान रखने में मदद कर सकती है। कई वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वे एआई की मदद से ऐसा फॉर्मूला विकसित कर सकते हैं, जिससे लोग जवान रह सकते हैं। हाल ही में ओपन एआई ने सिलिकॉन वैली की एक स्टार्टअप कंपनी रेट्रो बायोसाइंसेज के साथ मिलकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक खास एआई मॉडल बनाया है, जिसका नाम है जीपीटी -4बी माइक्रो है। यह एआई प्रोटीन सीक्वेंस, बायोलॉजिकल लिटरेचर और 3डी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पर ट्रेन हुआ है। इसका मकसद है शरीर के सेल्स को बेहतर बनाने में मदद करना। रिपोर्ट के मुताबिक, जीपीटी -4बी माइक्रो कोई आम चैटबॉट नहीं है। इसे खास तौर पर प्रोटीन को फिर से डिजाइन करने के लिए बनाया गया है, जो रेगेनरेटिव मेडिसिन के लिए बहुत जरूरी हैं। वैज्ञानिकों ने इस एआई को 'यामानाका फैक्टर्स' प्रोटीन को बेहतर बनाने का काम दिया। यामानाका फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये प्रोटीन एडल्ट सेल्स को फिर से स्टेम सेल में बदल सकते हैं। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर के किसी भी हिस्से की सेल बन सकती हैं। ओपन एआई ने अपने ब्लॉग में बताया कि जीपीटी-4बी माइक्रो ने यामानाका फैक्टर्स के नए और बेहतर रूप बनाए हैं। ये नए प्रोटीन पुराने प्रोटीन की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। लेबोरेटरी में किए गए टेस्ट में इन एआई मेड प्रोटीन ने कमाल दिखाया। इन प्रोटीन की मदद से सेल्स में स्टेम सेल मार्कर की मात्रा 50 गुना ज्यादा बढ़ गई। यही नहीं, इन प्रोटीन ने सेल्स में होने वाले डीएनए नुकसान को भी तेजी से ठीक किया। आसान भाषा में कहा जाए तो ये प्रोटीन बूढ़ी सेल्स को फिर से जवान जैसा बना सकते हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एआई की मदद से बनाए गए प्रोटीन ने पुराने प्रोटीन को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसकी मदद से भविष्य में ऐसी दवाइयां बन सकती हैं, जो बुढ़ापे को धीमा करें या कुछ हद तक उलट दें। इससे ना केवल बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है, बल्कि इंसान की जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सकता है। बुढ़ापे को रोकने की दिशा में भी कदम बढ़ सकते हैं।

विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की भूमिका

अशोक भाटिया
(वरिष्ठ स्तंभकार)

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियों ने तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन चुनौती दे रहा है। भाजपा के बड़े नेताओं के बिहार के लगातार दौरे हो रहे है । पिछले कुछ महीनों से बिहार के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एक बार फिर बिहार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 12,992 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें गंगा पर बना 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। इसके अलावा वैशाली से कोडरमा के बीच का बुद्ध सर्किट ट्रेन की शुरूआत भी हुई। इस बीच चुनाव में छोटी-छोटी पार्टियां भी बड़ी भूमिका अदा करने के लिए तैयार दिख रही हैं। ये छोटी पार्टियां भले ही कम सीटों पर अपना असर दिखाएंगी, लेकिन चुनाव के बाद बनने वाले सियासी परिदृश्य में किंगमेकर की भूमिक निभा सकती हैं।

इतिहास पर नजर डाले तो बिहार में 2020 का विधानसभा चुनावों बेहद रोमांचक साबित हुआ था। इसका एक कारण छोटे दलों का मजबूत प्रदर्शन था। 11 सीटों पर फैसला एक हजार से भी कम वोटों से हुआ, और 26 सीटों पर 1 प्रतिशत से 2।5 प्रतिशत के अंतर से जीत हासिल हुई थी। इसमें जद (यू) के कृष्ण मुरारी शरण (प्रेम मुखिया) की जीत भी शामिल है। उन्होंने हिलसा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 12 वोटों से जीत हासिल की, जो बिहार के इतिहास में कम से कम 14 चुनावों में सबसे कम अंतर से जीत थी। मुख्य मुकाबला भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच था, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (उपेंद्र कुशवाहा), जन अधिकार पार्टी (पप्पू यादव), जैसी कई छोटी पार्टियों ने उन सीटों पर चुनाव लड़ा जहां उनकी जाति या समुदाय का अच्छा प्रभाव है। सीटों की संख्या कम होने के बावजूद, उन्होंने मुकाबले को और व्यापक बनाया और पारंपरिक वोट बैंक को विभाजित किया।

वीआईपी पार्टी की स्थापना 2018 में हुई । पार्टी शुरू में महागठबंधन के साथ थी लेकिन सीट बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण मुकेश सहनी ने गठबंधन छोड़ दिया। 2020 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने एनडीए में शामिल होकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। हालांकि खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए। वोट शेयर 1. 52 प्रतिशत रहा। इस बार पार्टी 60 सीटों पर दावा कर रही है। सहनी इस समय विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा हैं।मुकेश सहनी का दावा है कि उनकी पार्टी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर, ओवैसी की एआईएमआईएम ने 2020 में बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से पांच मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में थीं। 1.24 प्रतिशत वोट शेयर के साथ, एआईएमआईएम ने किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में प्रभाव बनाया है, जो सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाताओं पर कब्जा जमाकर आरजेडी को चुनौती दे रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में वाम दल अब महागठबंधन का अहम हिस्सा बन गए हैं। 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम ने मिलकर 243 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे जिनमें से उन्होंने 16 सीटें जीती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने अकेले ही 12 सीटों पर जीत पायी थी। माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 40 से 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

इन दलों के अलावा बिहार के और दलों मेंपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) है। जीतन राम मांझी बिहार के एक बड़े दलित नेता हैं। 2015 के चुनावों में हम ने अकेले 21 सीटों में चुनावो लड़ा था जिसमें से केवल 1 सीट पर उन्हें जीत मिली थी और लगभग 2 प्रतिशत वोट हासिल किये थे। वही 2020 के चुनाव में हम ने जेडीयू के साथ लड़ा था और 7 सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी।

उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए में है। इस पार्टी को ज्यादातर कोयरी और कुशवाहा समाज का वोट मिलता है जो बिहार की प्रमुख पिछड़ी जाती में आती हैं। 2015 में पार्टी ने 23 सीटों में चुनाव लड़ा था और उनमें से 2 सीटें जीती थी और लगभग 2.56 प्रतिशत वोट पाया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन से अलग कर लिया और बहुजन समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी (सोशलिस्ट) के साथ गठबंधन कर लिया। 2020 में 104 सीटों से चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टियाँ एमआईएम और बीएसपी कुल मिलाकर 6 सीटें जीतने में कामयाब रहीं। सबसे दिलचस्प घटनाक्रम मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) का उदय है। 2024 के उपचुनाव में इस पार्टी ने चार निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत वोट हासिल किए, जिसमें इमामगंज निर्वाचन क्षेत्र में जितेंद्र पासवान को 20 प्रतिशत वोट मिले। जेएसपी की राज्यव्यापी 'बिहार बदलाव यात्रा' ने इसकी जमीनी पहुंच को बढ़ाया है। हालांकि इसमें बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को उलटने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन ग्रामीण असंतोष और दोनों गठबंधनों के खिलाफ युवाओं की शिकायतें इसके राजनीतिक भविष्य को आकार दे सकती हैं।

द प्लुरलस पार्टी की स्थापना 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी ने की। इस पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना चुनावी डेब्यू (पहला चुनाव) किया और सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जिसमें पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी शामिल थीं, जिन्होंने बांकीपुर और बिस्फी सीटों से चुनाव लड़ा था।

हिन्द सेना के शिवदीप वामनराव लांडे ये तक ऐलान किया कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनके अलावा जन सुराज पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने भी बिहार के औरंगाबाद से ऐलान किया की वो भी सभी 243 सीटों में अकेले उतरेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये सारे छोटे दल किसी भी बड़े दल के साथ गढ़बंधन करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे तो इनका वोटकटवा बनने के ज्यादा आशंका है। दरअसल, ऐसा देखा गया है कि छोटे दल बड़े पार्टियों के वोटों को काटने की भूमिका निभाते हैं क्यूंकि इनमे ज्यादातर कोई उम्मीदवार सत्ता में नहीं आता मगर कुछ वोट जरूर ले जाता है जिससे चुनाव के परिणाम में फर्क पड़ता है। समुदाओं के वोट बिखरने से नतीजा बदल जाता है।

जन सुराज और द प्लुरलस पार्टी को छोड़ दें, तो बिहार की ज्यादातर नई और छोटी पार्टियों का आधार जातीय और क्षेत्रीय है। लेकिन सिर्फ जाति के दम पर चुनाव जीतना अब मुमकिन नहीं रहा। ये बात चिराग पासवान समझ गए हैं- वो पासवान समुदाय के मजबूत नेता हैं लेकिन अब वो भी समझते हैं कि सिर्फ एक जाति के वोट से बात नहीं बनेगी। यही वजह है कि वे इस बार गैर-आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, ताकि व्यापक जनसमर्थन हासिल किया जा सके।

अगर हम पारंपरिक दलों की बात करें, तो राजद का मुख्य वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है। वहीं, जदयू का आधार कुर्मी और कोरी समुदाय रहा है। इसके अलावा, बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते जेडीयू को सवर्ण जातियों जैसे राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण का समर्थन भी मिलने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आने से पासवान यानी दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी एनडीए खेमे में जुड़ता दिख रहा है। वीआईपी का मुख्य वोट बैंक निषाद समुदाय है, जिसमें लगभग 20 से 22 उपजातियां शामिल हैं। बिहार में यह समुदाय अति पिछड़ा वर्ग में आता है।राज्य की कुल आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 10% मानी जाती है, जो इसे राजनीतिक रूप से एक अहम ताकत बनाती है।अब सवाल ये है कि नई पार्टियां जैसे हिंद सेना, इंकलाब पाटीर्या जन सुराज इन पारंपरिक जातीय समीकरणों में कितना घुस पाती हैं? क्या ये दल किसी विशेष समुदाय में अपनी पकड़ बना पाएंगे, या सभी जातियों को जोड़कर कोई नई राजनीति गढ़ेंगे? यह तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा।

विभाजक ताकतों को उलाहना देती बाबुश्किन की हिंदी

उमेश चतुर्वेदी
(वरिष्ठ पत्रकार)

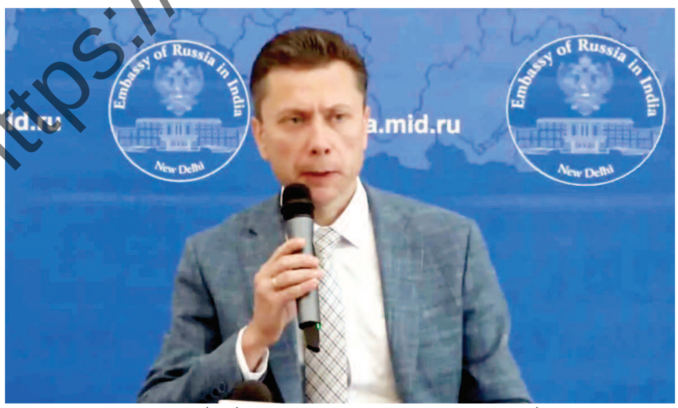

आज के रूस और उसके पूर्ववर्ती सोवियत संघ में हिंदी की पढ़ाई-लिखाई 1957 से ही शुरू हो गई थी, इस लिहाज से रूस के किसी नागरिक का हिंदी बोलना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। लेकिन आज के दौर में भारत स्थित रूसी दूतावास के दूसरे नंबर के अधिकारी रोमन बाबुश्किन अगर हिंदी के चंद लफ्जों का इस्तेमाल करें तो वह अहम हो जाता है। रूस से तेल खरीद के चलते अंकल सैम की आंखें इन दिनों भारत पर लाल हैं। इसी संदर्भ में 20 अगस्त को रूसी दूतावास ने एक प्रेस कांफ्रेंस रखी। उस प्रेस कांफ्रेंस में अपने संबोधन की शुरूआत बाबुश्किन ने हिंदी के दो वाक्यों से करके भारतीय भाषा प्रेमी पत्रकारों का दिल जीत लिया। बाबुश्किन का पहला वाक्य रहा, ह्यसभी का हार्दिक स्वागत है।ह्व

पत्रकारिता जगत की हस्तियों की श्रवणेंद्रिय इस हिंदी प्रयोग का झटका झेल रही थीं, कि बाबुश्किन ने ठेठ भारतीय सांस्कृतिक अंदाज में दूसरा वाक्य छोड़ दिया, 'हम शुरूआत करेंगे...भगवान गणेश के साथ। गणेश चतुर्थी आ रही है। बाबुश्किन का हिंदी बोलना भारतीय राजनीति और समाज के उस तबके के लिए सीख हो सकता है, जो हिंदी का सवाल आते ही भड़क उठते हैं। जिन्हें विदेशी अंग्रेजी तो ग्राह्य और स्वीकार्य है, लेकिन हिंदी उनकी अपनी अस्मिता पर सवाल उठाती लगती है। आजाद भारत की राजनीति जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किस कदर विभाजित हुई है, इसे समाज तो रोज ही झेलता-देखता है। इस विभाजक सोच का ही असर है कि हमारी अपनी भाषाओं के बीच भी झगड़े पैदा किए जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के विरोध में राजनीति खूब खड़ा कर रही है और इसके जरिए वह अपना सियासी उल्लू ही सीधा करती है। नैरंतर्य और सकारात्मकता के लिहाज से देखें तो इसके सामाजिक विघटन की नींव ही मजबूत हो रही है। अस्मिता बोध को जगाने की आड़ में भाषायी वैमनस्य की राजनीति का एकमात्र मकसद सामाजिक विघटन को बढ़ाना और उस बंटे समाज के बीच से अपने खांचे में फिट बैठने वाला बड़ा समर्थक आधार वर्ग तैयार करना है।

इसीलिए जब नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के जरिए प्राथमिक शिक्षा की बात होती है तो हिंदी को किनारे लगाने के लिए तमिल राजनीतिक अस्मिता उठ खड़ी होती है। कन्नड़ और बांग्ला भाषा बोध भी हिंदी के खिलाफ उठ खड़ा होता है। दिलचस्प यह है कि स्थानीय भाषा बोध के इन खिलाड़ियों के लिए वह अंग्रेजी अपनी हो जाती है, जिसकी कथित तौर पर वैश्विक व्यापकता है। हालांकि हकीकत यह है कि अंग्रेजी की व्यापकता गहराई से देखें तो अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और हांगकांग में ही है।

अंग्रेजी को तो बाबुश्किन ने भी अपना रखा है। भारतीय पत्रकारों के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बाद में वे अंग्रेजी में ही बोले। लेकिन हिंदी में बोलकर उन्होंने एक तरह से भारतीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी स्थानीय समुदायों के दिल तक अपनी पैठ बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं के कुछ शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरूआत करते रहे हैं। पता नहीं, बाबुश्किन ने हिंदी बोलकर वहां उपस्थित कितने भारतीय पत्रकारों का दिल जीता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया पर जब से उनकी मीठी प्रचारित हुई है,उन्होंने ठेठ भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया है।

सोवियत संघ में हिंदी फिल्में काफी पसंद की जाती रही हैं। एक दौर में राजकपूर की फिल्में खासा लोकप्रिय रही हैं। राज कपूर अभिनीत फिल्म श्री 420 का गीत ह्यमेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानीह्व एक दौर में सोवियत संघ के घर-घर का पसंदीदा गीत बन गया था। कम्युनिस्ट शासन के दौर में रूस की राजधानी मास्को में हिंदी में दो प्रकाशक भी सक्रिय रहे, प्रगति प्रकाशन और रादुगा प्रकाशन। इन प्रकाशनों के जरिए रूसी लेखकों के साथ ही लेनिन, स्टालिन आदि की रचनाएं हिंदी में अनूदित होकर सस्ते में उपलब्ध होती थीं। एक दौर में सोवियत संघ की दो पत्रिकाएं ह्यसोवियत देशह्व और 'स्पूतनिकह्व भारत में बहुत प्रचलित थे। हिंदी की वहां पढ़ाई भी खूब होती है। इसकी शुरूआत 1955 में हुई। उसके पहले तक रूस की भारत में दिलचस्पी संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन तक सीमित थी। साल 1955 में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव ने भारत का दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, "हम यह देखेंगे कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी विकसित हो जिसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण-सम्पन्न नई पीढ़ी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखें।"इसी के बाद सोवियत संघ में हिंदी प्रकाशन और पढ़ाई-लिखाई की शुरूआत हुई। आज रूस के मास्को राजकीय विश्वविद्यालय, रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्वविद्यालय, सांक्त

इसीलिए जब नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के जरिए प्राथमिक शिक्षा की बात होती है तो हिंदी को किनारे लगाने के लिए तमिल राजनीतिक अस्मिता उठ खड़ी होती है। कन्नड़ और बांग्ला भाषा बोध भी हिंदी के खिलाफ उठ खड़ा होता है। दिलचस्प यह है कि स्थानीय भाषा बोध के इन खिलाड़ियों के लिए वह अंग्रेजी अपनी हो जाती है, जिसकी कथित तौर पर वैश्विक व्यापकता है। हालांकि हकीकत यह है कि अंग्रेजी की व्यापकता गहराई से देखें तो अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और हांगकांग में ही है। अंग्रेजी को तो बाबुश्किन ने भी अपना रखा है। भारतीय पत्रकारों के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बाद में वे अंग्रेजी में ही बोले। लेकिन हिंदी में बोलकर उन्होंने एक तरह से भारतीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी स्थानीय समुदायों के दिल तक अपनी पैठ बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं के कुछ शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरूआत करते रहे हैं। पता नहीं, बाबुश्किन ने हिंदी बोलकर वहां उपस्थित कितने भारतीय पत्रकारों का दिल जीता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया पर जब से उनकी मीठी प्रचारित हुई है,उन्होंने ठेठ भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया है। सोवियत संघ में हिंदी फिल्में काफी पसंद की जाती रही हैं। एक दौर में राजकपूर की फिल्में खासा लोकप्रिय रही हैं। राज कपूर अभिनीत फिल्म श्री 420 का गीत ह्यमेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानीह्व एक दौर में सोवियत संघ के घर-घर का पसंदीदा गीत बन गया था। कम्युनिस्ट शासन के दौर में रूस की राजधानी मास्को में हिंदी में दो प्रकाशक भी सक्रिय रहे, प्रगति प्रकाशन और रादुगा प्रकाशन। इन प्रकाशनों के जरिए रूसी लेखकों के साथ ही लेनिन, स्टालिन आदि की रचनाएं हिंदी में अनूदित होकर सस्ते में उपलब्ध होती थीं। एक दौर में सोवियत संघ की दो पत्रिकाएं सोवियत देश और 'स्पूतनिक भारत में बहुत प्रचलित थे। हिंदी की वहां पढ़ाई भी खूब होती है। इसकी शुरूआत 1955 में हुई। उसके पहले तक रूस की भारत में दिलचस्पी संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन तक सीमित थी। साल 1955 में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव ने भारत का दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की।

पीटरबर्ग विश्वविद्यालय, विद्यालय क्रमांक 19, मास्को, फार ईस्ट विश्वविद्यालय, ब्लादीवोस्तक आदि में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिन्दी की कक्षाएं चल रही हैं। जिनमें हर आयु वर्ग लोग हिंदी सीख रहे हैं। साफ है कि विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं, भारत आए विदेशी हिंदी बोल रहे हैं। इस्कॉन के मंदिरों में जाकर देखा जा सकता है, भगवान कान्हा के विदेशी भक्त भी मीठी हिंदी में बात करते मिल जाएंगे। लेकिन हमारी ही राजनीति के ही एक वर्ग को हमारी हिंदी से परहेज है। ऐसे लोगों के लिए बाबुश्किन की मीठी हिंदी एक तरह मीठा उलाहना है। बाबुश्किन जैसों की जुबान से निकली हिंदी भारतीय भाषा प्रेमियों के लिए नव उत्साह के संचार का जरिया है। ऐसे सुखद हादसों से हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषा प्रेमी भी प्रेरित होते हैं। काश कि हमारी राजनीति भी इसे समझती, इससे प्रेरित होने की कोशिश करती और भाषा के नाम पर होने वाली विभाजनकारी राजनीतिक कर्म से बचती।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संपादकीय

मछुआरा बिल्ली की खोज में

डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन, सुशील चंदानी

भारत में जगंली (wild) बिल्ली परिवार की 15 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन ज़्यादा ध्यान अमूमन बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे शेर, बाघ पर दिया जाता है। लोगों को छोटी जंगली बिल्लियों, जैसे स्याहगोश (कैरकाल, caracal), रोहित-द्वीपी बिल्ली (rusty spotted cat), मछुआरा बिल्ली आदि के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये छोटी और गुमनाम बिल्लियां भी उचित पहचान की हकदार हैं, क्योंकि ये अपने से कहीं ज़्यादा बड़े और बढ़ते खतरों से भरी दुनिया में विचरण कर रही हैं।

भारत की आर्द्रभूमियां मछुआरा बिल्लियों (Prionailurus viverrinus) के घर हैं। देश में इनके कई नाम हैं- बनबिरल, खुप्या बाघ, माचा बाघा वगैरह। यह पश्चिम बंगाल की राज्य पशु है और इसे बघरोल या मेचो बिराल कहा जाता है।

ये बिल्लियां आकार में घरेलू बिल्ली से दुगनी होती हैं, वज़न 7 से 12 किलोग्राम होता है, और इनके भूरे-भूरे रंग के बालों पर काले चित्ते होते हैं। अपने अधिकार-क्षेत्र (इलाके) में यह बिल्ली अक्सर शीर्ष शिकारी होती है, यानी कोई अन्य प्राणी इनका शिकार नहीं करता। आर्द्रभूमियां जीवंत पारिस्थितिक तंत्र होती हैं, नदी के बाढ़ क्षेत्र या मैंग्रोव और दलदल जहां ये पाई जाती है।

मछुआरा बिल्ली में हुए कुछ असामान्य अनुकूलन उन्हें नम परिवेश में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। आंशिक रूप से जालीदार पंजे, घना जलरोधी आवरण (फर) और पानी में पूरी तरह डूबे होने पर भी तैरने की क्षमता इसकी जलीय प्रवृत्ति बताती है। उभरे हुए पंजे, जिन्हें पूरी तरह से अंदर नहीं खींचा जा सकता, बिल्ली को फिसलन भरी मिट्टी में पकड़ बनाने और मछलियों को पकड़ने में मदद करते हैं। बिल्लियों का आहार मुख्य रूप से मछली है, हालांकि कृंतक, मुर्गियां और अन्य छोटे जानवर खाने से भी ये परहेज़ नहीं करती हैं।

शिकार की फिराक में मछुआरा बिल्ली का आधा समय जलस्रोत के किनारे खड़े, बैठे या दुबके हुए बीतता है। इसके शिकार करने का बमुश्किल 5 प्रतिशत समय ही पानी के अंदर बीतता है। उथले पानी में बिल्ली धीरे-धीरे चलती रहती है, अपने पंजों से मछली को उचकाती है और फिर उसे मुंह से पकड़ लेती है।

मछुआरा बिल्लियों को फैलाव काफी बिखरा हुआ है- हिमालय का तराई क्षेत्र, पश्चिमी भारत के कुछ दलदली क्षेत्र, सुंदरवन, पूर्वी तट और श्रीलंका।

इन निशाचर, छुपी रुस्तम बिल्ली की बिखरी हुई आबादी पर नज़र रखने के लिए वन्यजीव सर्वेक्षणकर्ता जलस्रोतों के नज़दीक कैमरा ट्रैप लगाते हैं। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की तियासा आद्या और उनके सहयोगियों के एक नेटवर्क (द्धद्बह्यद्ध-द्धठ्ठद्दष्ड्डह्ल.श्र्ह्द) द्वारा चिल्का झील में विस्तृत गिनती की गई है, जहां मछलियां बहुतायत में हैं और मनुष्यों के साथ उनका टकराव सीमित है। उनके परिणामों का विस्तार करने पर ऐसा अनुमान है कि मछुआरा बिल्लियों की संख्या झील के 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीबन 750 है।

यह आशाजनक संख्या सुंदरबन में बिल्लियों की तेज़ी से घटती संख्या के विपरीत है। इस साल की शुरुआत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) में मछुआरा बिल्ली देखी गई है, इसके दिखने के पहले तक ऐसा माना जाता था कि मछुआरा बिल्लियां राजस्थान में विलुप्त हो चुकी हैं।

यह गिरावट मुख्यत- उनके प्राकृतवास में कमी के कारण है। ऐसा अनुमान है कि पिछले चार दशकों में भारत की 30-40 प्रतिशत आर्द्रभूमियां खत्म हो गई हैं या बहुत अधिक सिमट गई हैं। इसलिए, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना मछुआरा बिल्लियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के अतिक्रमण ने भी मछुआरा बिल्लियों और उनके प्राकृतवास को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई लोग उन्हें मछलियों और मुर्गियों के शिकारी के रूप में देखते हैं, नतीजतन मनुष्य अपने पालतुओं के शिकार का बदला इन्हें मारकर लेते हैं। मनुष्यों द्वारा बदले की भावना से की गई हत्याओं की एक बड़ी संख्या दर्ज है। समुदाय-आधारित संरक्षण कार्यक्रम इस शत्रुभाव को कम करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।

निरोगी काया के लिए कुछ बदलें कुछ सुधारें आदतें

रोज प्रातः हल्का पैदल चलना या कुछ व्यायाम अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम भी अवश्य करें। यह हो गया शारीरिक और मानसिक व्यायाम। ये न केवल आपकी ओबेसिटी पर प्रहार करेगा बल्कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा।

- डॉ. अंशुल उपाध्याय -

अगर आप बीमार है, और इलाज ढूंढ रहे हैं तो आपको अपनी बीमारी पर चारो तरफ से वार करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि, जब भी आपको मामूली बुखार, या सर्दी-खांसी होता है तो ,आप डॉक्टर के पास जाकर एलोपैथी दवाई ले आते हैं। और तीन-चार दिन में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। परंतु वह तीन-चार दिन भी जब आप बीमार हुए थे तब आपका शरीर तो अंदर से कमजोर हो गया और फिर कुछ दिनों बाद वापस वही सर्दी खांसी आपको लौट कर आएगी। एलोपैथी तुरंत आराम तो दे देती है पर वो आपके मर्ज को सिर्फ दवा कर रखती हैं उसे पूरी तरह से ठीक नहीं करती। ठीक तो आपके शरीर को खुद आपका शरीर ही करता है। इसलिए अगर किसी भी बीमारी का आप जड़ से इलाज चाहते हैं तो अपनी दैनिक जीवन चर्या में कुछ चीजों को आपको शामिल करना होगा।

व्यायाम-प्राणायाम बने जीवन का हिस्सा

रोज प्रातः हल्का पैदल चलना या कुछ व्यायाम अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम भी अवश्य करें। यह हो गया शारीरिक और मानसिक व्यायाम। ये न केवल आपकी ओबेसिटी पर प्रहार करेगा बल्कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा।

भोजन को चुनने में रखे सावधानी

आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हफ्ते में अगर आप दो दिन तला भुंजा खा रहे हैं तो 4 दिन सादा भोजन करे। हो सके तो हफ्ते में एक दिन 15 से 20 घंटे का उपवास अवश्य करें। इसके पश्चात भोजन में आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि,जो अनाज आप खा रहे हैं वह विभिन्न तरह के रासायनिक छिड़काव होने के बाद आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप उसे खा रहे हैं तो बीमारियों को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप जैविक खेती के द्वारा उत्पन्न कीटनाशी मुक्त अनाज जिसको कि आप ऑर्गेनिक कहते हैं वह खा रहे हैं, तो उसके द्वारा बहुत सी बीमारियों की संभावनाओं को तो आपने वैसे ही दूर कर दिया है। क्योंकि ÷जैसा खायेंगे अन्न वैसा ही रहेगाआपका मन÷

कीटनाशी युक्त भोजन आपके पेट में जाकर आपको नुकसान ही पहुंचाता है, आपके शरीर में यूरिया की मात्रा को बढ़ा देता है। किडनी, लीवर की समस्याएं बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ कई तरह के कैंसर सेल के विकास में भी यह कीटनाशी सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि भले थोड़ा महंगा अनाज खरीदे पर ऑर्गेनिक अनाज ही खरीदे और खाए। कीटनाशक युक्त अनाज और सब्जियां पाचन में भी अधिक समय लेते हैं। और वह जितने समय तक आपके शरीर के अंदर के फंक्शन में सफर करते रहते हैं,उतना ज्यादा उनके हार्मफुल इफेक्ट आपके शरीर को होते हैं जिनमें कब्ज, एसिडिटी की समस्या तो आम बन गई हैं।

भोजन पकाने के बर्तनों पर भी दे ध्यान

पीतल, तांबे के बटुए में बना हुआ भोजन ही खाएं। पीतल के बटुए को भीतर से रांगा की पॉलिश करवा लें इससे दही मट्ठेका भी अगर आप प्रयोग करके कुछ बना रहे हैं तो वह नुकसान नहीं करेगा। साथ ही एल्युमिनियम के बर्तनों को अपने किचन से निकाल दीजिए। बिल्कुल बहिष्कृत कर दीजिए। चाहे कढ़ाई हो, कुकर हो या भगोनी हो। क्यूंकि, एल्युमिनियम में ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपकी याददाश्त को प्रभावित करता है और यह धीरे-धीरे आपके भूलने की प्रवृत्ति को बढ़ता जाता है। हमारे देश में पहले एल्युमिनियम का उपयोग नहीं किया जाता था। पर जब अंग्रेज भारत आए तो अपने साथ एल्यूमीनियम ले कर आए और उसका कारण ही यही था कि भारत के लोग जो इतने बुद्धिमान और सृजनशील थे तो इनके दिमाग को सुस्त करके इन पर राज कैसे किया जाए। इसलिए अंग्रेजों ने एल्युमिनियम के बर्तनों का चलन भारत में बढ़ा दिया । सस्ता होने के कारण लोग उन्हें खूब खरीदने भीलगे। अंग्रेज स्वयं तो पीतल, तांबे और सोने, चांदी के बर्तन उपयोग करते थे। कांच के और चीनी मिट्टी के बर्तन उपयोग करते थे। पर भारतीयों को उनके पीतल और कांसे से उन्होंने धीरे-धीरे दूर कर दिया। आज लगभग हर घर में आपको एल्युमिनियम के कढ़ाई, कुकर आसानी से देखने मिल जाएंगे जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है ।

एलोपैथी दवाइयों का उपयोग करें सीमित

अगर आप स्वस्थ रहना चाहते है तो एलोपैथिक दवाइयो से भी थोड़ी दूरियां बना लें । थोड़ी बहुत सर्दी-खांसी के इलाज के लिए दो या तीन दिन तक तो आप कोई भी दवाई ना खाएं घर पर ही बना तुलसी-अदरक का काढ़ा पीए,जिसमें हल्दी-गुड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। विटामिन सी युक्त पदार्थ नींबू , मौसंबी , आंवला का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। जो भी जिस सीजन में आपको उपलब्ध हो।

इस तरह से घरेलू उपाय कीजिए। यदि बहुत अधिक बड़ी कुछ समस्या है जिसका घर पर इलाज संभव नहीं है उसके लिए ही एलोपैथी की तरफ जाए कहने का तात्पर्य ये है की, जरा सा सर दर्द हुआ थोड़ा बॉडी एक हो रहा है, थोड़ी सर्दी खांसी हो गई फटाफट एलोपैथी गोली खा ली ये कितना आसान हैं पर इससे आपको एक या दो दिन में आराम तो मिल जाएगा पर उसके जो साइड इफेक्ट होंगे वह आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको,आपकी नसों को ब्लॉक करने में और अन्य दूसरे बीमारियों को जनित करने में अपना योगदान निभाते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके एलोपैथी से परहेज कीजिए अगर आप युवा है, बच्चे हैं तो आप पूरी तरह से एलोपैथी को ना कर सकते हैं। आपके शरीर में खुद अपने आप को इम्यून कर लेने की क्षमता होती है।

पीने के पानी पर भी दें ध्यान

पानी से ही हमारा शरीर बना है और हमारे शरीर में पानी की मात्रा ही सबसे अधिक होती हैं। सो पीने के लिए हमेशा नेचुरल पानी का ही उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतलों में अगर पानी आप ले रहे हैं तो पहले इसे मटके में डालिए और उसके बाद उपयोग कीजिए और अधिक शुद्ध करना चाहते हैं तो ठंड के समय में तांबे-पीतल के घड़े में पानी राखिए इसके भीतर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और गर्मियों के समय में मिट्टी के घड़े में पानी रखिए और इसके अंदर एक तांबे का और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए इसके बाद जो आप यह पानी पियेंगे तो यह पूरी तरीके से शुद्ध पानी होगा। जो आपके शरीर में जाएगा। आर.ओ. के पानी का पी.एच.भी समय-समय पर चेक करवाते रहें।

ऊपर जो लिखा है आपको बस इतना ही करने की आवश्यकता है, यह सब कार्य आपके शरीर को इतना मजबूत बना देंगे कि, आपका शरीर छोटी-बड़ी बीमारियों से खुद ही अपने आप को इम्यून कर लेगा और आपको कभी भी किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आपका शरीर बचा रहेगा।

पांच नए समुद्री कानून भारत के विज़न आत्मनिर्भर भारत 2047 में विकसित राष्ट्र और वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने में अहम रोल अदा करेंगे

किशन सनमुखदास भावनानी

भारत को प्राचीन काल से ही समुद्री सभ्यता और व्यापारिक शक्ति के रूप में जाना जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल बंदरगाह से लेकर चोल साम्राज्य की दक्षिण-पूर्व एशिया तक विस्तृत समुद्री कूटनीति, भारत ने हमेशा सागर को अपनी समृद्धि और शक्ति का आधार बनाया है।लेकिन औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक समुद्री क्षेत्र में व्यापक सुधार नहीं हो पाए।वर्तमान में वैश्विक व्यापार का लगभग 80 पेर्सेंट वॉल्यूम और 70 पेर्सेंट वैल्यू समुद्री मार्ग से होती है। भारत की तटीय लंबाई 7,517 किमी है,200 से अधिक बंदरगाह और विशाल एक्सक्लुसिव इकोनॉमिक्स झोन है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि फिर भी भारत का योगदान वैश्विक शिपिंग में सीमित रहा।इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 2025 में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक साथ पांच बड़े समुद्री विधेयक लाकर संसद के दोनोंसदनों में पारित कर कानून बनाकर एक समग्र समुद्री सुधार पैकेज प्रस्तुत किए जो, सिर्फ विधायी सुधार नहीं, बल्कि भारत की समुद्री क्रांति हैं। ये कानून न केवल व्यापार दक्षता बढ़ाएंगे,बल्कि भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाएंगे। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज मिलेगा,बल्कि नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास औरआत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह कदम एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,भारत में पांच नए समुद्री कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज देने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्लू इकोनामी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेंगे। साथियों बात अगर हम संसद के मानसून सत्र 2025 के दोनों सदनों में पारित होकर कानून बनें इन पांचो समुद्री कानूनों को जानने की करें तो,(1) बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025- बिल्स ऑफ लैडिंग समुद्री व्यापारका सबसे अहम दस्तावेज होता है,जो माल ढुलाई का प्रमाण, स्वामित्व का सबूत और व्यापारिक अनुबंध का हिस्सा होता है। नए विधेयक का उद्देश्य इसे डिजिटल और ब्लॉकचेन- आधारित प्रणाली से जोड़ना है ताकि नकली दस्तावेज़, धोखाधड़ी और पारदर्शिता की कमी को दूर किया जा सके। इसका प्रभाव यह होगा कि निर्यातक और आयातक दोनों को सुरक्षित और तेज़ लेन-देन की सुविधा मिलेगी। (2) समुद्री माल ढुलाई विधेयक,2025-यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में माल ढुलाई अनुबंधों को विनियमित करेगा। अब जहाज़ कंपनियों, निर्यातकों और आयातकों के बीच विवाद समाधान तेज़ होगा। बीमा, देरी और हर्जाने के मामलों में स्पष्ट प्रावधान दिए गएहैं।इससे भारत का इज़ीऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग बेहतर होगी।(3) व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक,2025-यह कानून भारतीय जहाज़ी बेड़े के आधुनिकीकरण और नए पोतों में निवेश को बढ़ावा देगा। विदेशी जहाज़ कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा। साथ ही, घरेलूशिपबिल्डिंग इंडस्ट्री और रोजगार में उछाल आएगा।(4) तटीय नौवहन विधेयक,2025- तटीय नौवहन कानून घरेलू व्यापार और यात्री सेवाओं को नई दिशा देगा।यह ÷एक देश-एक परमिट÷ की अवधारणा लाता है, जिसके तहत जहाज़ आसानी से भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर बिना जटिल प्रक्रियाओं के संचालन कर सकेंगे।इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और माल परिवहन तेज़ होगा।(5) भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 -यह कानूनभारतीय बंदरगाहों को स्वायत्त, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर केंद्रित है। इसमें ग्रीन पोर्ट्स, स्मार्ट पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना है। इसका सीधा प्रभाव भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा। साथियों बात अगर हम इन पांचो कानून के फायदे को प्वाइंटों में समराइस करनें व एक साथ ही पेश पारितकरने को समझने की करें तो,(1)भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज-जीडीपी योगदान- 2030 तक भारत की ब्लू इकॉनमी जीडीपी का 12पेर्सेंट तक योगदान कर सकती है,जो वर्तमान में 4 पेर्सेंट हैं।(2) लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी- 13-14 पेर्सेंट से घटकर 8-9 पेर्सेंट तक। (3) रोज़गार सृजन- शिपबिल्डिंग और पोर्ट लॉजिस्टिक्स में 20 लाख से अधिक नए अवसर। (4)निर्यात प्रतिस्पधार्- तेज़ डिलीवरी और कम लागत से भारत डब्लूटीओ सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में मज़बूत होगा। (5) नीली अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ भूमिका-नीली अर्थव्यवस्था सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है। इसमें मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री खनिज, ऑफशोर ऊर्जा, और बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल हैं।यूएनसीटीएडी की 2023 रिपोर्ट बताती है कि ब्लू इकॉनमी से विश्व स्तरपर 3 डॉलर ट्रिलियन जीडीपी जुड़ी हुई है।भारत की,ईईजेड (2.4 मिलियन वर्ग किमी) दुनियाँ में सबसे बड़ी में से एक है।(6) नए कानून समुद्री ऊर्जा (ऑफशोरे विंडो,वेव एनर्जी), खनिज संसाधन (पॉलिमटेलिक नोडल्स), और समुद्री बायोटेक्नोलॉजी को कानूनी ढांचा देंगे। (7) व्यापार दक्षता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा- डब्लूटीओ की ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रीमेंट (टीएफए) में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और तेज़ क्लियरेंस की अनिवार्यता है,जो भारत के नए कानून इससे मेल खाते हैं। (8)आईएमओ के ग्रीन शिपिंग टारगेटस (2050) के तहत जहाज़ों से कार्बन उत्सर्जन 50 पेर्सेंट घटाने का लक्ष्य है। भारत का व्यापारिक पोत कानून इसी दिशा में ÷ग्रीन शिपिंग÷को बढ़ावा देगा। (9) चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव (बीआरआई) समुद्री बंदरगाह नेटवर्क तैयार कर रहा है। भारत इन सुधारों से एशियाई सप्लाई चेन में एक मज़बूत विकल्प बनेगा। (10) पांच विधेयक एक साथ क्यों- (द्ब)उद्योग को स्पष्ट संदेश कि भारत सिर्फ टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्र सुधार चाहता है।(द्बद्ब)डब्लूटीओ और आईएमओ की अंतरराष्ट्रीयबाध्यताओं को एक साथ पूरा करना। (द्बद्बद्ब)औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त करने का राजनीतिक और आर्थिक संकल्प।(द्ब1)÷मारिटाइम इंडिया विज़न 2047÷ का रोडमैप तैयार करना। (11) औपनिवेशिक कानून का अंत और नई शुरुआत- (i)अंग्रेजों के जमाने के कानून व्यापार को नियंत्रित करने के लिए थे, भारत के हितों के लिए नहीं। (ii) अब नए कानून भारतीय समुद्री स्वायत्तता का प्रतीक हैं। (iii) इससे तटीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा-(i) मछुआरों को आधुनिक कोल्ड-चेन और तेज़ निर्यात सुविधा। (ii) तटीय पर्यटन उद्योग को स्मार्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। (iii) स्थानीय युवाओं को लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार।

पर्व, मनोवैज्ञानिक रूप में समाज का दर्पण होता है

इन पचों में जहाँ आमोद-प्रमोद, उल्लास का वातावरण रहा है, वहीं मानव की कुछ विशेष भावनाएँ, कल्पना, आकांक्षाएँ, इच्छाएँ भी जुड़ी हैं। सुख व आरोग्य की कामना, वैभव-प्राप्ति की अभिलाषा और उसके साथ पारिवारिक, सामाजिक वातावरण में स्वच्छता, सुन्दरता, नयापन और अभिनव आकर्षण पैदा करने की स्वाभाविक उत्कंठा भी झलक रही है;

- कांतीलाल मंडोत -

देश मे गणेशजी की पूजा,अर्चना की धूम देखने को मिलेगी।डीजे की धुन पर गणपति बापा मोरया की ध्वनि से आकाश गुंजायमान होगा।गणपति की प्रतिमा की खरीदी भक्तजन करने लग गए है।गणपति के मंडप सजाए जा रहे है।इस बीच चौक चौराहा पर गणपति की प्रतिमा की पूजा,अर्चना और आरती का नियमित क्रम शुरू हो जाएगा। पर्व उस समाज की सभ्यता, संस्कृति, रुचि और इतिहास का प्रतीक होता है। वह अध्यात्म एवं समाज चेतना का अन्तःप्रवाही स्रोत है। पर्व के पीछे समाज के आदर्श कहीं प्रतीक कल्पना के रूप में और कहीं इतिहास के घटनाक्रम के रूप में जुड़े रहते हैं।पर्व मनोवैज्ञानिक रूप में समाज का दर्पण होता है। हमारे प्राचीन समाज संस्थापकों ने, इतिहास निर्माताओं ने तथा समाज के सुचारु संचालन के लिए आदर्श व रीति-रिवाज बनाने वालों ने पर्वो के रूप में जो परम्पराएँ, रीति-रिवाज, खान-पान, व्यवहार के आदर्श स्थापित किये हैं, उनके पीछे मानव समाज के चतुर्मुखी विकास की परिकल्पना रही है। पर्वो की प्रेरणा में सबसे मुख्य बात है सामूहिक भावना की। सबके साथ मिलकर आमोदमय वातावरण में पर्व मनाये जाते हैं। केवल देव-देवी की पूजा, मेले-ठेले और प्रसाद व मिठाइयाँ खाना मात्र पर्वो का उद्देश्य नहीं है।

पर्वो के लिए भारत के राष्ट्रीय जागरण के मुख्य सूत्रधार लोकमान्य तिलक ने एक विचारोत्तेजक प्रेरणा सूत्र दिया है-ग्रामे-ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे-ग्रामे कथा शुभा। पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सवः ॥ पर्वो के दिन गाँव-गाँव में सभा की जाये, प्रवचन आदि द्वारा पर्वो पर प्रकाश डाला जाय। पाठशालाएँ और व्यायामशालाएँ स्थापित की जायें जिससे जनता का अज्ञान एवं बीमारियाँ दूर हों इस प्रकार पर्व को सामूहिक रूप प्रदान करें।यद्यपि पर्वो की परम्परा के साथ धीरे-धीरे रूढ़ियाँ व गलत व्यवहार भी स्थापित हो गये। वर्तमान जीवन में जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने उनके साथ अपने व्यक्तिगत हित, स्वार्थ तथा रूढ़ मान्यताओं को भी इस प्रकार गड्ड-मड्ड कर दिया है कि समूचे पर्व का रूप ही विकृत हो गयां है। ऐसा होता है-गंगोत्री की धारा से बहने वाली गंगा की निर्मल धारा में जंगलों का कूड़ा कचरा,नगरों की गंदगी आदि भी मिलती रहती है। नवी का निर्मल जल गंदा होता रहता है। किन्तु पीने के लिए उस पानी को उपयोग करने वाले उसे शुद्ध निर्मल कीटाणुरहित करने की प्रक्रिया अपनाकर उस मलिन, दूषित जल को भी संस्कारित कर पीने योग्य बना लेते हैं। परम्परा और पर्षो की धारा भी इसी प्रकार अनेक रूढ़ियों, स्वार्थी, धारणाओं, अंध-विश्वासों आदि से दूषित होती आई है, किन्तु विवेकशील विचारक उनका कूड़ा-कचरा छाँटकर उनको सुधारकर सभाज के विकास व उल्ल्लास सूचक रीति-रिवाजों से सप्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं।पर्वो को सामूहिक विचार जागृति तथा सामुदायिक उल्लास के रूप में मनाने से समाज की नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है और कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है।

इन पचों में जहाँ आमोद-प्रमोद, उल्लास का वातावरण रहा है, वहीं मानव की कुछ विशेष भावनाएँ, कल्पना, आकांक्षाएँ, इच्छाएँ भी जुड़ी हैं। सुख व आरोग्य की कामना, वैभव-प्राप्ति की अभिलाषा और उसके साथ पारिवारिक, सामाजिक वातावरण में स्वच्छता, सुन्दरता, नयापन और अभिनव आकर्षण पैदा करने की स्वाभाविक उत्कंठा भी झलक रही है; इसलिए तो मैं मानता हूँ पर्व के रूप में मानव मन की अनेक गुप्त-सुप्त इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ अभिव्यक्त होती हैं। जिन भावों को वह वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता, उनको प्रकट कर देती है।

राहुल और तेजस्वी पारिवारिक विरासत सम्भाल रहे हैं

दोनो की विचारधारा एक है। यह साझा नजारा है। बड़ी सी मुस्कराहट और गर्मजोशी से झप्पी और एक दूसरे से हाथ मिलाने का नजारा देखने को मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा और न्याय में राहुल और तेजस्वी एक साथ लोगो से मिल रहे है।यात्रा का स्टेयरिंग तेजस्वी के हाथ मे है।

- कांतीलाल मंडोत -

राहुल और तेजस्वी यादव की बहुत गहरा याराना है।दोनो नेता के बीच बिहार में मतदाता सूची को लेकर काफी चिंता है।तेजस्वी की राह पर राहुल चल रहे है।

कांग्रेस-राजद गठबंधन नही है,लेकिन डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। बिहार में नया राजनीतिक प्रयोग प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी गठबंधन था। पचास साल का राजनीतिक इतिहास यही बताता है।इस मायने में इतिहास को नकारने की यह कोशिश है या राजनीतिक विवशता ? कांग्रेस का वर्चस्व 1967 में टूटा। तब गैर कांग्रेस वाद का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उसी के राजनीतिक परिणाम है, लालू प्रसाद यादव। उस प्रयोग ने ही अनेक टेढ़े-मेडे खतरनाक रास्ते पार किए। कांग्रेस को हासिए पर पहुंचा दिया।उसे भुलाना लालू के लिए आसान नहीं है,लेकिन तेजस्वी को उसको याद भी नहीं है। उनकी पारिवारिक विरासत राहुल संभाल रहे हैं, राजनीतिक विरासत नहीं। यही बात तेजस्वी यादव पर भी लागू होती है। वे लालू की राजनीतिक विरासत को भुला कर अपने बूते वोटरों को लुभाने पर तुले हैं। दोनो दल के नेताओ में इस अंतर्विरोध में एक समानता है। तेजस्वी और राहुल इतिहास के बोझ से मुक्त हैं। इतिहास दृष्टि से भी। इसलिए वे एक साथ खड़े हो सकते है। बिहार में नारा भी दे रहे है।तेजस्वी ने राहुल से हाथ मिलाने और भाजपा का विरोध करने की ठान ली है। गठबंधन की चाभी राहुल के पास है। तेजस्वी और राहुल मीडिया के सामनेभी साथ मे है। दोनो की विचारधारा एक है। यह साझा नजारा है। बड़ी सी मुस्कराहट और गर्मजोशी से झप्पी और एक दूसरे से हाथ मिलाने का नजारा देखने को मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा और न्याय में राहुल और तेजस्वी एक साथ लोगो से मिल रहे है।यात्रा का स्टेयरिंग तेजस्वी के हाथ मे है।गठबंधन की विरासत आगे बढ़ा रहे है।सासाराम से यात्रा शुरू की है।16 दिनों तक यात्रा जारी रहेगी। इस यात्रा से बिहार में कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश है।बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर फोकस किया जा रहा है।जुठ की सियासत पर पार्टी को जीवनदान देने के लिए गठबंधन की यात्रा को तूल दिया जा रहा है।वोटर अधिकार यात्रा में सभीदलों के नेता मौजूद है।सिकंदरा, जमुई के साथ तेजस्वी भी सहमत हुए है।तेजस्वी राहुल के रथ के सारथी बने हुए है।उनके इशारों पर राजनैतिक गर्मियां तेज हो गई है।गठबंधन के जरिये लोगो को वोटर अधिकार के लिए भाजपा के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगाकर सेंधमारी की कोशिश कहा तक ले जाएगी?यह समय की बलिहारी है।इस तरह नए राजनीतिक प्रयोग की शुरूआत हुई।सब कुछ पहले से तय लग रहा था। बिना वजह भाजपा को परेशान करना शुरूं किया है।

जूठे आरोप लगाकर मीडिया में छाए रहना दोनो का मकसद है।उतरप्रदेश में अखिलेश के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया।न साथ पसंद हैन काम पसंद वाली युक्ति फलीभूत नही हो सकी।अखिलेश भी साइकिल यात्रा निकाल रहे है।तेजस्वी के साथ राहुल का दोस्ताना गठबंधन से परे सतारूढ़ पर आरोप के लिए दिखाई दे रहा है। पूर्व विधानसभा चुनाव में अखिलेश के सलाहकारों ने उन्हें नारा दिया। जिसे वे बोले %साइकिल के साथ हाथ हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। से भूल गए कि साइकिल के साथ हाथ से रफ्तार नहीं आती। रफ्तार आती है, पैडल कितनी ताकत से चलाई जा रही है। रास्ता कितना सुगम या कठिन है। सपाट है या चढ़ाई है। मैदान है या पहाड़ है। इन बातों का अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ध्यान नही रखा।दोनो दलों के नेता चुनाव में धराशायी हो गए।

उतरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये बातें नारे में बंद नहीं हो सकी। उनका दायरा नारे से बाहर उनमें फैला हुआ था, जो उसे लगाते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

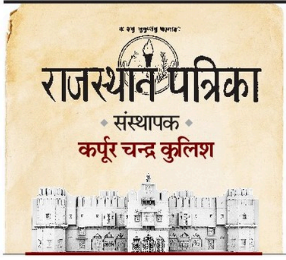

भारत से व्यापार समझौते की गेंद अमरीका के पाले में

जब कोई संकेतों से नहीं समझे तो उसे खरी-खरी सुनानी भी पड़ती है। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को लागू करने का दिन नजदीक है, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत की नीतियां वे ही होंगी, जिन्हें राष्ट्रीय हित में उचित समझा जाएगा। अमरीका से व्यापार समझौते को लेकर भारत ने लक्ष्मण रेखा खींचते हुए साफ कह दिया है कि भारतीय वस्तुओं पर पचास फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद किसानों, छोटे उत्पादकों और राष्ट्रीय स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जाहिर है, अब गेंद अमरीका के पाले में है कि वह व्यापार समझौता करे या न करे।

इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने अमरीका समेत तमाम दूसरे देशों को भी साफ कह दिया है कि भारत की विदेश नीति और उसके फैसले देशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर ही होंगे। उनके दो टूक जवाब को इस बात का भी संकेत समझा जाना चाहिए कि विकसित कहे जाने वाले देश इस भ्रम में कतई न रहें कि वे अपनी नीतियों को मनमाने तरीके से किसी भी देश पर थोपने में सफल हो जाएंगे। आमतौर पर कोई भी देश अपनी विदेश नीति को लेकर सार्वजनिक तौर पर बातें नहीं करता। अमरीकी राष्ट्रपति को लेकर विदेश मंत्री ने यह कहा भी है कि दुनिया ने कभी ऐसा अमरीकी राष्ट्रपति नहीं देखा, जिसने विदेश नीति को इतने सार्वजनिक रूप से संचालित किया हो। इसी संदर्भ में हमारे विदेश मंत्री ने अमरीका को सुनाने का काम ऐसे वक्त में किया है जब ट्रंप प्रशासन से जुड़े कई लोग भारत को लेकर चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखने व चीन से सामान्य होते भारत के रिश्ते अमरीका को खटकने वाले हैं। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो पहले ही सार्वजनिक बयान में कह चुके हैं कि भारत के रूसी कच्चा तेल खरीदने से मास्को को यूक्रेन से युद्ध जारी रखने में आर्थिक मदद मिल रही है। हैरत की बात यह है कि अमरीका ने ही कहा था कि दुनिया के ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने समेत जरूरी कदम उठाने चाहिए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि भारत को इसके लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ अमरीका का 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होना प्रस्तावित है।

अमरीका की ट्रेड डील पर बातचीत के लिए आने वाली टीम का प्रस्तावित दिल्ली दौरा टलने से अब टैरिफ से राहत मिलने को लेकर असमंजस बन गया है। हालांकि विदेश मंत्री कह चुके हैं कि वार्ता के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। बहरहाल, विदेश मंत्री ने यह जता दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत मजबूती से खड़ा है। वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। कोई दबाव भारत को झुका नहीं सकता।

ट्रंप की नीति: वाशिंगटन के बाद अब शिकागो और न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड की तैनाती करने की चेतावनी

कानून व्यवस्था की आड़ में संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

क्या अमरीकी संविधान में इतनी शक्ति है कि वह व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के सामने टिक सके? अगर संविधान और संस्थाएं कमजोर पड़ती तो यह एक खतरनाक संकेत होगा कि लोकतंत्र अब नाममात्र का बचा है।

अमरीका में राजनीति इन दिनों जिस दिशा में अग्रसर हो रही है, वह न केवल संविधान के मूल ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला संकेत भी है। वाशिंगटन डीसी में पुलिस पर संघीय नियंत्रण थोपने और नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद अब डॉनल्ड ट्रंप ने शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े डेमोक्रेट-शासित शहरों में भी इसी तरह के कदम उठाने की चेतावनी दी है। यह सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि अमरीकी संघीय व्यवस्था पर सीधा प्रहार है, जो वर्षों से स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण और राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित रही है।

ट्रंप का तर्क है कि डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहर अब 'कानूनहीन गिरोहों' और 'अपराधी प्रवृत्तियों' के गढ़ बन चुके हैं। उनका कहना है कि जब स्थानीय सरकारें विफल हो जाती हैं, तब संघीय सत्ता को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस तर्क के आधार पर उन्होंने वाशिंगटन में न केवल स्थानीय पुलिस की शक्तियों को कमजोर किया, बल्कि नेशनल गार्ड और संघीय एजेंसियों की प्रत्यक्ष तैनाती कर दी। अब यही प्रक्रिया शिकागो और न्यूयॉर्क में अपनाई जा रही है, जहां स्थानीय निकायों की सहमति के बिना संघीय हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे दिया गया तर्क यानी बढ़ता हुआ अपराध, तथ्यों पर आधारित नहीं है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 में इन शहरों में हिंसक अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए शिकागो, जो लंबे समय तक 'अपराध की राजधानी' के रूप में बदनाम किया गया, वहां हत्या और गोलीबारी की घटनाओं में दो अंकीय गिरावट आई है। न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो, वहां की गंभीर अपराध दर पिछले तीस वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका श्रेय सामुदायिक पुलिसिंग, सामाजिक योजनाओं में निवेश और बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली को जाता है।

इसके बावजूद ट्रंप लगातार यह नैरेटिव दे रहे हैं कि डेमोक्रेट संचालित शहर अराजकता के गर्त में डूबे हुए हैं। वाशिंगटन में जिस तरह से 'होम रूल एक्ट' का उल्लंघन कर स्थानीय प्रशासन की शक्ति छीनी गई, उसी प्रकार अब शिकागो और न्यूयॉर्क में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है। मेयरों और स्थानीय परिषदों ने इसे 'असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और सत्ता का दुरुपयोग' करार देते हुए इस कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने संघीय सरकार के इस हस्तक्षेप के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ने की घोषणा भी की है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड यदि जारी रहा तो अमरीका का संघीय ढांचा एक गहरे संकट में फंस सकता है। यह केवल वर्तमान संकट की बात नहीं, बल्कि भविष्य में एक खतरनाक मिसाल बन सकता है, जहां 'कानून-व्यवस्था' के नाम पर किसी भी असहमत शहर को संघीय नियंत्रण में लिया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की कठोर नीतियां केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। बेघरों और शरणार्थियों के खिलाफ उनकी नीति भी इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है। वाशिंगटन में जबरन बेघरों को हटाने के बाद अब न्यूयॉर्क और शिकागो में 'संघीय आश्रय शिविरों' के नाम पर विस्थापन का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बेघर नागरिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि यह कदम न केवल मानवीय संकट को बढ़ाएगा, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन भी करेगा।

यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि किस प्रकार 'सुरक्षा' और 'कानून-व्यवस्था' के नाम पर सत्ता आम नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब सत्ता भय और राष्ट्रवाद के मिश्रण से खुद को 'उद्धारक' के रूप में प्रस्तुत करती है, तब लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। 1968 में रिचर्ड निक्सन ने 'कानून और व्यवस्था' का नारा देकर कुछ ऐसा ही किया था। अपराध की बढ़ती हुई तस्वीर को अतिरंजित कर कठोर और दमनकारी नीतियों को वैधता देने की कोशिश की गई थी। आज ट्रंप उसी रणनीति को नए रूप में अपना रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अब उनके पास सोशल मीडिया और डिजिटल नैरेटिव की अपार शक्ति है। अब सवाल उठता है कि क्या अमरीका की संस्थाएं इस संकट का सामना करने में सक्षम हैं? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से इस तरह के हस्तक्षेप को असंवैधानिक घोषित कर पाएगी? क्या मीडिया और नागरिक समाज तथ्यपरक विमर्श को जीवित रख पाएंगे या वे भी सत्ता के दबाव में झुक जाएंगे?

इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमरीकी संविधान में इतनी शक्ति है कि वह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के सामने टिक सके? अगर संविधान और संस्थाएं कमजोर पड़ती तो यह एक खतरनाक संकेत होगा कि लोकतंत्र अब नाममात्र का बचा है। लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच की रेखा कोई ठोस दीवार नहीं, बल्कि एक धुंधली लकीर होती है, जो कभी भी मिट सकती है। जब सरकारें अपनी हिंसात्मक नीतियों को 'आवश्यक' और 'राष्ट्रहित' में बताकर प्रस्तुत करने लगें, तब पत्रकारों, न्यायाधीशों और नागरिकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। वाशिंगटन, शिकागो और न्यूयॉर्क की घटनाएं सिर्फ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे नहीं हैं। ये घटनाएं अमरीकी संघवाद की बुनियाद पर बड़ा प्रश्नचिह्न हैं। संघीय सत्ता यदि इसी तरह शहरों-राज्यों की स्वायत्तता को नजरअंदाज कर सत्ता का केंद्रीकरण करती है, तो पूरा तंत्र ऐसी अधिनायकवादी ढलान की ओर बढ़ेगा, जहां से वापसी कठिन होगी। डॉनल्ड ट्रंप का यह 'कानून-व्यवस्था' अभियान एक राजनीतिक हथियार के साथ-साथ एक संवैधानिक संकट भी बनता जा रहा है।

नेतृत्व

बांस से सीखें सामर्थ्य और लचीलापन

नेतृत्व को न तो ऊंची आवाज की जरूरत है और न ही कठोरता की

बांस आंधियों में झुकता है, टूटता नहीं। तीव्र गति से बढ़ता है, किंतु भीतर से खोखला रहता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक नेतृत्वकर्ता बनकर भी अहंकार रहित रहना, निरंतर बढ़ना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना संभव है।

विपत्ति में लचीलापन : जब प्रचंड तूफान धरती पर कहर बरपाते हैं, तब कई विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं, किंतु बांस सहजता से झुककर पुनः सीधा हो खड़ा होता है। जो लीडर अपने विचारों और तरीकों में कठोर रहते हैं, वे दबाव में टूट जाते हैं, जबकि जो समयानुकूल और लचीले रहते हैं, वही समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

आंतरिक विनम्रता : अपनी दृढ़ता के बावजूद बांस भीतर से खोखला होता है। यह अहंकार-शून्य नेतृत्व का गहन रूपक है। सच्चा लीडर अपने भीतर स्थान रखता है अन्य को सुनने के लिए, उनसे सीखने और दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए।

उद्देश्यपूर्ण तीव्र विकास : बांस शीघ्रता से बढ़ता है, परंतु उसका विकास सार्थक होता है। वह चारों ओर जीवन को पोषण, छाया और साधन देता है। एक लीडर को भी तीव्र किन्तु सार्थक प्रगति का प्रयास करना चाहिए, जिससे सफलता केवल स्वयं तक सीमित न रहे, बल्कि उसके अधीनस्थों, संस्था और समाज तक उसका लाभ पहुंचे।

समुदाय में सामर्थ्य : बांस अकेला नहीं उगता, वह झुरमुट में पनपता है और पारस्परिक जुड़ाव से शक्ति पाता है। यह हमें सिखाता है कि एकता और सहयोग ही स्थायित्व के स्रोत हैं। अकेला लीडर असुरक्षित होता है, पर जो विश्वास और पारस्परिक समर्थन को सशक्त करता है, वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है।

बांस हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व को न तो ऊंची आवाज की जरूरत है, न कठोरता की। यह लचीला होते हुए भी दृढ़, विनम्र होते हुए भी प्रभावशाली, तीव्र-विकासी होते हुए भी पोषणकारी है।

बुक इनसाइट

द मार्शियन्स : मंगल ग्रह की कथाएं

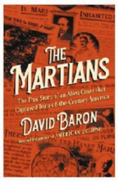

डेविड बैरन की लिखित 'द मार्शियन्स' एक रोचक पुस्तक है, जो मंगल ग्रह और उससे जुड़े मानव के जिज्ञासु इतिहास को सामने लाती है। पुस्तक हमें 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक पर्सिवल लोवेल से मिलवाती है, जो टेलिस्कोप से मंगल की सतह पर सीधे नहरों की कल्पना करते थे। इस पुस्तक में मंगल ग्रह की कथा को रोचक ढंग से पेश करते हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे 19वीं सदी में लोग मंगल ग्रह पर बस्तियों और नहरों की कल्पना करते थे। इस किताब में वैज्ञानिकों, खगोलविदों और लेखकों की कहानियां शामिल हैं, जो इस ग्रह के रहस्य को सुलझाने में लगे रहे। बैरन ने इतिहास और विज्ञान को मिलाकर एक ऐसी कथा रची है, जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

लेखक ने तथ्यों को रोचक घटनाओं के साथ पेश किया है, जिससे किताब मोनोटोनी से बची रहती है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज का यह सफर न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, बल्कि मानव की कल्पनाशीलता को भी दिखाता है। डेविड बैरन का लेखन रिसर्च-आधारित होते हुए भी बेहद रोचक और कहानीनुमा है।

फैक्ट फ्रंट

नेपेंथेस अटेनबरोई : मांसाहारी पौधा

नेपेंथेस अटेनबरोई जिसे अटेनबरो पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्लभ और आकर्षक मांसाहारी पौधा है। यह पौधा फिलीपींस के पालावान द्वीप के माउंट विक्टोरिया की ऊंची चोटियों पर पाया जाता है। इसकी घंटी के आकार की पिचर यानी घट-संरचना होती है। यह पौधा 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पिचर, जो कीटों और छोटे जानवरों को फंसाने के लिए विकसित होते हैं, वे 30 सेमी तक लंबे और 16 सेमी चौड़े हो सकते हैं। इनमें 1.5 लीटर से अधिक तरल भंडारण की क्षमता होती है। ये पिचर कीटों, चूहों और छिपकलियों को आकर्षित करने के लिए मीठी सुगंध छोड़ते हैं, जो फिसलन भरे किनारों के कारण फंसकर पाचक एंजाइमों में डूब जाते हैं।

नेपेंथेस अटेनबरोई की खासियत इसकी दो प्रकार की पिचर संरचनाएं हैं एक खाने वाली और एक फंसाने वाली। यह पौधा चट्टानी, अल्ट्रामाफिक मिट्टी में 1450-1726 मीटर की ऊंचाई पर उगता है और इसे उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह पौधा प्रकृति की अनोखी रचना का प्रतीक है।

चिंता पर्यावरण से बड़ा हो गया स्वहित का एजेंडा

वर्चस्व की राजनीति में फंस गई अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक संधि

इस बार भी प्लास्टिक को लेकर अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए हो रही शीर्षस्तरीय वार्ता बिना किसी सहमति के अगले दौर की चर्चा का निर्णय लेते हुए समाप्त हो गई। जिनेवा में अनगिनत स्वैच्छिक और उद्योग संगठनों की उपस्थिति के मध्य 183 देशों एवं 1000 पर्यवेक्षकों समेत करीब 2600 से अधिक प्रतिनिधियों तथा 70 से अधिक मंत्रियों की उपस्थिति में अंतिम दौर की वार्ता फिर पुराने बिंदुओं पर विकसित देशों की हठधर्मिता के आगे अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने प्लास्टिक के कहर को समझते हुए एक प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 2024 की समाप्ति पूर्व तक समस्त राष्ट्रों के मध्य एक निर्णायक एवं बाध्यकारी संधि की संकल्पना रखी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार तो दिसंबर 2024 में कोरिया के बुसान शहर में आयोजित पांचवें दौर की वार्ता के बाद संधि पर सहमति हो जानी चाहिए थी, किंतु प्लास्टिक उत्पादन, डिजाइन, वित्तीय प्रबंधन समेत महत्त्वपूर्ण विषयों पर अनेक राष्ट्रों की असहमति के रहते, जिनेवा में एक और दौर की वार्ता रखी गई। वैसे तो संधिवार्ता से पहले अमरीका एवं तेल उत्पादक देशों के रुख को देखते हुए यह आशंका प्रबल थी कि प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं हो पाएगी।

डॉ. विवेक एस. अग्रवाल
पर्यावरण विषय के जानकार
@patrika.com

इससे फिर एक बार साबित हो गया कि वैश्विक समस्याएं भी वर्चस्व की भेंट चढ़ जाती हैं। उपदेश तो स्वहित से ऊपर उठकर निर्णय लेने के दिए जाते हैं किंतु वास्तविकता में स्वहित ही सर्वोपरि रहता है। चिंतन का विषय यह भी है कि इस प्रकार के आयोजनों पर न सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से सैंकड़ों करोड़ रुपए का खर्च होता है, साथ ही इससे जुड़ी परिवहन व्यवस्थाओं इत्यादि के चलते भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन भी होता है। यदि यही निवेश प्लास्टिक के विकल्प तथा उससे जुड़ी मूल समस्या प्रबंधन को हल करने में किया जाए तो सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। यह सर्वज्ञात तथ्य जानते हुए भी कि 2020 से 2040 के मध्य 70 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्लास्टिक उत्पादन लगभग 74 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और लगभग 100 देशों के अथक प्रयास के बावजूद संधि अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। आम सहमति नहीं होने में मूलतः तेल उत्पादक देशों ने रोड़े अटकाए।

प्लास्टिक चूंकि जीवाश्म ईंधन का ही एक बाय प्रोडक्ट है, अतएव उनका हित तो टकराता ही है। संधि वार्ता के विफल होने पर तूवालू समेत प्रशान्त क्षेत्र के छोटे द्वीपों एवं विकासशील राष्ट्रों ने चिंता जाहिर करते हुए, छोटे द्वीपों को संपन्न राष्ट्रों के प्लास्टिक कचरागाह के रूप में उपयोग में लाए जाते रहने की आशंका प्रकट की। एक अच्छा पक्ष रहा कि चीन ने भी प्लास्टिक से हो रहे नुकसान को लेकर गहन चिंता जाहिर की। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्लास्टिक उत्पादन एवं उपयोग से न सिर्फ राष्ट्रों की सीमाओं के अंदर तक दुष्प्रभाव सीमित रहता है, अपितु उसका असर सीमा पार तक जाता है।

मिस्र की विरासत हत्शेपसुत का शवगृह मंदिर

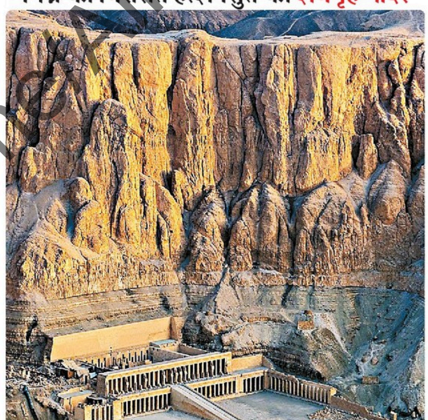

मिस्र में हत्शेपसुत का शवगृह मंदिर प्राचीन वास्तुकला और इतिहास का अनोखा प्रतीक है। देइर अल-बहारी की बलुआ पत्थर की चट्टानों में इसे तराशा गया है। हत्शेपसुत मिस्र के 18वें राजवंश की पांचवीं फराओ थीं और प्राचीन मिस्र की महिला शासकों में सबसे महत्त्वपूर्ण थीं। उनका शासन समृद्धि और स्थिरता लेकर आया, पर मृत्यु के बाद उनकी स्मृति मिटाने की कोशिश की गई।

समाधान समय निकालकर लोगों से मिलना जरूरी

सामाजिक जुड़ाव : अकेलेपन से लड़ने की सामूहिक राह

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर छठा इंसान अकेलापन झेल रहा है और हर साल लगभग आठ लाख लोग इस कारण अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर लेते हैं। भारत भी इस वैश्विक अकेलेपन के संकट से अछूता नहीं है। संयुक्त परिवारों का टूटना, महानगरीय जीवन का तनाव, कामकाजी जीवन का अत्यधिक दबाव और डिजिटल दुनिया का अति-प्रभाव- इन सबने मिलकर हमें अदृश्य दीवारों में कैद कर दिया है। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ने का दावा किया था, पर हकीकत में इसने हमें ऐसे आभासी मित्रों का जाल दिया है जो हमारी खुशियों में लाइक तो कर सकते हैं, लेकिन दुख में कंधा नहीं दे सकते।

सोनम लववंशी
स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी
@patrika.com

अकेलापन सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं, यह एक सामाजिक महामारी है। यह अवसाद, चिंता, आत्महत्या जैसे गंभीर मानसिक रोगों की ओर ले जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, करीब 14 फीसदी वयस्क मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें अकेलापन एक प्रमुख कारक है। ग्रामीण से शहरी भारत तक, यह समस्या हर वर्ग में दिख रही है। गांवों में पलायन के कारण बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, शहरों में माता-पिता बच्चों से दूर हैं, बच्चे हॉस्टलों में पल रहे हैं, और पति-पत्नी दोनों काम में डूबे हुए हैं। त्योहार, जो कभी मेल-मिलाप का अवसर थे, अब फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की औपचारिकता बनकर रह गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम 'कनेक्टेड' होते हुए भी 'डिस्कनेक्टेड' हैं। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम भीतर की कैद से मुक्त होंगे। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने डिजिटल जीवन और वास्तविक जीवन में संतुलन बनाना होगा।

आभासी मित्रता को वास्तविक संबंधों से प्रतिस्थापित करना होगा। इसका मतलब है, समय निकालकर मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों से आमने-सामने मिलना, उनके सुख-दुख में सहभागी होना। हमें यह स्वीकारना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता है। सामाजिक स्तर पर सरकार, संस्थाओं और समुदायों को मिलकर 'सामाजिक जुड़ाव' के कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। सामुदायिक केंद्र, मोहल्ला-स्तरीय पार्कों में नियमित मिलन कार्यक्रम, त्योहारों में सामूहिक भागीदारी और मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा, ये सब स्वस्थ व जुड़ा हुआ समाज बनाने में मदद करेंगे। कार्यस्थलों पर 'मानसिक स्वास्थ्य दिवस', लचीले कार्य घंटे और टीम-बिल्डिंग गतिविधियां इस दिशा में अहम कदम होंगी। मन में संकल्प लें कि हम अपने आसपास किसी को भी अकेलेपन की खाई में गिरने नहीं देंगे। हम पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देंगे, परिवार के साथ बैठकर भोजन करेंगे, सोशल मीडिया के लाइक्स से ज्यादा असल जीवन के स्माइल्स को महत्त्व देंगे।

आपकी बात

नशामुक्ति अभियान चलाएं

युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसके स्थायी समाधान के लिए शिक्षा संस्थानों में नशामुक्ति पर जागरूकता अभियान, परिवार व समाज का सकारात्मक सहयोग तथा सरकार की ओर से कड़े नियंत्रण-पुनर्वास सुविधाएं जरूरी हैं।

- सुनीता रानी, अनूपगढ़

बढ़ रहीं मच्छरजनित बीमारियां

मौसम परिवर्तन की वजह से मच्छरजनित बीमारियों डेंगू, मलेरिया आदि का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए आसपास जल भराव वाले क्षेत्रों, गड्ढों और गंदगी से भरी नालियों की नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए। स्थानीय निकाय को पानी की निकासी के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। - **प्रकाश भगत,** कुचामन सिटी

आज का सवाल

बदहाल राजमार्गों पर टोल वसूली को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ईमेल करें : editpatrika@gmail.com

नागरिक अधिकार सुरक्षा व प्रोटोकॉल महत्त्वपूर्ण हैं, पर दौरे नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण से लागू होने चाहिए

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वीआइपी दौरे : जरूरत या दिखावा?

गजेंद्र सिंह
लोकनीति विश्लेषक
@patrika.com

जब नेता या वरिष्ठ अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था और काफिले के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं और मार्ग भी बदल दिए जाते हैं।

भारत में 'अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति' की आवाजाही अक्सर सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन जाती है। बड़े नेता, विदेशी अतिथि या वरिष्ठ अधिकारी जब किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं तो उनके लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लग जाते हैं, रास्ते बदले जाते हैं और कभी-कभी सड़कें पूरी तरह बंद कर दी जाती हैं। परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित होता है।

किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने और 30 लोगों की मौत के बाद राहत कार्य चल रहे थे लेकिन 'वीआइपी दौरे' के कारण आम लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने अधिकारियों और नेताओं के लिए किए गए विशेष इंतजामों पर सवाल उठाए। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है- क्या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले इंतजाम उनकी सुरक्षा का जरूरी हिस्सा हैं? वीआइपी दौरे और उनके साथ किए गए विशेष इंतजाम अक्सर आम नागरिकों के अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं। सड़कों को बंद करना, मार्ग बदलना और काफिलों के लिए क्षेत्रों को घेर लेना नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही (अनुच्छेद 19(1)(डी)) और जीवन तथा आजीविका (अनुच्छेद 21) को प्रभावित करता है। सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स, चेकपॉइंट और भारी पुलिस तैनाती के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी)) पर भी असर पड़ता है। साथ ही, वीआइपी दौरे के लिए काफिले, समारोहात्मक सेटअप और सुरक्षा व्यवस्था से भारी सार्वजनिक संसाधनों की खपत होती है। जब नेता या वरिष्ठ अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था और काफिले के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं और मार्ग बदल दिए जाते हैं। इससे एंबुलेंस, राहत वाहन और बचाव दल समय पर प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसे दौरों के कारण प्रशासन की प्राथमिकताएं भी प्रभावित होती हैं व संसाधनों का समन्वय सामान्य राहत कार्यों के बजाय दौरे के अनुरूप हो जाता है। इससे नागरिकों और प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त असुविधा और तनाव उत्पन्न होता है। भारत में 'अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति' की सुरक्षा के लिए प्रशासन विशेष प्रोटोकॉल का पालन करता है, जिसमें सुरक्षा श्रेणियों (एसपीजी, जेड+, जेड, वाइ+, वाइ, एक्स) के अनुसार कमांडो और पुलिस कर्मियों की तैनाती, बैरिकेड्स, चेकपॉइंट और सुरक्षा वाहनों की व्यवस्था शामिल होती है।

हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसी तरह के दौरे प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने और राहत कार्यों में तेजी लाने में सहायक होते हैं। ऐसे दौरे व्यवस्था, राहत कार्यों की निगरानी और नियमन को सशक्त बनाते हैं, जिससे संबंधित विभागों में त्वरित समन्वय और कार्य में तेजी आती है। प्रशासनिक जिम्मेदारी की भावना से जनता के बीच शासन के प्रति विश्वास पैदा होता है। हालांकि अदालतों की ओर से भी सुझाव आते रहे हैं कि वीआइपी मूवमेंट से होने वाली असुविधा को कम करने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए और मार्गों को बदला जाए, न कि पूरी तरह बंद किया जाए। इससे आम नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं की सुविधा बनी रहेगी। साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

वीआइपी मूवमेंट और विशेष इंतजामों की आवश्यकता निश्चित रूप से है, लेकिन इसे संतुलित और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण से लागू करना चाहिए। सुरक्षा और प्रोटोकॉल महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन आम नागरिकों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए वीआइपी दौरे केवल आवश्यक समय और स्थान तक सीमित होने चाहिए और वर्चुअल या डिजिटल निरीक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, नागरिक अधिकारों और आपातकालीन सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए समन्वित योजना बनाई जानी चाहिए। नेतृत्व की उपस्थिति और जनता के अधिकारों के बीच संतुलन रखना आवश्यक है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 161

मौद्रिक नीति ढांचा कारगर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति ढांचे को लेकर एक चर्चा पत्र जारी किया है। मुद्रास्फीति को लक्षित करने की लचीली व्यवस्था की दूसरी समीक्षा मार्च 2026 में होनी है। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने चर्चा के द्वार खोल दिए हैं। यह चर्चा पत्र स्पष्ट करता है कि मौजूदा ढांचा जो मुद्रास्फीति के लिए 4 फीसदी का लक्ष्य (2 फीसदी कम या ज्यादा) का लक्ष्य लेकर चलता है उसने 2016 में अपनाए जाने के बाद से ही अर्थव्यवस्था की बेहतर मदद की है। मुद्रास्फीति का रुझान इस लक्ष्य के आसपास ही रहा है। अत्यधिक अस्थिरता के समय जरूर कुछ समस्या आई है।

बहरहाल इससे केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता मजबूत हुई है। परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं की बात करें तो कोविड महामारी के दौर में उसमें इजाफा हुआ था लेकिन उसके बाद से इसमें नरमी देखी गई है। इसके बावजूद चूंकि केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के मशविरे से हर पांच साल में इसकी समीक्षा करनी होती है इसलिए इस पर व्यापक चर्चा शुरू करके अच्छा किया गया है। यह चर्चा पत्र सार्वजनिक फीडबैक के लिए चार अहम प्रश्न सामने रखता है। पहला, क्या समग्र या मुख्य मुद्रास्फीति के आधार पर मौद्रिक नीति निर्धारित होनी चाहिए? दूसरा, क्या 4 फीसदी का लक्ष्य उचित है? तीसरा, क्या दो फीसदी का दायरा उपयुक्त है? आखिर में क्या इस ढांचे को एक तयशुदा लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए या अधिक लचीले दायरे को चुनना चाहिए? विश्वसनीयता के साथ अनुकूलन का संतुलन कायम करने की दृष्टि से ये प्रश्न बुनियादी हैं।

पहले प्रश्न पर चर्चा पत्र में मजबूत तर्क दिया गया है। भारत जैसे देश में खाद्य मुद्रास्फीति की अनदेखी करना लाखों लोगों के कल्याण की अनदेखी करना होगा जिनके लिए खाद्य व्यय पारिवारिक बजट का अहम हिस्सा है। कोर यानी मुख्य मुद्रास्फीति कम उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है लेकिन हेडलाइन यानी समग्र मुद्रास्फीति जीवन जीने के लिए जरूरी व्यय को सही ढंग से सामने रखती है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्ष्य मानक के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, चाहे आय स्तर या विकास की अवस्था कुछ भी हो। मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण वाले देशों में युगांडा एकमात्र अपवाद है। भारत के लिए भी समग्र मुद्रास्फीति को ही आधार बनाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि यह घरेलू उपभोग को बेहतर ढंग से दर्शा सके। जहां तक 4 फीसदी मुद्रास्फीति लक्ष्य की बात है, यह याद रखना चाहिए कि इसे गहन विचार-विमर्श के बाद चुना गया था। इस लक्ष्य को बढ़ाने से बाज़ारों में मूल्य अनुशासन के कमजोर होने का संकेत जा सकता है। हाल के वर्षों में किसी भी प्रमुख केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को नहीं बढ़ाया है। साथ ही, अनुभवजन्य साक्ष्य भी 4 फीसदी लक्ष्य का समर्थन करते हैं। इसलिए, इस लक्ष्य को लंबे समय तक बनाए रखना और विश्वसनीयता स्थापित करना समझदारी होगी, उसके बाद ही किसी बदलाव की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। 2 फीसदी के दायरे के तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसने जरूरी लचीलापन मुहैया कराया है। खासतौर पर आपूर्ति क्षेत्र के झटकों की अवधि के दौरान- मसलन यूक्रेन युद्ध। ऊपरी सिरा भी मुद्रास्फीति की सीमा से तय होता है जिसके परे जाने पर यह वृद्धि के लिए नुकसानदेह साबित होने लगता है। कई अर्थव्यवस्थाओं ने समय के साथ इस दायरे को कम कर दिया। हालांकि भारत की बात करें तो खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि फिलहाल इस दायरे को बरकरार रखा जाए।

आखिर में, क्या इस लक्ष्य की जगह कोई दायरा तय कर देना चाहिए? ऐसा करने से रिजर्व बैंक को और अधिक सुविधा होगी। परंतु जोखिम यह भी है कि इससे रिजर्व बैंक के कदमों का परिणाम धीमा हो जाएगा और अपेक्षाएं प्रभावित होंगी। एक ऐसे देश के लिए जहां मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को हाल ही में स्थिर किया गया है, विश्वसनीयता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक निश्चित लक्ष्य रखना, जिसमें एक सीमांत दायरा अप्रत्याशित झटकों के लिए व्यावहारिक गुंजाइश प्रदान करता है। पिछले दशक का अनुभव दिखाता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की नीति भारत के लिए लाभकारी रही है, और जब तक कोई ठोस अनुभवजन्य साक्ष्य बदलाव की आवश्यकता को सिद्ध न करे, तब तक मौजूदा ढांचे को जारी रखना उपयुक्त होगा।

ट्रंप और यूरोप के रिश्ते भारत के लिए सबक

यूरोपीय देशों ने ट्रंप के साथ उनकी शर्तों पर समझौता करने का निर्णय लिया है ताकि व्यापक पश्चिमी गठजोड़ बचा रहे। हमें देखना चाहिए कि इसमें भारत के लिए क्या सबक छिपे हैं।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

थोड़ी देर के लिए उस तस्वीर पर गौर कीजिए जिसे आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यूरोप के बड़े देशों के नेता और वोलोदीमिर जेलेंस्की, डॉनल्ड ट्रंप के सामने आज्ञाकारी स्कूली बच्चों की तरह खड़े हैं जबकि ट्रंप किसी शाही प्रधानाध्यापक की तरह नजर आ रहे हैं।

इसे देखकर आपके मन में पहली भावना कौन सी आती है: सहानुभूति, मनोरंजन, दया, परपीड़ा सुख या एक नई विश्व व्यवस्था के आह्वान की? पूरी संभावना है कि आपके भीतर सहानुभूति के अलावा उपरोक्त भावों का मिलाजुला स्वरूप आए। ऐसा इसलिए नही क्योंकि हम आज ट्रंप के द्वारा सबसे अधिक सताए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम यही सलाह देंगे कि हम आवेश में दी गई इस प्रतिक्रिया को संशोधित कर लें।

हम देख सकते हैं कि कम से कम एक नेता का दिमाग भावनात्मक घालमेल से परे है। व्लादीमीर पुतिन इसे विशुद्ध रूप से हिकारत से देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश, तीसरी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक (यूरोपीय संघ), दो परमाणु हथियार संपन्न देश, सभी घुटनों पर नजर आए।

वे सभी पश्चिमी गठजोड़ में सबसे अधिक मायने रखने वाले इकलौते नेता के सामने झुके नजर आए जिसे पुतिन कमजोर करने का प्रयास करते रहे हैं। ओवेन मैथ्यूज ने अपने आलेख में इस बात पर जोर दिया है जिसका शीर्षक है, 'पुतिन का जाल: कैसे रूस पश्चिमी गठजोड़ को बांटने की योजना बना रहा है?' पुतिन इसे इस बात की स्वीकारोक्ति के रूप में भी देखते हैं कि उन्होंने जंग जीत ली है। यह पूरी तरह उन पर है कि वे इस जीत के रूप में परिभाषित करें। यह यूरोपीय देशों के विपरीत है जिन्हें यह देखना होगा कि इसे किस तरह से बुरी हार के रूप में न दिखने दिया जाए।

पुतिन को पता है कि वे जो छीन चुके हैं उस पर काबिज रह सकते हैं। इसमें 2022 के हमले के बाद की जगहें ही नहीं बल्कि क्राइमिया और डोनबास भी शामिल हैं। यह यूक्रेन के कुल भूभाग का करीब 20 फीसदी है। इसके अलावा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का पूर्व की ओर विस्तार भी अब इतिहास हो चुका है। हम जानते हैं कि ट्रंप अपना दिमाग बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं, उतनी ही जल्दी जितना कि हम फिल्मों में तानाशाहों को बदलते देखते हैं। लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि वह अचानक यूक्रेन और यूरोप की महत्त्वाकांक्षी मांगों का समर्थन करने लगेंगे। इन मांगों में पुतिन की हार भी शामिल है।

रूस को काफी कुछ झेलना पड़ा है लेकिन वह अभी भी हमलावर है। भले ही उसे इसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही हो। अगर इस मोड़ पर शांति स्थापित होती है तो पुतिन जीत की घोषणा कर सकते हैं। वह क्राइमिया या मारियुपोल में विजय भाषण भी दे सकते हैं। शांति स्थापना के साथ ही प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। तब वह अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर सकते हैं।

अगर पुतिन यूक्रेन की संप्रभुता कम करने और वहां अपनी पसंद की सरकार बनाने के लक्ष्य नहीं पा सके हैं तो इसकी वजह है यूक्रेन की असाधारण बहादुरी और समझदारी। पश्चिमी गठजोड़ और अमेरिका ने भले ही संसाधनों के जरिये मदद की हो लेकिन यूक्रेन ने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़कर और बहुत भारी कीमत वसूल करके अपनी संप्रभुता को बचाए रखा।

यूक्रेन ने दुनिया को ड्रोन से युद्ध कौशल दिखाया। दूरदराज इलाके से छिपकर और बड़े पैमाने पर जंग करके दिखाया। महज 3.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद उसने न केवल अत्यंत साहसपूर्वक शहादतें दीं बल्कि रूस को भी जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी भारी क्षति पहुंचाई। दो बातों के चलते वे बेहतर नतीजे नहीं पा सके। पहला, यूरोपीय साझेदारों द्वारा सैन्य या आर्थिक कष्ट साझा करने में नाकामी और ट्रंप की वापसी।

इस बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ कहा और लिखा जाएगा लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं कि यूरोप ने कैसे खुद को स्वेच्छा से ट्रंप के नए साम्राज्यवाद का पहला शिकार बनने तक सीमित कर लिया, वह कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है और भारत के लिए क्या सबक हैं।

यूरोप ने अपनी सुरक्षा अमेरिका के हवाले करके भारी भूल की। इसकी शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के बाद स्वतः आरोपित शांति के रूप में हुई। उसके बाद सोवियत युग के बाद शीतयुद्ध समाप्त होने पर शिथिलता बरती गई। नाटो का विस्तार हुआ लेकिन यह भावना हमेशा रही कि कोई वास्तविक खतरा नहीं है और अमेरिका यूरोप की रक्षा करेगा। अब हालात ये हैं कि उन्हें सैन्य उपकरणों तक के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है।

रूस को लेकर डर ने यूरोप को ट्रंप के साथ एकतरफा संधि पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया। ट्रंप कहते हैं कि उनके पास ताकत है कि वह यूरोप द्वारा अमेरिका में निवेश के 600 अरब डॉलर के हर डॉलर का इस्तेमाल कर सकें। यह सुरक्षा निधि और साम्राज्यवाद है। अगर वे रक्षा पर और अधिक व्यय करते हैं तो भी उन्हें नए सैन्य विस्तार के लिए जवानों की कमी पड़ेगी। यूरोप में सैन्य संस्कृति बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। कुछ हद तक फ्रांस और ब्रिटेन में ही यह शेष है। तुर्किये को छोड़कर अन्य देश अमेरिका की दया पर हैं।

इसके अलावा, सस्ते चीनी सामानों, रूसी गैस और आउटसोर्स की गई विनिर्माण व्यवस्था पर आर्थिक निर्भरता भी आलस की अन्य निशानियां हैं। जिन टनल बोरिंग मशीनों को चीन ने हाल तक भारत को देने से इनकार किया था, वे वास्तव में जर्मन तकनीक की हैं। बस इतना हुआ कि अधिक लाभ कमाने के लिए उनका विनिर्माण चीन में स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रांस एक बार फिर अपवाद है।

अब यूरोप हिला हुआ है। एक अहम बात जो हम भारतीयों को भी ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि वे भावना से नहीं हकीकत को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। यूक्रेन और व्यापक यूरोप की सुरक्षा पर वे कम से कम बुरे विकल्प चुन लेंगे। राष्ट्रहित अक्सर ऐसी प्रतिक्रियाओं की मांग करता है जो संशय से भरी भले हों लेकिन भावनात्मक न हों।

ओवल ऑफिस की तस्वीर हमें यही बताती है। यूरोपीय लोगों ने ट्रंप से उनकी शर्तों पर बात करना स्वीकार कर लिया क्योंकि वे व्यापक पश्चिमी गठजोड़ को एकजुट रखना चाहते हैं। अमेरिका तो ट्रंप के जाने के बाद भी रहेगा। अभी वे ट्रंप को जो रियायतें दे रहे हैं वे उनके कार्यकाल के लिए ही हैं। कल फिर आएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। ऐसे में भारत के लिए भी सबक हैं:

1. अपनी सेना को मजबूत बनाएं और जंग के लिए तैयार रखें। कोई नारेबाजी नहीं, बड़ी-बड़ी बातें नहीं, आने वाले दशकों में क्या करेंगे ऐसा कुछ नहीं। हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। पहले पाकिस्तान से निपटने पर ध्यान देना होगा।

2. रूस के साथ रिश्ते मजबूत करें लेकिन किसी खेमे में जाने से बचें। लोकतांत्रिक भारत की तकदीर पश्चिम विरोधी नहीं है। चीन के साथ सकारात्मक रिश्तों को स्थिर बनाए रखें और साझा हित में काम करें। याद रहे चीन को हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वह पाकिस्तान के जरिये भी हमसे लड़ सकता है। अपना ध्यान वहां केंद्रित करें।

3. अपने आसपास के इलाके को शांत करें। भारत को हर मोर्चे पर शत्रुतापूर्ण माहौल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक अलग मुद्दा है लेकिन हर पड़ोसी रिश्ते को घरेलू राजनीति में खींचने से बचा जा सकता है। इससे विकल्प कम होते हैं।

4. अपने अवसर की पहचान करें और अमेरिका के साथ रिश्तों में समझदारी बरतें। भरोसा दोबारा कायम करने में समय लगेगा। याद रहे शीतयुद्ध का समय दोबारा नहीं आने वाला और अमेरिका विरोधी या पश्चिम विरोधी धड़ा नहीं बनेगा। एक बार यूक्रेन में शांति कायम होने के बाद पुतिन और ट्रंप दोबारा दोस्त बन जाएंगे। अमेरिका और चीन तो पहले ही सौदेबाजी में लग गए हैं।

हमें यूरोप से सीखने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि ट्रंप का दौर गुजर जाएगा। बस अपने राष्ट्रीय हित को कम से कम नुकसान होने देने का जतन करें। ट्रंप का समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ये वे सबक हैं जिन पर भारत को नजर डालनी चाहिए।

कच्चे तेल से मिले कड़वे सबक

रंजन मथाई

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का दबाव, एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। इसका मकसद यूक्रेन के मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन पर दबाव डालना और हमारे व्यापार वार्ताकारों से कुछ रियायतें हासिल करना हो सकता है। लेकिन ट्रंप का यह दावा हमारे लिए और भी अपमानजनक है कि एक अमेरिकी कंपनी, पाकिस्तान के 'विशाल' तेल भंडार का पता लगा सकती है और इसका कुछ हिस्सा भारत को बेचा जा सकता है।

भारत, जरूरत पड़ने पर बिना अधिक अतिरिक्त लागत के कई दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक, हम हर दिन जो 50 लाख बैरल तेल का आयात करते हैं, वह अब 40 अलग-अलग देशों से आता है। लेकिन ऐसा करने पर हमें राजनीति, नियमों के अनुपालन और प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और भारत के प्रसंस्कृत पेट्रोलियम निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। यह सब हमें उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था की कड़वी भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अहम सबक सिखाता है।

कई लोगों का मानना है कि ट्रंप की भू-राजनीतिक रणनीतियां, अमेरिका के तेल उत्पादन और निर्यात को बनाए रखने के उद्देश्य से जुड़ी हैं ताकि तेल की कीमतें अभी के ऊंचे स्तर पर बनी रहें। कच्चा तेल और गैस कंपनियों को (जिन्होंने पिछले एक दशक में अमेरिका में उत्पादन बढ़ाया है) मुनाफे में रहने के लिए 60-65 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की कीमतों की जरूरत होती है। कई उत्पादक शेल बेसिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और ट्रंप की 'ड्रिल' करने की अपील के बावजूद, कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के बजाय शेयरधारकों को रिटर्न देने को प्राथमिकता दे रही हैं।

तेल और गैस अमेरिका की सबसे बड़ी निर्यात वस्तुएं हैं, लेकिन ट्रंप द्वारा घोषित किए जाने वाले अरबों के ऊर्जा निर्यात के लिए यह जरूरी है कि कीमतें गिरें नहीं, भले ही तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन ओपेक+ उत्पादन में कटौती खत्म कर दे और वैश्विक आपूर्ति बढ़ा दे। ट्रंप वास्तव में ओपेक की इस लंबी रणनीति से वाकिफ हैं कि वह 2015 के बाद अमेरिका के हाथों गंवाए गए बाजार हिस्से को वापस पाना चाहता है।

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है जो हर दिन कच्चे तेल के आयात पर करीब 40 करोड़ डॉलर खर्च करता है। इसी वजह से भारत तेल बेचने वालों के लिए एक बड़ा बाजार है। लेकिन, अपनी खपत के लगभग 90 फीसदी हिस्से के लिए आयात पर निर्भर होने के कारण, हमारी आर्थिक तरक्की पर भू-राजनीतिक जोखिमों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में देश में घरेलू उत्पादन बढ़ाना अब एक आवश्यक रणनीति बन गई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल के वर्षों में किए गए बड़े सुधारों का जिक्र किया है। वर्ष 2022 से, करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के उन क्षेत्रों को भी खोज के लिए खोल दिया गया है जहां के लिए पहले मनाही थी। 29 जुलाई को उन्होंने राज्य सभा में बताया कि 2015 से अब तक 172 हाइड्रोकार्बन खोज किए गए हैं, जिनमें से 62 समुद्र में हैं। हालांकि उन्होंने जो आंकड़े दिए, उनके हिसाब से सिर्फ 60 करोड़ बैरल का अतिरिक्त संभावित भंडार मिला है, जिसमें से कुछ ही निकाला जा सकता है। यह मात्रा बहुत कम है।

नए खुले क्षेत्रों में अभी तक पर्याप्त खोज नहीं हो पाई है क्योंकि भारत में खोज और उत्पादन को आकर्षक बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। असल समस्या यह है कि पुरी, उन लोगों के कारण बंधे हाथों से काम कर रहे हैं जो कर लगाने का काम देखते हैं, जिनके लिए तेल उद्योग सिर्फ राजस्व का एक स्रोत है और वे इससे लगातार पैसा निकालना चाहते हैं।

वर्ष 2022 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने 2025 तक 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण करने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को 2030 तक बढ़ा दिया गया है जबकि अभी तक सिर्फ 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ही खोज हो पाई है! फरवरी 2025 में ओएनजीसी ने निवेशकों को बताया कि उसने 2024 में अन्वेषण से जुड़ी ड्रिलिंग पर करीब 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए। लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं बताया कि तेल उद्योग विकास उपकर के रूप में भी करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 1970 के दशक से चला आ रहा यह उपकर, तेल उद्योग के विकास के लिए नहीं है बल्कि कई दशकों से यह सिर्फ वित्त मंत्रालय की तेल कंपनियों पर कर लगाने की अतृप्त इच्छा को पूरा कर रहा है। पिछले तीन साल में उपकर के रूप में हासिल लगभग 43,000 करोड़ रुपये से खोज गतिविधियों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो सकती थी।

भारत के घरेलू तेल उत्पादकों ने 2022-24 में 'विंडफॉल टैक्स' के रूप में भी उद्योग से निकाले गए करीब 45,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा चुकाया। हालांकि नए निवेशों को कोई छूट नहीं मिली जैसा कि ब्रिटेन में हुआ। अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों ने जिनके पास अन्य जगहों पर भी निवेश के अच्छे मौके थे, उन्होंने भी इंतजार करने की नीति अपनाई ताकि यह देखा जा सके कि नीतिगत सुधारों के साथ-साथ खोज के जोखिमों की वित्तीय भरपाई हो पाएगी या नहीं।

हालांकि, कुछ हाल के घटनाक्रमों से घरेलू उत्पादन में सुधार की उम्मीद जगी है। फरवरी में, ओएनजीसी ने भारत पेट्रोलियम (बीपी) के साथ एक तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में अनुबंध किया, ताकि मुंबई के पुराने तेल क्षेत्र से उत्पादन में 40 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की जा सके। हाल ही में जारी किया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियम मसौदा, दूसरे पुराने क्षेत्रों में भी खोज को बढ़ावा दे सकता है।

ऊर्जा एजेंसी रिस्टैड ने बताया है कि कई देशों ने जोखिम भरी नई खोजों के बजाय लागत-प्रभावी 'बुनियादी ढांचा आधारित खोज' को प्राथमिकता दी है। भारत को दोनों की जरूरत है और इसलिए ओएनजीसी की बीपी और रिलायंस के साथ सौराष्ट्र के समुद्री तट पर एक संभावित ब्लॉक के अन्वेषण के लिए हाल में हुए एक और समझौते की घोषणा उत्साहजनक है।

पाकिस्तान के सिंधु घाटी से लेकर कच्छ/सौराष्ट्र तक फैले समुद्री क्षेत्र को संभावित तेल क्षेत्र माना जाता है, हालांकि अभी तक यहां व्यावसायिक स्तर पर कोई खोज नहीं हो पाई है। वर्ष 2024 में, कुछ संदिग्ध रिपोर्ट सामने आईं कि पाकिस्तानी जलक्षेत्र में तेल की बड़ी संभावना है जो एक अज्ञात 'दोस्त देश' के साथ किए गए लंबे सर्वेक्षणों पर आधारित थी जिसके बारे में माना जाता है कि यह देश तुर्किये है।

ट्रंप ने पाकिस्तान की क्षमता के बारे में कोई नया मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि, उनकी इस बात को महज अज्ञानता भरी बयानबाजी के रूप में नजरअंदाज करना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय तेल की अधिक खोज करना ही हमें आगे ले जाएगा।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

आपका पक्ष

अगले महीनों में आर्थिक वृद्धि को मिलेगी रफ्तार

इस समाचार पत्र में प्रकाशित आर्थिक वृद्धि में नरमी से संबंधित समाचार वर्तमान परिस्थितियों और विशेषकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत के प्रति दुराग्रही टैरिफ नीति और प्रतिबंधों को दृष्टिगत रखते हुए तथ्यपरक स्थिति से अवगत कराता है। परंतु एक बात तो निश्चित है कि किसी अर्थशास्त्री या आर्थिक विषयों के मर्मज्ञ ने अमेरिकी टैरिफ से किसी विशेष आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त नहीं की है। हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से अगस्त से अगले मार्च तक चलती हैं जिनमें त्योहारी सीजन, विवाह, पर्यटन एवं औद्योगिक उत्पादन चरम पर रहता है और आयकर के एडवांस टैक्स और जीएसटी संग्रहण से आर्थिक वृद्धि होती है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही तो हमारे देश में सदा आर्थिक शिथिलता का समय रहती ही है। जिस दिन हम सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिजों और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे और इस दिशा में केंद्र सरकार ने समय से आवश्यक निर्णय ले लिए हैं तथा औद्योगिक अनुपालन भी प्रारंभ हो गया है। यह निश्चित है कि अमेरिका और चीन जो भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी समझते हैं, भारत को अस्थिर करने के भरपूर प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे इसलिए रक्षा क्षेत्र में किसी भी तरह सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम छह फीसदी आवंटन करना एक सामरिक एवं सैन्य विवशता है। पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद में छह-सात प्रतिशत योगदान है और इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार में भी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय एवं विभाग हैं परंतु अभी भी हमारा पर्यटन क्षेत्र देश के विकास को आशातीत एवं क्षमतानुसार सहभागिता नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर की तो अर्थव्यवस्था ही पर्यटन के सहारे है। सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान दे जिससे स्थानीय उद्योग-धंधे, व्यापार और रोजगार का सृजन बड़े स्तर पर हो।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद में करीब 6 प्रतिशत योगदान है और इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं

ट्रंप शुल्क और तेल का खेल

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर अमेरिका के साथ व्यापार में भारी शुल्क लगाया है। ट्रंप ने खास तौर पर चीन और भारत पर भारी शुल्क लगाया है और कहा कि अगर ये देश रूस से कच्चे तेल खरीदना जारी रखते हैं तो शुल्क में और बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले दिनों अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे परिष्कृत कर दूसरे देशों को ऊंची कीमत में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। अमेरिका ने भारत के लिए भी यही बात कही है। भारत ने इसके जवाब में कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदना देश की ऊर्जा संरक्षण नीति का हिस्सा है और वह खरीदना जारी रखेगा। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि भारत रूस से अपनी जरूरत का 1 प्रतिशत कच्चा तेल खरीदता था जो बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है। हालांकि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने को स्वतंत्र है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आगामी गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित गति धीमी करने से संबंधित प्रणाली को परखने के लिए रविवार को पहला एकीकृत 'एयर ड्रॉप' परीक्षण (आईएडीटी-01) सफलतापूर्वक किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

THE HINDU

करुणा का अभ्यास करना

पशु आश्रयों की लागत को कम आंकना उन्हें कमज़ोर बनाता है

टी स्वतंत्र घूमने वाले कुत्तों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एक गंभीर प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है, भले ही अपर्याप्त हो, करुणा और सुरक्षा के प्रतिस्पर्धी दावों को फिर से समेटने का प्रयास। 11 अगस्त को, न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने और उन्हें आश्रयों में रखने का निर्देश दिया था। ग्यारह दिन बाद, इसने अपना रुख बदल दिया और टीकाकरण और कृमिनाशक के बाद जानवरों को छोड़ने की अनुमति दे दी और कहा कि आक्रामक या पागल जानवरों को रखा जा सकता है। भारत दुनिया में रेबीज के सबसे भारी बोझों में से एक है और मानवविज्ञान संबंधी विवरण स्पष्ट हैं कि यह खतरा दैनिक जीवन को आकार देता है, बच्चों की गतिविधियों को सीमित करता है और परिवारों को बार-बार चिकित्सा खर्चों में मजबूर करता है। रेबीज उन लोगों को भी असमान रूप से मारता है जो स्वास्थ्य प्रणाली का पता लगाने में सबसे कम सक्षम हैं। 11 अगस्त का आदेश महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने स्वीकार किया कि वर्तमान ढांचा, चाहे कितने भी अच्छे इरादे से बनाया गया हो, भारत की घनी बस्तियों के लिए अपर्याप्त है। यह आपत्ति कि आश्रय स्थल अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और रोगग्रस्त हो जाएँगे और स्थायी रूप से बंद करने से पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होगा, उन्हीं मुद्दों का सामना करते हैं जो नियमों को कमजोर करते हैं। उचित संसाधनों से युक्त और विनियमित आश्रय स्थलों का प्रबंधन पशु चिकित्सा मानकों, स्थान मानदंडों और पारदर्शी निरीक्षण के साथ किया जा सकता है। भारत पहले से ही बड़े पैमाने पर मवेशियों के लिए इसी तरह के संस्थान चला रहा है। लेकिन अगर कुत्तों के लिए सुविधाएं बदहाल हैं - जिसने शायद अदालत को अपना रुख बदलने के लिए प्रेरित किया हो - तो यह उसी प्रशासनिक उपेक्षा और राज्यों के बीच नीतिगत विखंडन के कारण होगा, जिन्होंने किसी भी बड़े शहर में नसबंदी कवरेज को 70% से अधिक नहीं होने दिया है,

आवारा कुत्ते भारत के शहरी ताने-बाने में रचे-बसे हैं, यहाँ तक कि बेघरों को भी साथ देते हैं। ऐसे दृष्टिकोण सांस्कृतिक विमर्श में जगह पाने के हक़दार हैं, लेकिन चोट लगने के डर के बिना सार्वजनिक स्थानों तक पहुँचने के मानव अधिकार को दरकिनार नहीं कर सकते। अगर कुत्तों को सार्वजनिक सड़कों से हटा दिया जाए, तो करुणा खत्म नहीं हो जाती; उन्हें फिर भी करुणापूर्वक पुनर्वासित किया जाना चाहिए, आश्रय दिया जाना चाहिए और जब वे असाध्य रूप से आक्रामक या बीमार हों, तो मानवीय तरीके से इच्छामृत्यु दी जानी चाहिए। पुराने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की जगह एक आधुनिक क़ानून लाना होगा। इसमें कुत्तों को गोद लेने योग्य, आश्रय-बद्ध या अनुपयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और नगरपालिका आश्रयों के लिए न्यूनतम मानकों का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारों को राज्यों में आवारा कुत्तों की गिनती करनी चाहिए और आश्रयों के रखरखाव की वास्तविक लागत का निर्धारण करना चाहिए, बजाय इसके कि वे इसे लगातार कम करके आँकें। इस व्यवस्था को राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संवर्ग का समर्थन, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और पालतू जानवरों को छोड़ने पर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। इन उपायों के बिना, शहरी भारत दृश्यमान खतरे के बदले अदृश्य उपेक्षा का शिकार होता रहेगा।

मानव निर्मित अकाल

दुनिया को इजरायल को भुखमरी के जरिए गाजा का विनाश करने से रोकना होगा

पिछले कुछ महीनों से, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह, सहायता संगठन और डॉक्टरों ने गाजा की गाजा ने चेतावनी दी है कि यह एन्क्लेव अकाल की कगार पर। गाजा के नागरिक सुरक्षा समूहों द्वारा दुनिया को बार-बार यह बताने पर कि कुपोषण के कारण हर दिन बच्चे मर रहे हैं, भुखमरी की हृदय विदारक कहानियाँ और तस्वीरें सामने आईं।

लेकिन पिछले 22 महीनों से गाजा में नरसंहार युद्ध छेड़ने वाले इजरायल ने इन रिपोर्टों को झूठ बताकर खारिज कर दिया, जबकि उसके पश्चिमी सहयोगियों ने सांकेतिक चिंता व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं किया। पिछले हफ्ते, संयुक्त राष्ट्र समर्थित निकाय, इंटीग्रेटेड फ़ूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन (आईपीसी) ने पुष्टि की कि गाजा के सबसे बड़े शहर और इसके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से "मानव निर्मित अकाल" फैल रहा है, जो पश्चिम एशिया में पहला सामाजिक रूप से घोषित अकाल है। कम से कम पांच घरों में से एक को अत्यधिक भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सभी बच्चों में से एक तिहाई या उससे अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। आईपीसी ने यह भी कहा कि हर 10,000 लोगों में से कम से कम दो लोग भुखमरी या कुपोषण और बीमारियों के घातक संयोजन से रोजाना मरते हैं। फिर भी, अगर किसी को उम्मीद थी कि एक प्रतिष्ठित संगठन की इतनी विनाशकारी रिपोर्ट का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध-पिपासु शासन पर प्रभाव पड़ेगा

इज़राइल ने गाजा में प्रवेश करने वाले सामानों पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाए हैं, जो 2007 से इज़राइल की नाकाबंदी के अधीन है; इसने हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद इन प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया। लेकिन मार्च 2025 में, श्री नेतन्याहू द्वारा युद्धविराम तोड़ने के बाद, इज़राइल ने गाजा में प्रवेश करने वाले सभी सामानों पर कुल तीन महीने की नाकाबंदी लगा दी। जब इसने सीमित मात्रा में भोजन की अनुमति देना शुरू किया, तो एक नए अमेरिकी और इज़राइल समर्थित संगठन, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) ने पिछले संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली खाद्य वितरण प्रणाली को बदल दिया। इस नाकाबंदी के साथ-साथ भोजन वितरण पर इज़राइल के सीधे नियंत्रण ने लाखों लोगों को तीव्र भूखमरी में धकेल दिया। जब हताश, भूखे फिलिस्तीनी जीएचएफ द्वारा चलाए जा रहे सीमित भोजन केंद्रों की ओर दौड़े, तो भीड़ नियंत्रण के नाम पर उन्हें इज़राइली सैनिकों और जीएचएफ स्वयंसेवकों ने गोली मार दी बढ़ते अंतरराष्ट्रीय आक्रोश और युद्ध अपराधों के आरोपों, और कतर व मिस्र द्वारा पेश किए गए नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव को हमास द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद, इज़राइल ने एक नए हमले की तैयारी में गाजा शहर पर हमले तेज़ कर दिए हैं। गाजा में अब जो कुछ हो रहा है, वह हमास को हराने और बंधकों को रिहा करने के इज़राइल के घोषित उद्देश्यों से कहीं आगे है। बढ़ते सबूत गाजा में ही फ़िलिस्तीनी जीवन और समाज को नष्ट करने की मंशा की ओर इशारा करते हैं। दुनिया की नज़रों के सामने 23 लाख लोगों के खिलाफ सबसे क्रूर अपराध किए जा रहे हैं। दुनिया इज़राइल को गाजा में और तबाही मचाने की इजाज़त नहीं दे सकती।

नया संविधान विधेयक, संतुलन की आवश्यकता

समयाता बाल

एक वकील, पूर्व विधान पार्षद हैं
संसद सदस्यों के सहायक (LAMP)

फेलो (2024-25), और, वर्तमान में, एक

संसदीय,
विधायी और
नीति शोधकर्ता

एम राजनीतिक वर्ग में मौखिक ईमानदारी एक विरोधाभास है जिससे भारत लगातार जूझता रहा है। एक ओर, मतदाता नैतिक मूल्यों की मांग करते हैं,

राजनीतिक वर्ग में ईमानदारी की कमी के बावजूद, राजनीतिक वर्ग में अपराध की एक व्यापक प्रवृत्ति व्याप्त रही है। प्रस्तावित संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था, का उद्देश्य एक शर्त प्रदान करके इस शून्यता को भरना है।

इसके तहत, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी या तो इस्तीफा देना होगा या स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा, यदि वे ऐसे अपराधों में 30 दिनों की लगातार अवधि के बाद भी हिरासत में रहते हैं, जिनमें अधिकतम पांच वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है।

सतह पर, कार्रवाई एक प्रतीत होती है स्वच्छ राजनीति को सक्षम बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल। यह हिरासत में बंद भ्रष्ट नेताओं के सत्ता पर काबिज होने के चिंताजनक तथ्य को छूता है, एक ऐसी स्थिति जिसने लोगों का शासन पर से भरोसा उठा दिया है। लेकिन इसके वादे के पीछे कुछ राजनीतिक खामियाँ और संवैधानिक दुविधाएँ छिपी हैं।

इस विधेयक का आधार अनुच्छेद 75 पर आधारित है, संविधान के अनुच्छेद 164 और 239AA, जो क्रमशः केंद्र, राज्यों और दिल्ली में मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित हैं। हालाँकि अनुच्छेद 75(1), 164(1) और 239AA(5) यह आदेश देते हैं कि मंत्री भारत के राष्ट्रपति (या राज्यपाल) की इच्छा पर ही पद धारण करेंगे, इस "प्रसन्नता" की न्यायिक व्याख्या संवैधानिक नैतिकता और कानूनी औचित्य की सीमाओं के भीतर की गई है, जैसा कि शमशेर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और नबाम रेबिया एवं आदि बनाम उपसभापति एवं अन्य जैसे मामलों में हुआ है।

न्यायिक निर्णय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में, संवैधानिक नैतिकता की भूमिका को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रेखांकित किया और कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को ईमानदारी और जवाबदेही के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए। बाद में, मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले में, न्यायालय ने मंत्री नियुक्तियों के नैतिक आयाम पर सीधे तौर पर विचार किया और चेतावनी दी कि गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को कार्यकारी शक्ति नहीं सौंपी जानी चाहिए।

हालाँकि न्यायालय ने स्वतः निष्कासन को अनिवार्य बनाने से परहेज़ किया, लेकिन उसने स्पष्ट संकेत दिया कि नैतिकता संवैधानिक ढाँचे का अभिन्न अंग है। इसलिए, यह विधेयक इन घोषणाओं से शक्ति प्राप्त करता है और लंबे समय से न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त नैतिक अनिवार्यता को विधायी रूप देने का प्रयास करता है।

लेकिन इस विधेयक की महत्वाकांक्षा ही इसकी कमजोरी हो सकती है। एड़ी। सबसे ज्वलंत मुद्दा निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत से संबंधित है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। गिरफ्तारी और हिरासत को समान मानना

संयुक्त संसदीय समिति को संविधान के निर्माण को सावधानीपूर्वक पुनर्संयोजित करने की आवश्यकता है

(एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025

बिना दोषसिद्धि या आरोप तय किए ही, हटाने के आधार पर किसी को हटाने से इस मूलभूत संवैधानिक मूल्य को कमज़ोर करने का जोखिम है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) कुछ मामलों में दोषसिद्धि पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल दोषसिद्धि पर ही कोई विधायक तुरंत अयोग्य हो जाता है। अपील दायर करने और विधायक के रूप में बने रहने के लिए तीन महीने की अवधि को भी रद्द कर दिया गया, इस प्रकार विधेयक के अस्तित्व में आने से पहले ही कड़ी जवाबदेही के लिए न्यायशास्त्रीय समर्थन प्रदान किया गया। यहाँ, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अयोग्यता तभी शुरू होती है जब किसी को दोषी ठहराया जाता है, न कि तब जब किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है।

समस्या इस विधेयक के कार्यकारी विवेक पर निर्भर होने से और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 5 के बाद खंड 5ए, अनुच्छेद 164 के खंड 4 के बाद खंड 4ए और अनुच्छेद 239एए के खंड 5 के बाद खंड 5ए जोड़ा गया है। मंत्रियों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसी सलाह को नज़रअंदाज़ किया जाए तो स्वतः निष्कासन लागू हो जाता है। यह दोहरी व्यवस्था प्रक्रिया का राजनीतिकरण करती है: एक प्रधानमंत्री 30 दिनों के लिए सहयोगियों को बचा सकता है, जबकि एक विरोधी मुख्यमंत्री स्वतः ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को सत्ता से बाहर होने दे सकता है। शासन को पक्षपात से बचाने के बजाय, यह विधेयक राजनीतिक गणनाओं के बदलते परिदृश्य में जवाबदेही को और भी गहरा करने का जोखिम उठाता है।

व्यवहार में असंगति विधायकों और मंत्रियों के बीच व्यवहार में असंगति मामले को और जटिल बना देती है। संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषसिद्धि होने पर ही अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, इस विधेयक के तहत मंत्रियों को केवल हिरासत में लिए जाने पर ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा।

इससे एक विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है जहाँ भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया विधायक तकनीकी रूप से तब तक मंत्री बना रह सकता है जब तक कि उसे अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित न कर दिया जाए, जबकि केवल गिरफ़्तार किए गए मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। यह असमानता कार्यपालिका के मानकों को ऊँचा उठाती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह लोक सेवकों के संवैधानिक व्यवहार में एकरूपता को भी कमज़ोर करती है। इससे सक्षम व्यक्तियों के मंत्री पद की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने से हतोत्साहित होने का ख़तरा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अप्रमाणित आरोपों के आधार पर उन्हें अपने विधायी समकक्षों की तुलना में कठोर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

"घूमते दरवाज़े" की समस्या भी है। चूँकि विधेयक किसी मंत्री के हिरासत से रिहा होने के बाद उसे दोबारा नियुक्त करने की अनुमति देता है, इसलिए कानूनी कार्यवाही की गति के आधार पर इस्तीफ़े और बहाली का चक्र चल सकता है।

कल्पना कीजिए कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 31 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और राज्यपाल तुरंत उसे बहाल कर देते हैं। राज्य को यह सब सहना पड़ता

नैतिक जवाबदेही में कोई खास लाभ न होने के साथ कई हफ़्तों तक राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी। ऐसी अस्थिरता न केवल शासन को कमज़ोर कर सकती है, बल्कि रणनीतिक कानूनी दांवपेंचों को भी बढ़ावा दे सकती है, जहाँ राजनीतिक कर्ता-धर्ता कानून का इस्तेमाल कार्यपालिका को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं।
महासागरों.

एक अधिक सूक्ष्म मॉडल की आवश्यकता। इनमें से किसी भी बात का अर्थ सुधार की तात्कालिकता से इनकार नहीं करना है। राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ना एक कटु वास्तविकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा 2024 के आम चुनाव में सभी 543 विजयी उम्मीदवारों के एक व्यापक विश्लेषण के अनुसार, 251 सांसदों (46%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जो 2019 में 43%, 2014 में 34% और 2009 में 30% से बढ़कर 15 वर्षों में 55% की वृद्धि दर्शाता है। फिर भी, इसके दृष्टिकोण की कठोरता निष्पक्षता के सिद्धांत और शासन की स्थिरता, दोनों को कमज़ोर करने का जोखिम उठाती है। एक अधिक सूक्ष्म मॉडल लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को कम किए बिना स्वच्छ राजनीति के संवैधानिक लक्ष्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा।

एक रास्ता यह हो सकता है कि निष्कासन को गिरफ्तारी से न जोड़कर, बल्कि न्यायिक मील के पत्थरों, जैसे कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप तय करने से जोड़ा जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल प्रारंभिक न्यायिक जाँच में पास होने वाले मामलों में ही इस्तीफ़ा दिया जाएगा, जिससे तुच्छ या राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियाँ बाहर हो जाएँगी। एक अन्य सुरक्षा उपाय एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र, जैसे कि एक न्यायाधिकरण या न्यायिक पैनल, की स्थापना हो सकती है, जो यह जाँच करे कि निष्कासन की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। इससे कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोका जा सकेगा और निष्पक्ष आवेदन सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार, सीधे निष्कासन के बजाय, कानून चल रहे मुकदमों के दौरान मंत्रिस्तरीय कार्यों के अंतरिम निलंबन का प्रावधान कर सकता है, जिससे जवाबदेही से समझौता किए बिना शासन जारी रह सके।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक को अपने दायरे को बढ़ाकर केवल नैतिक अधमता और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर लागू करना चाहिए, न कि पांच साल के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध पर व्यापक जाल बिछाना चाहिए, जिसमें अपेक्षाकृत मामूली आपराधिक आचरण भी शामिल हो सकता है।

संक्षेप में, संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, एक महत्वपूर्ण मानक स्थिति प्रस्तुत करता है जिसका नागरिक भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध एक सशक्त कदम के रूप में स्वागत कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रारूप न्याय के लोकतांत्रिक वितरण की सुरक्षा और नैतिक शासन की तत्काल माँगों के बीच अंतर्निहित तनाव को नज़रअंदाज़ कर देता है। जब तक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) उचित प्रक्रिया और संस्थागत जाँच को शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक पुनर्संतुलन नहीं करती - विधेयक जेपीसी के पास है - यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों को राजनीतिक बहिष्कार के साधनों में बदल सकता है, जो भारत के लोकतांत्रिक प्रयोग के नाज़ुक संतुलन की परीक्षा ले सकता है। क्योंकि, अंततः, ईमानदारी के बिना सत्ता लोकतंत्र को नष्ट कर देती है, और निष्पक्षता के बिना ईमानदारी उसे खतरे में डाल देती है।

पोषण से पोषण तक, पोषण और अनुभूति का संबंध

नीना बडगैयान

वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य
एशियाई में विशेषज्ञ (सलाहकार)

विकास बैंक

नाम्या महाजन

में सह-संस्थापक हैं
रॉकेट लर्निंग

मैं कल्पना कीजिए कि आपको दोपहर 2 बजे एक उड़ान पकड़नी है, दूरी जैसे कारकों को देखते हुए यात्रा, ट्रैक की स्थिति और हवाई अड्डे पर चेक-इन के समय के कारण, यदि आप 12 बजे अपने घर से नहीं निकलते हैं तो आपके उड़ान से चूकने की संभावना है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण समय है कि आप उड़ान पकड़ लें।

इसी तरह, एक बच्चे के लिए, उसके जीवन के पहले 1,000 दिन वह महत्वपूर्ण समय होते हैं - भविष्य की सफलता की नींव रखने का एक ऐसा अवसर जो जीवन में एक बार ही मिलता है। इस अवधि में मस्तिष्क का विकास और परिपक्वता के साथ-साथ पोषण के माध्यम से पर्याप्त वृद्धि भी होनी चाहिए, अन्यथा बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुँच पाएगा।

विज्ञान क्या कहता है विज्ञान निर्विवाद है। दो वर्ष की आयु तक, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का लगभग 80% हो जाता है। इस समय सिनैप्स का विकास चरम पर होता है, और प्रीस्कूल आयु तक सिनैप्टिक घनत्व वयस्क स्तर तक पहुँच जाता है। ललाट लोब का विकास, जो उच्च संज्ञानात्मक कार्यों (योजना, अनुक्रम और आत्म-नियमन सहित) को नियंत्रित करने वाला माना जाता है, जीवन के पहले दो वर्षों के दौरान तीव्र वृद्धि के साथ होता है। यदि मस्तिष्क और कौशल का आधारभूत विकास इन प्रारंभिक दिनों में ही रोक दिया जाता है, तो बाद में होने वाले विकास, जो प्रारंभिक परिपथों और कौशलों पर आधारित होते हैं, स्वाभाविक रूप से सीमित होंगे।

यह सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं है पहले 1,000 दिनों में परिभाषित। कुछ मामलों में, तीन साल की उम्र से पहले पोषण संबंधी कमियों को दूर करना असंभव है। हालाँकि भारत ने 1993 से 2021 के बीच के दशकों में पोषण संबंधी कमियों पर काबू पाने में प्रगति की है, लेकिन गिरावट की वर्तमान दर से, बौनापन (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) का प्रचलन 2075 तक ही 10% तक पहुँच पाएगा। क्या हम 2047 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गति को दोगुना कर सकते हैं? सफल होने के लिए, हमें पोषण और संज्ञान पर प्रयासों को मिलाकर प्रारंभिक बचपन के महत्वपूर्ण समय का लाभ उठाना होगा, जिससे बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का सर्वोत्तम अवसर मिल सके।

एक बच्चे के लिए, उसके जीवन के पहले 1,000 दिन उसके भविष्य की नींव रखने के लिए एक महत्वपूर्ण समय होते हैं; भारत में इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

पोषण और संज्ञानात्मक विकास सभी उद्देश्यों के लिए आवश्यक है साथ-साथ चलते हैं। ये दोनों उद्देश्य एक ही धागे , से बने हैं। मस्तिष्क के कार्य के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है, और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, स्थायी संज्ञानात्मक क्षति या विकलांगता हो सकती है। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जन्म-समूह अध्ययन में पाया गया कि बचपन में आयरन की कमी पाँच साल की उम्र में मौखिक प्रदर्शन और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण गति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और दो साल की उम्र से पहले अभिव्यंजक भाषा विकास को प्रभावित करती है।

शोध से यह भी पता चला है कि संयुक्त पोषण और प्रोत्साहन कार्यक्रमों की तुलना में, अकेले पोषण कार्यक्रमों का प्रभाव कम से मध्यम था। शुरुआती कुछ वर्षों में सीखना तेज़ और स्थायी होता है। तीन साल का बच्चा एक क्षेत्रीय भाषा बोलना शुरू कर देता है और उसे कभी नहीं भूलता। न्यूरोप्लास्टिसिटी की बदौलत हममें से ज़्यादातर लोगों को आज भी नर्सरी राइम्स याद हैं।

भारत में बाल देखभाल कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम, जो दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है, में प्रारंभिक बाल विकास के आधार स्तंभों के रूप में पोषण और शिक्षा, दोनों को प्राथमिकता देने की अनूठी क्षमता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "पोषण भी पढ़ाई भी" जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पोषण और संज्ञानात्मक विकास साथ-साथ चलें।

इसके अतिरिक्त, जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय ढाँचा - नवचेतना, बच्चे की आयु के आधार पर सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रोत्साहन हेतु सरल गतिविधियों के रूप में संरचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ढाँचा बच्चे की आयु के अनुरूप 140 गतिविधियाँ प्रदान करता है, जिन्हें 36 महीने के प्रोत्साहन गतिविधि कैलेंडर में प्रस्तुत किया गया है। इसे माता-पिता, देखभाल करने वालों और आंगनवाड़ी या क्रेच कार्यकर्ताओं द्वारा, विशेष रूप से गृह भ्रमण के दौरान, उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ये देखभाल करने वालों द्वारा समर्थित खेल-आधारित गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, औपचारिक अर्थ में 'सिखाया' जाने के बजाय। उत्तेजना कैलेंडर का उपयोग करते हुए अच्छी तरह से आयोजित घरेलू दौरे से तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके समग्र विकास में सहायता करने के लिए पर्याप्त, समय पर और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और पोषण संबंधी कमी के कारण विकासात्मक देरी के जोखिम को कम किया जा सकेगा।

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र यद्यपि लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र और कार्यकर्ता, विशेष रूप से पहले 1,000 दिनों में, बच्चों को पर्याप्त पोषण और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति में हैं, फिर भी अभी और सुधार की आवश्यकता है। आईसीडीएस कार्यक्रम को अपना दायरा बढ़ाने और स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा में उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ अपनी लक्षित आबादी को संतृप्त करने की आवश्यकता है। इसे प्रौद्योगिकी में प्रगति का लाभ उठाने, शहरी क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार और संवर्धन करने, और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोसामाजिक कल्याण के मूल्यांकन और मापन सहित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की पहुँच, क्षमता और वितरण में सुधार करने की आवश्यकता है।

अंततः, महिलाओं को उत्पादक कार्यबल में शामिल करने के लिए सशक्त बनाने हेतु, हमें सार्वजनिक रूप से संचालित, समुदाय द्वारा संचालित और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित कई मॉडलों की खोज करके क्रेच प्रावधान का विस्तार करने की आवश्यकता है।

हमें याद रखना चाहिए कि हम वही हैं जो हम खाते हैं और हम जो सोचते हैं, वह खो जाता है—और शुरुआती वर्षों में जो खो जाता है, उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। बचपन के शुरुआती पोषण और प्रोत्साहन में निवेश सिर्फ़ स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। यह बच्चों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने और समाज की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है।

प्रारंभिक बचपन में निवेश और निवेश ये मुद्दे विशेष रूप से जरूरी हैं क्योंकि हम स्वचालन, मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नति की तीव्र गति की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कम कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार में कमी आने की संभावना है।

संपादक के नाम चिठी

पहाड़ों में संकट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ से जुड़ी आपदाओं के हालिया मामले, जिनमें अचानक आई बाढ़, बादल फटना और भूस्खलन शामिल हैं, तत्काल ध्यान देने की माँग करते हैं। हो रहा भारी नुकसान पर्यावरणीय और विकास संबंधी ग़लतियों का एक चेतावनी संकेत है।

ये वे राज्य हैं जो पारिस्थितिक संकेतक स्वास्थ्य। चिंता की बात इन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता है।

बानी भाभा, अंबाला,
पंजाब

अभूतपूर्व उपकरण
पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस, 'सेरेबो', जो इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग करके मस्तिष्क को स्कैन करता है, एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव और एडिमा का पता लगाने में उपयोगी हो सकता है।

ट्रॉमा सेंटर जहां सीटी स्कैन मशीनें नहीं हैं

उपलब्ध (अंदर के पन्ने, 24 अगस्त)। यह अपेक्षाकृत सस्ता और गैर-आक्रामक उपकरण मरीज़ों के परिणामों में सुधार लाएगा और इसका इस्तेमाल आपातकालीन और सैन्य परिस्थितियों में किया जा सकता है।

डॉ. थॉमस पालोकारेन, वेल्लोर, तमिलनाडु

पुजारा रिटायर हुए
चेतेश्वर पुजारा का संन्यास के साथ ही भारत के सबसे ज़बरदस्त बल्लेबाज़ों में से एक का करियर खत्म हो गया। उन्हें राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों के साथ याद किया जाएगा।

वह ऑस्ट्रेलियाई किले में टीम की जीत के लिए जिम्मेदार प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे।

सुबाष बालकृष्णन, बेंगलुरु

सभी अच्छी चीजों को थम गया। 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाकर, पुजारा भारत के सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं। लेकिन क्रीज पर बिताया गया उनका समय और उनके द्वारा सामना की गई अनगिनत गेंदें—कुल 97,884 गेंदों में से 16,217 गेंदें—उन्हें इतना खास और अनोखा बनाती हैं।

एक्स पर उनकी पोस्ट सब कुछ कह देती है: 'भारतीय जर्सी पहनकर, राष्ट्रगान गाते हुए, और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए..." पुजारा एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक और कारण से भी अलग दिखते हैं - उनका बेदाग ड्रेस सेंस।

एपी तिरुवडी, चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में पूरा डाक पता और पूरा नाम या नाम के साथ प्रारंभिक अक्षर अवश्य होने चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नैतिकता परिपक्वता से आती है, जबकि जिज्ञासा और उत्साह युवा होने के लक्षण हैं।

- ग्राहम ग्रीन, उपन्यासकार

मर्यादाओं से ही जीवन में महान मूल्य आते हैं

जीवन-सूत्र

बीके शिवानी
प्रेरक वक्ता और विचारक

अगर आप गणेश जी की चार भुजाएं देखें तो पाएंगे कि उनमें बहुत सुंदर प्रतीक हैं। एक भुजा में कुल्हाड़ी है। यह ज्ञान की कुल्हाड़ी है, जिससे हमें अपने विकारों, अपनी नकारात्मकता और अपने पुराने बुरे कर्मों को समाप्त करना है। दूसरे हाथ में रस्सी है। संदेश यह है कि ज्ञान का हम उपयोग करें, ध्यान करें, लेकिन धारणा तभी होगी जब जीवन में अनुशासन होगा। संयम, नियम के बिना धारणा नहीं हो सकती। तो अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, पैसे कमाने गए तो किसी भी तरह का काम कर दिया, ऐसी आत्मा मेधावी नहीं बन सकती है। जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधें, जैसे सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही खान-पान, धन कमाने का सही तरीका।

फिर तीसरे हाथ को आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो सारा दिन हमें किसी से कुछ चाहिए होता है। प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, भरोसा चाहिए... मांगने की मुद्रा में हाथ रहता है हमारा, लेकिन गणेश जी का हाथ ऐसा नहीं है। उनका हाथ हमेशा देने की मुद्रा में है। मतलब चाहिए-चाहिए कुछ नहीं सबको देना है और उसमें भी सबको आशीर्वाद देना है। मतलब कोई भी आत्मा आएं, कैसे भी संस्कार हों, कैसा भी व्यवहार हो, वो अपने संस्कार लेकर आएंगे, वो अपने कर्म करेंगे, लेकिन हमसे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ-भावना, अच्छे शब्द और आशीर्वाद ही निःसृत होंगे।

फिर चौथे हाथ में मोदक है। अध्यात्म को अपने जीवन में लाना तो सहज है, लेकिन लापरवाह होकर यह नहीं हो सकता है। मोदक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अध्यात्म को भी पूरी तरह से अपने जीवन में ले आने में निरंतर ध्यानपूर्ण मेहनत करनी होती है। लेकिन एक बार वो मेहनत कर ली तो फिर मोदक मीठा बहुत होता है। मतलब कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है।

ध्यान तो कर लेंगे, लेकिन धारणा तभी होगी जब जीवन में अनुशासन होगा। संयम, नियम बिना धारणा नहीं हो सकती। जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना होगा।

लेकिन जब इतना सबकुछ अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर महिमा भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, बहुत लोग आपको अच्छा-अच्छा भी कहेंगे। उस समय ध्यान रखना है ज्ञान का अहंकार न आ जाए, विशेषताओं का अहंकार न आ जाए, जो कार्य परमात्मा आपसे करवा रहा है उसका अहंकार न आ जाए। तो मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत है, लेकिन गणेश जी उसको खाते नहीं हैं, केवल हाथ में ही रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि सफलता मिलेगी, लेकिन उसके अहंकार को स्वीकार नहीं करना है। उसको सिर्फ हाथ में ही रखना है। तो किसी भी मूर्ति में गणेश जी को मोदक खाते हुए नहीं दिखाते हैं। वे सिर्फ उसे सम्भालकर पकड़े हुए रहते हैं। सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार। वास्तव में वो इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है।

तो गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। जो आत्मा ये सबकुछ कर लेती है उसको विघ्नविनाशक कहते हैं। विघ्न तो उसके जीवन में आता ही नहीं है। आने से पहले ही विघ्न खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के भी दुःख हरके उनको सुख देते हैं।

▪ 2 मिनट रीड

खुशी की गाइड

उपलब्धियों को ही खुशी ना मान लें

रिसर्च, साइकोलॉजी टुडे, यूएस

अंदर की खुशी इस सच को जान लेने में है कि जिंदगी कोई उपलब्धियों की चेकलिस्ट या फेहरिस्त भर नहीं है। आपकी योग्यताएं, आपका रेज्यूमे जहां यकीनन आपके अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए मायने रखता है, वहीं यह भी सच है कि ये खुशी की गारंटी नहीं देते। प्रसन्नता की भावना इन सबसे कहीं बढ़कर है।

- साइकोलॉजी टुडे के एक शोध में पाया गया कि ये जरूरी नहीं कि अधिक उपलब्धियां हासिल करने वाला व्यक्ति भीतर से खुश भी होगा। उलटे, अपनी सफलता को बनाए रखने की महत्वाकांक्षाएं उसे भीतर से असंतुष्ट भी बनाए रख सकती हैं। एंग्जायटी को जन्म दे सकती हैं।
- मनुष्य सफलताओं की तुलना में अपनी असफलताओं से ज्यादा सीखते हैं। संघर्षों से उनका व्यक्तित्व परिपक्व होता है। कल्पनाशीलता उन्हें उत्साह और रोमांच देती है। रचनात्मक बनाती है। वास्तव में, हमारे जीवन में खुशियों के कई पल ऐसे होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की उपलब्धियों के सांचे में फिट नहीं किया जा सकता।
- मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी हैं और मित्रताओं, सम्बंधों से सच्ची खुशी पाते हैं। हर किसी के जीवन में निकट मित्र और करीबी सम्बंधी होते हैं। उनके प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता, स्वीकार्यता से मनुष्य का अंतर्मन पल्लवित होता है। ये खुशी रेज्यूमे में नहीं लिखी जा सकती।

▪ 1 मिनट रीड

सकारात्मक संकल्प

अच्छे दिन की कल्पना

कल्पना करने से क्या हो सकता है? बहुत कुछ। वास्तव में मनुष्य का जीवन उसकी कल्पनाओं, धारणाओं, विचारों से ही निर्धारित होता है। तो एक काम करें। सुबह उठें तो दो-चार मिनट शांति से बैठकर आज के अच्छे दिन की कल्पना करें। यह सोचें कि आज क्या अच्छा होने वाला है या आज आप क्या अच्छा कर सकते हैं। खुद को पूरे दिन के लिए तैयार करें। ऊर्जा, सकारात्मकता और संकल्प से भरें। नकारात्मक बातों को दिमाग में न लाएं और निराश विचारों से खुद को बचाएं। एक नया दिन नई शुरुआत का समय होता है और इस अवसर पर आपका उत्साह से भरा होना बहुत महत्व रखता है। दिन की अच्छी शुरुआत करें। ***सकारात्मक संकल्प लें कि दिन शुरू होने पर खुद को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे।*** ▪ 1 मिनट रीड

संघर्ष की कहानी **भारती सिंह,** कॉमेडियन

गरीबी में रहीं, बॉडी शेमिंग झेली, अब देश के सबसे महंगे कॉमेडियंस में से एक

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। फिलहाल भारती एक पॉडकास्ट की वजह से चर्चा में हैं। अपने काम से भारती ने अच्छी शोहरत कमाई है। लेकिन उनका ये सफर कई संघर्षों से भरा हुआ रहा है। आज जानते हैं उनकी संघर्ष से सफलता की कहानी...

करीब 2 साल की रही होंगी भारती, जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। उनकी मां के लिए परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उन पर भारती और दो भाई-बहनों की जिम्मेदारी भी थी। परिवार गरीबी से जूझ रहा था।

संघर्ष : बासी खाना खाया, परफॉर्मेंस के पैसे नहीं मिले

भारती की मां लोगों के घरों में साफ-सफाई का काम करती थीं। लोग अपने खाने के बाद बची हुई सब्जी उन्हें दे देते थे। वो बासी सब्जी भारती के परिवार के लिए ताजा समान हुआ करती थी। कई बार तो नमक रोटी खाकर ही भारती को सोना पड़ता था। भारती को त्योहारों के दिनों से डर लगता था। क्योंकि वे न तो उन दिनों में मिठाइयां खरीद पाते थे, न ही कपड़े। लोग पटाखे जलाते थे तो भारती बीच में खड़े रहकर ताली बजाकर खुश हो जाती थीं। भारती ने तीरंदाजी व राइफल शूटिंग में भी हाथ आजमाया। लेकिन राइफल महंगी होने के कारण खुद की राइफल नहीं ले पाईं। अपने लॉफ्टर करियर के शुरुआती दिनों में लोग उन्हें मोटी कहकर चिढ़ाते थे। कई बार तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के बदले पैसे तक नहीं मिला करते थे।

सफलता: 30 करोड़ रुपए के करीब है भारती की नेटवर्थ

साल 2008 में भारती को द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज से ब्रेक मिला। वहां उनका लल्ली किरदार बहुत ही मशहूर हुआ था। इसके बाद कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा शो में उनकी दमदार परफॉर्मेंस सराही गई। उन्होंने झलक दिखला जा, लॉफ्टर शेफ जैसे शो में भी काम किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वे एक एपिसोड के 10-13 लाख रुपए चार्ज करती हैं। आज भारती सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली कॉमेडियंस में से एक हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसपर 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कभी खाने तक के संकट से जूझीं भारती के पास आज मुंबई में आलीशान घर है। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्लू जैसी लग्जरी कारें भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीबन 30 करोड़ रुपए है। ▪ 1 मिनट रीड

असाधारण रिकॉर्ड **क्रिस्ट्रोफ स्ट्रेसर,** एथलीट

24 घंटे में 1000 किमी साइकिल चलाई

2021 में ऑस्ट्रिया के साइकिल चालक क्रिस्ट्रोफ स्ट्रेसर ने अपने नाम एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल क्रिस्टोफ 24 घंटे में साइकिल से सर्वाधिक दूरी तय करने वाले साइकिल सवार बने थे। उन्होंने इस दौरान 1026 किलोमीटर की दूरी तय की थी। स्ट्रेसर ने अपना यह अटैम्प्ट तेज बारिश व खराब मौसम के बीच शुरू किया था। 24 घंटे के समय में उनकी साइकिल सिर्फ 2 मिनट तक ही रुकी। इस दौरान उन्होंने दो बार कपड़े भी बदले। एक बार उनकी साइकिल का टायर भी पंक्चर हुआ। इस रिकॉर्ड अटैम्प्ट में स्ट्रेसर ने करीबन 14,400 कैलोरीज बर्न कीं। इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद स्ट्रेसर ने कहा कि इस खराब मौसम में भी यह उपलब्धि हासिल करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं 20 साल से इस स्पोर्ट में हूं। यह रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ▪ 1 मिनट रीड

सीख : स्ट्रेसर कहते हैं, आप इस तरह की एक्टिविटीज में होते हैं तो सपोर्ट स्टॉफ बड़ा साथी होता है। यानी कि सहयोग ही सबसे मूल्यवान होता है।

सबक वाला पाठ

दुनिया के 7 अजूबे

एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे सात अजूबों के बारे में लिखें। सभी बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। एक छात्र भी लिख रहा था। लेकिन जब उसे छोड़कर बाकी सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी, तो शिक्षिका ने पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें उत्तर पता नहीं?

छात्र ने कहा, दुनिया में इतने अजूबे हैं, जैसे चीन की दीवार, कोलोसियम, स्टोनहेंज, गीजा का पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, ताज महल, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, लेकिन कुछ अजूबे इनसे भी बढ़कर हैं। उन्हीं के बारे में लिख रहा था। जब शिक्षिका ने उसकी उत्तर पुस्तिका उठाई तो पाया कि उसने लिखा था : सबसे बड़े सात अजूबे हैं- देख पाना, सुन पाना, महसूस कर पाना, हंसना, सोचना, दयालु होना, प्यार करना! शिक्षिका इस उत्तर पर दंग रह गईं।

मोरल ऑफ द स्टोरी : प्रेरणा दूर से ही नहीं आती। पास की चीजों की भी कद्र करें। ▪ 1 मिनट रीड

सीनियर सिटीजन

खेल अच्छे हैं **गेम्स 80 वर्ष से अधिक उम्र** के बुजुर्गों में भूलने की आदत 40% तक कम कर सकते हैं

ये इनडोर गेम्स रखेंगे मानसिक सेहत मजबूत

डॉ. जयश्री नागवेकर
लाइफ कोच एंड डायरेक्टर न्यूरो रिहैबिलिटेशन सिनर्जी इंडिया, मुंबई

उम्र बढ़ने के साथ चाबियां, फोन रखकर भूल जाना या सही शब्द ढूंढ़ने में परेशानी जैसी बातें बुजुर्गों के सामने आ ही जाती हैं। लेकिन इन समस्याओं को बुजुर्ग सुधार सकते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक गेमिंग इसे सुधारने का सबसे कारगर उपाय है। गेम्स 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में भूलने की आदत को 40% तक कम कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए गेम्स मनोरंजन से अधिक मानसिक सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। ये डिमेंशिया से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही दिमाग को तेज रखते हैं।

स्क्रैबल, शतरंज, क्लासिक बोर्ड जैसे गेम याददाश्त और तर्कशक्ति को बढ़ाते हैं। साथ ही सार्थक सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। ये गेम्स मस्ती और हंसी के जरिए मस्तिष्क में एंडोर्फिन को बढ़ावा देते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं और जीवन जीने में आनंद लेते हैं। ऐसे ही कुछ गेम्स के बारे में जानते हैं, जो बुढ़ापे में आपकी याददाश्त तेज करेंगे, तर्कशक्ति को बढ़ाएंगे।

ये दिमागी और शारीरिक खेल मेलजोल बढ़ाते हैं और सेहत भी सुधारते हैं

स्क्रैबल: मस्तिष्क के कई भागों पर इसका असर

- शोध से पता चलता है कि यह आरामदायक खेल बीपी को कम करता है। याददाश्त में भी जबर्दस्त सुधार करता है। यह खेल मनोरंजन से कहीं अधिक लाभदायक है।
- वैज्ञानिकों ने कई शोध में पाया है कि शब्द-खेल खेलने वाले वृद्धों में 65 वर्ष की आयु के बाद मेमोरी लॉस ढाई साल तक कम हो सकता है।
- स्क्रैबल मस्तिष्क के कई भागों पर एक साथ काम करता है। शब्दों को याद करने से याददाश्त मजबूत होती है। आपकी शब्दावली और बोलने के कौशल में भी सुधार होता है।

शतरंज: डिमेंशिया होने की 35% संभावना कम

- एक शोध के मुताबिक 75 साल से ज्यादा उम्र के शतरंज खिलाड़ियों में गैर-खिलाड़ियों की तुलना में डिमेंशिया होने की संभावना 35% कम होती है।
- जर्नल ऑफ एप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च में पाया गया कि शतरंज खेलने वाले बुजुर्गों ने रणनीतिक सोच परीक्षणों में बेहतर अंक पाए।
- शतरंज खेलने से बुढ़ापे में भी अल्प व दीर्घकालिक स्मृति, गणना, समस्या-समाधान स्किल, पैटर्न पहचान, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति बढ़ती है और याददाश्त मजबूत बनी रहती है।

सुडोकू: निर्णय क्षमता बढ़ाता है

- सुडोकू जैसी संख्या आधारित पहेलियां स्मृति को सक्रिय करती हैं। ये निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं।
- ब्रिटेन में हुए एक शोध के मुताबिक सुडोकू खेलने वाले 50 से अधिक उम्र के व्यक्तियों में स्मृति कार्यों में अपने से 10 साल छोटे व्यक्ति जैसा तर्क कौशल पाया गया।
- सुडोकू जैसी पहेलियां हल करने से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उत्तेजित होता है।

फिजिकल: संतुलन बढ़ेगा

- टेबल टेनिस, शफलबोर्ड जैसे खेल संतुलन और समन्वय बनाए रखने में मदद करते हैं।
- डार्ट्स खेल बुजुर्गों में हाथों व आंखों का कॉर्डिनेशन अच्छा बनाते हैं। डार्ट्स में एक लक्ष्य पर निशाना लगाना होता है।
- कम श्रम वाले इन गेम्स से मस्तिष्क में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं, जो अधिक खुश और तनावमुक्त महसूस कराते हैं।

डिजिटल गेम: अकेलापन घटेगा

- कैंडी क्रश ऑनलाइन गेम है। ये बुजुर्गों के दिमाग को व्यस्त रखता है। इसमें कई तरह के लेवल होते हैं, जिन्हें पार करना होता है।
- वर्ड्स विद फ्रेंड्स स्क्रैबल जैसा गेम मोबाइल स्क्रीन पर शब्द निर्माण लाता है। यह केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी के साथ खेला जाता है।
- कनाडा की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक डिजिटल गेम बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर कर सकते हैं।

मन के रहस्य **नकारात्मक विचारों** से कैसे लड़ें?

आप अपनी गलत पहचानों को हटा दें, तो मन एक दर्पण की तरह हो जाएगा

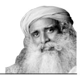

सद्गुरु
आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक

विचार एक ऐसी चीज है, जिसे आप खुद बनाते हैं। अगर आप यह समझ जाएं कि यह बस एक विचार है, तो इसमें कोई ताकत नहीं रह जाती। अगर आप इसे हकीकत मान लेते हैं, तो यह आपको नष्ट कर देता है। आप अपने विचारों को असली इसलिए मानते हैं, क्योंकि आप सही मायने में सोच नहीं रहे हैं। 'सोचने' शब्द का अर्थ है कि आप अपनी विचार प्रक्रिया का सचेतन रूप से उपयोग कर रहे हैं।

अनजाने में चल रही विचार प्रक्रिया सबसे नकारात्मक चीज है

- अभी आपका मन एक तरह के मानसिक दस्त की स्थिति में है। आप इन विचारों को पैदा करते हैं, और फिर आप ही उनसे लड़ते हैं! नकारात्मक या सकारात्मक विचार जैसी कोई चीज नहीं होती या तो यह एक सचेतन विचार है या यह बस दस्त है। सबसे नकारात्मक चीज विचार की सामग्री नहीं है, बल्कि यह है कि आपकी विचार प्रक्रिया अनजाने में चल रही है। इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है।
- यदि आपको शारीरिक दस्त हैं, तो सबसे पहले खराब भोजन खाना बंद करना होगा। आपके मानसिक दस्त के लिए, खराब भोजन बस इतना है कि आपने खुद की पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ ली है, जो आप नहीं हैं। एक बार जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप अपनी विचार प्रक्रिया को नहीं रोक सकते।
- शरीर भोजन का संग्रह है। मन जानकारियों का संग्रह है। आप जो इकट्ठा करते हैं, उसे अपना कह सकते हैं, पर कहते हैं, 'यह मैं हूं' तो आपको इलाज की जरूरत है।
- उदाहरण के लिए, आप कहते हैं, 'यह मेरी कार है' तो यह ठीक है, लेकिन आप कहते हैं, 'मैं कार हूं,' तो तुरंत इलाज की जरूरत है।
- आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी चीज में स्पष्टता लाने के लिए है कि क्या आपका है और क्या आप हैं। अगर आप अपनी गलत पहचानों को हटा दें, तो मन एक दर्पण की तरह हो जाएगा। वह कुछ भी नहीं कहेगा, बस सब कुछ प्रतिबिंबित करेगा।

अपने ऐसे अनुभव, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें, srcitizen@dbcorp.in पर भेजें। चुनिंदा पत्र प्रकाशित करेंगे।

टेक्नोलॉजी गाइड **ये डिवाइस** जीवन करेगी आसान

चलने-फिरने में दिक्कत है तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आपकी करेगी मदद

यदि चलने-फिरने में दिक्कत है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बाजार में बैटरी वाली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आ गई हैं। ये 45 हजार से 1.5 लाख कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं। ये व्हीलचेयर लेड-एसिड, लिथियम-आयन बैटरी के साथ आ रही हैं। इन व्हीलचेयर में इवॉक्स, कर्मा, मेड-इमूव, ऑस्ट्रिच, हीरो, विस्को सहित कई ब्रांड ऑफलाइन-ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की क्रूजिंग रेंज 12-30 किमी के बीच होती है। कुछ मॉडल 12-20 किमी चल सकते हैं।

- ***खासियत:*** *हेडरेस्ट वाली कैप्टन सीट उपयोगकर्ता को आराम देती है। इसमें रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट है, जिसे 180 डिग्री तक झुकाया जा सकता है। इसे आसानी से मोड़ सकते हैं, बैटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।*

ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड

100 की उम्र में दौड़ शुरू की, 200 मेडल जीत चुकीं

ये हैं हरियाणा की 107 वर्षीय एथलीट रामबाई। इनका जज्बा ऐसा है कि 100 वर्ष की उम्र में दौड़ शुरू की थी। अब तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीब 200 मेडल जीत चुकी हैं। दौड़, शॉट पुट व डिस्कस थ्रो में ये मेडल अपने नाम किए हैं। पिछले साल इन्होंने हैदराबाद में नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था।

आर्थिक साथी **इक्विटी-लिंक्ड** सेविंग स्कीम

डेढ़ लाख की टैक्स कटौती में छूट मिलेगी निवेश पर 14% तक मिल सकता है रिटर्न

वरुण निर्मलकर
म्यूचुअल फंड एडवाइजर

यदि आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) निवेश का ठीक विकल्प हो सकती है। यह एक प्रकार का टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड है। ये फंड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य हैं। इसमें डेढ़ लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फायदा आयकर भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर ही मिलेगा।

100 रुपए की SIP का भी विकल्प

ईएलएसएस का लॉकइन पीरियड तीन साल है। यानी कम से कम 3 साल तक निवेश करना होगा। इसमें 12-14% तक रिटर्न मिल सकता है। इसे 100 रु. की एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) से भी शुरू कर सकते हैं।

5 हजार निवेश, 5 साल में 5 लाख मिलेंगे

यदि आप इसमें 5 साल तक हर माह 5000 रुपए निवेश करते हैं तो 12-14% रिटर्न के अनुसार मैच्योरिटी पर करीब 5 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि ईएलएसएस इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही टाइप है, इसलिए जोखिम के अधीन है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आगे बढ़ता भारत

प्रधानमंत्री ने 'इकोनोमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम' में भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहते हुए आत्मनिर्भर बनने की जो जरूरत बतायी, उसे टैरिफ वार की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत इस स्थिति में है कि दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है. हमारा लक्ष्य भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके लिए अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा तथा 'दाम कम, दम ज्यादा' की नीति अपनानी होगी. रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत वैश्विक ग्रोथ को गति दे सकता है. उनके मुताबिक, 2047 में विकसित भारत का आधार स्पीड, स्केल और स्कोप के मंत्र वाली आत्मनिर्भरता होगी. देश की आर्थिक प्रगति का उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 100 देशों को इवी निर्यात करने जा रहा है और दिवाली तक जीएसटी में सुधार का काम पूरा हो जायेगा. खुदरा महंगाई 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है. देश में सेमीकंडक्टर की फैक्टरियां लगनी शुरू हो गयी हैं और इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जायेगी, 6जी पर हम तेजी से काम कर रहे हैं. वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स की भारत के बारे में ताजा रेटिंग ही बहुत कुछ बता देती है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहा, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने 18 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी. ये तमाम संकेत बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद से गगनयान मिशन जल्दी पूरा होगा तथा अगले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन होगा. प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि गहरे अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का समूह तैयार कर रहा है, जिसके लिए युवाओं को आगे आना होगा. आर्थिक शक्ति के साथ-साथ भारत कूटनीतिक शक्ति भी है. इसका पता इससे चलता है कि ट्रंप के भारत के प्रति सख्त रुख की अमेरिका में आलोचना हो रही है, तो चीन, रूस, ब्राजील आदि देश भारत के साथ खड़े है. देश की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी बेहद उत्साहवर्धक है कि भारत अब पीछे नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है.

प्रधानमंत्री ने 'इकोनोमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम' में देश की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर होने की जो जरूरत बतायी है, उसे टैरिफ वार की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है.

कूटनीति में ट्रंप पर भारी पड़ते पुतिन

शिवकांत
पूर्व संपादक, बीबीसी हिंदी
shivkant.sharma@gmail.com

लंदन से विशेष

अलास्का वार्ता के आईने में देखें, तो पुतिन की दिलचस्पी जेलेंस्की से बात करने में कम और अमेरिका के साथ संबंधों की बहाली में अधिक है. उसके लिए उन्हें युद्धविराम करना पड़ा, तो करेंगे. इस बीच ट्रंप का धीरज भी डोलने लगा है, वह फिर से सख्त प्रतिबंधों और टैरिफ की बातें करने लगे हैं. इसका सीधा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि रूस के तेल व्यापार पर टैरिफ की चोट करने के लिए ट्रंप फिर भारत को ही पहला निशाना बनायेंगे. उनके व्यापार और वित्त मंत्रियों के भारत विरोधी बयानों की कटुता निरंतर बढ़ रही है.

माना यह जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन के बीच बढ़ती गुटबंदी तोड़कर रूस को पश्चिमी खेमे की तरफ लाना चाहते हैं. इसीलिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना से बचते हैं. गाजा पर इस्राइली हमले बंद कराने में कामयाब न होने के बाद यूक्रेन का युद्ध रुकवा कर वहां सुलह-शांति कराने के उनके प्रयासों के पीछे नोबेल शांति पुरस्कार की चाह के अलावा शायद यह भी एक कारण रहा हो, परंतु पुतिन ने शतरंज के शातिर खिलाड़ी की तरह जिस चतुराई से अलास्का की शिखर बैठक में बिछायी ट्रंप की बिसात पर उन्हें मात दी है, उसके बाद से यह माना जाने लगा है कि पुतिन ने स्थायी समाधान की बातें बनाकर ट्रंप को नाटो गुट में फूट डालने की अपनी रणनीति के जाल में फंसा लिया है.

शिखर वार्ता के बाद ट्रंप ने पुतिन के शब्द दोहराते हुए युद्ध के जिन बुनियादी कारणों के समाधान की बात की, उनमें यूक्रेन के नाटो की सदस्यता हासिल करने के प्रयास, उसका सैन्यीकरण और कथित नात्सीकरण प्रमुख हैं, जिन्हें आधार बनाकर ही पुतिन ने 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया, फिर 2022 में यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी. ट्रंप ने सुलह-शांति के लिए यूक्रेन के कुछ भागों के लेन-देन की बात भी की, जिसका इशारा पिछले साढ़े तीन साल की लड़ाई में रूस द्वारा जीते गये यूक्रेनी प्रांतों की ओर था. चूंकि अलास्का शिखर वार्ता में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संघ के नेता शामिल नहीं थे, इसलिए वार्ताओं के बाद ट्रंप ने उन्हें फोन किये. अगले ही दिन वाशिंगटन में शिखर बैठक बुलायी गयी, जिसमें जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड के नेताओं और नाटो तथा यूरोपीय संघ के प्रमुखों ने भाग लिया. वाशिंगटन की शिखर बैठक में ट्रंप ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने पुतिन को शांति समाधान पर बातचीत के लिए तैयार कर लिया है. रूस यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार है. अमेरिका और नाटो सुरक्षा गारंटी में हाथ बंटा सकते हैं, परंतु यूक्रेन को नाटो की सदस्यता की कोशिशें छोड़नी होंगी.

ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि पुतिन जेलेंस्की के साथ शिखर बैठक के लिए और त्रिपक्षीय शिखर बैठक के लिए भी तैयार हैं, जिसमें ट्रंप भी शामिल होंगे. जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की दिलचस्पी यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की रूपरेखा और उसमें अमेरिका की भूमिका पर अधिक थी. बैठक के बाद जर्मन चांसलर ने ट्रंप से अनुरोध किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाने से पहले पुतिन पर युद्धविराम का जोर डालें, पर न तो ट्रंप ने इस पर ध्यान दिया और न ही पुतिन की ओर से इसका कोई इशारा मिला. उल्टे गत सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करते हुए उसके शहरों और ऊर्जा केंद्रों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किये, जिनमें पश्चिमी यूक्रेन में स्थित एक अमेरिकी कंपनी के भी कई कर्मचारी घायल हुए. वाशिंगटन की शिखर बैठक से दो-तीन मुख्य बातें सामने आयी हैं. पहली तो यह कि पुतिन यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में नाटो और अमेरिका की भूमिका स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाद के बयानों में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वह अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षा के लिए नहीं भेजेंगे. रूस ने भी जाहिर कर दिया कि वह यूक्रेन में नाटो सैनिकों की उपस्थिति स्वीकार नहीं करेगा. रूस यह भी चाहता है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने वाले देशों में उसे भी शामिल किया जाए और उसे यूक्रेन पर हमले की जवाबी सैन्य कार्रवाई को वीटो करने का अधिकार भी मिले. रूस यूक्रेन का विसैन्यीकरण भी करना चाहता है. ऐसे में यूक्रेन और यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसी सुरक्षा गारंटी का मतलब क्या रह जाता है.

दूसरी बात, शांति समाधान के लिए यूक्रेन के उन भागों के लेन-देन की थी, जिन पर रूस कब्जा कर चुका है. अभी तक यूक्रेन और यूरोपीय देश यूक्रेन के किसी भी भाग पर रूसी कब्जे का विरोध करते आये हैं, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर किसी देश की सीमा बदलना उसकी प्रभुसत्ता और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का खुला उल्लंघन है. यदि रूस को यूक्रेन की जमीन हड़पने दिया गया, तो दुनिया का हर बलशाली देश कमजोर पड़ोसियों पर चढ़ बैठेगा! इसके बावजूद वाशिंगटन शिखर बैठक के बाद यूक्रेन और यूरोपीय देश यूक्रेन की जमीन के लेन-देन की बात पर चुप रहे. जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत होनी जरूरी है, जिसके आसार भी धूमिल होते दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल पुतिन जेलेंस्की को इस युद्ध का एक मूल कारण मानते हैं. यदि उन्हें बातचीत के लिए तैयार कर लिया गया, तो भी बातचीत के स्थान को लेकर ऊहापोह चल रहा है. अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने पुतिन के खिलाफ युद्धापराध का वारंट निकाल रखा है. इसलिए वह केवल उन्हीं देशों में जा सकते हैं, जो या तो स्विट्जरलैंड की तरह तटस्थ हों या अमेरिका की तरह अपराध अदालत को न मानते हों. समीक्षकों का मानना है कि पुतिन शांति वार्ताओं में उलझा कर लड़ाई को सर्दियों तक खींचना चाहते हैं, ताकि डोनबास प्रांत के उन बचे हुए भागों पर भी उनका कब्जा हो सके, जहां यूक्रेनी सेना ने मोर्चाबंदी कर रखी है. उनकी दिलचस्पी जेलेंस्की से बात करने में कम और अमेरिका के साथ संबंधों की बहाली में अधिक है. उसके लिए उन्हें युद्धविराम करना ही पड़ा, तो करेंगे. इस बीच ट्रंप का धीरज भी डोलने लगा है, वह फिर से सख्त प्रतिबंधों और टैरिफ की बातें करने लगे हैं. इसका सीधा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि रूस के तेल व्यापार पर टैरिफ की चोट करने के लिए ट्रंप फिर भारत को ही पहला निशाना बनाएंगे. उनके व्यापार और वित्त मंत्रियों के भारत विरोधी बयानों की कटुता निरंतर बढ़ रही है.

दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप या उनके मंत्रियों ने अभी तक तुर्किये पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना तो दूर, सख्त बयान भी नहीं दिये हैं, जबकि तुर्किये अपना अधिकांश तेल रूस से ही खरीदता है. कुछ आलोचक इस दोहरी नीति को टैरिफ दस्युपन की संज्ञा भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भारत में तीन दशकों की मेहनत से जमाये उस विश्वास को खो रहा है, जिसके सहारे वह एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित करना चाहता था. कहां अमेरिकी कभी चीन की घेराबंदी की बातें करते थे और कहां अब सौदेबाजी में लगे हैं. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

आवारा कुत्तों पर अदालत का फैसला संतुलित

डॉ आरटी शर्मा
अध्यक्ष, पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, नयी दिल्ली
rt.yourvet@gmail.com

सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उस पर यदि तत्काल युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा. इसमें विशेषज्ञ नीतियां बनाएं, आरडब्ल्यूए को भी इनमें शामिल करें, ताकि उन्हें भी महसूस हो कि वे भी इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि अब कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जायेगा तथा आक्रामक व रेबीज संक्रमित कुत्तों को अलग रखा जायेगा. शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि स्थानीय निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक निश्चित स्थान बनायेंगे, कुत्तों को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता. शीर्ष अदालत का यह फैसला देशभर में समान रूप से लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संतुलित निर्णय दिया है. जब आप कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं, तो कुत्ते उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानने लगते हैं और वहां से हटते नहीं. ऐसे में, कई बार कुत्ते छोटे बच्चों पर हमला भी कर देते हैं. ऐसे में न्यायालय का यह निर्णय कि सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, सबको स्वीकार्य होना चाहिए. अनेक लोग तो मॉल में दूसरी, तीसरी मंजिल पर भी कुत्तों को खाना खिलाने लग जाते हैं. तीन-चार मंजिली बिल्डिंग में भी लोग कुत्तों को ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर खाने खिलाते हैं. इससे कुत्ते उस पूरे स्थान को अपना मानने लगते हैं और वहां से हटते ही नहीं हैं. इससे लोगों को, विशेषकर छोटे बच्चों को, आने-जाने में परेशानी होती है. कुत्ते प्रेमियों को इस सामाजिक पहलू से भी सोचने की जरूरत है. उन्हें थोड़ा संवेदनशील और जागरूक होने की आवश्यकता है. उन्हें चाहिए कि वे सोसाइटी के किसी कोने या कहीं और किसी कोने में एक जगह बना लें और वहीं कुत्तों को खाना खिलायें. इससे किसी को समस्या नहीं होगी, बल्कि इस तरह से सभी चीजें व्यवस्थित हो जायेंगी और जो पशुओं से थोड़ा डरते हैं, हो सकता है वे भी उनके दोस्त बन जाएं, धीरे-धीरे वे उनसे प्रेम करने लगें. यह भी जानना जरूरी है कि पशु किसी को भी ऐसे ही नहीं काट लेते हैं. जब उन्हें डर लगता है या वे असुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वे किसी पर हमला करते हैं, उसे काटते हैं. कोर्ट ने रेबीज से संक्रमित कुत्तों को शेल्टर में रखने और उन्हें वापस न छोड़ने की जो बात कही है, वह भी सही है और समझदारी वाली बात है. रेबीज एक घातक बीमारी है. एक बार किसी को हो जाए, तो वह जान लेकर ही जाती है, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है. जब हम रेबीज ग्रस्त मनुष्य को अलग-थलग रख सकते हैं, तो पशुओं को क्यों नहीं? हालांकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रेबीज एक अधिग्रहित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज है. कुत्ते रेबीज के साथ जन्म नहीं लेते. यह बीमारी उनमें उन रेबीज ग्रस्त जानवरों के जरिये आती है, जो उन्हें आकर काट लेते हैं. ऐसे कुत्ते जब किसी को काटते हैं, तो वह मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है. इस तरह रेबीज फैलती है. रेबीज को फैलने से रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है. कई देशों में रेबीज पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण होता है, ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश रेबीज मुक्त देश नहीं है.

एक और महत्वपूर्ण बात. इस बात का पता कैसे चलेगा कि किस कुत्ते को रेबीज है, किसे नहीं? कौन-सा कुत्ता आक्रामक है, कौन-सा नहीं? इसके लिए जितने भी पेशेवर लोग- मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, नीति-निर्माता- हैं, उन्हें एक दिशा-निर्देश तैयार करना चाहिए. ऐसे शेल्टर होम बनाने की जरूरत है, जहां ऐसे कुत्तों को अलग से रखा जाए, जिन्हें इस तरह का संक्रमण है या होने की आशंका है. और फिर, वहां पर पेशेवर उनका ब्लड सैंपल लेकर जांच करे कि कौन-सा कुत्ता संक्रमित है और कौन-सा नहीं. इसके साथ ही वह उसके व्यवहार पर भी निगरानी रखे. यदि कुत्ते को रेबीज है, तो उसे उसी शेल्टर में रखें और नहीं है, तो बिहेवियर काउंसेलिंग के लिए दूसरे शेल्टर में ले जाएं. यदि उसका व्यवहार सही है, वह आक्रामक नहीं है, तभी उसे लाकर उसके इलाके में छोड़ें. इसे लेकर एक बहुत ही मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण होना चाहिए. हमारे लिए सोशल और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उस पर यदि तत्काल युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा. इसमें विशेषज्ञ नीतियां बनाएं, आरडब्ल्यूए को भी इनमें शामिल करें, ताकि उन्हें भी महसूस हो कि वे भी इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं. एक बात और, जो पशु प्रेमी हैं और जो पशु से जुड़े एनजीओ हैं, उनको इस बात को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि हर कुत्ता रेबीज संक्रमित नहीं होता है, न ही हर कुत्ता आक्रामक होता है. यदि कोई कुत्ता आक्रामक है, किसी को काट रहा है, तो उस कुत्ते को अलग-थलग करने में प्राधिकरण की सहायता करनी चाहिए. इस मामले में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है. आखिर सारा काम स्थानीय निकायों को ही तो करना है. न्यायालय के निर्णय से आशा बंधी है कि इस मामले में सभी अपना-अपना योगदान देंगे.

(बातचीत पर आधारित)
(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

बढ़ता स्क्रीन टाइम भावनात्मक जुड़ाव को कम कर रहा है

हमारे द्वारा डिजिटल उपकरणों का लगातार उपयोग क्या हमें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनसे हम प्यार करते हैं? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि आजकल एक कमरे में होते हुए भी हमारा ध्यान अक्सर एक-दूसरे के बजाय अपनी-अपनी स्क्रीन पर होता है. इस स्थिति में हमारी अपनों के साथ शारीरिक निकटता तो रहती है, पर वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता है. यह वास्तविकता, पारिवारिक समय (फैमिली टाइम) की परिभाषा को चुनौती दे रही है. स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल एक बुरी आदत से कहीं अधिक है, यह एक बड़ा बदलाव है जो परिवारों की बातचीत और जुड़ाव के तरीके को प्रभावित करता है.

The Himalayan

यह वास्तविक जीवन की बातचीत, साथ में गेम खेलने और एक परिवार के रूप में उन पलों को स्मृति का हिस्सा बनाने के अवसरों को छीन लेता है. स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से हमारे संचार करने की क्षमता खराब हो रही है. वास्तविक तरीके से बातचीत, जो मानवीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण है, धीरे-धीरे गायब हो रही है. एक अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग संचार की गुणवत्ता को निम्न स्तर का कर देते हैं. इससे एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की हमारी क्षमता को हानि पहुंच सकती है. इससे हम आंखों के साथ होने वाले संपर्क और शारीरिक हाव-भाव जैसे गैर-मौखिक संकेतों को भी खो देते हैं. इससे हमारी संचार क्षमता- जो स्वस्थ संबंध के लिए जरूरी है- बाधित होती है. इस आदत से छुटकारा पाने का बेहतर तरीका यही है कि हम एक ऐसा समय और स्थान निर्धारित करें, जहां फोन ले जाने की अनुमति न हो. खाने की मेज इसका आदर्श उदाहरण हो सकता है. इससे आप दूसरों पर ध्यान केंद्रित कर पायेंगे. ध्यान केंद्रित करने के ये पल आपको खुलकर बात करने, दिनभर की अपनी बातों को साझा करने और मजबूत संबंध बनाने का मौका देंगे. **-राखी बिंद**

बोधि वृक्ष

वास्तविक सुख

जीवनभर कुछ न कुछ लालच लगा ही रहता है कि कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा. कई बार आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर भी लोग लालच करते रहते हैं. ऐसे व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा? न ही लोभी को, न ही कामी को सुख मिलता है. सुख उसे ही मिलता है, जो निसंग है. संग से मिलने वाला सुख दो कौड़ी का है. निसंग होकर जो सुख की उपज भीतर से आती है, वही वास्तविक सुख है. प्राण जला, तन जला, मन जला, बुद्धि भ्रमित हो गयी और व्यक्ति की मृत्यु हो गयी. फिर व्यक्ति उसी सुख की तलाश में जन्म लेकर फिर वहीं गोता लगाता रहता है. जब गुरु मिलते हैं तो कहते हैं- आप निरंजन हैं, आप प्रकाशमय हैं. फिर लगता है कि मैं जिसकी तलाश में जगह-जगह घूमता फिरता रहा, वह तो यहीं पर, इसी क्षण है. अब ताली बजा कर जोर-जोर से गाते हैं, भजन गाकर थक जाते हैं, तो दो मिनट के लिए अच्छा ध्यान लगता है. इस तरह से गाना भी एक क्रिया हुई. और जब हम पहाड़ चढ़-चढ़ कर वैष्णो देवी जाते हैं तो रजोगुण, तमोगुण दोनों समाप्त हो जाते हैं. हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों में देवी-देवताओं को इसीलिए बैठाया है. जब कोई कहता है कि आप क्रिया कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो मन नहीं लगता. अब वहां पहाड़ में, तीन पहाड़ चढ़िये और उतरिये. इतना करके तो मन शांत हो ही जाता है. तो जो अनुभव आपको पहाड़ चढ़ कर हुआ, वही अनुभव प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया करके, बैठे-बैठे वहीं हो गया. बस टांगों में दर्द नहीं हुआ. शरीर में, सिर में जो दर्द था, वह भी मिट गया. इस तरह जब कुछ करने के राग से छुटकारा मिल जाये, तभी हम निष्क्रिय हो सकते हैं.

आप कितना स्वाद ले सकते हैं, कितना भोजन कर सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितना सूंघ सकते हैं, कितना सुन सकते हैं? इन सब को भोगने की शक्ति सीमित है. मगर मन के लालच की कोई सीमा नहीं है. लालच ही तो हमें अपने आप से मिलने नहीं देता. देने में जो आनंद मिलता है, वही वास्तविक है. लेने का आनंद बचकाना है.

-श्री श्री रवि शंकर

प्रबंध सूत्र

जिसके साथ रहेंगे, वैसा ही बन जायेंगे

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

लोगों की एक किस्म हमेशा शिकायत की अवस्था में होती है- हमारे साथ जमाने ने सही नहीं किया, मां-बाप ने हमें यह नहीं दिया, हमें अच्छे दोस्त नहीं मिले. ऐसे शिकायतीचंद लोगों के साथ रहनेवाले भी शिकायती होने लगते हैं. हर दफ्तर में ऐसे लोग मिल जाते हैं. लोगों की एक किस्म और है. कोई क्लर्क बता सकता है कि पच्चीस साल पहले कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल गया था, जो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ जानते थे. उनके साथ रहकर निवेश के बारे में बहुत कुछ सीखा, इसलिए अब तमाम किस्म की आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिली हुई है. आप जिनके साथ रहेंगे, देर-सबेर वही बन जायेंगे, यह महीन सूत्र है. जिन लोगों के साथ रहना है, उन्हें एहतियात से चुनिये. दोस्तों को चुनने में सावधानी जरूरी है. दुश्मन आप नहीं चुन सकते, वे बन जाते हैं. हरेक से मिलना जरूरी होता है, पर हरेक से मित्रता करना जरूरी नहीं होता. आपके साथ वाले कई तरह की बातें करेंगे. कुछ का तात्कालिक असर होता है, कुछ का बाद में. कुछ का असर अवचेतन दिमाग पर होता है. शेयर, म्यूचुअल फंड वालों की सोहबत करेंगे, तो देर-सबेर गलतियां करके सही रास्ते पर लग जायेंगे. कुंठित लोगों की सोहबत रहेगी, तो आप भी अपनी हर नाकामी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने लगेंगे. लोगों की मानसिकता समूह से बनती है. आप किस समूह में है, यह देखना जरूरी है.

तुलसीदास 'रामचरित मानस' में लिख गये हैं-'सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई', यानी दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है. कंपनी, स्कूल, दफ्तर या कॉलेज में सही समूह का हिस्सा होना जरूरी होता है. किसी स्टार्ट अप की कामयाबी की कहानी देखिये. कुछ मित्र शुरू करते हैं और स्टार्ट अप सफल होते ही सब सफल हो जाते हैं. स्टार्ट अप डूब जाता है, तो भी सही समूह में गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं. सारा दोष जमाने पर नहीं डालते. कामयाबी और विफलता के बीच एक बड़ा फर्क उस समूह का होता है, जिसमें आप रहते हैं. देशों की कामयाबी और विफलता की भी यही कहानी है. किस तरह के व्यक्तित्वों से आप प्रेरित हैं, कौन आपके साथ हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण हैं.

आम तौर पर अच्छे समूह के लोग कई बार बहुत मनोरंजक बातें नहीं करते, पर काम की बातें करते हैं. अच्छे समूह मनोरंजक गतिविधियां नहीं करते, पर उत्पादक गतिविधियां करते हैं. इसलिए कई बार बहुत बोरिंग होते हैं. ज्ञानी व्यक्ति रुखी बातें करते हैं, पर उनकी सोहबत बहुत ज्ञान देनेवाली होती है. जरा गौर से देखिए कि आप किस समूह में हैं? क्या यह सही समूह है, जिसमें आपको होना चाहिए?

आपके पत्र

बढ़ता शहरीकरण : प्रकृति से बढ़ती दूरी

आज दुनिया में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. यह विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इस विकास की कीमत क्या है? हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो आधुनिक सुख-सुविधाओं से तो भरी है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण से दूर होती जा रही है. जिस तरह से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, हरियाली का दायरा सिकुड़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं. बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन, जलवायु परिवर्तन और मौसम के चक्र में आ रहे बदलाव के कारण पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

प्रसिद्ध यादव, पटना

आभासी रैली आज के समय की मांग

आज की भाग-दौड़ की जिंदगी में राजनीतिक रैलियां लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन गयी हैं. रैली के कारण घंटों लगनेवाले जाम में मरीजों व विद्यालय जाने वाले बच्चों को समस्या होती है. इसके कारण व्यापारियों का कामकाज बाधित होता है. सूचना क्रांति के दौर में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने संचार को बिल्कुल सहज और सुलभ बना दिया है. ऐसे में नेताओं को आभासी (वर्चुअल) रैली को अपनाना चाहिए. इससे वे अपने विचार को लाखों लोगों तक तुरंत पहुंचा सकते हैं, खर्च भी कम होगा और लोगों को असुविधा नहीं होगी.

हिमांशु शेखर, केसपा (गया जी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 25-08-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMTEN User: arvind.yadav1 Time: 08-24-2025 22:23 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । सोमवार, 25 अगस्त 2025

यह युद्ध का दौर नहीं

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्योता देकर सरकार ने संकेत दिया है कि शांति समझौता कराने में नई दिल्ली सक्रिय भूमिका निभा सकती है। इस कदम का स्वागत होना चाहिए। रूस और यूक्रेन को अगर भारत बातचीत की मेज पर ले आता है, तो यह पूरी दुनिया के हित में होगा।

जेलेंस्की को न्योता

बातचीत ही रास्ता । पिछले साल अगस्त में नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले उन्होंने रूस की यात्रा की थी। दोनों जगह उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट किया कि शांति बहाल होनी चाहिए, यह युद्ध का दौर नहीं है। हाल में अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के बीच हुई शिखर वार्ता का भी भारत ने स्वागत करते हुए कहा था कि बातचीत व कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

संतुलित नजरिया । ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने से लेकर अभी तक, यूक्रेन युद्ध का समीकरण काफी कुछ बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन, उनकी यह जल्दबाजी नीतियों में अस्थिरता के रूप में सामने आ रही है। कभी वह जेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, कभी पूतिन पर। हालांकि जब तक सहमति न बने, शांति थोपी नहीं जा सकती। इस मामले में भारत का नजरिया शुरू से संतुलित रहा है कि रूस और यूक्रेन, दोनों को शामिल किए बिना समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता।

शांति का समर्थन । यूक्रेन को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ने अमेरिका की साख को चोट पहुंचाई है, जबकि भारत ने शुरुआत से स्टैंड क्लियर रखा कि वह किसी के साथ नहीं, युद्ध के खिलाफ है। यूरोप और अमेरिका के दबाव डालने के बावजूद उसने किसी एक के पक्ष में खड़े होना नहीं चुना। यूक्रेन भी अब इस बात को मान रहा है कि भारत का रुख 'न्यूट्रल' नहीं, बल्कि वह शांति, कूटनीति और राजनीतिक संवाद का समर्थन कर रहा है।

दोनों का भरोसेमंद । किसी और देश की तुलना में भारत आज रूस और यूक्रेन, दोनों के बीच संवाद स्थापित कराने के लिए बेहतर स्थिति में है। उसे यह ताकत उसकी तटस्थता से ही मिली है। कीव और मॉस्को, दोनों उस पर भरोसा कर रहे हैं और दोनों को नई दिल्ली से ज्यादा सक्रियता की उम्मीद है। भारत के पास मौका है कि वह संवाद की राह में आ रही रुकावटों को दूर करे। भारत जैसे देश तब चुपचाप खड़े होकर नजारा नहीं देख सकते, जबकि वे निर्णायक भूमिका निभाने की हैसियत रखते हों।

चक्र-व्यू

हमारी डॉग यूनियन

राहुल पाण्डेय

हमारे मोहल्ले की कुत्ता यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले दिनों जब अदालत ने सभी कुत्तों को बाड़े में बंद करने का आदेश दिया, हमारी यूनियन सड़क पर उतर आई। सामने वाले गोल चक्कर पर सभी अपने-अपने कुत्ते लेकर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। अपने मालिक को नारेबाजी करते देख कुत्ते भी भला कैसे पीछे रहते। सभी सप्तम सुर में गाने लगे। इसी बीच पुलिस आ गई, जिसने यूनियन को समझा-बुझाकर कुत्तों समेत वापस भेजा। अब जबसे अदालत ने अपना आदेश बदला है, यूनियन में खुशी का माहौल है। मैं भी इस यूनियन का एक सदस्य हूं, लेकिन सक्रिय नहीं रहता। अब यूनियन ने कार्यक्रम बनाया है अदालती आदेश के पालन का। यह अच्छी बात है कि हमारी यूनियन किसी निगम के पास नहीं जाती। सभी लोग आपस में चंदा करके गली-मोहल्ले के कुत्तों का वैक्सीनेशन करा देते हैं। अदालती आदेश के बाद अब एक बार फिर से सभी कुत्तों का वैक्सीनेशन कराने का प्रोग्राम बना है। मैंने पूछा कि इन्हीं कुत्तों का तो दो महीने पहले वैक्सीनेशन हुआ है, अब फिर से क्यों? सबने मुझे यह कहते हुए चुप करा दिया कि तुम हमेशा चुप रहते हो तो अब भी चुप रहो। मैं चुप हो गया।

वैसे मैं इंसानों की भी कई यूनियनों में रहा हूं। इंसानों की यूनियनों में भी एका है। कुत्तों पर जब दोबारा फैसला आया तो यूनियन के ही एक पुराने साथी ने आह भरी। कहने लगे, काश, इंसानों के फैसले भी ऐसे ही फटाफट होते। मैंने विरोध किया। कहा, कुत्ते बोल नहीं सकते, सिर्फ भौंक या काट सकते हैं। वो बोले, कुत्तों वाली कई चीजें इंसानों में भी तो पाई जाती हैं। दुम हिलाना, नैन नचाना, भौंकना, काटना, कमजोर को दबाना और अपने इलाके पर कब्जा होने की सूरत में हिंसा पर उतरना। क्या नहीं है इंसानों में कुत्तों के जैसा? कटखन्ने इंसान बाड़े में ही बंद किए जाते रहे हैं। अब पूछने की बारी मेरी थी। मैंने पूछा, सब कुछ कुत्तों की तरह ही है, तो फिर इंसानों की यूनियन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? वो बोले, सिर्फ एक दिक्कत के चलते। इंसान की दुम नहीं दिखती! अगर दिखती, तो उनकी भी यूनियन इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती!

एकदा

स्वामीजी की चाय

लगभग सवा सौ साल पहले की बात है। विवेकानंद ने बेल्लूर मठ में गांजा और चिलम बंद करवा कर उसकी जगह चाय का सेवन शुरू करवाया था। उन्होंने सबको समझाया कि चाय का सेवन करने से दूसरी आदत नहीं रहेगी। मठ में चाय शुरू करने के पीछे विवेकानंद की भावना यही थी कि गांजा जैसे नशे का प्रचलन बंद हो। विरोधियों ने कहा कि चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शरीर में मादकता पैदा करती है। विरोधियों की शिकायत पर नगरपालिका ने दंड के रूप में बेल्लूर मठ पर टैक्स लगा दिया। स्वामी विवेकानंद ने टैक्स देने से इंकार करते हुए नगरपालिका पर केस कर दिया। मुकदमे की सुनवाई चिंसुराह जिला न्यायालय में हुई। क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए मठ के संयासियों को बुलाया गया। संन्यासियों ने स्वीकार किया कि वे चाय पीते हैं और यह मादक पदार्थ नहीं है। मैजिस्ट्रेट ने मठ का दौरा किया, वहां चाय पीने और पिलाने की जांच की और नगरपालिका को आदेश दिया कि चाय पीने के लिए लगाए गए टैक्स को वापस लें। विवेकानंद की जीत हुई। उन्होंने आज से लगभग सवा सौ साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में यह पदार्थ घर-घर पिया जाएगा। इसके फायदे-नुकसान पर बहस भले की जाए, यह तथ्य निर्विवाद है कि आज कुटिया से लेकर महलों तक में यह लोकप्रिय पेय बनी हुई है।

Subrata Dhar

संकलन : **हरिप्रसाद राय**

'आर्ट ऑफ हिटिंग' के दौर में 'आर्ट ऑफ लीविंग' वाले पुजारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

अपने समय का अलबेला क्रिकेटर

रूपेश रंजन सिंह

आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें। जवाब यही मिलेगा कि वह देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है। कुछ अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल लेते हैं। कुछ की तकदीर साथ नहीं देती और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर उतनी मेहनत नहीं करते, जितनी टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए दरकार होती है। पैसे छापने की मशीन T-20 फॉर्मेट के आने के बाद से तीसरी किस्म के क्रिकेटरों की तादाद बढ़ी है। वहीं चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद शुद्ध टेस्ट प्लेयर्स की संख्या घट गई।

15 साल पहले । 'आर्ट ऑफ हिटिंग' के इस दौर में 'आर्ट ऑफ लीविंग' की कला को जिंदा रखने वाले पुजारा ने भी बाजार के रुख को समझते हुए अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कुल 103 टेस्ट खेलने वाले इस 'आखिरी टेस्ट स्पेशलिस्ट' की अंतरराष्ट्रीय कहानी करीब 15 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शुरू हुई थी। सीरीज का दूसरा टेस्ट था और चौथी इनिंग में 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तीसरे ओवर में ही वीरेंद्र सहवाग का विकेट गंवा दिया।

खूबसूरत दस्तक । डेब्यू टेस्ट की पहली इनिंग में पुजारा प्रभाव नहीं छोड़ सके थे, इसके बावजूद कप्तान एमएस धोनी ने राहुल द्रविड़ को बैटिंग क्रम में नीचे करके उन्हें तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। डोमेस्टिक में तब तक अपनी पहचान गाढ़ी कर चुके पुजारा ने 72 रन की एक संतुलित पारी खेलकर विश्व क्रिकेट में अपनी खूबसूरत दस्तक दी। हालांकि भारतीय टीम का अहम हिस्सा वह तब बने, जब उन्होंने करीब दो साल बाद अपने चौथे टेस्ट मैच में शतक जड़ा। उसी साल दो महीने बाद अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा।

पारियों पर रिसर्च । पुजारा ने विपक्षी टीमों को यह विश्वास दिला दिया कि राहुल द्रविड़ की ही माफिक उनका डिफेंस तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। द्रविड़ के बाद पुजारा ने बल्लेबाजी में तीसरा क्रम अपने नाम करवा लिया। अपने करियर में पुजारा ने कई क्लासिक पारियां खेलीं। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रन हो या फिर जोहानिसबर्ग में डेल स्टेन ऐंड कंपनी की आग उगलती गेंदों के खिलाफ 153 रहे हों। लेकिन कुछ पारियां ऐसा भी रहीं जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक मजबूती, स्किल और इस खेल के प्रति अपने समर्पण की वह मुकम्मल तस्वीर बनाई, जो आने वाले समय में शोध का विषय होगी।

तंज वाली तालियां । 2018 में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में सफाए से बचने के लिए मैदान में उतरी थी। लेकिन जिस तेजी से दस ओवर के भीतर ही टीम ने अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिए, लगा नहीं कि वापसी हो पाएगी। वहीं तीसरे ओवर में ही क्रीज पर आ चुके पुजारा पारी के 20 ओवर पूरे हो जाने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल सके थे। जब कुल 53वीं गेंद पर पुजारा ने अपना खाता खोला तो दर्शकों ने तंज में उनके लिए तालियां बजाई। इस बल्लेबाज ने खुले दिल से उनकी तालियों का अभिनंदन किया।

एकाग्रता के पुजारी । पुजारा की उस धीमी पारी की चर्चा पूरे शहर में थी। युवा पीढ़ी हैरान थी कि कोई बल्लेबाज बिना रन बनाए इतनी देर क्रीज पर एकाग्रता के साथ खड़ा कैसे रह सकता है? पुजारा उस पारी में 179 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए। कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना भी की। लेकिन कुछ दिनों में ही साबित हो गया कि वो पुजारा की ही संयमित पारी थी, जिसके इर्द-गिर्द इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत कहानी लिखी गई।

आखिरी टेस्ट स्पेशलिस्ट

- 15 साल पहले शुरू किया था टेस्ट खेलना
- राहुल द्रविड़ की तरह पिच पर रहते थे अडिग
- आलोचनाओं का देते रहे बल्ले से जवाब

बुरे दौर में अडिग । एक ऐसी ही बेमिसाल पारी पुजारा ने साल 2021 में इंग्लैंड में खेली थी। बुरे दौर में बल्लेबाज हर गेंद इस डर के साथ खेलता है कि कहीं गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के हाथ में ना चली जाए। या कोई गेंद सीधे उसके पैड से ना टकरा जाए। पुजारा भी ऐसी ही मनोस्थिति से गुजर रहे थे। सीरीज के दूसरे टेस्ट में पुजारा ने अपना खाता खोलने के लिए 35 गेंद ली थीं, जबकि उनकी पूरी पारी 206 गेंद पर 45 रन की रही थी। कहा जाने लगा कि पुजारा रन बनाना भूल चुके हैं। लेकिन अगले ही टेस्ट में उन्होंने एक बार फिर 91 रन की पारी खेल डाली और अपने आलोचकों को एक बार फिर निशब्द कर दिया।

टेस्ट में खरे । टेस्ट क्रिकेटर कहलाने के हर मापदंड पर खरे उतरने वाले पुजारा करियर के आखिरी दिनों में अक्सर ही असली टेस्ट खेलने के कारण आलोचना का शिकार होते रहे। शायद यह बदलते वक्त और खेलने व देखने वालों के बदले मिजाज के कारण हुआ। आगे भी वक्त बदलेगा, मिजाज भी बदेलगा। लेकिन क्रिकेट में यह बात तो तय है कि टेस्ट 'क्रिकेट में स्पेशलिस्ट' का तमगा हासिल करने वाले पुजारा संभवतः अंतिम बल्लेबाज रहेंगे।

अनुभवों की सीख से बढ़ता जाता है सुख

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

'**इन दोनों** का एक लंबा इतिहास रहा है और उस इतिहास की अनदेखी करने का भी एक इतिहास रहा है।' विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर जब यह बात कही, तो इसके पीछे का सबक यही था कि अपने अतीत से सीखना कितना जरूरी है। हर किसी का जीवन भरा होता है अनुभवों से - चाहे वह कोई व्यक्ति हो, समाज या फिर देश। अतीत बस बीत नहीं जाता, वह हमारी स्मृति में छिपा खजाना बनकर हमारे साथ रहता है। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है, जब हम उन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं।

अतीत हमें आईना दिखाता है। अगर हम किसी गलती को बार-बार दोहराते हैं, तो उसका बोझ और पीड़ा भी उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम उसी गलती से सबक लेते हैं, तब अतीत मार्गदर्शक बन जाता है हमारा। यही सीख परिपक्व बनाती है जीवन को। प्राचीन भारतीय कहावत है कि अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। और यह अनुभव हासिल होता है बीती बातों की शिक्षा को संजोकर रखने से। यही पोटली जीवन भर साथ बंधी रहती है - समय के साथ बढ़ती हुई।

कभी सोचा है कि क्यों हम अपने बचपन की गलतियों को याद करके मुस्कुराते हैं? एक वजह यह भी है कि आज हम जानते हैं उन भूलों ने ही हमें सिखाया। पहली बार साइकल से क्यों गिरे - यह याद न रहे तो क्या बच्चा फिर साइकल संभाल पाएगा? उसका गिरना शर्मिंदा होने नहीं, सीखने का पल था। जब हम अपनी पुरानी असफलताओं को एक सबक के रूप में देखते हैं, तब उनमें भी एक गहरा सुख छिपा होता है। यह सुख वैसा ही है जैसे कठिन परीक्षा पास करने के बाद मिलने वाली राहत। प्राचीन धर्मग्रंथ भी बताते हैं कि धीर पुरुष वही है, जो अपने और पराए अनुभव से शिक्षा लेता है। हर सभ्यता यह जरूर बताती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन सीखने वाला हर परिस्थिति से कुछ पा लेता है।

अतीत से भागना या उसे कोसना व्यर्थ है। न इसे बदला जा सकता है, न झुठलाया। छिपाने की कोशिश भी बेकार है। परछाई की तरह है अतीत - किस्मत का सूरज जब सिर चढ़कर बोल रहा हो, तब भले यह किसी को नजर न आए, लेकिन इसे हमेशा के लिए ढक देना मुमकिन नहीं। कभी न कभी यह सामने आ खड़ा ही होता है।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विन्सटन चर्चिल का कहना था कि अगर हम भूत और वर्तमान के बीच जंग शुरू कर दें तो पाएंगे कि अपना भविष्य हार चुके हैं। यानी, स्वीकार करें, सीखें और आगे बढ़ें - अतीत की बुनियाद पर बेहतर भविष्य ऐसे ही बन सकता है।

अगर भविष्य आशंकाओं से भरा लग रहा है, तो एक बार वक्त में पीछे झांकिए। देखिए, कि तब कैसी मुश्किलें थीं और उनका सामना कैसे किया था आपने। इससे हौसला मिलेगा। इतिहास अनदेखी करने के लिए नहीं, जानने-समझने के लिए है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को यह मलाल रहा कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इस मलाल को दूर करने का मौका समय सभी को दे रहा है।

शेयर करें अपना अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesofindi.com** और सब्जेक्ट में लिखें- '**जीवन आनंद**'

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

फोन पर स्क्रैच नहीं पड़ने देते, तो मन मलिन क्यों

सलिल पाण्डेय

मनुष्य जीवन अपने आप में अनुपम है। यह जीवन आनंद, उल्लास और उमंग के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रत्येक क्षण हमें इस जीवन को आनंद से भरने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता और विवेक का परिचायक है। इसके विपरीत क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घमंड में डूबा व्यक्ति समझदार नहीं कहला सकता, क्योंकि वह जीवन के मूल उद्देश्य से विमुख हो जाता है।

यदि भौतिक वस्तुओं से तुलना करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम जीवन के साथ कितनी लापरवाही बरतते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नया एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए कवर और गार्ड लगाते हैं। यदि फोन पर स्क्रैच पड़ जाए तो तुरंत दुकानदार से ठीक कराने दौड़ पड़ते हैं। यहां तक कि उसमें जमा इलेक्ट्रॉनिक कचरे को हटाने के लिए क्लीनर तक का उपयोग करते हैं। यही नहीं, जिस घर में हम रहते हैं, उसमें समय-समय पर रंग-रोगन और मरम्मत कराते हैं ताकि घर की सुंदरता और मजबूती बनी रहे।

ये सब तो निर्जीव पदार्थ हैं। न इनके पास मन है और न सोचने-समझने की क्षमता। फिर भी हम उनकी सुरक्षा को लेकर इतने सजग रहते हैं। तो क्या यह उचित नहीं कि जब हमें इतना उत्तम मानव शरीर मिला है, तो उसकी देखभाल और उसकी शुद्धि के लिए भी सजग रहें? स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन हममें से कई देर तक सोते रहते हैं और उठते ही तनाव, चिड़चिड़ेपन और क्रोध से दिन की शुरुआत करते हैं। आधुनिक चिकित्साशास्त्र भी कहता है कि क्रोध और नकारात्मक भावनाएं लिवर, किडनी, हृदय और मस्तिष्क पर गहरा दुष्प्रभाव डालती हैं। ऐसे में मनुष्य सोचता है कि अच्छा भोजन करने के बावजूद वह रोगों से घिरा क्यों है। कारण यही है कि मन का वातावरण दूषित है।

विद्वानों का मत है, जहां एक शब्द से काम चल जाए, वहां पूरा वाक्य न बोलें। अधिक बोलने से विवाद बढ़ता है, जबकि संयमित वाणी से शांति और स्वास्थ्य, दोनों सुरक्षित रहते हैं। बोलने से पहले विचार करना वैसा ही है जैसे धन खर्च करने से पहले सोच लेना। धन एक बार गया तो लौट भी सकता है, लेकिन वाणी एक बार निकली तो वापस नहीं आती। लोग धन-संपत्ति के लिए चिंतित रहते हैं। धन निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन वह स्थायी और सुखद परिणाम नहीं देता।

इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद ढूंढ़ना ही श्रेष्ठ साधना है। मनुष्य शरीर वास्तव में आनंदधाम है, उसे दुख से क्यों भरें। केवल आवश्यकता भर बोलें, क्रोध और कटुता को त्यागें, और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। यही जीवन का सच्चा उपयोग है और यही हमारे भीतर छिपे ईश्वर की वाणी।

अफ़ग़ानिस्तान का अंधा युग

विचार विंडो

मृत्युंजय राय

अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिकी फौजें वापस लौटीं तो दुनिया भर के अखबारों में उससे जुड़ी खबरें सुर्खियां बनीं। अमेरिका की यह एक और हार थी।

अंधा युग । लेकिन सवाल ये है कि आज अफगानिस्तान जिस अंधेरे युग में जी रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और दो दशक तक वहां युद्ध करने वाले अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से कहां गलती हुई? क्या अफगानिस्तान को इस अंधे युग में जाने से बचाया जा सकता था? इन सवालों का जवाब जॉन ली एंडरसन की किताब **TO LOSE A WAR: The Fall and Rise of the Taliban** में मिलता है।

AI Image

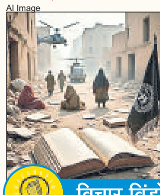

बदहाली का दस्तावेज । जॉन ने दो दशक से भी अधिक वक्त तक अमेरिकी मैगजीन न्यूयॉर्कर के लिए अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग की। वह अमेरिका के जाने-माने वॉर करेस्पॉन्डेंट रहे हैं। किताब में नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद शाह मसूद की हत्या के बाद यानी साल 2001 से 2021 तक की रिपोर्ट्स हैं।

नई आशा । किताब के शुरुआती अध्याय में 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी ताकत के बढ़ने और तालिबान के कमजोर पड़ने के बारे में बताया गया है। जॉन लिखते हैं कि अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद जब वह काबुल में थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह तालिबान वहां से भाग रहे थे। तब लग रहा था कि अगर इस देश को ठीक से संभाला गया तो उसका भविष्य उज्ज्वल है।

अमेरिका की गलती । उन्हीं दिनों जॉन ने पूर्व अफगानी कम्युनिस्ट गुलाम सरवर अकबरी का इंटरव्यू किया था। अकबरी उस इंटरव्यू में कहते हैं कि अमेरिका के चलते ही अफगानिस्तान आतंकवादियों की पनाहगार बना। उनके मुताबिक, जब सोवियत संघ की फौज की मुजाहिदीनों के हाथों हार हुई और उन्हें यहां से जाना पड़ा, तब अमेरिका ने अफगानिस्तान को भुला दिया। अगर तब अमेरिका ने अफगानिस्तान का सहयोग किया होता तो तालिबान को अपनी जड़ें मजबूत करने और सत्ता पर काबिज होने का मौका नहीं मिलता।

सपना टूटा । 9/11 के हमलों के बाद अल कायदा और उसे पनाह देने वाले तालिबान के खिलाफ अमेरिका को जंग छेड़नी पड़ी। इस तरह से जॉन पन्ना दर पन्ना बताते चले जाते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य का सपना बर्बाद हुआ।

2010 आते-आते मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी थी। तब तक अमेरिका को यह अहसास हो चला था कि अफगानिस्तान में वह लंबे युद्ध में फंस चुका है, जबकि 2001 में जब बुश के शासनकाल में फौज ने आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की थी, तब यही सोच थी कि यह लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। तालिबान टिक नहीं पाएंगे और फिर अमेरिका अपने हिसाब से वहां सरकार बनवा पाएगा। लेकिन सचाई इसके उलट निकली।

अस्पष्ट नीति । शुरुआती लड़ाई में भले ही तालिबान टूटकर बिखर गया, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी और अमेरिका का नुकसान भी। जॉन यह सवाल करते हैं कि अमेरिका इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि वह वहां कितने समय तक आतंकवादियों से लड़ाई लड़ेगा या उसका मकसद अफगानिस्तान का नवनिर्माण है?

ताकि प्यार बना रहे

आधी दुनिया

प्रणव प्रियदर्शी

अरुंधति रॉय जितना अपने लेखन के लिए सराही जाती हैं, उतनी ही अपनी प्रतिबद्धताओं और दृढ़ स्टैंड के लिए भी जानी जाती रही हैं। लेकिन शुरुआती पारिवारिक जीवन से जुड़े उनके अनुभव अब तक सार्वजनिक चर्चा से बाहर ही रहे हैं। इन पर रोशनी हाल में पड़ी जब इस बुकर प्राइज विनर लेखिका के संस्मरण 'मदर मेरी कम्स टु मी' पुस्तक रूप में छपकर आए। इस पुस्तक में अरुंधति का बेटी रूप, खासकर अपनी मां से उनके जटिल रिश्ते पूरी बारीकी के साथ उभरे हैं।

दिलचस्प है कि अरुंधति के भाई के मुताबिक, मां ने किसी और के साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं किया, जितना अरुंधति के साथ किया। इसके विपरीत खुद अरुंधति की यह राय है कि इस मामले में अव्वल स्थान उनका नहीं बल्कि उनके भाई का बनता है। बहरहाल, अरुंधति पता नहीं क्यों ऐसा मानती रही थीं कि मां उनसे ज्यादा जिएंगी। और जब ऐसा नहीं हुआ, 89 की उम्र में मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वह न सिर्फ स्तब्ध थीं, बल्कि पूरी तरह टूटी हुई महसूस कर रही थीं। उनकी इस प्रतिक्रिया से भाई हैरत में थे। लेकिन खुद अरुंधति के लिए यह कोई असहज या अस्वाभाविक बात नहीं थीं। बचपन से ही उन्होंने मां को अकेले जूझते देखा था। जब वह दो साल की थीं तभी उनके माता-पिता में तलाक हो गया था। मां ने ही उनके व्यक्तित्व को आकार दिया, लेकिन परवरिश का उनका अंदाज तकलीफदेह भी कम नहीं था। शायद इसीलिए 16 साल की उम्र में जब एकदम अनजान शहर दिल्ली में वह अकेली आईं तो फिर बरसों तक मां की सुध नहीं ली। लेकिन रिश्ते की सबसे खास बात अरुंधति के इस वाक्य में दर्ज होती है कि 'मैंने मां को इसलिए नहीं छोड़ा कि उनसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए छोड़ा ताकि उनको प्यार करती रह सकूं।' प्यार बनाए रखने की यह इच्छा ही शायद तमाम मानवीय संबंधों की जान है।

अरुंधति रॉय

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

राहुल-तेजस्वी का याराना

राहुल गांधी (कांग्रेस) और तेजस्वी यादव (आरजेडी) के बीच बहुत गहरा याराना है। दोनों नेताओं के बीच बिहार में मतदाता सूची को लेकर काफी चिंता है। इससे बिहार में नया राजनीतिक प्रयोग प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये दोनों पार्टियां परस्पर विरोधी रही हैं, क्योंकि राजनीतिक इतिहास यही बताता है। जब कांग्रेस का वर्चस्व टूटा था, तब गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उसी दौर में लालू यादव चमके। बहरहाल, दोनों दलों के इन नेताओं में एक समानता है। तेजस्वी और राहुल इतिहास के बोझ से मुक्त हैं, इसलिए वे एक साथ खड़े हो सकते हैं। तेजस्वी ने राहुल से हाथ मिलाने और बीजेपी का विरोध करने की ठान ली है। गठबंधन की चाबी राहुल के पास है। दोनों की विचारधारा एक है। सवाल यह है कि क्या यह साथ आरजेडी समर्थकों को रास आएगा?

-कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

अमेरिका को जवाब

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह भारत के खिलाफ अपनी मनमानी टैरिफ नीति लागू कर रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि आज अमेरिका का रवैया दोहरे मापदंडों पर टिका है। कभी यही अमेरिका मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा समर्थक था और दुनिया भर में उसके लिए दबाव बनाता था, लेकिन आज वही देश संरक्षणवाद की राह पर चल पड़ा है। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यह नया भारत है, जो आत्मविश्वास से भरा है। संदेश साफ है कि वह बराबरी के आधार पर संवाद चाहता है।

-विभूति बुपक्या, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

मस्क ने जिन्हें सांप बताया था, ट्रंप ने बनाया दूत- एक खबर

दिल बदल गए, रिश्ता बदल गया,
नजर भी बदल गई!

रेखा श्रीवास्तव

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 25 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

बलवान व्यक्ति की भी बुद्धिमानी इसी में है कि वह जानबूझ कर किसी को शत्रु न बनाए।
-शुक्र नीति

दृढ़ता है जरूरी

विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का बचाव करते हुए कहा कि भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा, अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत में अड़चन को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो न खरीदें। यूक्रेन संघर्ष पर दिल्ली का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा हम रूस-युक्रेन मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को याद दिलाया कि ओबामाकाल में वाशिंगटन ने चीन के साथ जी2 ढांचे का विचार पेश किया था। वह पहले भी स्पष्ट कह चुके हैं कि अमेरिका ही कह रहा है कि हम विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने हर संभव प्रयास करने चाहिए जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। चूंकि हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं इसलिए आपके (अमेरिका) तर्क से उलझन में हैं। भारत-रूस व्यापार पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। 2021 में 13 बिलियन डॉलर था, जो अब 2024-25 में बढ़ कर 68 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है जिसका बड़ा हिस्सा हाइड्रो कॉर्बन भी है। यह ट्रंप की आंख की किरकिरी बन रहा है। हालांकि भारत ने कूटनीतिक-आर्थिक बदलाव लाते हुए अपने सख्त तेवर दिखाए और अमेरिका के साथ ही यूरोपीय यूनियन की आलोचना करते हुए दोनों के रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर प्रक्रिया दी। भारत ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने को भी अविवेकपूर्ण ठहराया। विदेश मंत्री के तेवरों से स्पष्ट है कि सरकार अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इससे अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, घरेलू स्तर पर उसे अपनी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता प्रतीत हो सकता है। रूसी आयात पर लगाम लगाने की बजाय भारत इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब के साथ भी आयात विस्तार का विचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका को घुड़की देने मात्र के लिए अपने निर्णय पर अड़ा है, बल्कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के प्रति दृढ़ संकल्प भी है। रूस से तेल खरीद के चलते देश को 2025 में ही 3.8 अरब डॉलर की अतिरिक्त बचत हो चुकी है। ट्रंप के इस टैरिफ टैरर से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों से लेकर राजनेता व विशेषज्ञ भी खासे नाराज हैं। वे मान रहे हैं, यह अमेरिका के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। भारत सरकार ने विचारपूर्ण तरीके से ही अपना रुख सख्त रखा है। वह अब किसी दबाव के आगे नतमस्तक होते नहीं नजर आना चाहती।

कुत्तों पर मानवीय फैसला

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के फैसले में संशोधन करके सिर्फ पशु प्रेमियों को ही नहीं अपितु पूरे देश को राहत देने का काम किया है। अब कुत्ते बेरहमी से पकड़ कर आश्रय स्थलों में नहीं ठूंसे जाएंगे जैसा कि पूर्व के फैसले में आदेश दिया गया था। कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के बाद उनके पुराने इलाके में छोड़ने का निर्देश दिया है। फिलहाल यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में ही लागू होगा लेकिन कुत्तों को लेकर देश भर में जो प्रतिक्रिया देखने में आई उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत के आदेश से आवारा कुत्तों को लेकर सभी हाई कोर्टों में विचाराधीन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखने और किसी सूरत वहां से बाहर न आने देने के दो सदस्यीय बेंच के आदेश को बेहद कठोर बताया और याद दिलाया कि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के तहत कुत्तों को उनके इलाके में ही छोड़ना जरूरी है। अदालत ने कटखने कुत्तों पर सख्त रुख कायम रखते हुए उन्हें आश्रय स्थलों में ही रखने का निर्देश दिया ताकि बच्चे और बुजुर्ग बेखौफ सड़क और पार्कों में टहल सकें। रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को भी आश्रय स्थल से कतई नहीं छोड़ा जाए। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि एमसीडी अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और उनके लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने के 11 अगस्त के निर्देश का पालन करना जारी रखेंगे। इन्हें सड़कों से उठा कर आश्रय स्थलों में स्थाई रूप से स्थानांतरित करने के दो न्यायाधीशों की बेंच के 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा गया है। तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद खाना खिलाने के अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होगी जो उन्हें आश्रय स्थलों में मिलनी असंभव होती। कुत्ते मानव के दुश्मन नहीं मित्र होते हैं। उनके होने से डिप्रेशन नहीं होता। पहचान जाएं तो उनका लाड़ प्यार देखते ही बनता है।

बहस/ममता कुशवाहा

कम उम्र का मातृत्वः सेहत पर चोट

समाज में अक्सर विवाह और मातृत्व की उम्र पर चर्चा होती रही है, परंतु चिकित्सा विज्ञान और हालिया शोध बताते हैं कि जल्दी प्रसव, विशेषकर 21 वर्ष की आयु से पहले संतान जन्म, केवल सामाजिक या पारिवारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। यह समस्या उन युवतियों में अधिक देखी जाती है जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही मासिक धर्म का अनुभव किया हो।

ऐसे मामलों में यदि युवती 21 वर्ष से पहले संतान जन्म देती है तो उसके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जीवनभर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग द्वारा किए गए हालिया अध्ययन ने इस विषय को गंभीरता से उजागर किया है। शोध के अनुसार, जो महिलाएं 21 वर्ष से पहले संतान को जन्म देती हैं उनमें टाइप-2 डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे का खतरा कई गुना अधिक हो जाता है। यही नहीं, गंभीर मेटाबॉलिक विकारों का जोखिम चार गुना तक बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष केवल अनुमान या सामाजिक मान्यता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अध्ययन ने यह भी बताया कि प्रसव और प्रजनन की आयु, महिला की आनुवांशिक संरचना और उसके पूरे जीवन की स्वास्थ्य यात्रा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं में जब बहुत कम उम्र में गर्भधारण होता है, तो उनके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह विकसित नहीं होतीं। ऐसे में गर्भधारण और प्रसव शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इससे न केवल तत्कालीन जटिलताएं जैसे- खून की कमी, उच्च रक्तचाप, समय से पूर्व शिशु जन्म उत्पन्न होती हैं, बल्कि दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जल्दी मातृत्व और प्रसव केवल व्यक्तिगत निर्णय या पारिवारिक परंपरा का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे महिला स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। समय आ गया है कि समाज, परिवार और सरकार ऐसी नीतियां तैयार करें जहां हर युवती अपने जीवन का निर्णय स्वतंत्र रूप से कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और जागरूकता ही वे उपकरण हैं जिनसे जल्दी मातृत्व की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। यदि हम इस दिशा में ठोस कदम उठाएं, तो न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि पूरी पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित और उज्ज्वल बनाया जा सकेगा।

गुमनामी बाबा ही थे नेताजी

विचार

विनीत नारायण

बचपन से हमें पढ़ाया गया कि हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त, 1945 को ताइपे (ताइवान) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थ। पर उनकी मौत के विवाद को सुलझाने के लिए बने 'मुखर्जी आयोग' ने ताइपे (ताइवान) जाकर उनकी सरकार से संपर्क किया तो पता चला कि उस तारीख को ही नहीं, बल्कि उस पूरे महीने ही वहां कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। यानी नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। यह झूठी कहानी गढ़ी गई।

तो प्रश्न उठता है कि फिर नेताजी गए कहां? बाद के कई दशकों तक देश में चर्चा चलती रही कि नेताजी अचानक प्रगट होंगे। बाबा जयगुरुदेव ने देश भर की दीवारों पर बड़ा-बड़ा लिखवाया कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस जल्द ही प्रगट होंगे। पर वे नहीं हुए। मेरी मां बहुत राष्ट्रभक्त थीं और बड़े राजनैतिक परिवारों के बच्चे उनके साथ पढ़ते थे, सो उनकी शुरू से राजनीति में रुचि थी। उन्होंने मुझे 1967 में कहा था कि 'नेताजी अभी जिंदा हैं, और गुमनाम रूप से कहीं संत भेष में पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं।'

पर्दे वाले बाबा नाम से एक संत पचास के दशक में नेपाल के रास्ते भारत आए और गोपनीय रूप से बस्ती, लखनऊ, नैमिषारण्य, फैजाबाद व अयोध्या के मंदिरों या घरों में रहे। इस दौरान उनसे मिलने बहुत से लोग आते थे। पर सबको हिदायत थी कि उनके सामने कोई सुभाष नाम नहीं लेगा। इनमें 13 लोग जो वहीं के थे, जो उनके अंतरंग थे। बाकी अनेक लोग बंगाल से लगातार उनसे मिलने आते थे। उनमें दो लोग नेताजी की 'इंडियन नेशनल आर्मी' की 'इंटेलिजेंस विंग' के सदस्य थे। ये लोग हर 23 जनवरी को आते थे और बड़े हर्षोल्लास से पर्दे वाले बाबा का जन्म दिन मना कर लौट जाते थे।

गौरतलब है कि 23 जनवरी ही नेताजी का जन्म दिन होता है जिसे मोदी जी ने 'शौर्य दिवस' घोषित किया है। यही लोग हर वर्ष दोबारा दुर्गा पूजा के समय उनके पास आते थे। देश के कई बड़े राजनेता व सैन्य अधिकारी उनसे मिलने आते थे। पर सब उनसे पर्दे के सामने से ही बात करते थे। पत्रकार अनुज धर और पर्यावरणवादी चंद्रचूड़ घोष, इन दो लोगों ने अपनी जवानी के बीस वर्ष सिद्ध करने में लगा दिए कि 'पर्दे वाले बाबा', जिन्हें बाद में लोग 'गुमनामी बाबा' कहने लगे और जिन्हें उनके निकट के लोग 'भगवन जी' कहते थे, ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।

पिछले हफ्ते ये दोनों मेरे दिल्ली कार्यालय आए और विस्तार से मुझे इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने अपनी लिखी हिन्दी व अंग्रेजी की कई पुस्तकें भी दीं जिनमें वो सारे तथ्य, दस्तावेज और उन सामानों के चित्र थे जो 'गुमनामी बाबा' के कमरे से 16 सितम्बर, 1985 को उनकी मृत्यु के बाद, उनके दो दर्जन से ज्यादा बक्सों में से निकले थे। ये सब सामान देख कर कोलकाता से बुलाई गईं नेताजी की भतीजी ललिता बोस रोने लगीं और बेहोश हो गईं क्योंकि उसमें नेता जी और ललिता जी के माता-पिता के बीच हुए पत्राचार के हस्त लिखित प्रमाण भी थे। उनके परिवार के तमाम फोटो थे जिनमें नेताजी के माता-पिता का फ्रेम किया फोटो भी है। तब ललिता बोस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इन सामानों को सरकार की ट्रेजरी में जमा करवाने की मांग की। अदालत ने भी माना कि 'गुमनामी बाबा' के ये सब सामान राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। तब फैजाबाद के जिलाधिकारी ने उन 2760 सामानों की सूची बनवा कर ट्रेजरी में जमा करवा दिया।

बरसों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन सामानों को 'राम कथा संग्रहालय' अयोध्या में जन प्रदर्शन के लिए रखवा दिया। पता नहीं क्यों अब 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' उन्हें वहां से हटाने की प्रक्रिया चला रहा है? इन सामानों में गुमनामी बाबा (नेताजी) के तीन चश्मे, जापानी क्रॉकरी, बहुत महंगी जर्मन दूरबीन, ब्रिटिश टाइपराइटर, आईएनए की वर्दी जो नेता जी के साइज की है। लगभग एक हजार पुस्तकें, जो राजनीति, साहित्य, इतिहास, युद्ध नीति, होम्योपैथी, धार्मिक विषयों आदि पर हैं, मुख्यतः अंग्रेजी में हैं। तीन विदेशी सिगार पाइप, पांच बोरों में देश-विदेश के अखबारों में नेताजी के बारे में छपी खबरों की कतरन, आईएनए के अधिकारियों से उनका नियमित पत्राचार व आरएसएस प्रमुख श्री गुरु गोलवलकर का गुमनामी बाबा के नाम लिखा पत्र भी मिला। बड़े गत्ते पर गुमनामी बाबा के रूस से चीन, तिब्बत, नेपाल के रास्ते बस्ती (यूपी) आने के मार्ग का हाथ से बना नक्शा भी है।

अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष के शोध से पता चलता है कि नेताजी विमान दुर्घटना की झूठी कहानी के आवरण में रूस पहुंच गए जहां रूस की सरकार ने उन्हें गुलाग में एक बंगला, दो अंगरक्षक, एक कार और ड्राइवर की सुविधा के साथ महफूज रखा। तीन साल गुमनाम रूप से रूस में रहने के बाद वे चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते संत के वेश में भारत आए और 16 सितम्बर, 1985 को अपनी मृत्यु तक पर्दे के पीछे ही छिप कर रहे। पर्दे के भीतर जा कर उन्हें केवल फैजाबाद का डॉ. बनर्जी और मिश्रा जी का परिवार ही देख सकता था। सब उन्हें 'भगवन जी' कह कर ही बुलाते थे। जिस व्यक्ति की मृत्यु पर 13 लाख लोग जमा होने चाहिए थे, उनके अंतिम संस्कार में मात्र यही 13 लोग थे। उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे अयोध्या के 'गुप्तार घाट' पर किया गया जहां उनकी समाधि है। गुप्तार घाट पर ही श्रीराम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने जल समाधि ली थी। हजारों साल में उस स्थल पर आज तक केवल गुमनामी बाबा का ही अंतिम संस्कार हुआ है। प्रशासन और पुलिस दूर खड़े उनका अंतिम संस्कार देखते रहे।

इतना कुछ प्रमाण उपलब्ध है फिर भी आज तक केंद्र की कोई सरकार गुमनामी बाबा की सही पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार तक भी नहीं जबकि मोदी जी ने इंडिया गेट के सामने की छतरी में नेताजी की खड़ी प्रतिमा स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है। संघ के दिवंगत सर संघ चालक के एस सुदर्शन जी का एक सार्वजनिक वीडियो वक्तव्य है, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष बताते हैं कि पं. नेहरू से लेकर मोदी जी तक हर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, और नेताजी से 1945 तक जुड़े रहे उनके सहयोगी नेता उनसे मिलने जाते रहे। पर साधना में लीन गुमनामी बाबा नहीं चाहते थे कि कोई उनकी असलियत जाने। (*लेख में विचार निजी हैं*)

> इतना कुछ प्रमाण उपलब्ध है फिर भी आज तक केंद्र की कोई सरकार गुमनामी बाबा की सही पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने को तैयार नहीं हुई। मोदी सरकार तक भी नहीं जबकि मोदी जी ने इंडिया गेट के सामने की छतरी में नेताजी की खड़ी प्रतिमा स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है। संघ के दिवंगत सर संघ चालक के एस सुदर्शन जी का एक सार्वजनिक वीडियो वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे

(मीडिया इनपुट्स)

माता-पिता जो दहेज देते हैं, और अपनी बेटियों को दहेज के लोभियों के घर में ब्याह देते हैं, उन्हें अपने इस कृत्य में सुधार लाना चाहिए।

सबा नकवी, पत्रकार
@_sabanaqvi

नेताओं पर कम क्यों हो रहा भरोसा

मुद्दा | डॉ. घनश्याम बादल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह जनसुनवाई के दौरान राजेश भाई खीमजी भाई सकरिया नाम के व्यक्ति ने हमला किया, अपशब्दों का प्रयोग किया एवं पेशीय बल का प्रयोग किया वह चिंता का सबब है, और खतरनाक संकेत है कि हमारा लोकतंत्र सही दिशा में नहीं जा रहा। बेशक, ऐसी घटनाएं घोर निंदनीय हैं, लेकिन कई प्रश्न भी खड़े करती हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की घटना घटी हो।

राजनीति की खासियत रही है कि सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में हर दल व नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। सत्ता की लालसा के चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अक्सर राजनीतिक प्रदूषण का वीभत्स रूप बार-बार सामने आता रहा है। खूबियां व विपक्षी की कमियां गिनाना भी गलत नहीं है लेकिन इन सबके बीच जो गरिमा का पतन हो रहा है, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वह कहां तक जायज हैं? एक समय था जब शालीन तरीके से आलोचना करके, गद्दी हासिल की जाती थी पर अब तो बदमिजाजी, बदजुबानी व घटियापने की सारी हदें पार हो गई हैं। छुटभैये ही नहीं बड़े से बड़े नेताओं की जुबान पर भी गरिमाहीन शब्द चढ़ गए हैं। हर एक का मंतव्य एक ही कि जैसे भी हो बस चुनावी जंग जीत लो। अब जीते कोई भी पर भविष्य में लोकतंत्र के बहुत ही खतरनाक दौर का संकेत है यह। इससे पूर्व लोक सभा चुनावों में भी ऐसी ही बानगी देखने को मिली थी।

वैसे यह गंदगी अभी की बात नहीं है। यह तो काफी पहले ही जन्म ले चुकी थी। कुछ अति वाचाल नेता असंसदीय व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, और ऐसे शब्द बाण चलाते रहे हैं, जो कदाचित सभ्य समाज को अस्वीकार्य होंगे। ठीक है, आक्रामक होना आपका अधिकार हो सकता है पर सर्वाजनिक जीवन में मर्यादाएं तार-तार करने का किसी का भी हक नहीं है, यह अब हमारे नेताओं को सिखाने की जरूरत हो गई है। नेताओं की भाषा या उस पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के औचित्य पर टिप्पणी की बजाय आइए देखें कि कैसे भारतीय राजनीति में मर्यादा का स्थान जूतों, स्याही, कालिख, अंडे टमाटरों, थप्पड़ों, गालियों व असहिष्णु शब्दों ने ले लिया है।

बीफ पार्टी देने पर विधायक राशिद की पिटाई हुई, उनके मुंह पर कालिख पोती गई, एक पाकिस्तानी किताब का विमोचन करवाने के दोषी सुधीर कुलकर्णी का मुंह काला किया गया, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और यहां तक कि बहुत ही विनम्र डॉ. मनमोहन सिंह पर भी पर जूता उछला, चिदंबरम पर चप्पल फेंकी गई, प्रशांत भूषण पिटे, अन्ना पर भी वार हुआ, दिग्विजय को गालियां मिलीं, केजरीवाल को चप्पल, थप्पड़ व स्याही मिले, गोपाल यादव का मुंह काला किया गया और भी ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं।

आखिर, हम कर क्या रहे हैं? किस युग में जी रहे हैं? और किस अंधयुग की तरफ जा रहे हैं? किसी भी तर्क का सहारा लेकर जूतों, थप्पड़ों, गालियों को लोकतंत्र में सही नहीं ठहराया जा सकता परंतु सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसी स्थिति आती ही क्यों हैं, गहरी छानबीन की जरूरत है।

यदि समस्या की जड़ में जाने से बच कर विपक्षी की जलालत पर हम हंसते रहे तो फिर लोकतंत्र की तस्वीर भयावह होने जा रही है। लोकतंत्र में सबको अपने-अपने तरीके से रहने, बोलने, सोचने व खाने-पीने की छूट तो है पर किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का हक लोकतंत्र नहीं देता, यह बात जहां नेताओं को आम जन को समझानी चाहिए वहीं वे खुद ही ऐसा करके माहौल खराब करते रहे हैं। क्या अब नहीं मान लेना चाहिए कि सत्ता की भूख कुछ भी नैतिक-अनैतिक नहीं देख पाती। इसलिए भावनाएं भड़का कर सत्ता सुख लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और खेद का विषय है कि एक भी दल इससे बच नहीं पा रहा है। जनतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है।

देश का आम जन और वोटर अभी तक भी नहीं जान पाया है कि चुनावों के हसीन सपने अलग बात हैं पर सत्ता में आने पर सेवा, जनकल्याण व समस्या निवारण कहने की बातें रह गई हैं। सत्ता के इर्द गिर्द शायद कहीं कुछ ऐसा है जो कुछ सार्थक करने नहीं देता। वह क्या है? जब सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी ओढ़े तटस्थ होने का ढोंग बुद्धिजीवी करते हैं तो लगता है जैसे वे भी इस पाप में शामिल हैं। बुद्धिजीवी लोकतंत्र को एक अंधेरे गड्ढे में जाते हुए चुपचाप देखते हैं, तो फिर भविष्य कैसा होगा, सोचा जा सकता है। पावर, पॉलिटिक्स व पैसों का खेल अब बेलगाम हो गया है। सरकारें भले ही बदलें, चेहरे भले ही बदलें पर प्रवृत्ति नहीं बदल रही। कालिखों, जूतों, गालियों का होना लोकतंत्र में सही नहीं है पर ऐसी स्थिति आती ही क्यों है, इस पर भी छानबीन की जरूरत है। भविष्य में लोकतंत्र के लिए खतरनाक दौर का संकेत है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

चिनगारी | श्रीराम शर्मा आचार्य

दुर्दांत रावण का अंत होना था, तो दो तापसी युवक ही उस विशाल परिकर को धराशायी करने में समर्थ हो गए। दुर्धर्ष हिरण्यकश्यपु हारा और प्रह्लाद का सिक्का जम गया। समय आने पर, किसी दिग्भ्रांत करने वाले झाड़-झंखारों के जंगल को दावानल बन कर नष्ट करने में एक चिनगारी भी पर्याप्त हो सकती है। प्रलय की चुनौती जैसी ताड़का को राम ने और पूतना को कृष्ण ने बचपन में ही तो धराशायी कर दिया था। महाकाल का संकल्प यदि युग परिवर्तन का तारतम्य इन्हीं दिनों बिठा ले, तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। निकट भविष्य की कुछ सुनिश्चित संभावनाएं ऐसी हैं, जिनमें हाथ डालने वाले सफल होकर ही रहेंगे। अर्जुन की तरह नियति द्वारा पहले से ही मारे गए विपक्षियों का हनन करके अनायास ही श्रेय और प्रेम का दुहरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी माहौल में उन्हें प्रतिभा परिवर्धन का वह लाभ भी मिल जाएगा, जिसके आधार पर मूर्द्धन्य युग शिल्पियों में उनकी गणना हो सके। अगले दिनों प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों में से अधिकांश अपनी मौत मरेंगी, जिस प्रकार शीत ऋतु में मक्खी-मच्छरों का प्रकृति परंपरा के अनुसार अंत हो जाता है। अंधविश्वास, मूढ़मान्यताएं, रूढ़ियां अंध परंपराएं, दूरदर्शी विवेकशीलता का उषाकाल प्रकट होते ही, उल्लू-चमगादड़ों की तरह अपने कोटरों में जा घुसेंगी। संग्रही और अपव्ययी जिस प्रकार आज अपना दर्प दिखाते हैं, उसके लिए तब कोई आधार शेष न रहेगा। संग्रही, आलसी और लालची तब भाग्यवान होने की दुहाई न दे सकेंगे। एक और भी बड़ी बात होगी कि चिरकाल से उपेक्षित नारी वर्ग न केवल अपनी गरिमा को उपलब्ध करेगा वरन उसे नर का मार्गदर्शन-नेतृत्व करने का गौरव भी मिलेगा। पिसे हुए, पिछड़े हुए ग्राम उभरेंगे और उन सभी सुविधाओं से संपन्न होंगे, जिनके लिए उस क्षेत्र के निवासियों को आज शहरों की ओर भागना पड़ता है। समता और एकता के मार्ग में अड़े हुए अवरोध एक-एक करके स्वयं हटेंगे और औचित्य के विकसित होने का मार्ग साफ करते जाएंगे। सम्मान वैभव को नहीं, उस वर्चस्व को मिलेगा जो आदर्शों के लिए उत्सर्ग करने का साहस संजोता है। पाखंड का कुहासा पिछले दिनों कितना ही सघन क्यों न रहा हो, अगले दिनों उसके लंबे समय तक पैर जमाए रहने की कोई संभावना नहीं है।

रीडर्स मेल

ग्रेटर नोएडा की घटना निंदनीय

देश के विकसित इलाके ग्रेटर नोएडा से निक्की के साथ जैसी दिल दहला देने वाली घटना घटी है, घोर निंदनीय है। मामला दहेज का हो या कुछ और, यह अलग विषय है। मगर 21वीं सदी में दहेज जैसी कुप्रथा को आधुनिकता का पर्याय मान दूल्हा एवं दुल्हन पक्ष द्वारा प्रोत्साहित करना कहां तक उचित है? खैर, इन दिनों स्त्री-पुरुष संबंधों के विभिन्न रूपों को जिस वीभत्स तरीके से खत्म होते देखा जा रहा है, यह कहीं से आधुनिकता और प्रगतिशीलता नहीं है। प्रेमिका-प्रेमी, विवाहेतर संबंध, सह-संबंधों को आधुनिकता की दुहाई दी जाती है। मगर इसके खत्म होने के तौर-तरीकों में जुड़े लोग आधुनिक व प्रगतिशील होने का परिचय नहीं दे पाते हैं। दरअसल, जब तक हमारा मन-मस्तिष्क का आधुनिक नहीं होगा, आधुनिकता को हम स्व आनंद के तराजू पर तोलते रहेंगे। ऐसे भोगवादी संबंधों का अंजाम बुरा होगा। सबसे अहम है सभी तरह के संबंधों दायित्व बोध का अभाव।

मुकेश कुमार मनन, ई मेल से

नेताजी की अस्थियां लाई जाएं

सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व त्याग, साहस और संकल्प का पर्याय है किन्तु यह राष्ट्रीय विडंबना है कि जिन नेताजी ने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया, उनकी अस्थियां अब तक जापान के टोक्यो स्थित रेन्कोजी मंदिर में रखी हुई हैं। बोस की सुपुत्री अनिता बोस कई बार भारत सरकार से अपने पिता की अस्थि-कलश को भारत लाने तथा उसका डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर चुकी हैं ताकि यह साबित हो सके कि वो नेताजी की ही अस्थियां हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग नहीं सुनी गई। नेताजी का जीवन स्वयं रहस्य और रोमांच से भरा रहा। 1945 की विमान दुर्घटना में उनके निधन की खबर आई, किंतु इस पर संदेह और विवाद आज तक बने हुए हैं। अब जब भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है कि आखिर, नेताजी की अस्थियां उनकी मातृभूमि पर क्यों नहीं लाई जा सकीं? नेताजी की अस्थियों को भारत लाना, वास्तव में अधूरे इतिहास को पूरा करना होगा। सरकार और समाज, दोनों को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए ताकि यह अधूरा अध्याय पूर्ण हो सके।

आदित्य राज सोनी 'सार्थक', धार, मप्र

बिहार में पाला बदल जल्द?

बिहार में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा से एनडीए के पक्ष में मतदाताओं को लुभा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा से जनता में इंडिया ब्लॉक के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 13000 करोड़ रुपये की सौगात बिहार को समर्पित की है जबकि तेजस्वी यादव ने कूटनीतिक वक्तव्य देते हुए दावा किया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार में इस समय मतदाता गहन परीक्षण, बांग्लादेशी घुसपैठिया, अन्य राज्यों में पलायन, कानून व्यवस्था, एवं बाढ़ग्रस्त जिलों के मुद्दे पूरी तरह चुनावी माहौल को गरमाए हुए हैं। आज की प्रधानमंत्री की रैली में राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायकों की उपस्थिति इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में पाला बदल संस्कृति का हिस्सा बनने वाले हैं।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 11
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

भारत-अमेरिका के 'सम्बन्ध'

आजादी के बाद से ही अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्ध उतार-चढ़ाव लेते रहे हैं परन्तु वर्तमान समय में ये सम्बन्ध दरारों में फंसते नजर आ रहे हैं। इसकी मूल वजह बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापारिक व विदेश नीति ही कही जा सकती है जिसके तहत वह लगातार भारत को चेतावनी मुद्रा में रख रहे हैं। मगर ऐसा करते हुए वह शायद भूल रहे हैं कि भारत ने पिछले 76 सालों में जो भी प्रगति की है वह अपनी निर्दिष्ट व्यापार नीति व स्पष्ट विदेश नीति के अन्तर्गत ही की है। भारत की विदेश नीति आपसी सहयोग व शान्ति पर टिकी रही है और व्यापार नीति राष्ट्रीय हितों के समरूप रही है। भारत की आजादी के बाद इसके प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्येय बनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी परक उद्योगों की नींव डाली। मगर ऐसा करते हुए उन्होंने पहले अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नजरंदाज नहीं किया। उन्होंने भारत में स्टील कारखाने शुरू करने से पहले अमेरिका से इसमें सहयोग करने की अपील की परन्तु अमेरिका ने उनके प्रस्ताव को यह कह कर टाल दिया कि स्टील उद्योग पूंजी मूलक उद्योग है और भारत बहुत गरीब देश है। अत: वह बजाये अपने कारखाने लगाने के स्टील अमेरिका से आयात करे। इसके बाद ही नेहरू जी ने सोवियत संघ का रुख किया और भारत के औद्योगीकरण में उसका सहयोग पाया जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने उस दौर में पाकिस्तान का रुख किया और उसे भारी आर्थिक व वित्तीय मदद दी। 1953 में अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी मदद देने का ऐलान किया।

> भारत अपनी शर्तों पर ही तरक्की करते हुए आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो आज अमेरिका भारत से लगभग डेढ़ सौ अरब डालर का आयात करता है और करीब एक सौ अरब डालर का निर्यात करता है। हमने यह तरक्की पं. नेहरू के कार्यकाल से लेकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तक की है परन्तु आज डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच बहुत करीबी सम्बन्ध हैं जिनके तहत भारत रूस से कच्चा पैट्रोलियम तेल सस्ती दरों पर आयात करता है और फिर उसे अन्य देशों को निर्यात कर मुनाफा कमाता है। इस बारे में विदेश मन्त्री एस. जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत से तेल खरीदने के लिए कोई देश बाध्य नहीं है।

यह भी हकीकत है कि 1947 से पहले अमेरिका भारत के दो टुकड़े करने के पक्ष में नहीं था और चाहता था कि चीन में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को एकजुट व मजबूत रखा जाये परन्तु ब्रिटिश सरकार के रवैये के चलते भारत को दो टुकड़ों में काट कर पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। अंग्रेजों का तर्क था कि रूस-चीन के बीच पाकिस्तान को एक ऐसा देश बनाया जा सकता है जो मौका पड़ने पर पश्चिमी देशों व अमेरिका के लिए सहायक देश सिद्ध हो। इसके जरिये पश्चिमी देश मध्य एशिया के मुस्लिम देशों पर भी अपनी पकड़ बनाये रख सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों का दिल्ली स्थित वायसराय भारत से ही मध्य एशियाई देशों पर अपनी पकड़ बनाये रखता था। यही वजह थी कि इनमें से अधिसंख्य देशों में भारत की मुद्रा रुपये का प्रचलन था जो कि 1959 तक जारी रहा। इस नीति के चलते अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम इस हद तक जारी रहा कि इसने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत को मिलने वाली खाद्यान्न मदद को भी रोक दिया।

पीएल-480 के तहत मिलने वाली भारत को अन्न मदद रोक कर अमेरिका पाकिस्तान की सीधी मदद इसलिए कर रहा था जिससे भारत की विशाल जनसंख्या उसकी ताकत को पहचान सके। इसके बाद ही भारत में हरित क्रान्ति हुई और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना लेकिन अमेरिका ने भारत की स्वावलम्बी योजना का हमेशा से ही विरोध किया और 1974 में भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण पोखरन में किया तो अमेरिका ने अपनी विदेशी व्यापार धारा-300 के तहत भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये और नवीन टैक्नोलॉजी से इसे महरूम कर दिया। इसके बावजूद भारत लगातार तरक्की करता रहा और हालत यहां तक पहुंची कि जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो अमेरिका ने धारा-300 के विभिन्न उपबन्धों को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1998 में जब भारत ने पोखरन में दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो फिर से नये आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। ये प्रतिबन्ध 2008 में तब जाकर उठे जब भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया। अत: बहुत स्पष्ट है कि भारत अपनी शर्तों पर ही तरक्की करते हुए आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो आज अमेरिका भारत से लगभग डेढ़ सौ अरब डालर का आयात करता है और करीब एक सौ अरब डालर का निर्यात करता है। हमने यह तरक्की पं. नेहरू के कार्यकाल से लेकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तक की है परन्तु आज डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच बहुत करीबी सम्बन्ध हैं जिनके तहत भारत रूस से कच्चा पैट्रोलियम तेल सस्ती दरों पर आयात करता है और फिर उसे अन्य देशों को निर्यात कर मुनाफा कमाता है। इस बारे में विदेश मन्त्री एस. जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत से तेल खरीदने के लिए कोई देश बाध्य नहीं है।

विश्व में तेल व गैस के भावों को स्थिर रखने की गरज से ही भारत ऐसा कर रहा है। यह उसकी व्यापार नीति है। मगर ट्रम्प भारत पर दबाव बनाने की गरज से उसके साथ होने वाली व्यापार वार्ता को बीच में ही लटकाये रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत से आयातित माल पर सीमा शुल्क 50 प्रतिशत कर दिया है। यह इकतरफा दंडात्मक कार्रवाई भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने 25 अगस्त से अमेरिका को भेजे जाने वाले हवाई पार्सलों पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि चिट्ठी- पत्री जाती रहेंगी और 100 डालर तक की कीमत वाले उपहार पार्सलों आदि पर भी रोक नहीं रहेगी। भारत यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई तीसरा देश उसे इस वजह से दंडित करे कि उसने किसी तीसरे देश के साथ व्यापार किया है। भारत कोई सामान्य देश नहीं है। यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बसती है और इसका लोकतन्त्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है जो कि पूरे विश्व में एक उदार ताकत माना जाता है। अमेरिका को भारत की इस ताकत को पहचानना होगा। ट्रम्प इकतरफा गाड़ी किसी कीमत पर नहीं चला सकते हैं।

यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

यह सवाल प्रख्यात उर्दू शायर साहिर लुधियानवी ने लगभग आधी सदी पहले अपनी एक नज़्म के माध्यम से उठाया था। यही सवाल आज पांच दशक बाद भी पूरी तरह प्रासंगिक है। इस बार विभाजन-विभीषिका को लेकर देशभर में पुरानी बातें फिर से याद की गई। बचे-खुचे चंद लोग शेष बचे हैं जिन्हें वे किस्से- कहानियां अब भी याद हैं, मगर अब सारी यादें, सभी किस्से-कहानियां, 'इवेंट मैनेजमेंट' के खाते में सरकती जा रही हैं। अब 'विभाजन-विभीषिका' को 'फेस्टिवल' की शक्ल में मनाया गया। सम्मान समारोह, प्रदर्शनियां, किस्से-कहानियां, सब का सचित्र बयान जारी रहा। इधर, कुछ सनकी, समर्पित लोग अब भी विभाजन-पीड़ितों का दु:ख-दर्द, 'वीडियोज़' और यू-ट्यूब आदि के माध्यम से बांटने की मशक्कत में लगे हैं।

ऐसे ही लोगों में दो की चर्चा प्रासंगिक होगी। इन्हें इस बात का भी कोई मलाल नहीं कि उनके प्रयासों से उनका अपना खर्च भी नहीं निकल पाता, मगर जब कोई पत्रकार खुले मन से उन्हें चर्चा के केंद्र में ले आता है तो उन्हें थोड़ा सुखद एहसास होने लगता है कि 'उनके' काम को किसी ने सराहा तो सही। वे जो भी करते हैं किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं। उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें इस काम के लिए कोई राजकीय सम्मान भी नहीं मिल पाएगा। मगर वे हारते नहीं हैं। इनमें से दो की चर्चा इस मामले में प्रासंगिक है हालांकि जैसे प्रयास वे कर रहे हैं, ऐसे सरहद के उस पार भी कुछ समर्पित यू-ट्यूबर्स भी कर रहे हैं। फिलहाल इन पर ही एक सीमित सी चर्चा।

इनमें से एक है सौदागर सिंह चुन्नी कलां और दूसरे हैं कुरुक्षेत्र के केशु मुल्तानी। सौदागर सिंह ने 16 वर्ष तक मोहाली के केंद्रीय सरकारी संस्थान सेमीकंडक्टर में तकनीशियन की नौकरी भी की थी। जब इस इकाई में आग लगी तो नौकरी खतरे में आ गई। तब उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ली और 'मनरेगा' के तहत काम करने लगे। अब वह पूरा वक्त अपने इंटरनेट-सैट पर ही लगे रहते हैं। उन्हें उस दिन चैन की नींद आती है जिस दिन वे बिछुड़े लोगों या परिवारों को आपस में मिला देते हैं। उनकी अपनी आंखें अक्सर नम रहती हैं।

दूसरे शख्स हैं केशु-मुल्तानी। अब तक सैकड़ों परिवारों को मिला चुके हैं। 'वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिलसिला तो 2006 में शुरू हो गया था और सबसे पहले रिकार्ड किए गए थे हांसी के विधायक विनोद भयाना के पिता जी महेश भयाना जी, उसके बाद मेरे मामा भी जिनका सरहद पार दोस्त मिल गया था और उसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रथम रंजन राजबाड़ी 2007 में रिकार्ड किया गया, उसके बाद यह सिलसिला कुछ वर्षों तक कछुए की चाल चलता रहा और इसमें गति पकड़ी 2016 के आखिरी महीने अब मेरे द्वारा वीडियो रिकॉर्ड की संख्या तो हजार से भी ज्यादा है।' और 47 के दंगों में जो परिवार या कोई समुदाय बिछुड़ गए थे तो तकरीबन 300 से

में जिसका सफर अब तक जारी है।'

इस सफर में केशव को सिर्फ मुल्तान के लोग ही नहीं मिले, पेशावरी मिले, लाहौरी मिले, सिख मिले और राजपूत मिले और तो और मुझे 'डकोत' भी मिले, जिन्हें शनिदेव महाराज जी के नाम से जाना जाता है। जो घर-घर जाकर तेल मांगते थे, यहां भी और वहां भी। ज्यादा केशु मिलवा चुका है। इसी तरह कुछ और 'यू-ट्यूबर्स' भी इसी तरह का काम पाकिस्तान में कर रहे हैं जिनमें मोहम्मद आलमगीर नाम का शख्स और खय्याम चौहान प्रमुख हैं।

कुरुक्षेत्र के इस युवा छायाकार एवं फोटो जर्नलिस्ट ने एक ऐसा अभियान छेड़ रखा है जिसका पूरी गंभीरता से नोटिस लिया जाना चाहिए। केशव नामक यह युवा फोटो पत्रकार अब तक लगभग 160 ऐसे परिवारों को अपने यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से परस्पर मिलवा चुका है जो भारत-पाक विभाजन के समय बिछुड़ गए थे। उसकी ज़्यादातर कवरेज मुल्तान, बहावलपुर, अहमदपुर और राजस्थान की सीमा के दोनों ओर बसे, बिछुड़े परिवारों पर केंद्रित होती है। उसे वहां यानि मुल्तान, बहावलपुर में बसे लोग भी केशु के नाम से ही पुकारते हैं और इधर कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत व आसपास बसे मुल्तानी परिवार भी इसी नाम से जानते हैं। किसी बुज़ुर्ग को जब कभी अपने किसी बिछड़े यार की यादें जीवन के अंतिम पहर में सताती हैं तो वह अपने बच्चों-पोतों के माध्यम से 'केशु' से संपर्क करता है। केशु अपने चैनल व सम्पर्क सूत्रों के माध्यम से पुराने बिछुड़ों के बीच यादों का सैलाब ला देता है। केशु यह सारे काम मुफ्त में करता है। मैं पूछता हूं कि 'क्या मिलता है भाई, इस मुफ्त की मशक्कत से? तो उसका जवाब होता है, 'कभी यादों के उस सैलाब से हाथ-मुंह धोकर देखें, नई ऊर्जा मिलेगी।'

यदि रिश्तों की गर्माहट या ठंडी छांव का एहसास महसूस करना हो तो कभी केशु से बात कीजिए, चला आएगा यादों का 'बॉयस्कोप' उठाए और आपको मुफ्त में भीतर तक सुकून पहुंचाकर चुपचाप लौट जाएगा। ऐसे उत्साही युवा को भी नमन।

नि:संदेह गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

बचपन से हमें पढ़ाया गया की हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को ताइपे (ताइवान) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पर उनकी मौत के विवाद को सुलझाने के लिए बने 'मुखर्जी आयोग' ने ताइपे (ताइवान) जाकर उनकी सरकार से संपर्क किया तो पता चला कि उस तारीख को ही नहीं बल्कि उस पूरे महीने ही वहां कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। यानी नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। ये झूठी कहानी गढ़ी गई। तो प्रश्न उठता है कि फिर नेताजी गए कहां? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। बाद के कई दशकों तक देश में चर्चा चलती रही कि नेताजी अचानक प्रकट होंगे। बाबा जयगुरुदेव ने देश भर की दीवारों पर बड़ा-बड़ा लिखवाया कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस जल्दी ही देश के सामने प्रकट होंगे। पर वे नहीं हुए। मेरी मां बहुत राष्ट्रभक्त थीं और बड़े राजनैतिक परिवारों के बच्चे उनके साथ पढ़ते थे, सो उनकी शुरू से राजनीति में रुचि थी। उन्होंने मुझे 1967 में कहा था कि 'नेता जी अभी जिंदा हैं और गुमनाम रूप से कहीं संत भेष में पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं।'

पर्दे वाले बाबा नाम से एक संत पचास के दशक में नेपाल के रास्ते भारत आए और गोपनीय रूप से बस्ती, लखनऊ, नैमिषारण्य, फैजाबाद व अयोध्या के मंदिरों या घरों में रहे। इस दौरान उनसे मिलने बहुत से लोग आते थे। पर सबको हिदायत थी कि उनके सामने कोई सुभाष नाम नहीं लेगा। इनमें 13 लोग जो वहीं के थे, जो उनके अंतरंग थे। उनमें से दो परिवारों ने तो उन्हें पर्दे के पीछे जाकर भी देखा था। बाक़ी अनेक लोग बंगाल से लगातार उनसे मिलने आते थे। उनमें दो लोग नेता जी की 'इंडियन नेशनल आर्मी' की 'इंटेलिजेंस विंग' के सदस्य थे। ये लोग हर 23 जनवरी को आते थे और बड़े हर्षोल्लास से पर्दे वाले बाबा का जन्मदिन मना कर लौट जाते थे। गौरतलब है कि 23 जनवरी ही नेताजी का जन्मदिन होता है। जिसे मोदी जी ने 'शौर्य दिवस' घोषित किया है। यही लोग हर वर्ष दोबारा दुर्गा पूजा के समय उनके पास आते थे। इसके अलावा बाबा की जरूरत के हिसाब से बीच-बीच में भी लोग आते जाते रहते थे। देश के कई बड़े नामी राजनेता व बड़े सैन्य अधिकारी भी लगातार उनसे मिलने आते थे। पर सब उनसे पर्दे के सामने से ही बात करते और सलाह लेते थे।

पत्रकार अनुज धर और पर्यावरणवादी चंद्रचूड़ घोष, इन दो लोगों ने अपनी जवानी के बीस वर्ष इसे सिद्ध करने में लगा दिए कि 'पर्दे वाले बाबा' जिन्हें बाद में लोग 'गुमनामी बाबा' कहने लगे, जिन्हें उनके निकट के लोग 'भगवन जी' कहते थे, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। पिछले हफ्ते ये दोनों मेरे दिल्ली कार्यालय आए और विस्तार से मुझे इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने अपनी लिखी हिंदी व अंग्रेज़ी की कई पुस्तकें भी दीं। जिनमें वो सारे तथ्य, दस्तावेज़ और उन सामानों के चित्र थे जो 'गुमनामी बाबा' के कमरे से 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु के बाद, उनके दो दर्जन से ज़्यादा बक्सों में से निकले थे। ये सब सामान देखकर कोलकाता से बुलाई गयीं नेताजी की भतीजी ललिता बोस रोने लगी और बेहोश हो गई। क्योंकि उसमें नेता जी और ललिता जी के माता-पिता के बीच हुए पत्राचार के हस्त लिखित प्रमाण भी थे। उनके परिवार के तमाम फोटो थे। जिनमें नेताजी के माता पिता का फ्रेम किया फोटो भी है। तब ललिता बोस ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर के इन सामानों को सरकार की ट्रेज़री में जमा करवाने की मांग की।

अदालत ने भी ये माना कि 'गुमनामी बाबा' के ये सब सामान राष्ट्रीय महत्व के हैं। तब फैजाबाद के जिलाधिकारी ने उन 2760 सामानों की सूची बनवाकर ट्रेज़री में जमा करवा दिया। बरसों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इन के अख़बारों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में छपी ख़बरों की कतरने, आईएनए के वरिष्ठ अधिकारियों से उनका नियमित पत्राचार व आरएसएस प्रमुख श्री गुरु गोलवलकर का गुमनामी बाबा के नाम लिखा एक पत्र भी मिला है। इसके अलावा एक बड़े गत्ते पर

> पत्रकार अनुज धर और पर्यावरणवादी चंद्रचूड़ घोष, इन दो लोगों ने अपनी जवानी के बीस वर्ष इसे सिद्ध करने में लगा दिए कि 'पर्दे वाले बाबा'' जिन्हें बाद में लोग 'गुमनामी बाबा'' कहने लगे, जिन्हें उनके निकट के लोग 'भगवन जी'' कहते थे, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।

सामानों को 'राम कथा संग्रहालय' अयोध्या में जन प्रदर्शन के लिए रखवा दिया। पता नहीं क्यों अब 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' उन्हें वहां से हटाने की प्रक्रिया चला रहा है?

इन सामानों में गुमनामी बाबा (नेताजी) के तीन चश्मे, जापानी क्रॉकरी, बहुत महंगी जर्मन दूरबीन, ब्रिटिश टाइपराइटर, आईएनए की वर्दी जो नेता जी के साइज़ की है। लगभग एक हज़ार पुस्तकें जो राजनीति, साहित्य, इतिहास, युद्ध नीति, होम्योपैथी, धार्मिक विषयों आदि पर हैं व मुख्यत: अंग्रेज़ी में हैं। तीन विदेशी सिगार पाइप, पांच बोरों में देश-विदेश गुमनामी बाबा के रूस से चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते बस्ती (उ.प्र.) आने के मार्ग का हाथ से बना विस्तृत नक्शा भी है।

अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष के शोध से पता चलता है कि नेता जी विमान दुर्घटना की झूठी कहानी के आवरण में रूस पहुंच गए। जहां रूस की सरकार ने उन्हें गुलाग में एक बंगला, दो अंगरक्षक, एक कार और ड्राइवर की सुविधा के साथ महफ़ूज़ रखा। तीन साल गुमनाम रूप से रूस में रहने के बाद वे चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते एक संत के वेष में भारत आए और 16 सितंबर 1985 को अपनी मृत्यु तक पर्दे के पीछे ही छिप कर रहे। पर्दे के भीतर जा कर उन्हें केवल फैजाबाद का डॉ. बनर्जी व मिश्रा जी का परिवार ही देख सकता था। उनकी दबंग आवाज़, बंगाली उच्चारण में हिंदी और फर्राटेदार अंग्रेजी सुन कर पर्दे के सामने बैठा हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। फिर भी सबको यह हिदायत थी कि उनके सामने 'सुभाष' नाम नहीं लिया जाएगा। सब उन्हें 'भगवन जी' कह कर ही बुलाते थे। जिस व्यक्ति की मृत्यु पर 13 लाख लोग जमा होने चाहिए थे, उनके अंतिम संस्कार में मात्र यही 13 लोग थे। उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे अयोध्या के 'गुप्तार घाट' पर किया गया, जहां उनकी समाधि है। गुप्तार घाट वही स्थल है, जहां भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने जल समाधि ली थी। हज़ारों साल में उस पवित्र स्थल पर आज तक केवल गुमनामी बाबा का ही अंतिम संस्कार हुआ है। सारा ज़िला प्रशासन और पुलिस दूर खड़े उनका अंतिम संस्कार देखते रहे।

इतना कुछ प्रमाण उपलब्ध है फिर भी आज तक केंद्र की कोई सरकार गुमनामी बाबा की सही पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार तक भी नहीं। जबकि मोदी जी ने इंडिया गेट के सामने की छतरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खड़ी प्रतिमा स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है। आरएसएस के दिवंगत सर संघ चालक के.एस. सुदर्शन जी का एक सार्वजनिक वीडियो वक्तव्य है, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने साफ़ कहा है कि गुमनामी बाबा ही नेता जी सुभाष चंद्र बोस थे। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष बताते हैं कि पंडित नेहरू से लेकर मोदी जी तक हर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है और नेताजी से 1945 तक जुड़े रहे उनके सहयोगी नेता उनसे मिलने जाते रहे। पर साधना में लीन गुमनामी बाबा ये नहीं चाहते थे कि कोई उनकी असलियत जाने।

25 अगस्त भारत के इतिहास का काला दिन, जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर

भारत के हालिया इतिहास में 25 अगस्त का दिन एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। 2003 में मुंबई और 2007 में हैदराबाद दो सीरियल ब्लास्ट से दहल गए थे। इन घटनाओं ने न सिर्फ कई मासूम जिंदगियां छीन लीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। आज इन हमलों को क्रमश: 22 और 18 साल हो चुके हैं। 25 अगस्त 2003, यह वह तारीख है जब बम धमाके से पूरी मुंबई दहल गई। मुंबई में दोहरे कार बम विस्फोट हुए, जिसमें 54 लोग मारे गए और 244 लोग घायल हो गए थे। एक धमाका गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा जावेरी बाजार में हुआ था। अहम यह है कि दोनों हमलों में काम करने का तरीका एक जैसा था। टैक्सी में बम लगाए गए थे, जो एक निश्चित समय पर फटे।

यह भी पहला मामला था जब किसी परिवार में पति, पत्नी और बेटी- तीनों ही एक साजिश में शामिल थे। तहकीकात हुई तो पता चला कि इन तीनों का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर से था। उस मामले में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने एक बयान में कहा था कि यह बात साबित हुई है कि दोषी लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हुए थे। यह भी साबित हुआ कि इन लोगों ने दुबई में बैठकर धमाकों की साजिश रची थी।

मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि 25 अगस्त 2003 को मुंबई को दहलाने के लिए हनीफ ने अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों के संग टैक्सी किराए पर ली, जिससे वे गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचे। साथ में एक बैग था। परिवार टैक्सी ड्राइवर से यह कह कर बैग छोड़ गया कि वे सभी खाना खाने के बाद लौटेंगे, लेकिन कुछ देर बाद धमाके हुए तो पूरी मुंबई दहल गई।

धमाकों के बाद की भयावह स्थिति थी। दोनों ऐसी जगह थीं, जहां हर समय अच्छी भीड़भाड़ रहती है। धमाकों के बाद मलबा चारों ओर बिखरा था। करीब 200 की दूरी पर ज्वेलरी शोरूम के शीशे तक चकनाचूर हो गए थे। धमाके में एक टैक्सी वाले की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा बच गया था। लगभग 6 साल बाद कोर्ट ने हनीफ सईद, उसकी पत्नी फहमीदा सईद और अशरफ अंसारी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि, 2007 तक भारत के यह घाव ठीक से भरे नहीं थे कि 25 अगस्त को ही निजामों के शहर हैदराबाद को धमाकों से दहला दिया। 25 अगस्त, 2007 को हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में लगभग एक साथ हुए विस्फोटों में 42 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा घायल हुए थे।

पहला बम हैदराबाद के लुंबिनी पार्क में खचाखच भरे लेजर शो ऑडिटोरियम में फटा, जिसके कुछ ही मिनट बाद शहर के दूसरे हिस्से में गोकुल चाट रेस्टोरेंट में विस्फोट हुआ। बम फटते ही चारों तरफ लाशें बिछ गई थीं। दिलसुखनगर में भी एक बम प्लांट था, जिसे वक्त रहते निष्क्रिय कर दिया गया।मार्च 2009 में पहली गिरफ्तारी हुई, ठीक उसी साल जब अगस्त 2009 में मुंबई हमलों (2003) के दोषियों को सजा सुनाई गई थी।

-आईएएनएस

नील आर्मस्ट्रांग, दुनिया के पहले शख्स जिन्होंने चांद पर रखा कदम

25 अगस्त 2012 को दुनिया ने एक ऐसे नायक को खो दिया, जिसने चांद पर पहला कदम रखकर मानवता के सपनों को नई उड़ान दी। नील आर्मस्ट्रांग, ये वो नाम है जो साहस, विज्ञान और असंभव को संभव बनाने की जीवटता का प्रतीक है। अपोलो 11 मिशन के कमांडर के रूप में उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यह क्षण न केवल इतिहास के पन्नों में, बल्कि हर उस दिल में अमर है, जो अनंत आकाश की ओर देखता है।

नील एल्डन आर्मस्ट्रांग का जन्म 5 अगस्त 1930 को ओहायो (अमेरिका) के छोटे से कस्बे वपाकोनेटा में हुआ। बचपन से ही उन्हें आसमान में उड़ते विमानों से लगाव था। 16 साल की उम्र में, जब अधिकांश किशोर साइकिल और खेलों में व्यस्त होते हैं, तब आर्मस्ट्रांग ने पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। यहीं से उनकी जिंदगी ने आसमान की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी।

1949 से 1952 तक उन्होंने अमेरिकी नौसेना में बतौर नेवल एविएटर सेवा दी और कोरियाई युद्ध के दौरान 78 लड़ाकू मिशन पूरे किए। इस साहस के लिए उन्हें 'एयर मेडल' और दो 'गोल्ड स्टार' से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एयरोनॉटिक्स यानी एनएसीए (बाद में नासा) में बतौर टेस्ट पायलट शामिल हो गए। वह एक्स-15 जैसे हाइपरसोनिक रॉकेट विमानों के टेस्ट फ्लाइट में शामिल हुए और 3,989 मील प्रति घंटे (मैक 5.74) की रफ्तार तक पहुंचे।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

प्रकृति मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराती है, लेकिन तभी, जब हम अपनी भूख पर नियंत्रण रखें। -विलियम रकेल्सहॉस

ऐसे समय में, जब अतार्किक टैरिफ को लेकर भारत व अमेरिका के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं, तब ट्रंप का दायां हाथ माने जाने वाले सर्जियो गोर की बतौर राजदूत भारत में नियुक्ति एक अर्थ में भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है, पर कई अन्य पहलुओं के मद्देनजर यह सतर्क कूटनीति की मांग भी करती है।

नियुक्ति के निहितार्थ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विश्वसनीय सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत और दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित कर ऐसा कदम उठाया है, जिसका अर्थान्वयन कई दृष्टियों से किया जा सकता है। दरअसल, यह नियुक्ति भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, खासकर ऐसे समय में, जब अतार्किक टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच संबंध सहज नहीं हैं। हालांकि अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो गोर की नियुक्ति ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं को समझने और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की चुनौती के साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। 38 वर्ष के सर्जियो गोर भारत में तैनात किए गए अब तक के सबसे युवा अमेरिकी राजदूत तो हैं ही, ट्रंप का दायां हाथ भी माने जाते हैं। ऐसे में नई दिल्ली में उनके होने से सरकार अपने पक्ष को उनके जरिये अधिक आसानी से व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकती है। यह देखते हुए कि गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए भी विशेष दूत होंगे, उनकी तैनाती सीधे भारत में करने का यह अर्थ भी हो सकता है कि अमेरिका क्षेत्रीय कूटनीति में भारत को केंद्र में रखना चाह रहा हो, जो हमारे लिए फायदे की स्थिति है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। सर्जियो गोर अमेरिकी राजनीति में विवादित रहे हैं। नहीं भूला जा सकता कि उन पर रूसी जासूस होने के आरोप लगे, तो मस्क ने उन्हें सांप तक कह दिया था। दूसरी बात यह कि पिछले करीब दो दशकों से अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण 'रणनीतिक साझेदार' मानता आया है, लेकिन जब ट्रंप भारत के विषय में यह लिखते हैं कि दुनिया के 'सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र' के लिए यह जरूरी है कि वह अपने किसी विश्वासपात्र की नियुक्ति करें, तो इससे भारत की स्थिति को लेकर उनके नजरिये में बदलाव की झलक भी मिलती है। यह अमेरिका की शीतयुद्धकालीन नीति का संकेत भी हो सकता है, जिसके तहत वह भारत और पाकिस्तान को एक ही चश्मे से देखता था। लिहाजा भारत के लिए इस नियुक्ति का यह अर्थ भी हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन क्षेत्रीय नीतियों में भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखने के बजाय, उसे दक्षिण एशिया के व्यापक संदर्भ में देखना चाह रहा हो। इस पर गोर का रवैया क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आशंकाओं को अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से जोड़ कर देखा जाए, तो यह स्थिति भारत से अपने हितों की रक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कतापूर्ण कूटनीति की मांग तो करती ही है।

ये आपदाएं क्या कह रही हैं

हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप मिलकर इस क्षेत्र को आपदाओं की प्रयोगशाला में बदल रहे हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में हिमालयी राज्यों की स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में फ्लैश फ्लड ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के ठीक एक या दो दिन बाद, कठुआ जिले में भी इतनी ही भीषण क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश भी पिछले तीन वर्षों से लगातार इसी तरह की अतिवृष्टि और क्लाउड बर्स्ट को झेल रहा है। हाल ही में, अकेले हिमाचल प्रदेश में छह स्थानों पर बादल फटे और भारी तबाही मच गई। उत्तराखंड में धराली की घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि पूरा एक गांव ही सिरे से साफ हो गया। शुक्रवार की रात चमोली के थराली में बादल फटने से हुई तबाही ने भी देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें 90 से अधिक परिवारों के 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एक युवती की मौत हुई है और एक बुजुर्ग लापता हैं।

हिमालय में त्राहि-त्राहि की स्थिति अब सिर पर चढ़कर बोलने लगी है। यह सच है कि केवल अतिवृष्टि ही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिमालयी प्रकृति में आए बदलाव भी इसका बड़ा कारण हैं। यही बदलाव आज गंभीर संकट का रूप ले चुके हैं।

कश्मीर भी इस आपदा से अछूता नहीं है, जहां पिछले 7–10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें, तो वर्ष 2020 में सात, वर्ष 2021 में 11, वर्ष 2022 में 14, वर्ष 2023 में 16 और वर्ष 2024 में अब तक 15 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा कई छोटी-बड़ी घटनाओं ने भी स्थानीय जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

इसी तरह हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 5–6 बार बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जो भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर सालाना 15–20 तक पहुंच गई है। केवल उत्तराखंड की बात करें, तो पिछले एक दशक में 67 बड़ी और व्यापक तबाही वाली घटनाएं घट चुकी हैं।

इन आंकड़ों और हालिया घटनाओं से यह स्पष्ट है कि हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बादल फटने की घटनाएं न केवल पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप मिलकर इस क्षेत्र को आपदाओं की प्रयोगशाला में बदल रहे हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में हिमालयी राज्यों की स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

पिछले एक दशक में हिमालय में जो हो रहा है, वह गंभीर तो है ही, हम इसके कारणों को समझने में भी चूक रहे हैं या उसकी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसी घटना केरल में भी हुई थी, जिसने सारे देश और दुनिया में सुर्खियां बटोरीं। पिछले वर्ष सिक्किम में भी ऐसी ही घटना हुई। बाढ़ या बादल फटने जैसी तबाही किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, इसलिए अब इस पर विचार करने का वक्त आ गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं।

जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम समझने में विफल हो रहे हैं, वह यह है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ आशंका नहीं रह गया है, बल्कि वास्तविक रूप में उसका असर दिखने लगा है। यह केवल अपने ही देश में नहीं, बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। चाहे वह चीन, अमेरिका, यूरोप के देश हों या थाईलैंड, इन सभी में इसी तरह की घटनाएं पिछले एक दशक से लगातार देखी जा रही हैं। तो शायद स्थान विशेष के कारण और घटना के अलावा जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह यह है कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है, जो किसी भी समय और किसी भी मौसम में ढेर सारी बारिश से जनजीवन को तबाह कर दे रही है।

यह सब कुछ अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की कृपा से हो रहा है, और यह प्रकृति का अपना तरीका है, अपने बदलाव को जताने का। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने पिछले दो दशकों में इस तरह की कई रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। उनमें साफ-साफ इंगित था कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में सब कुछ बदल डालेगी, और यह सच भी हो रहा है।

इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, जिसे हम समझना नहीं चाहते। हम कभी जंगल काटने को दोष देते हैं, कहीं विकास के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अब ऐसी तबाही के कारण कुछ भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आप यह भी संज्ञान में लें कि जब भी इस तरह की बड़ी बाढ़ आती है, न जंगल बचते हैं और न ही मकान, और न ही हमारी बसावट। यही सब कुछ इन सभी घटनाओं के पीछे है।

इसका एकमात्र कारण यही है कि दुनिया की बदलती जीवन-शैली ने पृथ्वी को इस हद तक तपा दिया कि अब एक नया दौर हमारे बदलते मौसम का कारण है, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट या अतिवृष्टि का नाम दे सकते हैं। और यह कहां, किस रूप में बरसेगा, यह इस पर निर्भर नहीं करेगा कि कहां विकास हुआ है और कहां नहीं। यह दोनों को बराबर ही दर्जे से देखेगी। यही समझ आज सबसे महत्वपूर्ण भी होनी चाहिए कि मनुष्यजनित इस प्राकृतिक व्यवहार का दोषी स्वयं मनुष्य है। प्रकृति के साथ मनुष्य ने जो छेड़छाड़ की है, वह उसी की प्रतिक्रिया दे रही है।

बदलती परिस्थितियों के प्रति हम कई तरह की विवेचना कर रहे हैं, उसके कारणों को देख रहे हैं। लेकिन जब तक हम इसकी गंभीरता को समझेंगे नहीं, हमारे पास कोई समाधान ही नहीं होगा। हिमालय इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि नमी वाली हवाएं ऊंचाइयों पर पहुंचकर जैसे ही निचला तापक्रम देखती हैं, वे बरस पड़ती हैं। आईपीसीसी ने भी यही कहा है।

इन्हीं बातों को लेकर अब एक और अंतरराष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ है, जिसको एजीई के नाम से जाना जाता है–अलायंस फॉर ग्लोबल एन्वॉयरन्मेंट। इसका मानना है कि अब इन परिस्थितियों में अगर हमको समाधान ढूंढने हैं, तो वे स्थानीय स्तर पर ही संभव होंगे। यह संगठन ऐसी ही समझ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कि कैसे इन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर जुटाया जाए। यह समझ जरूरी है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, वह मनुष्य जनित है, क्योंकि प्रकृति ने दंड देने की रफ्तार पकड़ ली है। अभी इसकी रफ्तार सुस्त ही है, जब तेज होगी, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

विक्टर ह्यूगो

प्रेम एक पेड़ की तरह है, यह खुद बढ़ता है, हमारी पूरी सत्ता में गहरी जड़ें जमाता है, और कभी-कभी एक वीरान दिल पर भी हरी पत्तियां उगाता है। प्रेम वे लोग करते हैं, जो छोटे-छोटे कार्यों में अपनी जान डालते हैं।

जीवन एक फूल है, जिसका मधु प्रेम है

जीवन कठिन है, यह ज्यादा देर नहीं टिकता और कभी-कभी व्यर्थ लगता है। फिर भी, जीवन में महान दुखों के लिए साहस रखें और छोटे दुखों के लिए धैर्य। जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह विश्वास करना है कि हम खुद के लिए प्रिय हैं। प्रेम क्या है? इसका उत्तर एक रोज सड़क पर मिला, मैं बहुत ही गरीब युवक से मिला, जो प्रेम में था। उसकी टोपी पुरानी थी, उसका कोट घिसा हुआ था, पानी उसके जूतों से होकर गुजर रहा था और तारे उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहे थे। प्रेम गरीबी और कठिनाई के बीच भी, हर मुश्किल रेखा को पार करने की क्षमता रखता है, उसकी आंखों में एक ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जीवन की गहराइयों में, प्रेम ही वह मोती है, जो अंधेरे में चमकता है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। जीवन की सच्ची विभाजन रेखा प्रकाश और अंधेरे में रहने वालों के बीच है। हमारा लक्ष्य अंधेरे में रहने वालों की संख्या कम करना होना चाहिए। प्रेम आत्मा का एक हिस्सा है, और यह उसी प्रकृति का है, जो जीवन में प्रकाश लाता है। प्रेम एक पेड़ की तरह है, यह खुद बढ़ता है, हमारी पूरी सत्ता में गहरी जड़ें जमाता है, और कभी-कभी एक वीरान दिल पर भी हरी पत्तियां उगाता है। प्रेम का सबसे शक्तिशाली लक्षण वह कोमलता है, जो कभी-कभी असहनीय हो जाती है। प्रेम का महान कार्य वे लोग करते हैं, जो छोटे-छोटे कार्यों में अपनी जान डालते हैं। जीवन एक फूल है, जिसका मधु प्रेम है। करुणा इस मानवता का दिल है। महान प्रेम के कार्य छोटे कार्यों से होते हैं। दया प्रेम का एक रूप है। जिस समाज में दया, सहानुभूति और करुणा की भावना कम हो जाती है, तो उस समाज का स्तर निम्न, असंवेदनशील और बुरा हो जाता है। उच्च समाज और ऊंची मानवता के लिए, हमें करुणा को अपनाना होगा। मानवता पर विचार करें। मानव आत्मा को वास्तविक से अधिक आदर्श की जरूरत है। वास्तविक से हम अस्तित्व में हैं, आदर्श से हम जीते हैं। मानवता की उन्नति के लिए, हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हीरे तो धरती के अंधेरे गर्तों में ही मिलते हैं, उसी प्रकार सत्य तो विचारों की गहराइयों में ही मिलते हैं। प्रेम और शिक्षा का प्रकाश जलाएं और अंधेरे में छिपे हीरे को ढूंढ लें। पढ़ना एक परिवर्तनकारी क्रिया है, जो एक ज्वाला जलाने के समान है, जिसमें प्रत्येक अक्षर और शब्द ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना को प्रकाशित करने वाला ईंधन प्रदान करते हैं। जीवन में प्रेम करें, करुणा दिखाएं, और मानवता को ऊंचा उठाएं। दुनिया बदल रही है, लेकिन ये सत्य शाश्वत हैं। प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। हम उतना ही क्षमा करते हैं, जितना हम प्रेम करते हैं। प्रेम स्वयं के प्रति एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है, जो अकेलेपन के डर को, यहां तक कि एकांत में भी, दूर कर देता है। यह पूर्ण महसूस करने के लिए बाहरी मान्यता या संगति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भीतर पूर्णता और शांति पाने के बारे में है। करुणा रखें, क्योंकि बिना उसके हम कुछ नहीं। मानवता को अपनाएं, क्योंकि हम सब एक हैं।

धैर्य रखें

सूत्र

जीवन की डगर कितनी भी कठिनाइयों और मुसीबतों से क्यों न भरी हो। यदि उस पर चलने वाले व्यक्ति के भीतर प्रेम की लहरें दौड़ रही हों, तो वह हर डगर को पार तो करेगा ही, उस डगर को बेहतर बनाता जाएगा। अपने काम से प्रेम करें, या उस काम को ऐसा बनाएं कि उससे प्रेम हो जाए, जीवन सुंदर हो जाएगा। जीवन में कुछ भी पाने के लिए जरूरी है धैर्य रखना।

दूसरा पहलू

यदि दुनिया भर में सभी लोग एकसाथ बत्तियां जलाएं, तो आकाशीय चमक का क्या नजारा होगा?

दुनिया के सभी बल्ब एकसाथ जलें, तो क्या होगा

हेरोल्ड वालेस

कोयला और परमाणु संयंत्र हमेशा भरपूर बिजली दे सकते हैं, लेकिन इन्हें बंद करने के बाद दोबारा चालू करने में कई घंटे लग सकते हैं।

जब कोई अपनी लाइट जलाता है, तो वह ग्रिड से बिजली खींचता है। जनरेटर को तुरंत ग्रिड में समान मात्रा में बिजली देनी चाहिए। अगर सिस्टम कुछ सेकंड के लिए भी असंतुलित हो जाए, तो ब्लैकआउट हो सकता है।

यदि एकसाथ दुनिया भर के लोग अपनी बत्तियां जलाएं, तो सबसे बड़ा असर 'बिजली की मांग' में वृद्धि के रूप में होगा। पावर ग्रिड को स्थिर रखने के लिए बिजली आपूर्ति को मांग के हिसाब से तुरंत बढ़ाना या घटाना पड़ता है। जब कोई अपनी लाइट जलाता है, तो वह ग्रिड से बिजली खींचता है। जनरेटर को तुरंत ग्रिड में समान मात्रा में बिजली देनी चाहिए। अगर सिस्टम कुछ सेकंड के लिए भी असंतुलित हो जाए, तो ब्लैकआउट हो सकता है। बिजली की मांग दिन-रात और मौसम के अनुसार काफी बदलती रहती है। बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी हो जाने पर बिजली संयंत्रों को सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ाना होगा। कोयला और परमाणु संयंत्र हमेशा भरपूर बिजली दे सकते हैं, लेकिन इन्हें बंद करने के बाद दोबारा चालू करने में कई घंटे लग सकते हैं। प्राकृतिक गैस से चलने वाले विद्युत संयंत्र तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मांग बढ़ने पर इनका इस्तेमाल होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पानी से उत्पन्न बिजली कम प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, पर इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है, क्योंकि हवा हमेशा एक ही गति से नहीं बहती है और न ही हर दिन एक समान धूप होती है। ग्रिड प्रबंधक मांग बढ़ने और घटने पर बिजली प्रवाह को सुचारु रखने के लिए बड़ी बैटरियों का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी तक बैटरियों में इतनी बिजली संग्रहीत करना संभव नहीं है कि एक पूरे कस्बे या शहर को रोशन किया जा सके। कुछ जल विद्युत संयंत्र कम मांग के समय पानी को झीलों में जमा करते हैं, फिर जब मांग बढ़ती है, तो उस पानी से बिजली बनाते हैं।

अगर सभी लोग एकसाथ बत्तियां जलाएं, तो कोई बहुत बड़ा सिस्टम क्रैश नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में हर देश के अपने-अपने कई क्षेत्रीय ग्रिड हैं। एलईडी बल्बों से ग्रिड पर बोझ कम पड़ता है। अगर सारी बत्तियां एकसाथ जलें, तो रात में आकाशीय चमक बहुत बढ़ जाएगी। यह वह धुंधली रोशनी है, जो शहरों और कस्बों के ऊपर दिखती है। यह तब होता है, जब रोशनी हवा में मौजूद धूल और नमी के कणों से टकराकर बिखरती है, जिससे आसमान धुंधला हो जाता है। प्रकाश का ऐसा प्रदूषण इन्सानों के सोने और जागने के प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ सकता है। साथ ही, यह कीड़े, पक्षी, समुद्री कछुए और अन्य जीवों को भटका सकता है। अगर सब लोग एकसाथ बत्तियां जलाएं, तो बिजली की खपत में बढ़ोतरी होने के साथ आकाशीय चमक बढ़ने से रात में तारे दिखना बंद हो जाएंगे, जो कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं होगा। -द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

दुनिया में ब्लू कार्बन

आईयूसीएन के अनुसार, समुद्री व मुहाने के मैंग्रोव के साथ ज्वारीय दलदल स्थलीय वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहीत करते हैं।

समुद्री मैंग्रोव	2,243
मुहाना मैंग्रोव	1,524
खारा दलदल	949
उष्ण. वर्षावन	800
समुद्री घास	511

आंकड़े संग्रहीत कार्बन के टन में। | स्रोत : IUCN

मनु और शतरूपा ने वर्षों तक तपस्या की, तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया। इसी कारण सूर्यवंश में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु जन्मे।

भगवान की आराधना

अंतर्यात्रा
संकलित

पूर्वकाल में स्वयंभू मनु और शतरूपा ने घोर तप किया। वे हजारों वर्षों तक एकांत में रहकर भगवान की एकाग्रचित्त आराधना करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु, अपनी आदि शक्ति सहित, उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान मेघ-गंभीर वाणी में बोले, 'हे दंपती! मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो।' भगवान के त्रिभुवन-कमनीय रूप को देखकर वे स्वयं को भूल गए। उस रूप के दर्शन से ही उनकी तृप्ति हो गई।

मनु महाराज बोले, 'भगवान! मुझे कहने में संकोच होता है, किंतु बिना कहे रहा भी नहीं जाता। मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र बिल्कुल आपके समान हों।' भगवान हंसते हुए बोले, 'मेरे समान दस-बीस थोड़े ही हैं, मैं तो अकेला हूं। अतः मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तुम 'सूर्यवंश' में महाराज दशरथ होगे, तुम्हारी पत्नी शतरूपा कौशल्या होंगी। तब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा।' स्वयंभू मनु यह सुन अति प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, 'भगवान! एक बात और है। आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लें, तो मुझमें आपके प्रति पुत्रवत् ममता हो। मैं पुत्र समझकर ही आपके प्रेम में सदा निमग्न रहूं।' भगवान 'ऐसा ही होगा' कहकर अंतर्धान हो गए। कालांतर मनु और शतरूपा ने त्रेतायुग में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 25 अगस्त, 1950

नागरिकों पर निर्मम बमबारी का भारत सख्त विरोध करेगा

शांत नागरिकों पर निर्मम
का भारत सख्त विरोध
सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में

अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से कोरिया के शांत नागरिकों व गांवों के गैर फौजी क्षेत्र पर बमबारी कर रहे हैं। इस निर्मम बमबारी से भारत काफी चिंतित है और वह अमेरिका को इसके बारे में विरोध पत्र लिखेगा।

केवल प्रतिबंध लगाना ही मकसद नहीं

ऑनलाइन गेमिंग संबंधी नया कानून केवल प्रतिबंध के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी है।

सुनील कुमार गुप्ता, (पूर्व आईपीएस)

मुद्दा

बीते 22 अगस्त को भारत ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जब ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। यह कानून वास्तविक धन आधारित गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और साथ ही ई-स्पोर्ट्स व सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए ढांचा तैयार करता है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2024 में 3.7 अरब डॉलर का था, जिसमें 1,900 कंपनियों में 1.3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे थे। करीब 59.1 करोड़ गेमर्स के साथ (जो वैश्विक गेमिंग आबादी का 20 फीसदी है) भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग बाजार बन चुका है। इस कानून के तहत वास्तविक धन वाले गेम्स पर प्रतिबंध से इस उद्योग की दिशा बदल जाएगी। कानून ऑनलाइन गेमिंग की तीन श्रेणियों में स्पष्ट अंतर करता है। पहला, ***पूर्ण प्रतिबंध:*** सभी वास्तविक धन वाले गेम्स जिनमें पैसे या दांव लगाकर धन लाभ की उम्मीद की जाती है, अब अवैध हैं। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी जैसे लोकप्रिय प्रारूप शामिल हैं। दूसरा, ***प्रोत्साहन:*** ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार इस श्रेणी के लिए प्रशिक्षण अकादमियां, वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक तंत्र स्थापित करेगी। और तीसरा, ***विनियमन:*** अन्य वैध डिजिटल गेम्स के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो गेम्स को वर्गीकृत करेगा, शिकायतें सुनेगा और अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, बार-बार अपराध करने पर पांच साल तक की कैद और दो करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विज्ञापन उल्लंघन पर 50 लाख रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।

सरकार इस प्रतिबंध के पीछे सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं का तर्क देती है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच कर्नाटक पुलिस ने 32 आत्महत्याओं को ऑनलाइन जुए के नुकसान से जोड़ा है। तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ने भी ऐसे मामलों को चिह्नित किया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 45 करोड़ भारतीय ऐसे गेम्स खेलते हैं और कई परिवार वित्तीय नुकसान से बर्बाद हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग डिसऑर्डर को चिकित्सकीय समस्या माना है। सरकार का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य हानि, पारिवारिक कर्ज और आत्महत्याओं जैसे सामाजिक नुकसान आर्थिक लाभ से कहीं बड़े हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसियों ने पाया कि कुछ प्लेटफॉर्म आतंकवाद वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संचार के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ऑफशोर प्लेटफॉर्म घरेलू नियमन से बाहर थे और बड़े पैमाने पर धन देश से बाहर भेज रहे थे। इस प्रतिबंध का आर्थिक नुकसान भी होगा। वर्ष 2024 में वास्तविक धन वाले गेम्स से 85.7 फीसदी यानी 3.2 अरब डॉलर का राजस्व आया। 2029 तक इस उद्योग के 9.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। अब यह सब संकट में है। आईटी सचिव एस. कृष्णन के अनुसार, इससे सरकार को सालाना 15,000–20,000 करोड़ रुपये जीएसटी का नुकसान होगा। कुल कर हानि 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। उद्योग निकायों का कहना है कि दो से चार लाख नौकरियां दांव पर हैं और 25,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभावित होगा। ड्रीम 11 ने कानून पारित होते ही सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए और अब वह केवल 'फ्री-टू-प्ले' प्रारूप और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी तरह, एमपीएल और अन्य कंपनियां भी नए मॉडल तलाश रही हैं–जैसे विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन आधारित गेम्स।

इस कानून के बन जाने से वर्षों से चली आ रही इस बहस का भी अंत हो गया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और रम्मी कौशल आधारित गेम्स हैं या नहीं। अब कोई अस्पष्टता नहीं रही। यह कमजोर आबादी को नशे की आदत डालने वाले एल्गोरिदम से भी बचाता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह कानून भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। इसके चलते उपयोगकर्ता ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं, जहां न उपभोक्ता सुरक्षा है और न ही कर वसूली। सरकार कहती है कि यह कानून केवल प्रतिबंध के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी है। ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर, प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित कर और गैर-मौद्रिक गेमिंग में नवाचार को प्रोत्साहित करके युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'ऐतिहासिक सुधार' बताते हुए कहा है कि यह समाज की रक्षा करेगा और ई-स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा।

कुल मिलाकर, यह कानून भारत की डिजिटल नीति में मील का पत्थर है। यह कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। *(साथ में अक्षिता गुप्ता)*

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

विदेश मंत्री की खरी-खरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जिस वक्त भारत में अपने नए राजदूत के नाम का एलान कर रहा था, लगभग उसी समय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को की धरती से जो कुछ कहा, उसके गहरे निहितार्थ हैं। विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत का अपना है और इसके बारे में वह स्वतंत्र निर्णय लेना जारी रखेगा। जिन मुल्कों को भारत से तेल खरीदने में परेशानी है, वे न खरीदें। उन्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा। गौरतलब है, रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका नई दिल्ली पर दबाव बनाना चाहता है, बल्कि उसने इसी बहाने से उस पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी लाद दिया है। यह शुल्क चंद दिनों में लागू होने वाला है। इस नाजुक मोड़ पर जयशंकर का ताजा बयान भारतीय रुख की सशक्त अभिव्यक्ति है। रूस से तेल खरीदने के भारतीय कदम की मुखर आलोचना करने वाले यूरोपीय देशों को भी अब यह साफ हो जाना चाहिए कि भारत बिना किसी दबाव में आए अपने हितों के अनुरूप हर मुमकिन कदम उठाता रहेगा।

भारतीय विदेश मंत्री ने वर्ष 2022 में ही यूरोपीय संघ को आईना दिखाया था कि किस तरह उसके देश एक तरफ यूक्रेन को रूस से जंग जारी रखने के लिए धन व हथियार मुहैया करा रहे हैं और दूसरी तरफ, मॉस्को के साथ कारोबार भी कर रहे हैं। तब उन्होंने तफसील के साथ पश्चिमी मीडिया को बताया था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को तय करने का अधिकार किसी अन्य को नहीं दे सकता। भारत रूस से जितना तेल खरीद रहा है, उससे अधिक यूरोप के सिर्फ दस देश उससे ले रहे हैं। इसी 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप-पुतिन शिखर-वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की तस्दीक की थी कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका और रूस के द्विपक्षीय कारोबार में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि चीन कहीं ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, फिर किस नैतिक आधार पर पश्चिम भारत से त्याग की उम्मीदें पाल रहा है?

एस जयशंकर का ताजा बयान भारतीय रुख की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों के अनुकूल स्वतंत्र निर्णय करता रहेगा।

दरअसल, इस समय दोनों देशों के बीच टैरिफ के मसले पर गहन बातचीत चल रही है। ट्रंप प्रशासन भारतीय बाजार तक उन्मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। भारत की मजबूरी यह है कि वह इसकी इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से यहां के किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों को गंभीर चोट पहुंचेगी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के संकेत दे चुके हैं और अब विदेश मत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ व्यापार-वार्ता में हमारी सीमाएं तय हैं। सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति की आलोचना खुद अमेरिका के भीतर वरिष्ठ राजनेताओं व विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। खुद उनकी पार्टी के कई नेता उन्हें आगाह कर चुके हैं। मगर इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप पिछले दो दशकों में मजबूत हुए द्विपक्षीय संबंधों को दांव पर लगाने को आमादा हैं। निस्संदेह, यह भारतीय राजनय के धैर्य और कौशल की परीक्षा की घड़ी है। उसने अब तक पूरी दृढ़ता और कुशलता से अपना पक्ष रखा है। उम्मीद है कि अमेरिका जमीनी वास्तविकताओं को तस्लीम करेगा और उसके नए राजदूत सर्जियो गोर दोनों देशों के आपसी रिश्तों की नई गुत्थियों को सुलझाने में अहम कड़ी साबित होंगे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 25 अगस्त, 1950

विफलता की जिम्मेदारी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने सर ओवन डिक्सन के मिशन की विफलता पर कराची में एक प्रेस कांफ्रेंस के सामने विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट किये हैं। भारत के प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने भी उसके बाद नई दिल्ली में पत्रकारों के सम्मुख अपने विचार रख दिये हैं। सर ओवन ने अपने वक्तव्य में विफलता के लिए किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने से परहेज किया है। किन्तु श्री लियाकत अली ने पहले दोषारोपण का सिलसिला शुरू किया, जिसके फलस्वरूप नेहरूजी को भी प्रत्युत्तर देना पड़ा। श्री लियाकत अली ने सर ओवन के प्रयत्नों की विफलता की पूरी जिम्मेदारी भारत पर डाली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन नहीं कर रहा है और काश्मीर से अपनी फौजों को हटाने से इनकार करके निष्पक्ष और स्वतंत्र जनमत-संग्रह के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होने में बाधा डाल रहा है। ...श्री लियाकत अली की स्थापनायें सत्य से उतनी ही दूर हैं, जितना जमीन और आसमान के बीच अंतर है।

नेहरूजी ने श्री लियाकत अली की तुलना जो एलिस से की है, वह हमको बिलकुल यथार्थ प्रतीत होती है। बालिका एलिस स्वप्नलोक में जो अद्भुत दृश्य देखती है, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। श्री लियाकत अली भी काश्मीर की चर्चा करते समय किसी स्वप्न लोक में प्रविष्ट हो गये प्रतीत होते हैं। ...सच्चाई यह है और उसको किसी तरह नहीं छिपाया जा सकता कि कबायलियों ने पाकिस्तान की मदद से काश्मीर पर आक्रमण किया और आगे चलकर पाकिस्तान खुद भी आक्रमण में शामिल हो गया। इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने काश्मीर की जितनी भूमि पर कब्जा कर लिया है, उससे हटना नहीं चाहता। अपने ही अधिकृत इलाके में उसने जो सेना खड़ी कर ली है, उसे भंग करने को तैयार नहीं। स्वयं आक्रमणकारी होकर भारत पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाता है। खुद निष्पक्ष और स्वतंत्र जनमत-संग्रह के अनुकूल वातावरण पैदा करने को तैयार नहीं और भारत पर यह आरोप लगाता है कि वही जनमत-संग्रह होने देने में बाधक हो रहा है। यह तो ठीक वही स्थिति हुई कि कोई आदमी पांवों के बल जमीन पर खड़ा हो और कहा जाये कि वह सिर के बल पर खड़ा हुआ है।

तकनीक में ताकतवर बनना जरूरी

प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता से भारत को जल्द से जल्द मुक्ति पानी होगी और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी क्षमता व सामर्थ्य में इजाफा करें।

यहां स्कैन करें

प्रांजल शर्मा | डिजिटल नीति विशेषज्ञ

यह एक ऐसा भू-राजनीतिक दौर है, जिसमें लगभग हरेक उत्पाद या सेवा को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में, महत्वपूर्ण सेवाओं, सामग्रियों और उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने से भारत को रणनीतिक नुकसान हो सकता है। आज की दुनिया में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल रॉकेटों या टैंकों से मुमकिन नहीं है। इसमें अब आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सुरक्षा का बेहद अहम योगदान है। चूंकि इन सभी के मूल में उभरती तकनीकी का महत्व है, इसलिए भारत को तकनीकी संप्रभुता पाने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ानी चाहिए।

तकनीकी संप्रभुता का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि भारत उन प्रौद्योगिकियों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, जिनका सामरिक महत्व है या जो तकनीक बतौर हथियार इस्तेमाल की जा सकती है। इस दिशा में काम हो भी रहा है। मसलन, हाल-फिलहाल हमने दूरसंचार से जुड़े हार्डवेयर को देश में विकसित करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। बिजली उत्पादन उपकरणों के विकास को भी हमने प्रोत्साहित किया है। दवा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के ठोस प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही, घरेलू उपग्रहों, ड्रोनों के विकास और सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की दीर्घकालिक योजना भी सराहनीय प्रयास है।

यह सब करना कितना जरूरी है, इसका अंदाज पिछली कुछ घटनाओं से लगाया जा सकता है। जैसे, अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली 'स्विफ्ट' ने रूस के कुछ बैंकों को अपनी सेवाएं देनी बंद कर दीं। इसी तरह, माइक्रोसॉफ्ट ने ऊर्जा कंपनी नायरा को दी जाने वाली सेवाएं अचानक बंद कर दीं, क्योंकि वह रूस से तेल खरीदती थी। माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले ने बताया कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारत किस कदर निर्भर है। हालांकि, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी

शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के भारत में कौशल-विकास केंद्र हैं, लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका इन कंपनियों पर ऐसे कदम उठाने का दबाव डाल सकते हैं, जो हमारी संस्थाओं के लिए नुकसानदेह हों।

इसी तरह, चीन ने कई देशों को किए जा रहे एक खास खनिज के निर्यात पर रोक लगा दी, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरियों के निर्माण को नियंत्रित करना चाहता है। चूंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सेवा का इस्तेमाल भू-राजनीतिक हितों को साधने के लिए बतौर हथियार किया जा सकता है, इसलिए भारत को अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी, ताकि वह बाहरी ताकतों के ब्लैकमेल का शिकार न बन सके। इसके लिए कुछ क्षेत्रों में तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है।

पहला है, क्रांतिक चुंबकीय (क्रिटिकल मैग्नेट्स) क्षेत्र। आज बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुर्लभ मृदा चुंबक के उत्पादन में घरेलू क्षमता विकसित करने में जुटी हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। दुर्लभ मृदा चुंबकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजना बनाने का एलान किया है। सरकार इस बाबत 1,345 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू करने जा रही है, और उसका लक्ष्य उन लोगों तक पहुंचना है, जो इसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, यानी दुर्लभ मृदा ऑक्साइड से लेकर चुंबक बनाने तक। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती खपत के कारण भारत में दुर्लभ मृदा चुंबकों का आयात बढ़ा है। चूंकि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है, इसलिए भारत को स्थानीय स्तर पर इससे जुड़ा अन्वेषण बढ़ाने और आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है।

दूसरा है, डिजिटल कनेक्टिविटी। यह एआई के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जैसे-जैसे दुनिया एआई को आत्मसात करने और उसको नियंत्रित करने के लिए खुद को संगठित कर रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश महत्वपूर्ण साबित होता जा रहा है। माना जाता है कि समुद्र के अंदर केबल बिछाने और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे कामों में किए जा रहे अरबों डॉलर के निवेश का सुफल एआई के स्मार्ट उपयोग व प्रबंधन के रूप में निकल सकता है। इस साल दो अन्य 'अंडर-सी केबल' (इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस) की शुरुआत हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे भारत की डाटा ट्रांसमिशन की क्षमता चार गुना तक बढ़ जाएगी। यही नहीं, ये केबल देश को दुनिया के प्रमुख बाजारों से जोड़ देंगी। लिहाजा, अब भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी घरेलू क्षमताएं वैश्विक कंपनियों द्वारा दी जा रही सेवाओं जितनी ही मजबूत हों।

तीसरा क्षेत्र है, जेनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भारत ने इंडियाएआई मिशन और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए धनराशि बढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बजट में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बेशक, यह आवंटन महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्नत विनिर्माण तंत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपाय करने होंगे। प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का एक अहम पहलू समझना होगा और साइबर सुरक्षा के लिए अधिक निवेश, अधिक पूंजी और अधिक संस्थागत प्रयास की जरूरत होगी। एआई को लेकर चल रही प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में छोटे भाषा मॉडल की आवश्यकता भी बढ़ेगी, इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

चौथा है, तकनीकी जोखिम और साइबर सुरक्षा। चूंकि परिवर्तन की लहर अपने साथ जोखिम भी लाती है, इसलिए तकनीकी विकास के साथ-साथ खतरे भी बहुआयामी होते जा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर जासूसी व युद्ध, और जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियारों का आपसी संयोजन मानव समुदाय के लिए काफी बड़ा खतरा है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि बेशक जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति सेहत और नवाचार में बड़ी संभावनाएं पैदा करती हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाए, तो इससे गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। चूंकि इन प्रौद्योगिकियों का व्यापकता में इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए 'नॉन-स्टेट एक्टर्स' के हाथों तक इनके पहुंचने की आशंका भी बढ़ने लगी है। ऐसे में, हमारी साइबर सीमाएं भी भू-राजनीतिक सीमाओं जितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

साफ है, भारत को दूसरों पर निर्भरता से मुक्ति पानी होगी और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमता व सामर्थ्य में इजाफा करें। लिहाजा, यह सही समय है कि हम तकनीकी संप्रभु बनने का संकल्प लें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नेपाल में नए नक्शे को लेकर निशाने पर ओली सरकार

यहां स्कैन करें

पुष्परंजन | वरिष्ठ पत्रकार

नेपाल इस बार भारत से कम और चीन से ज्यादा नाराज है। दरअसल, चीन ने उस नक्शे को मान्यता दी है, जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को भारत का हिस्सा माना गया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नेपाल का विपक्ष सवाल कर रहा है कि आपने चीन को 'चुच्चे मानचित्र' यानी नया नक्शा क्यों नहीं भिजवाया था?

यह 18 मई, 2020 की बात है, जब नेपाल का राजनीतिक मानचित्र संसद से पारित किया गया था। तत्कालीन सरकार ने नेपाल की सीमा में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को शामिल करते हुए नए मानचित्र में नेपाल के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया था, जिससे कुल क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 147,516 वर्ग किलोमीटर हो गया। मगर इस नए मानचित्र को चीन और भारत के साथ साझा करना ओली सरकार भूल गई। इस बीच 28 अगस्त, 2023 को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपना 'मानक मानचित्र, 2023 संस्करण' जारी किया। उसमें पुराने मानचित्र को ही स्वीकृति दी गई, जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को भारत का हिस्सा माना गया था। नेपाली विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें चीन के नए नक्शे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। यह बयान जिस भी नेपाली नागरिक ने सुना, अपना माथा पीटकर रह गया। लोगों ने जब नेताओं और नौकरशाहों को कठघरे में खड़ा करना शुरू किया, तब अपनी खाल बचाने के लिए ओली सरकार बयान देने लगी कि चीन ने नए मानचित्र की अनदेखी की है, जिसे 1816 की सुगौली संधि के आधार पर संसद ने मंजूरी दी थी।

चीन ने नेपाल के उस नक्शे को मान्यता दी है, जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख व कालापानी को भारत का हिस्सा माना गया है।

कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नए मानचित्र के बारे में न केवल पड़ोसी देशों, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी औपचारिक जानकारी न देना नेपाल की खुद की कमजोरी है। उनके मुताबिक, किसी भी देश को अपने मानचित्र में बदलावों के बारे में संबंधित पक्षों को सूचित करना होता है। अब वे पूछ रहे हैं, क्या नेपाल सरकार ने मानचित्र में बदलावों और नए मानचित्र के अनुसार प्रतीकों, चिह्नों को बदलने जैसे संविधान संशोधन के बारे में मित्र देशों को सूचित किया था? अगर किया था, तो उसने इसे मॉनिटर किया या नहीं? नेपाली विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेवा लम्साल का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देशों को इस नक्शे के बारे में लिखा था या नहीं?

बहरहाल, 2 नवंबर, 2019 को भारत ने लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को शामिल करते हुए एक नया नक्शा जारी किया था, जिसका नेपाल में कड़ा विरोध हुआ था। उसके अगले साल 8 मई, 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन किया। 80 किलोमीटर लंबी यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला को भारत-चीन सीमा के पास लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नेपाल में उन दिनों भारत के विरुद्ध काफी तनावपूर्ण माहौल बना दिया गया था। नेपाल ने तब समस्या सुलझाने की खानापूर्ति भर की, मगर 18 मई, 2020 को संसद में नया नक्शा पास किया, जिसके बारे में दोनों पड़ोसियों को अवगत न कराकर चुप्पी साध ली।

नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री भेष बहादुर थापा का कहना है कि यह दावा नहीं किया जा सकता कि बाकी दुनिया को इस मामले की औपचारिक जानकारी थी। थापा कहते हैं, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नया नक्शा जारी होने के बाद नेपाल को कूटनीतिक बातचीत जारी रखनी चाहिए थी। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि नेपाल सरकार की कूटनीतिक निष्क्रियता का दुष्परिणाम है यह। नेपाल के पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई कहते हैं कि इस घटना के बाद यह बात पुख्ता हो गई है कि उत्तरी और दक्षिणी, दोनों पड़ोसी देश अब नेपाल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खैर, जो भी हो, जब यह जानकारी मिली कि इसी मार्ग से भारत-चीन सीमा-पार व्यापार के लिए सहमत हुए हैं, नेपाल में कुछ लोग फिर से इस पर विवाद खड़ा करे में जुट गए हैं। मगर नेपाल के पास अब एक ही विकल्प है, *बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेइ!*

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सबकी आखिरी तारीख

इस दुनिया में हर चीज पर 'एक्सपायरी डेट', अर्थात वह तारीख दर्ज होती है, जिसके बाद वह बेअसर हो जाएगी। इससे गहरा संदेश जाता है कि हर चीज, जो पैदा होती है, उसका मृत्यु दिवस तय होता है। इसे हम एक सिद्धांत की तरह तो जानते हैं, पर जीवन में नहीं उतारते। जिस तरह वस्तुओं की मरने की तारीख लिखी जाती है, वैसी क्या मनुष्य की लिखी जा सकती है? यदि वह भी लिखी जाए, तो मरने के आसपास जो भय, अनिश्चितता व आडंबर पैदा किया जाता है, वह नहीं होगा। फिर तो जिंदगी में हम जो दोस्ती और दुश्मनी में उलझ जाते हैं, लालच व क्रोध से परेशानियां खड़ी करते हैं, वे नहीं करेंगे।

क्या आपने कभी सोचा, संबंधों की भी 'एक्सपायरी डेट' होती है? गौर से देखें, तो रिश्ते भी पहले जिंदा होते हैं और एक खास समय के बाद मर जाते हैं, क्योंकि रिश्ते बनते हैं भाव से; और भाव एक बहती हुई ऊर्जा है, वह एक जैसी हो नहीं सकती। मगर इसे महसूस करने के लिए पैनी नजर और संवेदनशील हृदय होना जरूरी है। अन्यथा लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह संबंध अब पुराना पड़ चुका है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उसे वे ढोए चले जाते हैं। और गहरे जाएं, तो विचारों और भावों की भी एक्सपायरी डेट होती है। इस क्षण हम जो सोचते हैं, जरूरी नहीं कि कुछ समय बाद वैसा ही सोचें। आज किसी के लिए नफरत है, तो जरूरी नहीं कि उससे आप जिंदगी भर नफरत करते रहें। या आज प्रेम हो, तो ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रेम हमेशा रहेगा।

एक दफा मुझे इस एक्सपायरी डेट का बड़ा मजेदार अनुभव हुआ। मैं मशहूर हिंदी फिल्म *ए वेडनसडे* देखने गई थी। पहला शो खत्म होने में थोड़ी देर थी, सो सभी लोग हॉल के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। युवकों की भीड़ सामने खड़ी गप्पें हांक रही थी। और जैसा होता है, जब बहुत से हमउम्र जुट जाएं, तो दूसरों का मजाक उड़ाना, खासकर बुजुर्गों पर व्यंग्य करना होता रहता है।

उनमें से एक ने कहा, 'ये अनुपम खेर-वेर, नसीरुद्दीन शाह-वाह जैसे एक्टरों की एक्सपायरी डेट निकल गई। इन्हें एक्टिंग-वैक्टिंग बंद कर देनी चाहिए।' अगले ने हामी भरी, 'हम जैसे जवानों को मौका मिले।'

लेकिन हुआ यह कि फिल्म में नसीरुद्दीन, जो एक अधेड़ आम आदमी का किरदार कर रहे हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को झांसा देने के लिए एक से एक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं। तरह-तरह के सिम कार्ड, ब्लूटूथ, लैपटॉप के करिश्मे के जरिये। उस किरदार की मुस्तैदी और बुद्धिमानी लड़कों के तकनीकी दिमाग में तीर की तरह घुस रही थी। जब आधी फिल्म हो चुकी, तब मुझे अचानक ख्याल आया कि पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही। उनके व्यंग्य, फिकरे, सब खामोश थे। शायद उनकी भी 'एक्सपायरी डेट' हो गई थी।

संबंधों की भी 'एक्सपायरी डेट' होती है? एक खास समय के बाद वे मर जाते हैं, क्योंकि रिश्ते बनते हैं भाव से; और भाव एक बहती हुई ऊर्जा है, वह एक जैसी हो नहीं सकती।

अमृत साधना

उर्सुला वॉन डेर लेयेन | अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग

यूक्रेन के साथ यूरोपीय संघ की एकजुटता अटूट है। संघ आज उसकी मदद के लिए चार अरब यूरो से अधिक की राशि जारी कर रहा है। यह न सिर्फ उसके पुनर्निर्माण, बल्कि एक संप्रभु देश के रूप में उसके भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

अनुलोम-विलोम

जेल से सरकार

इस संविधान संशोधन की सख्त जरूरत

भारतीय राजनीति में कभी यह परंपरा थी कि जैसे ही किसी मंत्री या सांसद पर गंभीर आपराधिक आरोप लगते या उनकी गिरफ्तारी होती, तो वह स्वेच्छा से पद छोड़ देता था। लालकृष्ण आडवाणी ने जैन हवाला कांड में नाम आते ही लोकसभा की अपनी सदस्यता त्याग दी थी और स्पष्ट कहा था कि दोषमुक्त होने तक संसद नहीं लौटेंगे। ऐसी परंपराएं राजनीतिक जीवन में नैतिकता को मजबूत करती थीं और जनता में उसके प्रति विश्वास बढ़ाती थीं।

मगर आज स्थिति बदल गई है। अब नेता गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने पर भी पद से चिपके रहते हैं। कुछ तो जेल में रहते हुए भी सरकार चलाने का दावा करते हैं। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण सबके सामने है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि इससे शासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक पेश किया गया है कि केंद्र या राज्यों के मंत्री यदि किसी संगीन मामले में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिनों के लिए जेल जाते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। ऐसा न करने पर वे स्वतः पदमुक्त मान लिए जाएंगे। संविधान सभा ने सोचा था कि कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति ऐसी स्थिति आने पर खुद ही पद छोड़ देगा, इसलिए उसने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। मगर आज की राजनीति में जब नैतिकता बेहद कमजोर पड़ चुकी है, तब संविधान संशोधन अपरिहार्य हो गया है।

फिर भी, विपक्ष, विशेषकर ममता बनर्जी जैसी नेता, इसे 'सुपर आपातकाल' बताकर विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि केंद्र में सत्तासीन दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसा सकता है और उनसे मंत्री पद छीन सकता है। बेशक, यह चिंता पूरी तरह निराधार नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन इस व्यवस्था में सत्ता पक्ष के लिए भी कोई छूट नहीं रखी गई है। यह नियम सब पर समान रूप से लागू होगा। यदि इसे निष्पक्ष भाव से देखें, तो यह लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने और राजनीति में स्वच्छता लाने का मजबूत प्रयास है। हां, इसका उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग न हो और मंत्रियों की गिरफ्तारी के ठोस आधार हों, यानी बिना ठोस सुबूत के उनकी गिरफ्तारी न हो। इस तरह के प्रावधान इसमें जोड़े जा सकते हैं। इसलिए यह विधेयक लोकतंत्र की गरिमा बहाल करने के लिए लाया गया है, हालांकि इसके साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता की गारंटी भी उतनी ही जरूरी है।

मधु बुड़ावनवाला, टिप्पणीकार

विपक्ष के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा

राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए नेताओं को नैतिकता का पर्याय होना चाहिए। यह पूरा देश चाहता है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री (यहां तक कि प्रधानमंत्री भी) 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे पद से हटना होगा। यह विधेयक स्वागतयोग्य है, क्योंकि देश में राजनीति जितनी स्वच्छ होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे की मंशा कितनी पवित्र है? इस बात की क्या गारंटी है कि उक्त बिल पास होकर कानून बन गया, तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा? 2014 के बाद जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनको डर दिखाया गया, यह पूरे देश ने देखा है। महज आरोप लगाने या ईडी-सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लेने मात्र से कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता, पर बिना पुख्ता सुबूत के कुछ खास नेताओं को 30 दिनों से अधिक जेल में रखा गया। साफ है, उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। बेशक, यह विधेयक सही हो, मंशा भी सही हो, लेकिन इसका दुरुपयोग हो सकता है। इससे भारतीय राजनीति शायद ही स्वच्छ और पारदर्शी हो सकेगी।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

'हमें ईडी के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेंगी। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए। इसके लिए ईडी का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है?' सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी 21 जुलाई की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी और एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया था। इस केस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ईडी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां पर उन्हें यह प्रतिकूल टिप्पणी सुननी पड़ी। कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता वाकया हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी हो चुका है। पिछले वर्षों में ईडी के माध्यम से कई सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास हुए और वे सारे प्रयास असफल हो गए। अब एक काला कानून बनाया जा रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन जेल में रह लेता है, तो वह पद से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब किसी को भी फर्जी केस में फंसाया जाएगा और सरकार गिरा दी जाएगी। सवाल न उठे, इसलिए मुख्यमंत्री-मंत्री के साथ प्रधानमंत्री को भी जोड़ दिया गया है। अगर यही सब होना है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? चुनाव, लोकतंत्र, संविधान आदि का दिखावा क्यों किया जा रहा है? जाहिर है, यह विपक्ष को निपटाने और संविधान की कब्र खोदने के लिए लाया गया है।

कृष्णकांत, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संयम ही विपत्ति में ढाल बनता है

स्थानीय निकायों पर निगाह

यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि आवारा कुत्तों की समस्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित अंतरिम फैसले के बाद केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर सक्रियता दिखाती। उसने सभी राज्यों को 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण का जो निर्देश दिया, वह समय की मांग है। केंद्र सरकार ने यह निर्देश देते हुए राज्यों को वित्तीय मदद देने का भी आश्वासन दिया है और हर माह आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट लेने की भी पहल की है। स्पष्ट है कि अब राज्य सरकारों को इस मामले में गंभीरता का परिचय देना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि स्थानीय निकायों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के मामले में स्थानीय निकाय एक बड़ी हद तक अक्षम और असफल ही साबित हुए हैं। इसी कारण इस समस्या ने इतना गंभीर रूप लिया। अपने देश में आवारा कुत्तों के काटने और लोगों के रैबीज से ग्रस्त होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष रैबीज से संक्रमित कुत्तों के काटने के कारण मरने वालों की संख्या 18 से 20 हजार के बीच है और स्पष्ट है कि यह सही संख्या नहीं है, क्योंकि न जाने कितने मामले दर्ज ही नहीं होते। क्या यह सामान्य बात है कि प्रतिवर्ष 18 से 20 हजार लोग रैबीज से ग्रस्त होकर मर जाएं? ध्यान रहे कि इनमें एक बड़ी संख्या बच्चों और किशोरों की होती है।

समझना कठिन है कि आवारा कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश पर कुछ कथित पशु प्रेमी लोग और संगठन असंतोष क्यों व्यक्त कर रहे हैं? असंतोष तो उन्हें व्यक्त करना चाहिए जो इससे चिंतित हैं कि क्या देश भर के नगर निकाय आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण कर पाएंगे? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वे आक्रामक और रैबीज ग्रस्त कुत्तों को आश्रयगृहों में रख पाएंगे? यह एक तथ्य है कि देश के महानगरों तक में पर्याप्त संख्या में आवारा कुत्तों के लिए आश्रयगृह नहीं हैं। यह ठीक है कि अधिकांश स्थानीय निकाय वित्तीय कठिनाइयों से दो चार हैं और संख्याबल के अभाव से भी ग्रस्त हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी समस्या उनकी ओर से अपने हिस्से की किसी भी जिम्मेदारी के निर्वहन में ढिलाई बरतना है। इसी कारण हमारे छोटे-बड़े शहर अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें से एक समस्या आवारा कुत्तों के आतंक की भी है। यदि राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को जवाबदेह नहीं बनाया तो भारत 2030 तक कुत्तों से होने वाले रैबीज के खात्मे के अपने लक्ष्य को पाने में नाकाम ही रहेगा।

अच्छी पहल

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में कई कार्य पहले से चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लगातार नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। स्थानांतरण की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था की गई, जिसका बड़ी संख्या में शिक्षक लाभ उठा रहे हैं। इसके बावजूद अक्सर सूचनाएं आती हैं कि कई विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित नियमानुसार नहीं है। कहीं छात्रों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं तो कुछ विद्यालयों में अधिक छात्र। तब भी शिक्षकों की कमी है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों, छात्र-शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता (विषयवार) का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। यह अगले सप्ताह से शुरू होगा। सर्वे में प्रत्येक विद्यालय में रिक्ति, छात्र-शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या का ब्योरा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो सितंबर तक अपलोड करने कार्य पूरा करना है। इससे अगले चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के पदस्थापन में सुविधा होगी। इस सर्वे से स्पष्ट हो सकेगा कि कहां शिक्षकों की कमी या अधिकता है। उस आधार पर छात्र-शिक्षक का जो निर्धारित अनुपात है, उसका पालन हो सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। यह अति आवश्यक है तभी शैक्षणिक कार्य में संतुलन दिखेगा और शिक्षक भी अनुकूल वातावरण का अनुभव कर सकेंगे।

> सरकारी विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव दिखेगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

क्या करता! प्रखर, ईमानदार लिखकर भीड़ नहीं जुट रही थी इसलिए आपके पोस्टर पर जुझारू, बाहुबली लिखा!

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सर्जियो गोर की राजदूत के रूप में नियुक्ति से भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार होने के आसार हैं?

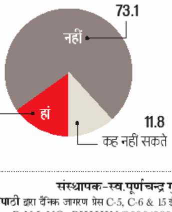

आज का सवाल
क्या मंत्रियों की गिरफ्तारी वाले विधेयक से संबंधित जेपीसी के बहिष्कार से जुड़ा विपक्षी दलों का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सुधार की दिशा में उठे कदम

जीएन वाजपेयी

जीएसटी में सुधारों का आर्थिक प्रभाव कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन की चर्चा अभी तक जारी है। लाल किले की प्राचीर से दिया गया उनका संबोधन ऊर्जावान, प्रेरक और आश्वस्तकारी था। व्यापक विषयों के समावेश वाले इस भाषण में भविष्य की झलक भी दिख रही थी। इस संबोधन में उस नेता की भावनाएं मुखर हो रही थीं, जिसने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं से ओतप्रोत किया है। राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाने वाले उनके संबोधन की गूंज पूंजी बाजार तक सुनाई दी। इससे सेंसेक्स में तेजी और रुपये की स्थिति में मजबूती का रुख दिखा। आर्थिक समृद्धि और किसी राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भू-राजनीतिक तथा ऊर्जा सुरक्षा के साथ गहराई से जुड़ा होता है। मोदी ने अपने सारगर्भित संबोधन में बताया कि ये तीनों सुरक्षा तत्व किस तरह उनके दृष्टिकोण में भारत के भविष्य का तानाबाना बुनेंगे।

आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में महान अर्थशास्त्री जान मेनार्ड कींस ने एनिमल स्पिरिट यानी उत्साही प्रवृत्ति की आवश्यकता रेखांकित की थी। इस उत्साही प्रवृत्ति को कारोबारी सुगमता और जीवन सुगमता से प्रोत्साहन मिलता है। इस दिशा में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधारों की घोषणा महत्वपूर्ण और दूरगामी असर करने वाली रही। जुलाई 2017 में तमाम जटिल करों और अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्र-एक कर जैसी संकल्पना के साथ जीएसटी अस्तित्व में आया। इसे 1991 के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार दिया गया। इसने कर राजस्व बढ़ाने के साथ अनुपालन को बेहतर बनाया। इसके चलते निवेश बढ़ा और एकीकृत बाजार के रूप में भारत का कायाकल्प हुआ। जीडीपी वृद्धि पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारों के बावजूद इसने संघीय सहमति का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि इसमें कायम कुछ विसंगतियां उद्यमों, राजस्व और विभिन्न हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल रही थीं। इसमें टैक्स ढांचे की जटिलता, नियमों और दरों में अक्सर होने वाले परिवर्तन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जुड़े मसले और कुछ मामलों में अनुपालन बोझ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अच्छी बात है कि इन विसंगतियों का संज्ञान लेकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने की पहल हुई है। जीएसटी सुधारों का प्रस्तावित उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना और इसे एक विश्वस्तरीय अप्रत्यक्ष कर संरचना में बदलना है। प्रस्तावित सुधारों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: दरों को तार्किक बनाना और घटाना, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन, अनुपालन बोझ को कम करना और विवादों का समाधान करना। उम्मीद है कि 12 प्रतिशत की 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत वाली श्रेणी में और 28 प्रतिशत वाली 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत वाली श्रेणी में स्थानांतरित हो जाएंगी। नई दरें न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे विकसित बाजारों के अनुरूप ही होंगी। इन देशों में जीएसटी दरें 5 से 15 प्रतिशत के बीच हैं।

अवधेश राजपूत

दरों को तार्किक बनाने से विसंगतियों पर भी अंकुश लगेगा। इससे उद्योग की लागत में बढ़ोतरी, मूल्य श्रृंखला में विसंगतियां और इनपुट क्रेडिट का संचय होता रहा। वर्गीकरण की जटिलता को समाप्त करने से अनुपालन में सुधार होगा एवं कर संरचना और मजबूत बनेगी। आवश्यक और आकांक्षी वस्तुओं पर कर की दर में कमी आम आदमी, एमएसएमई, किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ ही खपत को बढ़ावा देगी और अंततः जीडीपी वृद्धि में योगदान करेगी। कुछ क्षेत्रों में इनपुट क्रेडिट की विसंगतियां जैसे कच्चे माल और तैयार माल के लिए अलग-अलग दरों को तार्किक बनाना एवं उनका स्पष्टीकरण भी स्थिति को सुधारेगा। प्रौद्योगिकी संचालित समाधान जैसे निर्बाध पंजीकरण, पूर्व में भरे हुए रिटर्न और स्वचालित रिफंड अनुपालन में आसानी प्रदान करेंगे और प्रशासन की लागत को काफी घटाने का काम करेंगे। त्वरित रिफंड कार्यशील पूंजी में वृद्धि करेगा, ब्याज लागत को कम करेगा और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।

जीएसटी के आठ वर्षों के दौरान कई विवाद भी सामने आए। खासतौर से वर्गीकरण को लेकर ऐसा कई बार दिखा। उन विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने से जटिलता, अनिश्चितता को कम किया जाएगा और भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुगम बनाने और भरोसा बढ़ाने में सहायक होगा।

विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने प्रस्तावित दरों में परिवर्तनों से राजस्व संग्रह पर प्रभावों का अपना आकलन दिया है। इस कड़ी में एचएसबीसी बैंक ने 1.43 लाख करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया है तो एसबीआइ के अनुसार यह 85,000 करोड़ रुपये है, जिसमें केवल 45000 करोड़ रुपये वर्तमान वर्ष के लिए है। एसबीआइ की ही रिपोर्ट में इससे खपत में 1.98 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है और आयकर दरों में कमी के साथ मिलकर इसे 5.31 लाख करोड़ रुपये आंका है, जो जीडीपी का 1.6 प्रतिशत तक हो सकता है। इसका दूसरा पहलू यही है कि खपत में वृद्धि कर राजस्व में वृद्धि करेगी और समय के साथ दरों में कमी और उनके तर्कसंगत के कारण संभावित अनुमानित क्षति की समय के साथ भरपाई होती जाएगी।

जीएसटी में सुधारों का आर्थिक प्रभाव 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, उद्यमों को औपचारिक स्वरूप अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अनुपालन में सुधार करेगा, कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएगा। इससे जहां महंगाई की स्थिति सुधरेगी, वहीं जीडीपी में 0.20 से 0.22 प्रतिशत का योगदान बढ़ेगा। हालांकि इस भली मंशा वाले सुधार की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर ही निर्भर होगी।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

श्रम बल में बढ़े महिलाओं की हिस्सेदारी

अनुरोध ललित जैन

भारत का आर्थिक भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि आधी आबादी की क्षमता को वह कितनी गंभीरता से लेता है

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ। यह टैरिफ भारत से अमेरिका को होने वाले 40 अरब डालर के व्यापार को निशाना बनाता है। इससे देश की जीडीपी में लगभग एक प्रतिशत की कमी आ सकती है। यह टैरिफ कपड़ा और रत्न जैसे उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है, जहां उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। लगभग 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा और रत्न जैसे क्षेत्र 50 प्रतिशत तक के निर्यात में गिरावट का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और अफ्रीका, यूरोप जैसे क्षेत्रों में निर्यात विविधीकरण के कारण अमेरिकी टैरिफ की चुनौती का सामना करने में सक्षम दिख रहा, जबकि भारत इस मामले में असुरक्षित है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं-एक तो भारत का 18 प्रतिशत निर्यात अमेरिका पर निर्भर है और दूसरा, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पाद 30-35 प्रतिशत तक महंगे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। ऐसे संकट के समय में महात्मा गांधी के शब्द प्रासंगिक लगते हैं, 'किसी राष्ट्र की ताकत उसकी महिलाओं में निहित होती है।'' ऐसे में आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर हम भी इस चुनौती से पार पा सकते हैं।

भारत में महिला श्रम बल की बेहद कम भागीदारी है, जो 37 प्रतिशत से 41.7 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। जबकि वैश्विक औसत और चीन की दर लगभग 60 प्रतिशत है। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इस बात का प्रमाण हैं कि जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो समावेशी विकास संभव हो पाता है। जापान ने 'वुमेनामिक्स' रणनीति अपनाकर महिला भागीदारी को 74 प्रतिशत तक पहुंचाया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी महिलाओं की भागीदारी से मिली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस लैंगिक अंतर को समाप्त करने से भारत 2025 तक अपनी जीडीपी में 27 प्रतिशत यानी 770 अरब डालर की वृद्धि कर सकता है। 2047 तक यह आंकड़ा 14 लाख करोड़ डालर तक पहुंच सकता है, पर इसके रास्ते में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, नीतिगत निष्क्रियता और रोजगार के लिए प्रणालीगत बाधाएं आड़े आ सकती हैं। आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी और अब टैरिफ का खतरा-देश की आर्थिक क्षमता को और कमजोर कर सकता है।

ट्रंप टैरिफ ने महिला कामगारों की बढ़ाई चुनौती ● फाइल

भारत इस समय अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के शिखर पर है। यह एक ऐसा दौर है जब काम करने वाली आबादी आश्रितों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अवसर सीमित समय के लिए है और 2045 तक समाप्त हो जाएगा। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इसी अवसर का लाभ उठाकर विकसित हुए हैं। भारत को इस क्षणिक अवसर को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। इसका एकमात्र रास्ता महिलाओं को पूरी तरह से कार्यबल में शामिल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन यह ज्यादातर अवैतनिक और पारिवारिक कार्यों तक सीमित है, जिसकी उत्पादकता कम है। दूसरी ओर, शहरी भारत में महिला श्रम बल भागीदारी स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता की कमी और अवैतनिक देखभाल कार्य का भारी बोझ महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों से दूर करता है।

आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी विकास पर नकारात्मक असर डाल रही है। इसे बदलना होगा। कर्नाटक की 'शक्ति' योजना, जो महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा प्रदान करती है, एक बेहतरीन उदाहरण है। 2023 में इसके लांच के बाद से महिला यात्रियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना ने महिलाओं की काम, शिक्षा और उद्यम के लिए गतिशीलता को बढ़ाया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इससे महिलाओं की नौकरी तक बेहतर पहुंच बनी है, पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हुई है और उनकी स्वायत्तता बढ़ी है। इसी तरह राजस्थान की 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' ने चार करोड़ से अधिक मानव-दिवस का काम सृजित किया है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता, पौधरोपण और देखभाल जैसे कार्यों ने उन महिलाओं को भी कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है, जो पहले घरेलू जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाती थीं। 'अर्बन कंपनी' जैसे अग्रणी गिग प्लेटफार्म ने 45,000 से अधिक महिला सेवा प्रदाताओं को जोड़ा है, जो प्रतिमाह 18,000 से 25,000 रुपये तक कमाती हैं। इन महिलाओं को दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। यह दर्शाता है कि गिग कार्य माडल विशेष रूप से अर्ध-कुशल शहरी महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का माध्यम बन सकता है।

ट्रंप का टैरिफ एक चेतावनी है, लेकिन यह एक अवसर भी है। एक ऐसा अवसर जो हमें अपनी महिलाओं की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी आधी आबादी की क्षमता को कितनी गंभीरता से लेता है।

(लेखक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

कर्म

संसार में कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें नैतिक और अनैतिक कर्मों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनैतिक कर्म पाप और अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन अनैतिक कर्मों के भी दो प्रकार हैं- पहला, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को न निभाते हुए पाप कर्मों को मूकदर्शक बनकर देखना और दूसरा, अपने स्वार्थ या इंद्रिय पूर्ति के लिए दूसरों की संपत्ति या अधिकारों को छीनने के लिए शक्ति का प्रयोग करना।

जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कोई मनुष्य अपने कर्मों की विवेचना करता है। जब वह यह अनुभव करता है कि उसने स्वार्थ पूर्ति और इंद्रियों की तृप्ति के लिए पाप किया है, तो उसके अंदर अपराध बोध जागृत होता है। इसी अपराध बोध के साथ उसका अंत समय आ जाता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जीवन के आखिरी क्षणों में प्राणी की जो मनोदशा होती है, उसी के अनुसार उसे अच्छे या बुरे का अनुभव होता है और प्राणी को उसके अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है।

मनुष्य योनि को संसार में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि केवल इसी में प्राणी को विवेक प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए शुभ या अच्छे कर्म कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप वह भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जटायू है, जिसने पक्षी होते हुए भी सीताहरण जैसे पाप के विरुद्ध आवाज उठाई और रावण को रोकने के लिए युद्ध के लिए ललकारा, जिसमें उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके लिए भगवान श्रीराम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। वहीं द्रौपदी के चीरहरण जैसे पाप कर्म को मूकदर्शक बनकर देखने के कारण भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में छह महीने तक बाणों की शैया पर पड़े रहे। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए।

कर्नल शिवदानसिंह

पाठकनामा
pathaknama@pat.jagran.com

आनलाइन मनी गेमिंग पर रोक

''एक बुरे धंधे पर लगाम'' शीर्षक से प्रकाशित संजय गुप्त का आलेख पढ़कर मन को संतोष हुआ। मोदी सरकार ने आनलाइन पैसों वाले गेम पर रोक लगाकर सचमुच जनता का बड़ा भला किया है। यह धंधा खासकर युवाओं और छोटे बच्चों तक को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। पढ़ाई-लिखाई और करियर बिगड़ने लगे थे, कई परिवार कर्ज में डूब गए और मानसिक तनाव बढ़ गया था। कई बच्चे तो चोरी-झपट तक करने लगे थे। यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि कालाधंधा बन चुका था। अब इस कानून से ऐसे धंधों पर लगाम लगेगी, मनी लांड्रिंग और आर्थिक नुकसान रुकेंगे और समाज में सुधार होगा। सच तो यह है कि इस बुराई पर बहुत पहले रोक लग जानी चाहिए थी, पर देर से ही सही, अब इसका अंत हुआ है। जरूरी है कि सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करे, ताकि कोई रास्ता बचकर फिर से यह धंधा न पनप पाए। यही जनता की सच्ची जीत होगी। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कंपनियां कोई चोर रास्ता खोजकर अपने बुरे धंधे चालू रखती हैं। अच्छा होता कि लेखक यह बताते कि कौशल वाले आनलाइन गेम को देश में कैसे बढ़ावा दिया जाए।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

जुआ बुरी बला

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'एक बुरे धंधे पर लगाम' पढ़ा। सदियों से जुआ खेला जा रहा है। यह बुरी बला है, इसके विनाशकारी परिणाम से सभी परिचित हैं, इसके बावजूद देश का युवा वर्ग तेजी से जुए की गिरफ्त में जा रहा है। महाभारत का युद्ध भी जुए की वजह से हुआ था। जुए की लत नशे के समान है। इंटरनेट के दौर में आनलाइन जुए का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। आनलाइन जुए में कई बार बच्चे माता-पिता का बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। बार-बार जुए में हारने से कई लोग अवसाद का शिकार हो गए हैं, कुछ लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से चलने वाले इस अवैध कारोबार ने युवाओं और आम नागरिकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। घर बैठे दांव लगाने की सुविधा ने लोगों को नशे की तरह जुए की लत लगा दी है। इसकी वजह से समाज में आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह और अपराध जैसी समस्याएं बढ़ रही थीं। आनलाइन जुए से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन सरकार ने युवाओं को आनलाइन जुए की लत से बचाने के लिए नया कानून लाया है। नए कानून के बनने के उपरांत कई आनलाइन कंपनियों ने अपना धंधा समेटना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम सामाजिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करेगा एवं पारिवारिक व आर्थिक स्थिरता भी लाएगा। इस कानून के द्वारा अपराधों में कमी आएगी और लाखों परिवार कर्ज व बर्बादी से बच सकेंगे और देश में खुशहाली आएगी। युवाओं में जुए की लत लगती है और वह भटक जाते हैं। कई बार पैसा गंवाने की वजह से या तो खुदकुशी कर लेते हैं या अवसाद में चले जाते हैं। इसलिए इस पर रोक जरूरी थी।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी।

युद्धस्तर पर हो सुधार

टेंपो व ट्रक की टक्कर हो या बाइक की आपस में टक्कर अथवा अन्य हादसे के बाद का वीभत्स दृश्य दिल दहला देता है। फिर भी हमारी यातायात व्यवस्था सुधारी नहीं जा रही। जबकि सड़क निर्माण व यातायात से जुड़ी खामियां जवाबदेह पदाधिकारियों को पता है। शायद ही कोई दिन होता होगा, जब सड़क दुर्घटना की खबर समाचार पत्रों की सुर्खियों नहीं बनती होगी। सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान अधूरे रह जाते हैं। कभी-कभी दुर्घटना में घायल अथवा मारे गए व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी जान से हाथ धोना पड़ता है। पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है। अंतरिक्ष तक की यात्रा सुरक्षित हो गई है, लेकिन हम सड़क पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। ऐसा कब तक चलता रहेगा। सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए बीच-बीच में प्रशासनिक पहल होती है, पर यह शत प्रतिशत कारगर नहीं पाती। क्षतिग्रस्त सड़क की समय पर मरम्मत करने की आवश्यकता हो या वाहनों की संख्या के अनुरूप सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो अथवा जर्जर सवारी वाहनों को सड़क पर चलने से रोकने की बात हो, इनपर युद्धस्तर पर कार्य व सुधार करने की जरूरत है। कोई सड़क बेकारण नहीं होता। सड़कें बेहतर हों, पर चालकों को भी रफ्तार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

X पोस्ट

देर-सबेर भारत और अमेरिका में व्यापार समझौता हो जाएगा। यह होना ही है, लेकिन अमेरिका के प्रति भारतीय भरोसा 1998 वाले स्तर पर चला गया है। ट्रंप और उनके प्यादे दशकों में मजबूत हुए संबंधों को क्षति पहुंचाने पर आमादा हैं। रक्षा सौदे भी इसमें भरोसा नहीं बढ़ा पाएंगे। कोई नई राह तलाशनी होगी।

शिव अरूर@ShivAroor

लोग यह गलत सोच रहे हैं कि अभी ट्रंप को करीब साढ़े तीन साल और झेलना होगा। अगले साल नवंबर में कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसमें अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी का मामूली बहुमत खिसक सकता है। यानी करीब 14 महीनों में ही ट्रंप की नीतियों पर अंकुश लगने की स्थिति बन सकती है।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

भारतीय क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा का योगदान केवल आंकड़ों से ही नहीं आंका जा सकता। एक दशक से भी अधिक तक उन्होंने अपने प्रदर्शन और जज्बे से भारतीय टीम को मजबूती प्रदान की। उनको भविष्य के लिए शुभकामना।

अयाज मेमन@cricketwallah

जनपथ

नेता-जज-इंजीनियर सब बन रहे कुबेर,
सबके घर में दिख रहे हैं नोटों के ढेर।
हैं नोटों के ढेर और सोने की खानें,
सोचो, हम भगवान इन्हीं लोगों को मानें!
नोटों के भंडार जमा जो है कर लेता,
उसको ही हम लोग मानते बड़का नेता!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 134

****

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

कल्पमेधा

ईर्ष्या से सावधान रहें, क्योंकि यह वह हरी आंखों वाला दैत्य है जो उसी शरीर का तिरस्कार करता है और धोखा देता है, जिस पर वह पलता है।
– विलियम शेक्सपियर

सहयोग की कड़ियां

चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 31 अगस्त से एक सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के बीस से अधिक देशों के नेता तथा दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से भारत, चीन और ब्राजील समेत कई देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद इस सम्मेलन को कई मायनों में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे अमेरिकी नीति के बरक्स लामबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस तो पहले से ही भारत के साथ है, लेकिन अब शुल्क के मुद्दे पर चीन भी सहयोग की मुद्रा में है। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मेलन से इतर चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात होगी और इस दौरान द्विपक्षीय मसलों के अलावा शुल्क के मुद्दे पर भी एकजुट होने को लेकर चर्चा हो सकती है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो इससे अमेरिका के उन प्रयासों को झटका लगेगा, जिनके तहत वह दूसरे देशों पर अपनी मनमानी व्यापार नीतियां थोपकर निजी हित साधने का मंसूबा पाले हुए है।

एससीओ एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मकसद सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन के सम्मेलन समय-समय पर होते रहते हैं, लेकिन दुनिया में बदल रही भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस बार के सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरान तीन बड़ी शक्तियां रूस, चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर होंगे। दुनिया की राजनीति में यह बदलाव अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति और ब्रिक्स को लेकर उनके रुख के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और संगठन के विकास की नई रणनीतियों का खाका तैयार किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि ये तीनों अमेरिका से अलग-अलग स्तर पर असहमत हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं।

हालांकि, यह बात छिपी नहीं है कि भारत और चीन के बीच पारंपरिक रूप से संबंध ज्यादा प्रगाढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिकी शुल्क के एलान के बाद से दोनों देशों के बीच नजदीकियां नजर आने लगी है। शुल्क के मुद्दे पर चीन की ओर से भारत का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल में चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान कई मसलों पर सार्थक बातचीत हुई। यानी अब भारत-चीन रिश्ते, तनाव से संवाद की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2020 के गलवान विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भारत-चीन संबंधों में एक नई शुरुआत की उम्मीद है। उधर, रूस भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि भारत पर शुल्क को लेकर अमेरिकी दबाव पूरी तरह अनुचित है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एससीओ सम्मेलन में तीनों देशों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीक पर नए समझौते होने की भी संभावना है। यह व्यापार के लिए नए बाजार सुनिश्चित करने की कवायद हो सकती है, जो निश्चित रूप से अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करने की दिशा में बढ़ा कदम होगा।

नाहक वसूली

शहरों-महानगरों में महंगे रेस्तरां में भोजन के लिए जाने वाले ज्यादातर लोग शायद इस बात पर बहुत गौर नहीं करते कि वे कितने पैसे चुका रहे हैं। यही वजह है कि रेस्तरां में खाने-पीने के कुल खर्च के अलावा भी अलग से सेवा शुल्क जोड़ दिया जाता है। या तो लोग इसके औचित्य से अनजान रहते हैं या फिर उसे चुकाने में उन्हें कोई उज्र नहीं होता। जबकि यह सीधे-सीधे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है और किसी वस्तु की निर्धारित से ज्यादा कीमत वसूलने का अवांछित प्रयास है। इसे कानूनन भी गलत माना जाना चाहिए। हालांकि इस तरह अनधिकृत रूप से ज्यादा कीमत वसूलने के मुद्दे पर पहले भी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि रेस्तरां अपने बिल में अलग से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते। अदालत ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को सबसे अहम बताया था। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ग्राहकों से नाहक पैसे वसूलने के मसले पर रेस्तरां मालिक क्यों अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं।

अब एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस्तरां एसोसिएशन से यह पूछा है कि जब आप खाने-पीने की चीजों पर पहले से ही अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा शुल्क वसूल रहे हैं, तब फिर अलग से सेवा शुल्क क्यों ले रहे हैं। यह जगजाहिर हकीकत है कि किसी भी महंगे रेस्तरां में अगर कोई व्यक्ति भोजन करने जाता है तो उसे वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थों के लिए वाजिब से काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अतिरेक तब हो जाता है, जब रेस्तरां की ओर से न केवल सामान्य कीमतों से अधिक मूल्य पर वस्तुएं दी जाती हैं, बल्कि खाना परोसने के नाम पर कुल बिल में अलग से सेवा शुल्क भी जोड़ दिया जाता है। सवाल है कि क्या ग्राहकों के सामने यह स्पष्ट किया जाता है कि रेस्तरां में उनकी सीट पर खाने-पीने का सामान पहुंचाने के लिए अलग से पैसे जोड़े जाएंगे। यही नहीं, आमतौर पर बिल चुकाने के बाद रेस्तरां या होटल के बैरे को बख्शीश देना भी एक रिवायत-सी बन चुकी है। इस तरह, ऐसे होटलों या रेस्तरां में कुल खर्च के ऊपर भी कई बार खासी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसी वसूली पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस्तरां एसोसिएशन के रुख पर वाजिब सवाल उठाया है।

प्रदूषण से संकट में समुद्री जीवन

एक तरफ अंधाधुंध तरीके से समुद्री जीवों का शिकार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर समुद्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रहा है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

समुद्र के बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक आगाह करते रहे हैं। मगर मनुष्य के निजी स्वार्थ, लापरवाही और अनदेखी करने की प्रवृत्ति के कारण समुद्री जीवन का दम घुट रहा है। दुनिया के तीन अरब से अधिक लोग अपनी गुजर-बसर के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर हैं, लेकिन इस संपदा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गैरकानूनी तरीके से मछलियां पकड़ने, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री जैव विविधता पर संकट गहराने लगा है। ऐसे में महासागरों के साथ ही वैश्विक आबादी के भविष्य को बचाने के लिए अब गंभीरता से प्रयास करना जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकारों, व्यावसायिक संरक्षकों और मछुआरों के लिए प्राथमिकताएं तय कर दिए जाने के बावजूद मुनाफे की होड़ में कोई भी अपने दायित्व को समझने और उस पर पूरी तरह अमल करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ अंधाधुंध तरीके से समुद्री जीवों का शिकार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर समुद्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रहा है।

पेरिस समझौते में बढ़ते वैश्विक औसत तापमान में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद भू-मध्यसागर का तापमान बढ़ने की गति वैश्विक औसत से बीस फीसद अधिक हो चुकी है। महासागरों की सेहत बचाने के प्रयासों को वास्तव में बल मिलता है या फिर केवल संकल्पों का पुलिंदा, यह देशों और समुदायों द्वारा पेश किए जाने वाले उपायों और समाधानों पर निर्भर है। महासागरों के उपयोग में बड़ा बदलाव केवल मछलियां पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तरीकों से भी जुड़ा हुआ है। इस समय साठ फीसद से अधिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का शिकार है। एक आकलन के मुताबिक, वर्ष 2040 तक प्लास्टिक का प्रदूषण वर्तमान स्थिति से करीब दोगुना हो जाएगा। हर वर्ष महासागरों में जाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2.3 से 3.7 करोड़ टन तक हो जाएगी।

'माइक्रोप्लास्टिक' आज जल-जीवन ही नहीं, हमारे भोजनचक्र में भी शामिल हो गया है। दुनियाभर के वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसा प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जैव अपघटन मुमकिन हो। यानी जो सड़-गल कर प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाए। तोक्यो विश्वविद्यालय के 'रिकेन सेंटर फार इमर्जेंट मैटर' के शोधकर्ताओं ने एक नया पदार्थ तैयार किया है, जो बहुत जल्दी टूट जाता है और अपने पीछे कोई तलछट या अपशिष्ट नहीं छोड़ता। इससे पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक प्रदूषण को घटाने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने अभी इस पदार्थ को व्यापारिक तौर पर पेश करने की योजना नहीं बनाई है। यह नया पदार्थ उतना ही मजबूत है, जितना कि प्लास्टिक, लेकिन जब इसे नमक के संपर्क में लाया जाता है तो यह अपने मूल घटकों में तुरंत टूट जाता है। उन घटकों को फिर प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले जीवाणु खत्म कर देते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में हानिकारक 'माइक्रोप्लास्टिक' नहीं बनता है। वैश्विक संगठन वर्ष 2030 तक महासागरों के तीस फीसद हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक बार इस्तेमाल में लाए जाने

वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध ढंग से हटाने और पुनर्चक्रण में तकनीकी प्रगति अब जरूरी पहलू हो गया है। खास जोर महत्त्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं के साथ समुद्रों में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई पर होना चाहिए, जो पेरिस जलवायु समझौते के 1.5 डिग्री लक्ष्य के अनुरूप हो। विश्वभर में जैसे-जैसे

> **वैश्विक जनजीवन को पोषित करने में महासागरों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वे जलवायु आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के प्रयासों को गति देने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक संसाधनों का अभाव है। एक आकलन के मुताबिक, महासागरों के संरक्षण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए सालाना करीब 175 अरब डालर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ दस अरब डालर ही मुहैया हो पा रहे हैं। दूसरी ओर, हर वर्ष करीब 1.2 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में समा जाता है।**

प्रवाल भित्तियों का क्षरण हो रहा है, वैसे ही मछलियों के भंडार दरक रहे हैं और समुद्री तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश और समुद्री संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से महासागरों को लेकर अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। अप्रैल 2025 में समुद्री सतह का तापमान अपने दूसरे सबसे ऊंचे स्तर को छू गया था। कैरीबियाई, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में यह देखा गया है कि चिंताजनक रफ्तार से बड़े पैमाने पर मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंच रहा है। वे सफेद पड़ती जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवों की करीब पच्चीस फीसद प्रजातियों को पोषित करती हैं।

ऐसे में पर्यटन तथा मछुआरा समुदाय के कारोबार ने नुकसान ही पहुंचाया है। इतना ही नहीं, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण निकलने वाले अत्यधिक ताप का करीब नब्बे फीसद हिस्सा महासागर ही अवशोषित करते हैं। यह मात्रा अब अपनी सीमाओं को छू रही है। इसी कारण कुछ वर्ष पूर्व विश्व व्यापार संगठन को अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने पर लगाम लगाने के लिए एक समझौते के तहत सबसिडी पर रोक लगानी पड़ी थी। लंबे गतिरोध के बाद सदस्य देशों के बीच एक संधि पारित की गई, ताकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री जीवन को संरक्षित किया जा सके, लेकिन समुद्र विज्ञानियों का मानना है कि केवल कागजी नीतियों से पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उपजे इस जोखिम को दूर नहीं किया जा सकता है। इन नीतियों पर प्रभावी तरीके से अमल करने की जरूरत है।

वैश्विक जनजीवन को पोषित करने में महासागरों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वे जलवायु आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के प्रयासों को गति देने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक संसाधनों का अभाव है। एक आकलन के मुताबिक, महासागरों के संरक्षण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए सालाना करीब 175 अरब डालर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ दस अरब डालर ही मुहैया हो पा रहे हैं। हर वर्ष करीब 1.2 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है। वैश्विक मछली भंडारण वर्ष 1970 में अपने सुरक्षित जैविक स्तर का 90 फीसद था, जो 2021 में घट कर 62 फीसद रह गया है। वर्ष 2017 के प्रथम महासागर सम्मेलन के बाद से अब तक हजारों स्वैच्छिक संकल्प व्यक्त किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजे ढाक के तीन पात ही हैं। जैव विविधता संरक्षण पर वर्ष 2022 में हुए समझौते में वर्ष 2030 तक कम से कम तीस फीसद समुद्री और पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर जोर दिया गया था। अब जरूरत है इस दिशा में प्रभावी तरीके से प्रयास करने और लक्ष्य हासिल करने की।

ग्यारह जून 2025 को फ्रांस में हुए जलवायु और पर्यावरण पर केंद्रित तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में एक आंकड़े ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसमें कहा गया कि विश्व के कुल मछली भंडार का पैंतीस फीसद हिस्सा जिन तौर-तरीकों से पकड़ा जा रहा है, वे ठीक नहीं हैं। इस वजह से समुद्रों में मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट जारी है। अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने, गहराता जलवायु संकट और समुद्री संसाधनों के कुप्रबंधन से महासागरों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। एक अध्ययन में 2,570 समुद्री मछली भंडारों पर केंद्रित डेटा विश्लेषण में बताया गया है कि कुल भंडारण में से एक तिहाई से ज्यादा मछलियों का शिकार किया जा रहा है। ऐसे में अब दुनिया भर में मत्स्य नीतियों पर नए सिरे से पुनर्विचार की जरूरत है, ताकि वर्ष 2030 तक 30 फीसद महासागरीय क्षेत्र और पृथ्वी पर जलीय जीवों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

कृतज्ञता का संबल

दुनिया मेरे आगे

रजनीश जैन

आभार या कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो मानव जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। यह केवल एक शब्द या औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जो हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को समृद्ध करती है। आभार वह दृष्टिकोण है जो हमें हमारे जीवन में मौजूद सकारात्मकता को देखने और उसकी कद्र करने की प्रेरणा देता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों और समुदाय को भी मजबूत करता है। आभार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच हम अक्सर नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं। आभार का अभ्यास हमें उन छोटी-छोटी चीजों की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक हैं। उदाहरण के लिए, सुबह की ताजा हवा, परिवार का साथ या एक गर्म भोजन- ये साधारण चीजें हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव करा सकती हैं।

वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आभार का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं, वे अवसाद के लक्षणों से कम प्रभावित होते हैं। आभार पत्रिका लिखना, जिसमें हम हर दिन उन चीजों को नोट करते हैं, जिनके लिए हम आभारी हैं। यह एक प्रभावी अभ्यास है जो हमारे मन को सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण देता है।

> **आभार हमें आत्म-विकास के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों की कद्र करते हैं, तो अपने लक्ष्यों की ओर ज्यादा प्रेरित और केंद्रित होते हैं। आभार सिखाता है कि हम जो हासिल करते हैं, वह सिर्फ मेहनत का फल नहीं, बल्कि उसमें दूसरों की मदद का भी योगदान होता है।**

आभारी लोग तनाव के कम स्तर का अनुभव करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तनाव हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और नींद की समस्याओं का कारण बन सकता है। आभार का अभ्यास करने से तनाव हार्मोन, जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। इससे हमारा हृदय स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा, आभारी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। वे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने की ओर अधिक ध्यान देते हैं। दरअसल, आभार हमें अपने शरीर और जीवन के प्रति अधिक सम्मान और देखभाल का भाव सिखाता है।

यह हमारे सामाजिक संबंधों को गहरा और मजबूत करता है। जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह न केवल उस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भीतर से संतुष्टि प्रदान करता है। एक साधारण 'धन्यवाद' कहना या किसी की मदद की सराहना करना रिश्तों में विश्वास और निकटता को बढ़ाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से, आभार एक ऐसी शक्ति है जो समुदायों को जोड़ती है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है।

जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों की कद्र करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रेरित और केंद्रित होते हैं। आभार हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह केवल हमारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। यह हमें विनम्र बनाता है और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करता है। आभारी व्यक्ति अधिक लचीले होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता ढूंढ़ लेते हैं, जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।

भारतीय संस्कृति में आभार का विशेष महत्त्व है। हमारी परंपराओं में प्रकृति, गुरु, माता-पिता और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना एक अभिन्न हिस्सा रहा है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि हमारा जीवन केवल हमारी उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े ताने-बाने का हिस्सा है। आभार का यह भाव हमें अपने अहंकार को कम करने और जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। आध्यात्मिक स्तर पर, आभार हमें अपने भीतर शांति और संतुष्टि का अनुभव भी कराता है। यह हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन एक उपहार है और हमें इसे पूरे उत्साह एवं कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए।

आभार को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जिनके लिए हम आभारी हैं। इसे एक डायरी में लिखना और भी प्रभावी हो सकता है। दूसरा, अपने आसपास के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें- चाहे वह छोटी-सी मदद के लिए हो या उनके निरंतर समर्थन के लिए। इसके अलावा, नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता ढूंढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन, अगर कोई योजना असफल हो जाती है, तो इसके पीछे छिपे सबक के लिए आभारी रहें। यह दृष्टिकोण जीवन की हर स्थिति में आभार का भाव बनाए रखने में मदद करेगा।

आभार एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को हर स्तर पर समृद्ध करती है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, और हमें आत्म-विकास और आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। आभार का अभ्यास न केवल हमें खुशहाल बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। भारतीय संस्कृति में आभार का महत्त्व सदियों से चला आ रहा है। आधुनिक युग में भी यह उतना ही प्रासंगिक है। हमें अपने जीवन में आभार को अपनाना और इसे एक आदत बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन और अधिक सुखमय और अर्थपूर्ण बन सके।

ऊर्जा के विकल्प

आधुनिकता और भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में मनुष्यों ने प्रकृति को नजरअंदाज कर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अगर सरकार और समाज सामूहिक तौर पर पहल करें, तो आधुनिक विकास के साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। अक्षय ऊर्जा का मतलब समझना जरूरी है। इस ऊर्जा को तैयार करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, वह पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। इसमें वह ऊर्जा शामिल है, जो प्रदूषण नहीं फैलाती है। उसके स्रोत का क्षय नहीं होता। सौर एवं पवन ऊर्जा, जलविद्युत उर्जा, ज्वार-भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस और जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा इनके कुछ उदाहरण हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकारें अक्षय ऊर्जा के प्रति गंभीरता से काम करें, तो हमारा भारत अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। जर्मनी के लोग बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत हैं। वहां के होटलों, विद्यालयों, अस्पतालों में सोलर पैनल से बिजली प्राप्त की जा रही है। इससे बिजली बिल में कटौती होती है, दूसरा पर्यावरण पर भी प्रभाव नहीं पड़ता।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

शुचिता की चिंता

एक दौर में राजनीति सेवा का पर्याय थी, लेकिन आज राजनीति पद और धन प्राप्त करने का जरिया बन गई है। पूर्व में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद लोकतंत्र की गरिमा और शुचिता बनाए रखने के लिए नेता और मंत्री त्यागपत्र दे देते थे। हमारे सामने ऐसे नेताओं के उदाहरण हैं। कई नेताओं ने आरोप लगने के बाद जेल जाने से पहले त्यागपत्र दिया। मगर अब अमूमन ऐसा नहीं होता है, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है और लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इस तरह की घटनाओं के दौरान संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता को शिद्दत से महसूस किया गया, ताकि कोई भी नेता जेल जाने के बाद संवैधानिक पद पर आसीन नहीं रहे। राजनीति की गरिमा बनाए रखना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। संसद में लाया गया इससे संबंधित संशोधन विधेयक लोकतंत्र की शुचिता के लिए उठाया गया सकारात्मक कदम है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

सुरक्षा में सेंध

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन शिकायत कार्यक्रम के दौरान हुए हमले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिरकार उनकी कड़ी सुरक्षा में सेंध कैसे लगी? इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा एजंसियां क्या कर रही हैं? जब एक मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है, तो आम आदमी की हिफाजत कैसे होगी। याद रखना चाहिए कि इस देश में कभी मंत्री, तो कभी मुख्यमंत्री और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री भी इस प्रकार के हादसे के शिकार हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा तंत्र की तैयारी में कमी और लापरवाही ही सामने आती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री को मिली सुरक्षा में कहां कमी रह गई थी, यह भी जांच का विषय है। आरोपी मुख्यमंत्री कार्यालय की रेकी करता रहा और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। यह सुरक्षा में खामी नहीं, तो और क्या है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, मगर इस मामले से उसे सबक लेना चाहिए।

– मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली

बदलती मानसिकता

समय और तकनीक ने इंसानों के सोचने-समझने के तरीके को बहुत प्रभावित किया है। पहले लोग रिश्तों, आपसी समझ और संस्कारों को महत्त्व देते थे, वहीं आज का इंसान भौतिक सुख-सुविधाओं और अपने हितों में उलझा नजर आता है। सोशल मीडिया और आधुनिक जीवनशैली ने सोच को आधुनिक तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही सहनशीलता और संवेदनशीलता में भी कमी आई है। मानसिकता में बदलाव का सबसे बड़ा असर युवाओं में देखा जा सकता है। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन तुलना किए जाने से तनाव का शिकार हो जाते हैं। समाज में दिखावे की संस्कृति भी बढ़ रही है, जहां व्यक्ति अपनी असली पहचान की जगह दूसरों के सामने 'बेहतर' दिखने की होड़ में रहता है। इससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं।

– रागिनी कुशवाहा, सिंगरौली, मप्र

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 25 अगस्त 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

लोकतंत्र में नए नारे की धूम

वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा इस समय पूरे बिहार में धूम मचा चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के सारे दलों की वोटर अधिकार यात्रा को इस समय बिहार में भारी समर्थन मिल रहा है। यात्राएं हमेशा ही नयी मंजिल पर ले जाती हैं, फिर चाहे वह राजनैतिक यात्रा ही क्यों न हो। पाठक जानते हैं कि राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है और अब एक तरह से दिन और दूरी के हिसाब से ये उनकी तीसरी बड़ी यात्रा है। पिछले साल जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, तब भी राहुल गांधी ने संक्षिप्त यात्रा निकाली थी, हालांकि उसका कोई लाभ नहीं मिला। हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी महायुति के सामने हार गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष का आरोप है कि इन चुनावों में चोरी हुई है। लगभग साल भर से यही आरोप लग रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इन पर इंकार करते हुए उल्टा विपक्ष पर ही सवाल उठाए। लेकिन विपक्ष के इरादे इन सवालों से बदले नहीं और अब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने ऐलान कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, हम वोट चोरी होने नहीं देंगे।

इस वोट चोरी के इल्जाम के पीछे मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है, जिसमें भाजपा के साथ-साथ चुनाव आयोग भी मतदाता सूची शुद्धिकरण कह रहा है। लेकिन किसी कवायद में संस्कृतनिष्ठ शब्द जोड़ देने मात्र से वह सही नहीं हो सकती। कोई भी बात तभी सही होती है, जब उसे करने के पुख्ता आधार हों। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की जो बात महात्मा गांधी कहते थे, चुनाव आयोग को उसे समझने की जरूरत है। विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और एक भी नया नाम जोड़ा नहीं गया, ये कैसा शुद्धिकरण या गहन पुनरीक्षण है। रविवार को अररिया की एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि जब विपक्ष को 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने में कुछ गड़बड़ दिख रही है, और वो सवाल कर रहा है, तो भाजपा को इसमें कुछ अटपटा क्यों नही लग रहा। क्यों उसने चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं किए। इसी तरह कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटों के सबूत जब राहुल गांधी दिखा रहे थे, तो उसी वक्त चुनाव आयोग से उन्हें शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने कहा गया। जबकि राहुल गांधी के बाद भाजपा से अनुराग ठाकुर ने वैसे ही फर्जी मतदाताओं की बात कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों पर कही तो चुनाव आयोग ने आज तक उनसे शपथपत्र नहीं मांगा। गौरतलब है कि पिछले रविवार को ही एक प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया था कि या तो वे माफी मांगे या शपथ पत्र दें, वर्ना ये सबूत बेकार माने जाएंगे। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि इस अल्टीमेटम की याद चुनाव आयोग ने दिलाई हो। बल्कि राहुल गांधी ने फिर से एक प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव आयोग और भाजपा अपने आरोप दोहराए हैं, अपनी चेतावनी याद दिलाई है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे।

एक वक्त था जब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति लोकतंत्र के जीवित होने का प्रमाण बन गई थी। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हांफते-थकते लोकतंत्र में नयी जान भर चुका है। जिन लोगों में यह हताशा भर गई थी कि हमारे बोलने या शिकायत करने से क्या होगा, उन लोगों में राहुल-तेजस्वी जैसे नेताओं के कारण संघर्ष करने और सच के लिए लड़ने का जज्बा फिर से भर गया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अपने आप हजारों-लाखों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। चाहे बारिश हो, बिजली चली जाए, कच्चे रास्ते हों या कोई और रुकावट, लोग बिना किसी परवाह के आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा में कई बच्चे उनके पास आकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। उनके मुताबिक बिहार का बच्चा-बच्चा अब राजनैतिक तौर पर जागरुक हो चुका है। यह असल मायने में जीत है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि -सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए।' आज इस देश को, भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम विपक्ष ही कर रहा है, जबकि खुद वाजपेयी की पार्टी भाजपा ऐसे फैसले ले रही है, जिनमें किसी न किसी तरह लोकतंत्र को कुचलने की बदनीयत दिखती है। जिस एसआईआर पर भाजपा चुनाव आयोग के सामने ढाल की तरह खड़ी हो जाती है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी बताते हैं कि इसमें कुछ न कुछ खोट है, जिसे सुधारने की जरूरत है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करें और इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाए। यानी जिस बात पर विपक्ष शुरु से सवाल उठा रहा था कि आधार कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है, जबकि यह लगभग हरेक के पास होता है, उस सवाल पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ही जवाब दे दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की पूरी कोशिश थी कि भाजपा के घुसपैठिए वाले एजेंडे को एसआईआर के जरिए आगे बढ़ाए, लेकिन शुक्रवार को इस मुहिम में भाजपा को झटका लग गया है। इसलिए जयराम रमेश ने कहा है कि 'लोकतंत्र भारतीय निर्वाचन आयोग के क्रूर हमले से बच गया है।'

राहुल की भारत एक खोज पार्ट टू यात्रा से बिहार यात्रा तक की कहानी

राहुल अच्छे यात्री हैं। सफल। मगर दफ्तर में भी कोई होना चाहिए। सब व्यवस्था बनाए रखने के लिए। राहुल का मिज़ाज अभी तक कांग्रेसियों की समझ में आ जाना चाहिए। बहुत मेहनती, लोगों से खुश होकर मिलने वाले। यह तीसरी बड़ी यात्रा है और जिस उत्साह और शौक से कर रहे हैं इसे देखकर लगता है कि अभी बिहार में ही एक और यात्रा कर सकते हैं। चुनाव की घोषणा होने से पहले तक वे पूरा बिहार कवर कर लेंगे।

लेकिन इन यात्राओं से जो माहौल बनता है उसे वोट में बदलने के लिए एक अलग व्यवस्था की जरुरत होती है। कांग्रेस उस इलेक्शन मैनेजमेंट व्यवस्था को अब तक बना नहीं सकी है।

इसलिए एक सेन्ट्रलाइजड आफिस (केन्द्रीय कार्यालय) और एक राजनीतिक समझ वाली टीम बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने यह सब काम किए। मगर आधे अधूरे तरीके से। एक वार रूम बनाया। बहुत चर्चा में रहा। 15 जीआरजी (गुरुद्वारा रकाबगंज रोड) एक ऐसा नाम जिसके अंदर प्रवेश की हसरत हर कांग्रेसी रखता था। 10 जनपथ जहां सोनिया गांधी रहती हैं जाना आसान था मगर वार रुम सपना।

उसके बाद उसी तर्ज पर अपना नया मुख्यालय इंदिरा भवन। जिसके बनने में कांग्रेसियों और जनता ने भी पैसे दिए हैं वहां भी प्रवेश निषेध। अब जहां जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता जा सकते हैं उस 24 अकबर रोड के पुराने मुख्यालय में कोई पदाधिकारी नहीं आता। कोई बड़ा नेता नहीं।

मल्लिकार्जुन खरगे जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि वे अकबर रोड मुख्यालय के अपने कमरे में बैठेंगे। मगर वे भी नहीं बैठे। विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस का कोई नेता जनता या कार्यकर्ता को सुलभ नहीं है। सत्ता में जब थे तब तो सवाल ही नहीं। सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थीं। कई बार मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों से कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता से मिला करो। मगर किसी ने नहीं सुना।

जनता और कार्यकर्ताओं को अब एक ही मौका मिला राहुल की यात्राओं में। यहां वे कुछ समय के लिए मिल सकते हैं। इसी तरह की राहुल से दूसरे जिम्मेदार नेताओं से मिलने की व्यवस्था दिल्ली में, राज्यों के मुख्यालयों में होना चाहिए। और इस सारी व्यवस्था को मानिटर करने के लिए एक जिम्मेदार टीम। जो दिल्ली में एक आफिस में बैठे।

अभी आप किसी पदाधिकारी से पूछ लो कि 2004 से अभी तक राहुल ने कितनी यात्राएं की हैं, उनका क्या फालोअप है तो कोई नहीं बता पाएगा। राहुल 2004 से जब पहली बार सांसद बने थे तब से यात्राएं कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं। दलितों के घर गए, किसान मजदूर के घर गए। खाना खाया रात रुके।

उनकी मदद की। और यह सब बातें उस समय की हैं जब केन्द्र में उनकी सरकार थी। मगर उस समय भी यह सारी बातें सही तरीके से लोगों के सामने रखी नहीं गईं।

राहुल ने पहली अखिल भारतीय यात्रा उसी समय की थी। 2006 से। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से होते हुए कर्नाटक आंध्र के उन वन प्रांतों की जहां चंदन तस्कर वीरप्पन के मरने के बाद भी कई सालों तक भय का वातावरण रहा। हम उस समय ज्यादातर यात्राओं में साथ थे। और भी पत्रकार थे। बहुत कठिन यात्राएं थीं वह। आज भी राहुल के साथ चलना बहुत मुश्किल है। मगर उन दिनों तो वे ज्यादा यंग थे। अभी की यात्राओं में रात को प्रापर रुकते हैं। मगर उन दिनों तो आप कह सकते हैं कि चौबीस घंटे चलते थे। गाड़ी में ही सो लो और सुबह कहीं नहा-धो कर फिर गाड़ी में बैठ जाओ। उस समय हमने लिखा था भारत एक खोज पार्ट टू। वाकई देश को समझने की वे बेमिसाल यात्राएं थीं।

शकील अख्तर

> तो यात्राएं लगातार दे रही हैं। मगर इससे कई गुना और ज्यादा दे सकती हैं। ये जो मिल रहा है अपने आप। देसी भाषा में कहते हैं अपरस आ रहा है। और अगर सिस्टम हो तो राहुल की मेहनत का पूरा फायदा मिल सकता है। लास्ट। उदाहरण के तौर पर बिहार में सही सीट शेयरिंग। फिर ईमानदारी से टिकट वितरण और आपस में एक दूसरे को हराने पर सख्ती से पाबंदी।

2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला। अकेले 200 से ऊपर सीटें जीतीं। सत्ता में आई। 2011 में राहुल ने उत्तर प्रदेश के नोएडा के भट्टा पारसोल में यूपी सरकार द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने के खिलाफ किसान संदेश यात्रा की थी। उस समय यूपी में मायावती की सरकार थी। और वह आखिरी मायावती की सरकार साबित हुई। उसके बाद उनका ग्राफ लगातार गिरता चला गया। और अब लोकसभा में उनके पास एक सीट भी नहीं है। और विधानसभा में केवल एक सीट। और वह भी प्रत्याशी उमाशंकर सिंह के अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण। बलिया जिले की रसड़ा सामान्य सीट। उमाशंकर सिंह तीसरी बार जीते। सुरक्षित सीटों से सब जगह बसपा हारी। यह राहुल की दूसरी यात्रा का प्रभाव।

भारत जोड़ो यात्रा 2022 जिसने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई है उससे पहले भी राहुल कई यात्राएं कर चुके हैं। जैसा दो तो पहले बताईं। भारत एक खोज पार्ट टू और भट्टा पारसोल में किसानों के लिए किसान संदेश यात्रा। उसके बाद 2015 केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहुल वहां पैदल गए। गौरीकुंड से पहाड़ी चढ़ाई। 4 घंटे में 13 किलोमीटर चढ़ गए। साथ के सब लोग या तो बैठ गए या मुख्यमंत्री थे हरीश रावत उन्होंने घोड़ा लिया। ऐसे ही 2018 की उनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा रही। पैदल यात्रा। वहां भी 7 घंटे में 34 किलोमीटर। इसी तरह 2021 में पैदल ही चलते हुए उन्होंने वैष्णों देवी के दर्शन किए थे। रास्ते भर लोगों से मिलते बात करते हुए। इससे पहले भी सांसद बनने के साथ ही वे 2005 में भी वैष्णों देवी जा चुके हैं।

तो राहुल के साथ चलना बहुत मुश्किल है। मगर वे जहां जाते हैं। जो करते हैं। कहते हैं उनका फालोअप करना इतना मुश्किल नहीं है। राहुल के बुंदेलखंड दौरे के बाद यूपीए सरकार ने वहां के विकास के लिए 7266 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया था। जिसमें मध्य प्रदेश वाले हिस्से के लिए 3760 करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए 3506 करोड़ रूपए का प्रावधान था। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए और अतिरिक्त की बात थी। मगर उसका कोई ठीक से उपयोग नहीं हुआ। जो राजनीतिक मानिटर करना चाहिए था नहीं हुआ। और सब सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ गया।

राहुल की आगे की सफलताओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो निर्णय हों, घोषणाएं हो वे पूरी हों। पार्टी के स्तर से भी इसकी शुरूआत की जा सकती है। और जहां सरकारें हैं वहां से भी।

यह साल कांग्रेस ने संगठन का साल घोषित किया था। पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जनरल सैकेटरी का, राज्यों के अध्यक्ष का और डिपार्टमेंटल हेड का। कितने हैं जिन्हें बदलने की कई बार बात हुई। मगर नहीं हटाए। जहां बदले वहां फायदा दिखा। बिहार में सफल यात्रा के पीछे वहां के बदले गए इंचार्ज कृष्णा अल्लावरु की संगठन और प्रबंधकीय क्षमता का बड़ा हाथ है।

आज स्थिति यह है कि राहुल, प्रियंका, अध्यक्ष खरगे से मिलने का कोई सिस्टम नहीं है। बड़े नेताओं को भी यहां वहां पूछना पड़ता है। देखिए यात्रा में मिले, किसी कार्यक्रम में मिले, संसद में मिलने से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। वह तो आफिस में बैठकर बात करने से ही चीजें समझ में आती हैं।

तो यात्राएं राहुल और भी करेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा 2022 की बात कही थी ऊपर वह 4000 किलोमीटर की पैदल थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और उसके बाद पूर्व से पश्चिम तक। पिछले साल ही। 2024 में। जो 6600 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा थी और नतीजा तत्काल दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार की बात कर रहे थे। 240 पर रुक गए। और कांग्रेस 100 पार कर गई।

तो यात्राएं लगातार दे रही हैं। मगर इससे कई गुना और ज्यादा दे सकती हैं। ये जो मिल रहा है अपने आप। देसी भाषा में कहते हैं अपरस आ रहा है। और अगर सिस्टम हो तो राहुल की मेहनत का पूरा फायदा मिल सकता है। लास्ट। उदाहरण के तौर पर बिहार में सही सीट शेयरिंग। फिर ईमानदारी से टिकट वितरण और आपस में एक दूसरे को हराने पर सख्ती से पाबंदी। साथ ही वोट चोरी पर कड़ी नजर, चुनाव आयोग पर दबाव और कटे हुए नामों को वापस जोड़ने के काम में कोई कोताही नहीं। तब राहुल की मेहनत पूरी वसूल होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

संसद के मानसून सत्र ने सत्ताधारी दल की बढ़ती तानाशाही को उजागर किया

■ डॉ. ज्ञान पाठक

जहां तक कार्य निष्पादन का सवाल है, 21 अगस्त, 2025 को समाप्त हुए भारतीय संसद के एक महीने लंबे मानसून सत्र को लगभग व्यर्थ ही गया कहा जा सकता है। फिर भी, इसके लक्षण भारत के आगे के बड़े संघर्ष का संकेत दे रहे थे। विपक्ष पूरे सत्र के दौरान संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ता रहा, जिससे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में व्यवधान और बहिर्गमन हुआ, जबकि सत्ताधारी दल ने विपक्ष की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ विधेयक पेश करने और पारित करने की पूरी कोशिश की, जो अपने आप में लोकतंत्र का मखौल उड़ाना था। इनमें से एक विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से संबंधित है, जिसमें न्याय का नामोनिशान तक नहीं है, क्योंकि यह बिना आरोप-पत्र के, केवल 30 दिनों की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें हटाने का प्रावधान करता है।

इसलिए, मानसून सत्र की किसी भी समीक्षा को न केवल सत्र के परिणामों के आधार पर, बल्कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में जिन मुद्दों पर बहस हुई और जिन मुद्दों को सत्ताधारी दल ने पारित कराने की पूरी कोशिश की, जिनमें कई विवादास्पद विधेयक भी शामिल थे, के आधार पर भी किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ एनडीए ने उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर, जिस पर सरकार ने विपक्षी दलों के कड़े संघर्ष के बाद चर्चा के लिए सहमति जताई थी। व्यवधान के कारण, लोकसभा अपने निर्धारित समय के केवल 29 प्रतिशत में ही कार्य कर पाई, जबकि राज्यसभा ने केवल 34 प्रतिशत समय का उपयोग किया। प्रश्नकाल लोकसभा में निर्धारित समय का 23 प्रतिशत और राज्यसभा में 6 प्रतिशत ही चला।

> यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद ने विधेयकों पर गहन चर्चा नहीं की। विधेयकों पर सीमित चर्चा हुई और कुछ ही मिनटों में उन्हें पारित कर दिया गया। लोकसभा में पेश किए गए लगभग 27 प्रतिशत विधेयक समितियों को भेजे गए हैं। किसी भी विधेयक को विभाग-संबंधित स्थायी समितियों को नहीं भेजा गया है। लोकसभा की कार्यवाही का लगभग 50 प्रतिशत समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में व्यतीत हुआ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद ने विधेयकों पर गहन चर्चा नहीं की। विधेयकों पर सीमित चर्चा हुई और कुछ ही मिनटों में उन्हें पारित कर दिया गया। लोकसभा में पेश किए गए लगभग 27 प्रतिशत विधेयक समितियों को भेजे गए हैं। किसी भी विधेयक को विभाग-संबंधित स्थायी समितियों को नहीं भेजा गया है। लोकसभा की कार्यवाही का लगभग 50 प्रतिशत समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में व्यतीत हुआ। दोनों सदनों में कोई भी निजी प्रस्तावों पर कार्य नहीं हुआ। सत्ताधारी दल लोकसभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के प्रति कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध और पहलगाम हमले तथा उसके बाद के घटनाक्रम, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में भूमिका निभाने के बार-बार दावे शामिल हैं, पर हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने सदन की उत्पादकता में आई कमी पर निराशा व्यक्त की। केंद्र सरकार द्वारा एसआईआर पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करने के कारण ही दोनों सदनों में दैनिक आधार पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। ओम बिडला ने केवल विपक्ष को दोषी ठहराया और इसे 'संगठित व्यवधान' करार दिया।

सत्र के पहले ही दिन, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, जो सत्ताधारी दल द्वारा उन पर थोपा गया था, क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उपराष्ट्रपति के इस कदम को स्वीकार नहीं कर सकी और उन्हें पर्याप्त संकेत दिए गए थे-या तो इस्तीफा दें या महाभियोग का सामना करें। किसानों के मुद्दे सहित कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने वाले धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। फिर भी, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) पर सत्तारूढ़ दल द्वारा महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस मुद्दे की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह आक्रामक दिखा। उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था क्योंकि जिस तरह से भारत का चुनाव आयोग इसे संचालित कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ गठबंधन कर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिखाया था कि कैसे चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी में मोदी सरकार के साथ मिलीभगत की और 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान 'वोट चोरी' का आरोप लगाया।

यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को अनुमति दी, जिन्होंने भाजपा के पक्ष में संतुलन बनाया, जिसका सीधा लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। आगामी बिहार चुनाव में, चुनाव आयोग ने ऐसे प्रावधान लागू किए जिनसे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने का खतरा पैदा हो गया, कथित तौर पर भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर कराने का इरादा जताया, जिससे विपक्षी सभी राजनीतिक दल चिंतित हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि एसआईआर मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को मजबूती से एकजुट कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के कथित अपवित्र गठबंधन को हराने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है, और संसद में विरोध प्रदर्शन कर रोजाना व्यवधान पैदा किया है।

सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान इसके बाद एक आश्चर्यजनक विधेयक लेकर आई- संविधान 130वां संशोधन विधेयक, 2025, जिसने विपक्षी एकता को और भी मज़बूत कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को दो अन्य विधेयकों के साथ इस विधेयक को पेश किया, जिन्हें अंततः सदन में हंगामे के बीच संयुक्त संसदीय समितियों को भेज दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक, 2025, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों- को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर स्वतः हटाने का प्रस्ताव करता है।

विपक्ष इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा और देश में संविधान और लोकतंत्र पर एक और हमला मानता है। वे पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को कठोर कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फंसा रही है और उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआईए, आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा रही है। उनमें से कई को बिना मुकदमे और आरोपपत्र के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस तरह के विधेयक का पेश होना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करने वाली एक तानाशाही सरकार की स्थापना की ओर काम कर रही है। साथ ही, उन्होंने आने वाले महीनों में संसद के अंदर और बाहर, इन मूल्यों को बचाने के लिए और भी ज़ोरदार लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर अपनी बात रखी है, जो उनके अनुसार संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र के प्रतीक हैं।

आपके पत्र

चुनावी प्रचार सोशल मीडिया पर, तो विधानसभा क्यों नहीं?

यदि विधानसभा की कार्यवाही सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है तो फिर नेताओं और दलों को भी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज वोट मांगने के लिए रैलियों और टीवी के साथ-साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। ऐसे में केवल सदन की कार्यवाही को रोकना अनुचित प्रतीत होता है। लोकतंत्र में नियम सबके लिए समान हों, तभी व्यवस्था पर जनता का विश्वास कायम रह सकता है। भारत में 82 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 45 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। टीवी दर्शकों की संख्या घट रही है और लोग मोबाइल पर सीधे समाचार देखना पसंद करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही केवल टीवी चैनलों तक सीमित करने का निर्णय लोकतांत्रिक पारदर्शिता को सीमित कर सकता है। बेहतर उपाय यह होगा कि विधानसभाएं अपने आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, जहां कार्यवाही का सम्पूर्ण और सत्य प्रसारण हो। इस तरह सदन की गरिमा भी बनी रहेगी और जनता को सूचना तक पहुंच का अधिकार भी मिलेगा।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताक़त उसकी पारदर्शिता और जनता की भागीदारी में निहित है। संसद और विधानसभाएं जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं और वही स्थान हैं जहां नीतियां, कानून और जनहित से जुड़े अहम मुद्दे तय किए जाते हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही तक जनता की पहुंच किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरत कही जा सकती है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया गया यह निर्णय कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और वेब चैनलों पर अब विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण नहीं किया जाएगा, कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। यह फैसला पारदर्शिता को सीमित करने वाला है या फिर सदन की गरिमा को बचाने वाला—यही इस मूल प्रश्न है।

पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में एक नई क्रांति ला दी है। पहले जहां लोग टीवी समाचार चैनलों या अख़बारों के भरोसे रहते थे, वहीं अब फेसबुक लाइव, यूट्यूब स्ट्रीमिंग और ट्विटर अपडेट्स से उन्हें तुरंत जानकारी मिल जाती है। विधानसभा या संसद जैसी संस्थाओं की कार्यवाही अब केवल दीवारों के भीतर सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे जनता के मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचने लगी।

यह बदलाव सकारात्मक भी था। आम नागरिक, खासकर युवा, लोकतांत्रिक विमर्श से जुड़ने लगे। उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि उनके चुने प्रतिनिधि सदन में उनके मुद्दों पर किस तरह की बहस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इसके नकारात्मक पहलू भी सामने आए। कई बार सदन की गंभीर बहस के छोटे-छोटे अंश निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए, जिनका प्रयोग राजनीतिक प्रचार, व्यंग्य या ग़लतफ़हमियां फैलाने के लिए किया गया। नतीजतन, कार्यवाही का वास्तविक उद्देश्य पीछे छूट गया और विवादों ने ज़्यादा सुर्ख़ियां बटोरीं।

हरियाणा प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हरिविंद्र कल्याण का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते वीडियो-संदेशों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कई बार असंसदीय शब्दों, हंगामों और कटाक्षों के छोटे-छोटे हिस्सों को बार-बार प्रसारित किया जाता है, जिससे जनता तक केवल नकारात्मक छवि ही पहुंचती है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब से केवल मान्यता प्राप्त टीवी चैनल ही कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर सकेंगे, जबकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव या रिकॉर्डिंग डालने पर सख़्त प्रतिबंध रहेगा। उनका तर्क यह भी है कि सदन की कार्यवाही से हटाए गए शब्दों और अंशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करना सीधा नियमों का उल्लंघन है। इसलिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

ललित सुरजन की कलम से

सातवां वेतनमान: खेतों में सूखा : बाजार में बहार

सरकारी कर्मचारियों को उनके काम के मुताबिक संतोषजनक वेतन मिले इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, किन्तु यहां पहला बुनियादी सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सरकारी कर्मचारी देश के अन्य नागरिकों से भिन्न किसी प्रजाति के हैं। दूसरे- वे जो काम कर रहे हैं वह किसके लिए? मात्र अपने लिए वेतन अर्जित करने अथवा समाज की बेहतरी के लिए? तीसरे- यदि प्रशासनतंत्र में कसावट नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्यों आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सुनने मिलती हैं? क्यों प्रधानमंत्री को सफाई देना पड़ती है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है?

(देशबन्धु में 2 जुलाई 2016 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/07/blog-post.html

गुरवाणी विचार

मानव एकता के अग्रदूत: गुरु ग्रंथ साहिब

आज प्रथम प्रकाश पर्व पर आदि श्री गुरु ग्रंथ की संपादना सिक्खों के पांचवें नानक गुरु अर्जुन देव द्वारा की गई। इसका प्रकाश भादों सुदी 1 सन् 1604 में इसका पहला प्रकाश हरिमंदर साहिब अमृतसर में किया गया जिसके प्रथम ग्रंथी के रूप में बाबा बुड्ढाजी की सेवाएं ली गई। इस आदि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुदेव ने अपने से पहले चार गुरुओं द्वारा रचित वाणी स्वयं उस वक्त के निर्गुण विचारधारा के 15 भक्तों की वाणी गुरु घर के तीन गुरु सिखों की वाणी एवं 11 भट्टों की वाणी का समावेश किया गया। बाद में दसम गुरु गोविंद सिंह द्वारा नौवें नानक गुरु तेग बहादुर द्वारा रचित वाणी भी दर्ज की गई और आज भी प्रचलित दमदमी बीड़ जिसे सिखों के गुरु हेने का सन् 1708 में मान प्राप्त हुआ।

गुरु ग्रंथ साहिब में अलग-अलग धर्मों की समानता मानव एकता धर्मनिरपेक्षता सद्भावना तथा समस्त विश्व को ईश्वरीय भक्ति के साथ सूत्रबद्ध किया गया है। समूचे रूप में गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को संत भाषा कह सकते हैं। इसमें भारत में प्रचलित समस्त भाषाओं जैसे मुलतानी, सिंधी,हिन्दी, मराठी, गुजराती, अरबी, फारसी. पंजाबी, ब्रज आदि भाषाओं का समावेश है। इस तरह गुरुदेव ने यह बात हर घर पहुंचा दी-एक पिता एकस के हम बारिक, हम सब एक प्रभु परमात्मा की संतानें हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की समस्त भाषा काव्यमयी है इसलिए सभी लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में आश्चर्यजनक नवीनता है। इसमें समस्त मानव जीवन को समझाया गया है-

नाम जपो कीरत करो वंड छको तथा परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग प्रेम भक्ति ही है-सांचि कहूं सुन लेहो सभै।
जिन प्रेम क्यिो लिन ही प्रभ पाइयो।।

समस्त नारी जाति को समानता का दर्जा दिया गया है सो क्यों मर्दो आखिये, जित जमें पादान गुरमत के अनुसार हमें वन कंदराओं में जाकर या किसी भी प्रकार शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या करने की जरूरत नहीं है गृहस्थ में ही रहकर अपना कार विहार करते हुए मन से निरंकार का लिमरन करते रहने पर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है-

नामा कहै त्रिलोचना- मुख ते नाम सम्भाल।
हाथ पांव से काम सब चित निरंजन नाल।।

हमें अपना और परिवार का उदर पोषण करने के लिए कार विहार भी करना है पर मन हमारा हर वक्त उठते बैठते सोते जागते प्रभु सिमरन में लगे रहना चाहिए=उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। इस समस्त संसार की रचना प्रभु परमात्मा ने की है और रचना करने के बाद हर प्राणी के कर्मों का लेखा-जोखा, पाप पुण्य कर्मों के अनुसार पाप कर्मों का दंड चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है और ईनाम के रूप में इस संसार से पार उतार कर प्रभु के सांचे दरबार में स्थान प्राप्त हो सकता है। प्रभु परमात्मा की आरती हर वक्त हो रही है। गगन रूपी थाली में सूरज-चंद्रमा और तारे दीपक का काम कर रहे हैं और हवा सुगंधी बटोर-बटोर उन पर निछावर कर रहे हैं चिड़ियों और पक्षियों की चहचहाट उनके अनहद नाद गा रही हैं।

गगन में थाल रख चांद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती।
धूप मलियान लो पवन चवरो करे- सगल बनलाये फुलंत जोति।।

तभी तो जब रविंद्रनाथ टैगौर से किसी ने सवाल किया कि अगर समस्त संसार का एक ही धर्म हो तो कौन सा होना चाहिए और उसका राष्ट्र गान क्या होना चाहिए?

तब उन्होंने कहा था- सिख धर्म होना चाहिए और राष्ट्र गान गगन में थाल वाला होना चाहिए। संसार में बहुत से धर्मग्रंथ हैं-वेद पुराण, कुरान अजील सब पूजनीय हैं पर गुरु का दर्जा केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही है। चौथे नानक गुरु अमरदास जी ने कहा है-

वाणी गुरु गुरु है वाणी विच बाणी अमृत सारे।
गुरुवाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निसतारे।।

गुरुवाणी जो हमारे गुरुओं ने उचारा है वे सब प्रभु परमात्मा से हमें प्राप्त हुई है।

-इंदर सिंह आहुजा

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

भारत को सचेत आर्थिक सुधारों की त्वरित जरूरत

मौजूदा खौफनाक टैरिफ दौर में भारत को अपने सचेत आर्थिक सुधारों की जरूरत है। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए आर्थिक सुधारों का खाका पेश किया है। इससे पहले भी अनेक अर्थशास्त्रियों, वित्तीय संगठनों ने भारत में अगले चरण के आर्थिक सुधार में तेजी लाने का सुझाव दिया है। इसी वर्ष फरवरी में विश्व बैंक ने भारत को चिली, दक्षिण कोरिया, पोलैंड का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से नए सुधार की जरूरत है। वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे बाद की सरकारों ने आगे बढ़ाया। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सुधारों में और तेजी आई। वर्ष 2014 में जब केंद्र में पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार आई तो कई सुधार किए गए। जनधन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, जीएसटी, नोटबंदी, पीएलआई, एफडीआई नियमों में ढील समेत अनेक सुधार किए गए, लेकिन कुछेक वर्षों से देश में आर्थिक क्षेत्र में नीतिगत स्टैगनेशन है। अभी जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में उच्च टैरिफ वार छेड़ा है, उससे वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इसी के साथ भारत ने जो अपने लिए वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे देखते हुए देश में अगले चरण के आर्थिक सुधार की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही है। सीआईआई ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में सुधार का जो खाका पेश किया है, उसमें सरलीकृत जीएसटी संरचना, गैर-रणनीतिक सावजनिक उपक्रमों का निजीकरण, युक्ति संगत शुल्क संरचना, विवादों के शीघ्र समाधान, राष्ट्रीय रोजगार और गिग अर्थव्यवस्था नीतियों पर जोर दिया गया है। सुधार के क्षेत्रों में राजकोषीय सूझबूझ, मुद्रास्फीति प्रबंधन और आधुनिक सांख्यिकीय प्रणालियां, गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, एक संप्रभु धन कोष का निर्माण, छोटे उल्लंघनों का गैर-अपराधीकरण, समयबद्ध अनुमोदन, एकल-खिड़की मंजूरी और दूसरी पीढ़ी के आईबीसी सुधार, सुव्यवस्थित श्रम संहिताएं, न्यूनतम वेतन रूपरेखा और त्वरित विवाद समाधान शामिल हैं। उद्योग मंडल ने ऊर्जा नीति सुधारों की भी सिफारिश की है, जिनमें प्रतिस्पर्धी शुल्क, क्रॉस-सब्सिडी यानी एक की कीमत पर दूसरे को सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त करने, मजबूत पारेषण नेटवर्क, परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी और हरित हाइड्रोजन खाका की बात है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने जीएसटी में सुधार का ऐलान किया और सरकार जीएसटी के चार से दो स्लैब करने की तैयारी कर रही है। विश्व बैंक ने फरवरी की रिपोर्ट में कहा था कि भारत को 2047 तक उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने के लिए 22 वर्षों में औसतन 7.8 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। 2000 और 2024 के बीच भारत की औसतन 6.3 प्रतिशत की विकास दर रही है। संकेत साफ है कि जीडीपी में गति लाने के लिए धरेलू खपत के साथ निर्यात अर्थव्यवस्था की रफ्तार निरंतर बनाए रखनी होगी। भारत को सार्वजनिक व निजी निवेश में जीडीपी के 40 फीसदी तक वृद्धि, एफडीआई के नए द्वार खोलने, श्रम शक्ति भागीदारी को 70 फीसदी के स्तर पर ले जाना, नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, स्ट्रक्चरल सुधार व प्रौद्योगिकीकरण में तेजी, राज्यों में आर्थिक समावेशन व गतिविधियों को तेज करने के साथ उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। निर्यात के लिए एफटीए के जरिये नए बाजार का जाल तैयार करना होगा।

पर्यावरण

ज्ञानेन्द्र रावत

पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रही आपदाएं व इंसानी दखल

बीते कुछ सालों से हिमालय का पर्वतीय अंचल आपदाओं के कहर से दो-चार हो रहा है। वह चाहे 2013 की केदारनाथ की आपदा हो, 2021 में ऋषिगंगा की आपदा हो, सिक्किम की 2023 की ल्होनक में ग्लेशियर झील के फटने की हो, जोशीमठ की भूधंसाव की घटना हो, बीते दिनों धराली और किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना हो या फिर बीते रविवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बादल फटने तथा जम्मू-कश्मीर के कठुआ में भूस्खलन की घटना हो, इन सबके पीछे जलवायु परिवर्तन तो एक अहम कारण है ही। मानसून कहें या मौसम में आये अप्रत्याशित बदलाव, अरब सागर में गर्म होती हवायें, मध्य एशिया में तेजी से बढ़ता तापमान और दक्षिण - पश्चिमी हवाओं का उत्तर की ओर झुकाव के साथ उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में बारिश का तूफानी पैटर्न है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण प्रकृति में इंसानी दखल भी है जिसका खामियाजा हम भीषण तबाही के रूप में साल दर साल ऐसी आपदाओं के नतीजे के रूप में भुगत रहे हैं। अब तो ये आपदायें आये-दिन की बात हो गयी हैं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। असलियत यह है कि यह सब प्राकृतिक आपदायें हमारी नीतिगत विफलताओं का जीता-जागता सबूत हैं जबकि बरसों से समूची दुनिया के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समय-समय पर जारी रिपोर्टें, शोध और अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ों पर अवैज्ञानिक और अनियोजित निर्माण, पहाड़ों को काटकर या विस्फोट के जरिए नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं, रेल मार्ग का निर्माण, बेतहाशा खुदाई, नदी-नालों के कुदरती मार्गों में अवरोध पैदा करने से आपदाओं को हम खुद-ब-खुद निमंत्रण दे रहे हैं। किंतु विकास के नाम पर सरकारी लापरवाही का आलम यह है कि संवेदनशील भूस्खलन वाले इलाकों में भी बहुमंजिला इमारतों, आवासीय भवनों, होटलों और सड़कों का निर्माण आज भी अनियंत्रित रूप से निर्बाध गति से जारी है। यहां यह गौरतलब है कि जब धरती की सतह बार-बार खोदी जाती है, पहाड़ों का सीना बारम्बार चीरा जाता है, काटा जाता है, उस स्थिति में बारिश की हर बूंद उस नाजुक धरातल को चीरते हुए बहुत तेजी से बह निकलती है। नतीजतन मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ती है और आपदा का आकार कई सौ गुणा बढ़ जाता है। यही वह अहम कारण है कि ऐसी स्थिति में पहाड़ों पर भूस्खलन का दायरा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वैज्ञानिक बार-बार चेता रहे हैं कि जलवायु में आ रहे बदलाव और पहाड़ों पर विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण विनाश का कारण बन रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट साफ-साफ कहती है कि ऊंचे इलाकों में एक डिग्री तापमान बढ़ने पर वर्षा की तीव्रता 15 फीसदी बढ़ जाती है। यह कि जब गर्म समुद्री हवा भारी नमी लेकर हिमालय से टकराती हैं तब पहाड़ उसे रोकते हैं। इससे क्यूम्यलोनिम्बस बादल बनते हैं जो 50,000 फीट ऊंचाई तक जा सकते हैं और जब ये फटते हैं तो अपने साथ पूरी की पूरी घाटी में भीषण तबाही लाते हैं। इस बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डीआरडीओ की मानें तो हिमालय के ग्लेशियर हर साल औसतन 15 मीटर पीछे खिसक रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। कहीं- कहीं कुछ इलाकों में ग्लेशियर के पीछे हटने की दर 20 मीटर से भी ज्यादा है। दरअसल जब-जब और जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, उसके नीचे की जमीन अस्थिर होती जाती है। पिघलती बर्फ, दरकती चट्टानें और अचानक बनने वाली झीलें सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इनके टूटने से भयंकर तबाही आती है, गांव के गांव बह जाते हैं। ये आपदायें आबादी क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। प्रकृति की संवेदनशीलता के प्रति हमें अति संवेदनशील होना होगा। यदि हम प्रकृति से खिलवाड करेंगे तो निश्चित है कि हमें ऐसी आपदाओं से आये-दिन दो-चार होना पड़ेगा। सरकार के साथ हमारी भी जवाबदेही है। हमें व सरकार को भूविज्ञानियों,पर्यावरणविदों की संस्तुति-चेतावनियों को मानना होगा जिन्हें हम बराबर नकारते आ रहे हैं। उसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक पर्यावरणीय दृष्टि से अर्ली वार्निंग प्रणाली पर तत्काल काम करना होगा और क्षेत्र वार आपदा जोखिम की पहचान के साथ साथ उसके न्यूनीकरण के लिए भी हर समय न केवल तैयार रहना होगा बल्कि उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम भी करना होगा। यह जानते हुए कि पर्वतीय इलाकों में मैदानी इलाकों की तरह काम नहीं हो सकता। इसके लिए अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रकृति की राह में यदि हम आये तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सियासत

राज कुमार सिंह

उप-राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणायन राजनीति

उप राष्ट्रपति चुनाव में मुख्यतः उत्तर और पश्चिम भारत में जनाधार वाली भाजपा की अगुवाई वाले राजग ने तमिलनाडु मूल के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने आंध्र प्रदेश मूल के बी सुदर्शन रेड्डी को। इसे दक्षिण भारत में चुनावी बिसात बिछाने की कवायद भी माना जा रहा है। राधाकृष्णन की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता असंदिग्ध है तो किसान परिवार से आने वाले रेड्डी की न्यायाधीश के रूप में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर भी कभी कोई सवाल नहीं उठा। उप राष्ट्रपति पद संवैधानिक होने के बावजूद उस तक पहुंचने का रास्ता राजनीति से ही निकलता है।

उप राष्ट्रपति चुनाव ने भारतीय राजनीति को दक्षिणायन बना दिया है। मुख्यतः उत्तर और पश्चिम भारत में जनाधार वाली भाजपा की अगुवाई वाले राजग ने तमिलनाडु मूल के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने आंध्र प्रदेश मूल के बी सुदर्शन रेड्डी को। इसे दक्षिण भारत में चुनावी बिसात बिछाने की कवायद भी माना जा रहा है। पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाये जाने से पूर्व राधाकृष्णन मूलतः भाजपा के नेता रहे हैं। रेड्डी पर अभी तक राजनीतिक पहचान का ठप्पा नहीं रहा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति- उप राष्ट्रपति का पद संवैधानिक माना जाता है, लेकिन उसके लिए चुनाव राजनीतिक तिकड़मों से मुक्त नहीं रह पाता।

'मिसाइल मैन' अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने जैसे उदाहरण अपवादस्वरूप ही हैं। बेशक उसका श्रेय भाजपा को जाता है। एक महीने पहले 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के बीच ही रहस्यमयी इस्तीफे के चलते इस उप राष्ट्रपति चुनाव की नौबत आयी है। जैसा कि अक्सर होता है, धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में इस पद के लिए राजग के संभावित उम्मीदवार की अटकलें शुरू हो गयी थीं। आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से शुरू अटकलें बाद में संघ-भाजपा के निष्ठावानों के नामों पर सिमट गयीं। जनता दल से राजनीति शुरू कर कांग्रेस के रास्ते भाजपा में आये धनखड़ के साथ कटु अनुभव के बाद पार्टी ने वैसा जोखिम नहीं उठाया। वैसे सीपी राधाकृष्णन के चयन से इस धारणा को बल मिला है कि दौड़ में आगे बताये जाने वाले अक्सर भाजपा में मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हां, राज्यपाल रहे व्यक्ति को राष्ट्रपति–उप राष्ट्रपति बनाने का भाजपाई रुझान बरकरार है। पहले बिहार के उप राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया तो फिर पश्चिम बंगाल के उप राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उप राष्ट्रपति और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन की बारी है। नौ सितंबर को होने वाले उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा (पूर्व में जनसंघ) के प्रति निष्ठावान रहे राधाकृष्णन पर दांव के मूल में दक्षिण भारत में राजनीतिक बिसात बिछाने की कवायद भी साफ समझी जा सकती है। केंद्र समेत तमाम राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा का दक्षिण भारत में एकमात्र सत्ता-दुर्ग कर्नाटक ही बन पाया था, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छीन लिया। इसलिए तमिलनाडु के प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से आने वाले राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना कर भाजपा ने दक्षिण में अपने प्रसार की रणनीति भी बनायी है। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्दगिर्द घूमती रही है, लेकिन जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक के बिखराव में भाजपा अपने लिए संभावनाएं देख रही है। दूसरे, तमिल उम्मीदवार के चलते वहां के सत्तारूढ़ दल द्रमुक पर भी समर्थन के लिए दबाव बनाने की रणनीति भाजपा की रही होगी। द्रमुक विपक्षी गठबंधन इंडिया का मजबूत घटक दल है और उसकी सरकार की केंद्र सरकार से तल्खी

किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का दबाव दिखा, जब द्रमुक ने तमिलनाडु से ही 'इंडिया' का उम्मीदवार बनाने की इच्छा जतायी। कुछ नामों पर विचार भी हुआ, लेकिन टीएमसी की गैर राजनीतिक उम्मीदवार की इच्छा ने बी. सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के द्वार खोल कर उप राष्ट्रपति चुनाव को दिलचस्प बना दिया है।

रेड्डी भी दक्षिण भारत से ही आते हैं, लेकिन तमिलनाडु के बजाय आंध्र प्रदेश से, जहां अब चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राजग सरकार है। नीतीश कुमार की तरह पाला बदल के लिए चर्चित नायडू की पार्टी टीडीपी की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने में बड़ी भूमिका रही है। अगर तमिल उम्मीदवार से द्रमुक पर समर्थन का दबाव बन सकता है, तब क्या तेलुगु उम्मीदवार से टीडीपी समेत अन्य तेलुगु दलों पर समर्थन का दबाव नहीं बनेगा? मुख्य विपक्षी दल वाईएसआरसीपी राजग और 'इंडिया' के बीच तटस्थ रही है, पर उप राष्ट्रपति चुनाव में उसे किसी एक उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला करना ही पड़ेगा। फिर आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना भी तेलुगु राज्य है। वहां अब कांग्रेस की सरकार है, पर मुख्य विपक्षी बीआरएस के पास भी राज्यसभा में चार सांसद हैं। बेशक उप राष्ट्रपति चुनने वाले लोकसभा और राज्यसभा सांसदों में बहुमत का गणित भाजपा के पक्ष में साफ नजर आता है, पर लगभग सवा सौ सांसद उन दलों के भी हैं, जो खुद को तटस्थ कहते हैं, लेकिन तटस्थता का राग इस चुनाव में तो छोड़ना ही पड़ेगा। जाहिर है, देश के नये उप राष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, के चुनावी समीकरण को तटस्थ दलों की भूमिका काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। विपक्ष के लिए पहला शुभ संकेत यही है कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस से तल्खी के चलते 'इंडिया' से नाता तोड़ लेने वाली आप ने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का ऐलान किया है। टीएमसी के गैर राजनीतिक उम्मीदवार के सुझाव के पीछे निश्चय ही दलगत राजनीति से परे भी समर्थन जुटा सकने की रणनीति रही होगी। दरअसल विपक्ष उप राष्ट्रपति चुनाव को दो विचारधाराओं का मुकाबला बना कर अपने अंतर्विरोधों को छिपाते हुए आने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को गति देना चाहता है। पिछले उप राष्ट्रपति चुनाव से कांग्रेस ने भी सबक सीखा लगता है।

पिछली बार कांग्रेस ने धनखड़ के विरुद्ध संपूर्ण विपक्ष को विश्वास में लिए बिना अपनी नेत्री मारग्रेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया था। जिस बैठक में अल्वा का नाम तय हुआ, टीएमसी और आप उसमें शामिल नहीं हुईं। बाद में आप ने तो अल्वा का समर्थन कर भी दिया, लेकिन ममता की टीएमसी दूर ही रही। इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार विपक्ष पर थोपने की गलती नहीं दोहरायी है। बेशक दोनों की उम्मीदवार इस पद के योग्य हैं। राधाकृष्णन महाराष्ट्र से पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं तो रेड्डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। राधाकृष्णन की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता असंदिग्ध है तो किसान परिवार से आने वाले रेड्डी की न्यायाधीश के रूप में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर भी कभी कोई सवाल नहीं उठा।

हां, यह अवश्य विचारणीय है कि अभी तक दूर ही रहे रेड्डी ने एक मुश्किल चुनाव लड़ कर खुद पर राजनीतिक रुझान का ठप्पा लगवाने का जोखिम क्यों उठाया है, क्योंकि उप राष्ट्रपति पद संवैधानिक होने के बावजूद उस तक पहुंचने का रास्ता राजनीति से ही निकलता है। इसीलिए उस पर आसीन व्यक्ति राजनीतिक रुझान से मुक्त कम ही नजर आते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं। लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।)

ईश्वर की प्राप्ति ही तो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य

संकलित

दर्शन

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के तीन -ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्ग बताए हैं। ज्ञान मार्ग में सांख्य की सहायता से मनुष्य तर्क-वितर्क द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु अक्सर तर्क-वितर्क में वह अपने मार्ग से भटक जाता है। कर्म मार्ग में भी मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना होता है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। इसलिए इसमें भी भटकने की पूरी संभावना होती है। वहीं भक्ति मार्ग में वह अपने आप को पूर्णतया ईश्वर भक्ति में समर्पित कर देता है। वह स्वयं को विचलित नहीं करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर प्राप्ति की पूरी संभावना होती है। इन तीनों मार्गों पर चलकर सफल होने के लिए मनुष्य को अष्टांग योग के पहले दो चरणों को जीवन में अपनाना जरूरी है। यह हैं यम और नियम। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्माचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह आते हैं। सत्य शब्द से तात्पर्य है सत्यता का जीवन में हर समय पालन करना। अहिंसा केवल जीव हिंसा से ही संबंधित नहीं है, इसमें दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना भी आता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आवश्यकता से ज्यादा किसी वस्तु या धन का संग्रह न करना। वहीं नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान आते हैं। शौच से मतलब मन की सफाई होता है। इसके लिए मनुष्य को स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। यम और नियम को जीवन में अपनाने के लिए सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी है।

तुलसीदास जी द्वारा विप्रचंद ब्राह्मण पर कृपा

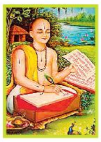

संकलित

प्रेरणा

एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गई और उस हत्या के प्रायश्चित के लिए वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था- राम राम ! मै हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्टदेव का अतिसुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे ह्रदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपनी पंक्ति में बैठकर प्रसाद खिलाया जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना ये ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया? गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। भगवन्नाम के प्रताप से ही यह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको कैसे होगा विश्वास वह उपाय कहिए? इस पर ब्राह्मणों ने कहा- यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा लें तो हम लोग इसे अपनी जाति, पंगति में ले सकते हैं अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे जहां शर्त रखी गई थी। श्री गोस्वामी जी ने नन्दीश्वर से कहा- हे नंदीश्वर ! यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए नन्दीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम

23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 को चांद पर इसरो ने सफलता से उतारकर देश का मान बढ़ाया था। इसी तारीख को यादगार बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की जो घोषणा की और जहां चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, उस जगह को शिवशक्ति का नाम दिया। चंद्रयान-3 को संचालित करने में महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर ने जो भूमिका निभाई, उसने एक तो उन लोगों को आईना दिखाया जो बेटियों को कमजोर समझते हैं, दूसरा चंद्रयान-3 की लैंडिंग के समारोह में इन वैज्ञानिकों ने देश की संस्कृति के अनुसार जो पहनावा पाया था और श्रृंगार किया था, उसने सारी दुनिया को हमारी संस्कृति से परिचित कराया।

- अनित मिश्रा, जगदलपुर

करंट अफेयर

द. अफ्रीका में एचआईवी के इलाज के लिए जूझ रहे लोग

अमेरिका की ओर से मिलने वाली विदेशी सहायता बंद होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में 'ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस' (एचआईवी) से पीड़ित हजारों लोग इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनियाभर में एचआईवी संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या दक्षिण अफ्रीका में है। छह महीने पहले अमेरिका की ओर से दी जाने वाली वाली विदेशी सहायता बंद करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद निशुल्क एचआईवी सेवाएं प्रदान करने वाले कई गैर-लाभकारी क्लीनिक 24 घंटे अंदर बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण जोहानिसबर्ग में यौनकर्मियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। क्लीनिकों के बंद होने की खबर फैलते ही एचआईवी पीड़ित और वे लोग

तुरंत जीवन रक्षक दवाएं खरीदने पहुंच गए, जिन्हें एचआईवी होने का खतरा है। देश भर में बंद हुए 12 क्लीनिकों में 63,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा रहा था। ऐसे में 2,20,000 से ज्यादा लोगों को अपनी दैनिक एचआईवी दवा लेने में रुकावट का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने वादा किया है कि वह अमेरिका के सहायता वापस लेने से अपने एचआईवी कार्यक्रम को ध्वस्त नहीं होने देगी। यौनकर्मी दक्षिण अफ्रीका के सबसे असुरक्षित वर्ग के लोग माने जाते हैं क्योंकि उनका काम अवैध है।

ऑफ बीट

मस्तिष्क की अवस्थाएं और तरंगें क्या होती हैं ?

हमारे सभी सरल और जटिल व्यवहार, साथ ही हमारी अनुभूति (विचार) का आधार मस्तिष्क गतिविधि, या 'तंत्रिका गतिविधि' है। न्यूरॉन्स -

मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं - विद्युत आवेगों और 'न्यूरोट्रांसमीटर' नामक रासायनिक संकेतों के अनुक्रम द्वारा संचार करती हैं। न्यूरॉन्स रक्त से मिलने वाले ईंधन के लिए बहुत लालची होते हैं और उन्हें साथी कोशिकाओं से बहुत अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए, मस्तिष्क गतिविधि की साइट, मात्रा और समय का अधिकांश माप विद्युत गतिविधि, न्यूरोट्रांसमीटर स्तर या रक्त प्रवाह को मापने के माध्यम से किया जाता है। इस गतिविधि पर हम तीन स्तरों पर विचार कर सकते हैं। पहला एकल-कोशिका स्तर है, जिसमें व्यक्तिगत न्यूरॉन्स संचार करते हैं। लेकिन इस स्तर पर माप कठिन (प्रयोगशाला-आधारित) है और एक सीमित तस्वीर प्रदान करता है। इस प्रकार, हम नेटवर्क स्तर पर किए गए मापों पर अधिक भरोसा करते हैं, जहां न्यूरॉन्स या नेटवर्क की एक श्रृंखला सक्रिय होती है। या, हम संपूर्ण मस्तिष्क गतिविधि पैटर्न को मापते हैं जिसमें एक या अधिक तथाकथित 'मस्तिष्क अवस्थाएं' शामिल हो सकती हैं।

ट्रेंड

ई-केवाईसी अनिवार्य

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तथ्यों को सही से समझने की जरूरत है। लाभार्थियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी का निर्देश उच्चतम न्यायालय ने दिया था और केंद्र केवल राज्यों से इसे लागू करने के लिए कह रहा है।

- प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय खाद्य मंत्री

आपदा का दंश

आपदा का स्वरूप और दायरा बढ़ता जा रहा है, आज प्रदेश के कई जिले आपदा की चपेट में हैं। सरकार से आग्रह है कि आपदा का दंश झेल रहे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मदद की जाए।

-जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम, हिमाचल प्रदेश

बदले की राजनीति

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को मामूली आरोपों में हिरासत में लिए जाने पर मैं चिंतित हूँ। मैं श्रीलंका सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह बदले की राजनीति का त्याग करे और अपने पूर्व राष्ट्रपति के साथ उस गरिमा के साथ पेश आए जिसके वे देश के प्रति दशकों की सेवा के बाद हकदार हैं।

- शशि थरूर, सांसद, कांग्रेस

बैंकों की सख्ती

बैंक जिस तरह गरीब किसान से कर्ज के पैसे वसूल रही है अगर वो सख्ती, भाजपा का प्रश्रय प्राप्त उन खरबपतियों के खिलाफ दिखाई होती जो कई लाख करोड़ लेकर फरार हो गये तो आज अर्थव्यवस्था, कारोबार और किसानी की इतनी दुर्दशा न होती।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारत और रूस

संबंध मज़बूत होते जा रहे हैं

ऐसे समय में जब दुनिया भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के पुनर्संरेखित होने के कारण उतार-चढ़ाव की स्थिति में है - पुराने सहयोगियों के बीच दरार बढ़ रही है और नए गठबंधन सामने आ रहे हैं - भारत और रूस के संबंध अप्रभावित बने हुए हैं। सौहार्द की भावना को और मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस सप्ताह मास्को यात्रा ने एक स्पष्ट संदेश दिया हैः भारत रूस को एक विश्वसनीय, अपरिहार्य भागीदार के रूप में देखता है, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसके बारे में क्या सोचते हों। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जयशंकर की बैठक, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक चर्चाओं के साथ, न केवल भारत-रूस संबंधों की गहराई को रेखांकित करती है, बल्कि अमेरिकी दबाव के बावजूद एक स्वतंत्र विदेश नीति का रास्ता तय करने के नई दिल्ली के दृढ़ संकल्प को भी रेखांकित करती है।

यह यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का

नया टैरिफ लगाने के बाद हुई है भारत के लिए, ऊर्जा का प्रश्न स्थिरता और सुरक्षा का है, अवसरवाद का नहीं। जयशंकर ने न केवल भारत के विकल्पों का बचाव किया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय हित के व्यापक तर्क के भीतर भी प्रस्तुत किया। रूस के साथ भारत की मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है और समय की मार झेलती रही है। मास्को ने नई दिल्ली का उस तरह से साथ दिया है जैसा बहुत कम साझेदारों ने दिया है। शीत युद्ध के दौरान रूस एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, जिसने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर वीटो लगाया और उसके सामरिक हितों का समर्थन किया, विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान।

रक्षा ऐतिहासिक रूप से इस संबंध का आधार रही है। भारत का 60 प्रतिशत से अधिक सैन्य हार्डवेयर रूसी मूल का है, और जबकि नई दिल्ली ने हाल के दशकों में आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाई है, मास्को कलपुर्जों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे संयुक्त उद्यमों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

रूस भारत को रणनीतिक रूप से राहत भी प्रदान करता है। जैसे-जैसे पश्चिम वैश्विक राजनीति को द्विआधारी शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा है - लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद - रूस भारत को एक प्रतिसंतुलन प्रदान करता है, जिससे उसे रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद मिलती है। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स सहित वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका के लिए मास्को का समर्थन इस साझेदारी को और मज़बूत करता है।

फ़िलिहाल, ट्रम्प ने भारतीय निर्यात और ऊर्जा व्यापार को निशाना बनाकर नई दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया है। वह रूसी तेल ख़रीदने के लिए भारत को दंडित करना चाहता है। लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह, मास्को ने भारत के साथ अपने ऊर्जा व्यापार को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए एक ₹विशेष तंत्र₹ पहले ही सक्रिय कर दिया है, जो अनुकूलनशीलता और प्रतिबद्धता दोनों का संकेत देता है। भारत-रूस की यह मित्रता सिर्फ़ अतीत की यादों का प्रतीक नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकताओं की एक व्यावहारिक पहचान भी है।

हमारी गलतियों के लिए पश्चिम दोषी नहीं

कांगो को जबरन श्रम और हिंसा द्वारा क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था, जिसमें वस्तुओं की यूरोपीय मांग को पूरा करने के लिए अनुमानित 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। ये त्रासदियाँ शोषण के लंबे इतिहास के केवल शुरुआती अध्याय हैं

निलांथा
इलांगमुआ
लेखक - स्तंभकार

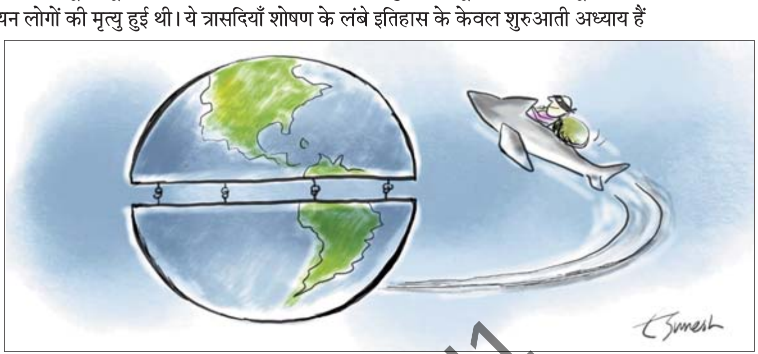

हाशिये पर रहने वालों को कितनी बार एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था के तहत कष्ट सहना पड़ता है जो उन्हें लगातार बाहरी करार देती है—शक्तिहीन, उन ताकतों द्वारा संचालित जो आज़ादी देने का दावा तो करती हैं लेकिन उन पर निर्भरता और गहरी होती जाती है? हम कितनी बार ₹वैश्विक दक्षिण₹ और पश्चिम के बीच के सरल विभाजन को सच मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह वैश्विक आर्थिक और सामाजिक संबंधों को आकार देने वाले जटिल जाल को छुपाता है? उपनिवेश-विरोधी और उत्तर-औपनिवेशिक आंदोलनों से उपजा ₹वैश्विक दक्षिण₹ शब्द, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। फिर भी, विडंबना यह है कि यह उत्पीड़न की कई परतों को छुपाता है जो सीमाओं से परे हैं, और प्रतिरोध के बारे में संकीर्ण, जड़ विचारों को जन्म देता है।

₹वैश्विक दक्षिण₹ की कहानी निर्विवाद औपनिवेशिक लूट से शुरू होती है। लेकिन इसे केवल पीड़ित होने के इतिहास के रूप में देखना, एक कहीं अधिक जटिल आख्यान को सीमित कर देना है, जो निरंतर प्रभावों और टूटनों से भरा है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पर विचार करें, जिसने ख्1 बिलियन (उस समय 100 बिलियन डॉलर से अधिक) से अधिक की लूट की, जिससे एक ऐसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई जो कभी विश्व उत्पादन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा थी। राजा लियोपोल्ड द्वितीय के शासनकाल में,

कांगो को जबरन श्रम और हिंसा द्वारा क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था, जिसमें वस्तुओं की यूरोपीय मांग को पूरा करने के लिए अनुमानित 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। ये त्रासदियाँ शोषण के लंबे इतिहास के केवल शुरुआती अध्याय हैं।

स्वतंत्रता के बाद, कई राष्ट्रों ने नए सिरे से उभरने की आशा की, लेकिन पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को धन संचय करने वाले तानाशाह बनते देखा। ज़ैरे में मोबुतु सेसे सेको ने लगभग 5 बिलियन डॉलर चुराए और उसे पश्चिमी बैंकों में जमा कर दिया, जिससे उनका देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। नाइजीरिया के सानी अबाचा ने लगभग 3.4 बिलियन डॉलर चुराए, जिनमें से अधिकांश अभी भी आंशिक रूप से ही वसूल हो पाए हैं। फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस ने 5 से 10 बिलियन डॉलर के बीच विदेशों में छिपाए, जिनमें से अधिकांश अभी भी उनकी पहुँच से बाहर हैं। ये भारी नुकसान एक कठोर सच्चाई को उजागर करते हैंः उत्तर-औपनिवेशिक सरकारें कभी-कभी देशभक्ति की आड़ में शोषण के नए रूपों को जारी रखती थीं।

फिर भी, वैश्विक दक्षिण को केवल एक अकेले पश्चिमी उत्पीड़क का विरोध करने वाले पीड़ितों के एक समूह के रूप में देखना आज के उलझे हुए वैश्विक संबंधों को अति-सरलीकृत कर देता है। राष्ट्रवादी बयानबाजी में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले आर्थिक आत्मनिर्भरता या अलगाव के आ''ान, वैश्विक व्यापार और निवेश के माध्यम से बनने वाले जटिल अंतर्संबंधों को गलत समझते हैं।

राष्ट्र धन, माल और श्रम के प्रवाह से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी अर्थव्यवस्थाएँ अपने उत्पादों के लिए पश्चिमी बाज़ारों पर निर्भर हैं; पश्चिमी कंपनियाँ इन अर्थव्यवस्थाओं में भारी निवेश करती हैं; और उत्तर में प्रवासियों द्वारा घर भेजे गए धन से लाखों लोगों का भरण-पोषण होता है। ये परस्पर निर्भरताएँ मुक्ति के सरल आख्यानों का विरोध करती हैं।

यह जटिलता कोई छलावा नहीं है; यह वैश्वीकरण के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है—सहयोग और विरोधाभास का मिश्रण। यह हमें अलगाव या संरक्षणवाद का गुणगान करने वाली पुरानी धारणाओं से आगे बढ़ने और इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर आधारित रणनीतियों को अपनाने का आग्रह करती है। ₹वैश्विक दक्षिण₹ को एक निश्चित राजनीतिक लेबल के बजाय, उत्पीड़ित लोगों के बीच गठबंधन बनाने के आ''ान के रूप में अधिक समझा जाना चाहिए, चाहे वे पूर्व उपनिवेशों में हों या पश्चिम के हाशिए पर पड़े समुदायों में। यह दृष्टिकोण इस धारणा को चुनौती देता है कि वैश्विक दक्षिण अलग-थलग या बंद है। यह साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ अलग-अलग संघर्षों को जोड़ने के महत्व पर जोर देता है, उन्हें परस्पर जुड़े उत्पीड़न की एक बड़ी व्यवस्था के पहलुओं के रूप में पहचानता है। वाल्टर रॉडनी ने देखा कि ₹अफ्रीका का शोषण और अविकसितता साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा की गई, जिनकी संपत्ति अफ्रीकी संसाधनों और श्रम के शोषण पर आधारित थी।₹ उनकी अंतर्दृष्टि अफ्रीका से आगे तक फैली हुई है, शोषण की एक वैश्विक व्यवस्था को उजागर करती है जो सीमाओं और पीढ़ियों से परे है।

आज, चुनौती केवल अतीत की चोरी को याद करने या पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों को दोष देने की नहीं है, बल्कि कथित रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के भीतर चल रही असमानता की जाँच करने की है। धन का गबन जारी है—अब अवैध वित्तीय प्रवाह के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के देशों से अरबों डॉलर गुप्त पश्चिमी बैंक खातों में स्थानांतरित हो रहे हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुमान है कि ये नुकसान सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है—जो सभी आधिकारिक विकास सहायता को मिलाकर भी अधिक है। यह एक स्पष्ट दोहरे मापदंड को उजागर करता हैः वैश्विक उत्तर भ्रष्टाचार-विरोधी और विकास का उपदेश देता है, जबकि चोरी की गई संपत्ति को छिपाने वाले तंत्रों का संचालन करता है। एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। वैश्विक दक्षिण को अब केवल संरक्षणवाद या राजनीतिक चालबाजी के प्रतीक के रूप में काम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, इसे वैश्विक एकजुटता का केंद्र बनना चाहिए—एक ऐसा स्थान जहाँ सभी पृष्ठभूमियों के उत्पीड़ित लोग महाद्वीपों और वर्गों से एकजुट होकर प्रणालीगत अन्याय का मुकाबला करें। जैसा कि कोफी अन्नान ने चोरी की गई संपत्ति वसूली पहल के दौरान जोर दिया था

यह संघर्ष औपनिवेशिक काल के नक्शों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साझा मिशन है, जो हर जगह हाशिए पर पड़े समुदायों को एकजुट करता है—रियो के झुग्गी-झोपड़ियों और जोहान्सबर्ग के कस्बों से लेकर पेरिस के अप्रवासी इलाकों और लंदन के मजदूर वर्ग के ज़िलों तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रूर वैश्विक पूंजीवाद और दमनकारी शासनों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई, चाहे वे कहीं भी हों। वैश्विक दक्षिण का पुनर्निर्माण एक शब्दार्थ अभ्यास से कहीं अधिक है—इसके लिए दुनिया के अंतर्संबंधों पर गहन पुनर्विचार की आवश्यकता है, साथ ही इसकी जटिलताओं का सम्मान भी करना होगा। फ्रांट्ज़ फैनन ने हमें याद दिलाया कि ₹प्रत्येक पीढ़ी को, अपेक्षाकृत गुमनामी से, अपने मिशन की खोज करनी चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए या उससे विश्वासघात करना चाहिए।₹ आज, चुनौती पीड़ित होने के विरासत में मिले आख्यानों से आगे बढ़कर वैश्विक पूंजी और राजनीति की उन शक्तिशाली, छिपी ताकतों का सामना करने की है जो असमानता को कायम रखती हैं। गुप्त वित्तीय प्रवाह, भ्रष्ट नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के माध्यम से शोषण जारी है जो इसे जारी रहने देते हैं। इस वास्तविकता से निपटने के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आलोचना और पुनर्निर्माण दोनों करे—राष्ट्रवादी नारों और अलगाववादी विचारधाराओं के पीछे छिपे नुकसानों को उजागर करे।

इस रणनीति को सीमा पार गठबंधन भी विकसित करने होंगे, जो पूंजीवाद और सत्तावादी शासन के तहत उत्पीड़न का सामना करने वाले सभी लोगों को एकजुट करेंगे। एंटोनियो ग्राम्शी की ₹ऐतिहासिक ब्लॉक₹ की अवधारणा - विचारकों और कार्यकर्ताओं का एक शक्तिशाली गठबंधन - मार्गदर्शन प्रदान करती हैः हमें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ बनानी होंगी जो उत्तर-दक्षिण के द्विभाजन से परे हों। उत्पीड़न किसी एक भूगोल को नहीं जानता; उत्तर में अप्रवासी दक्षिण के ग्रामीण समुदायों की तरह ही अन्याय सहते हैं। तत्काल कार्य प्रतिरोध का एक वैश्विक आंदोलन है जो इस साझा संघर्ष को समझता है और उस पर कार्य करता है। वैश्विक दक्षिण के मिथक का खंडन कोई अकादमिक अभ्यास नहीं है; यह हमारे युग को परिभाषित करने वाली वर्चस्व की स्थायी संरचनाओं के विरुद्ध दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने के लिए आवश्यक है।

विकसित भारत के लिए मोदी के सुधारों का ब्रह्मास्त्र

दशकों तक, झिझक और "नो गो" क्षेत्रों ने अन्वेषण को बाधित किया और आयात पर निर्भरता बढ़ा दी। वह दौर अब बीत चुका है।

हरदीप एस पुरी
केन्द्रीय पेट्रोलियम
एवं प्राकृतिक
गैस मंत्री

मुझे अपने स्कूल के दिनों से ही 15 अगस्त के भाषणों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का 12वें स्वतंत्रता दिवस का भाषण अभूतपूर्व और असाधारण था। इसमें विकसित भारत के पथ पर भारत की गति बढ़ाने के दिशा में सीधे तौर पर लक्षितझ्ब्रह्मास्त्र- अर्जुन का अकाट्य पौराणिक अस्त्र - छोड़ा गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त असामान्य उथल-पुथल के दौर के बीच, विकसित भारत का सपना संजोए भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निरंतर आगे बढ़ना जारी रखे हुए है। यह भाषण केवल अपनी व्यापकता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दायरे– साहसिक, भविष्योन्मुखी और 1.4 बिलियन लोगों के भाग्य को नया आकार देने में सक्षम अगली पीढ़ी के सुधारों –और उस विजन के प्रति स्पष्टता के लिए भी उल्लेखनीय है, जिसका यह राष्ट्र इससे पहले कभी साक्षी नहीं रहा। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया स्टैक को ही लें, यूपीआई दुनिया के आधे रीयल-टाइम लेनदेन के लिए उत्तरदायी है और साल के अंत तक होने वाला, पहली मेड-इन-इंडिया चिप का लॉन्च, वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रों की नियति सेमीकंडक्टर निर्धारित करते हैं, महत्वपूर्ण तकनीकों पर संप्रभुता का भारत का यह दावा किसी डिजिटल स्वराज से कम नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से भारत के विकास की राह की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। दशकों तक, झिझक और ''नो गो'' क्षेत्रों ने अन्वेषण को बाधित किया और आयात पर निर्भरता बढ़ा दी। वह दौर अब बीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने ईईजेड में ''नो गो'' क्षेत्रों को लगभग 99% तक कम कर दिया है, जिससे 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ईएंडपी के लिए मुक्त हो गया है। ओएएलपी के साथ, इसने भारतीय और वैश्विक दिग्गजों, दोनों के लिए समान रूप से एक विशाल क्षेत्र खोल दिया है—हमारे हाइड्रोकार्बन बेसिन अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए उपयोग में लाए जाएँगे।

लाल किले की प्राचीर से घोषित ऐतिहासिक राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक महत्वाकांक्षी दूरदर्शी एजेंडा निर्धारित करता है। इस मिशन का लक्ष्य लगभग 40 वाइल्डकैट कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से 600-1200 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है। पहली बार, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारत अपनी जटिल अपतटीय सीमाओं को व्यवस्थित रूप से खोलेगा, एक ऐसे ढाँचे के साथ जो सूखे कुओं की स्थिति में 80 प्रतिशत तक और व्यावसायिक खोज पर 40 प्रतिशत तक लागत की वसूली की अनुमति देकर निवेश के जोखिम को कम करता है। यह पहल एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2032 तक घरेलू तेल और गैस उत्पादन को तिगुना बढ़ाकर 85 मिलियन टन और राष्ट्रीय भंडार को दोगुना करके एक से दो बिलियन टन के बीच किया जा सकता है। लगभग 8 मिलियन टन उत्पादन के बराबर, अतिरिक्त 100-250 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध कराने के लिए प्लग-एंड-प्ले आधार पर अपतटीय साझा बुनियादी ढाँचा बनाया जाएगा। ये सभी उपाय न केवल पहले से अटकी हुई खोजों का मुद्रीकरण करेंगे, बल्कि एक आत्मनिर्भर ईएंडपी इकोसिस्टम का निर्माण भी करेंगे, जहाँ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की हिस्सेदारी आज के 25-30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। यह आज़ादी के बाद से भारत का सबसे व्यापक अपस्ट्रीम सुधार है।साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। भारत 2030 के लक्ष्य से पाँच साल पहले ही 2025 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य तक पहुँच गया है। जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक स्तर से उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं; इथेनॉल मिश्रण और सीबीजी स्केल-अप एक नए ग्रामीण-औद्योगिक आधार का निर्माण कर रहे हैं; एलएनजी के बुनियादी ढाँचे का विस्तार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में, 10 नए परमाणु रिएक्टर चालू हैं, और भारत का लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भव्य योजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा हमारी औद्योगिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ऐसे समय में जब दुनिया लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व , निकल और कोबाल्ट के सामरिक महत्व को पहचान रही है, भारत ने 1,200 से अधिक स्थलों पर अन्वेषण शुरू किया है और साझेदारी, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण का ढाँचा तैयार कर रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ईवी और उन्नत रक्षा क्षेत्र कभी भी बाहरी अवरोधों के अधीन न रहें। राष्ट्रीय सुरक्षा लाल किला चार्टर का एक अन्य स्तंभ था। ऑपरेशन सिंदूर ने परमाणु ब्लैकमेल के युग का अंत करते हुए वास्तविक समय में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यह संदेश दिया कि आक्रमण का जवाब तेज़ी और कुशलता से दिया जाएगा। सिंधु जल संधि को स्थगित करना संप्रभुता का साहसिक दावा है। सबसे बढ़कर, मिशन सुदर्शन चक्र का अनावरण, युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की रक्षा से प्रेरित है, जो मोदी की शैली–सभ्यतागत प्रतीकवाद के अत्याधुनिक तकनीक से मेल का प्रतीक है।एक बहुस्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों की साइबर, भौतिक और हाइब्रिड खतरों से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले इंजनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती जारी की है, और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और संस्थानों से संयोजन या असेंबली से ऑथरशिप तक की छलांग लगाने का आ''ान किया है।

प्रधानमंत्री ने कठोर सत्यों से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने उद्योग जगत और किसानों से आत्मनिर्भरता अपनाने और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। हालाँकि भारत दुनिया की फार्मेसी है, जो वैश्विक टीकों का 60% का उत्पादन करता है, अब इसे नई दवाओं, टीकों और उपकरणों के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यह बायोई3 नीति के तहत बायोफार्मा को निर्णायक बल देने के साथ-साथ है, जहाँ हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी दवाओं का पेटेंट और उत्पादन करना है जो किफायती और विश्वस्तरीय दोनों हों।

घोषित किए गए कर और कानूनी सुधार भी उतने ही साहसिक हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1961 का आयकर अधिनियम, जो स्वयं उस युग का अवशेष है, अब बदला जा रहा है। नया आयकर विधेयक जटिलता को कम कर रहा है, 280 अनावश्यक धाराओं को समाप्त कर रहा है और 12 लाख रुपये तक की राहत प्रदान कर रहा है। फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत ने प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और भ्रष्टाचार-मुक्त बना दिया है। दिवाली तक लॉन्च किया जाने वाला अगली पीढ़ी का जीएसटी 2.0, दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाएगा और अनुपालन को बढ़ावा देगा।

आप की बात

बाढ़...बाढ़.....बाढ़.... ?

" .... कभी अधिक वर्षा होने पर "पानी....पानी.....पानी...₹ की ख़बरें कुछ राज्यों की अख़बारों में छपा करती थीं. अब जिधर देखो उधर ही "बाढ़.... बाढ़....बाढ़....." के नज़ारे प्रिंट मीडिया व टीवी चैनलों पर पढ़ने व देखने में रोज-रोज आ रहे हैं. फिर चाहे जम्मू-कश्मीर हो या बिहार, उत्तरप्रदेश हो या राजस्थान, महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड-हिमालचल प्रदेश आदि. जहाँ बाढ़ ही नहीं बल्कि पहाड़ों के दरकने, बादलों के फटने, सड़कों के गायब होने, पुलों के बहने, मकानों के ताश के पत्तों की तरह ढ़हने और लोगों के जलसमाधि बनने जैसे दुखद व डरावने प्राकृतिक आपदाओं के चलते देखने,सुनने व पढ़ने आ रहे रहे हैं. ऐसा लगता है कि जहाँ-जहाँ भी बाढ़ आ रही है या बादल फट रहे हैं जैसे "जलजला" या "जल प्रलय" ही हो रहा हो. प्रभु !प्रक्रुति से छेड़छाड़ (पहाड़ों को काटने, हरे-भरे जंगलों को उजाड़ने, नदी-नालों में बसाहट करने, सीमेंट-कांक्रीट के जंगल स्थापित करने, बेतरतीब गाँवों व शहरों के अंधाधुन्द विकास करने, जलनिकास और जलसंवर्धन की व्यवस्था न रखने, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं के अव्यवस्थित निर्माण करने आदि जैसी) अपने स्वार्थ पूर्ति के चलते मानव द्वारा लगातार की जाने वाली गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा तो मत दो कि मेरे राम... !

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

चुनाव आयोग बाध्य

आधार कार्ड को मतदाता सूची में प्रविष्टि के लिए मान्य कर देने का निर्देश देकर सुप्रीम कोर्ट ने वही करने पर चुनाव आयोग को बाध्य किया है जिससे बचने के लिए बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर प्रभावी ढंग से किया जा रहा था। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को या तो स्वयं इस बात में रुचि है कि अनाधिकृत विदेशी घुसपैठ करने वाले मुसलमान भी बिहार में मतदाता बने रहें जिससे किसी भी प्रकार वहां भाजपा गठबंधन की सरकार न बन सके या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि का दबाव इतना अधिक था जिसे ये जज सह नहीं पाए । अन्यथा सुनवाई के समय एक बार आधार सम्बन्धी चुनाव आयोग के तर्क से सहमत होकर भी आधार मान्य करने का अनर्गल आदेश न तर्कसंगत है, न न्याय और न ही संविधान सम्मत । स्वयं अपनी नियुक्ति करने वाले ये बड़के जज अनेकों बार एक बिगड़ैल बालक जैसा व्यवहार करते हुए सब प्रकार की नैतिकता और संवैधानिक प्रक्रिया को न मानते हुए देशद्रोहियों, नक्सलियों, जिहादियों के हाथों में खेलते हुए जिस प्रकार राष्ट्रद्रोह सा कृत्य करते हैं तो राष्ट्रवादियों की चिन्ता स्वाभाविक ही है । इस सन्दर्भ में चुनाव आयोग को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आधार सम्बन्धी आदेश को मानने से मना कर दे, अवमानना हो तो हो ।

-डॉ. जय प्रकाश गुप्त, अम्बाला छावनी

ट्रंप को जवाब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह भारत के खिलाफ अपनी मनमानी टैरिफ नीति लागू कर रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि आज अमेरिका का रवैया दोहरे मापदंडों पर टिका है। कभी यही अमेरिका मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा समर्थक था और दुनिया भर में उसके लिए दबाव बनाता था, लेकिन आज वही देश संरक्षणवाद की राह पर चल पड़ा है। यह नीति न तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और न ही उसके वैश्विक नेतृत्व को।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यह नया भारत है, जो आत्मविश्वास से भरा है और दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं। भारत का संदेश साफ है कि वह बराबरी के आधार पर संवाद चाहता है, न कि किसी महाशक्ति के हुक्म पर। ट्रंप और अमेरिकी अरबपति कारोबारी जिस तरह दूसरे देशों पर आरोप मढ़ते हैं कि वे व्यापार में ईमानदारी नहीं बरत रहे, यह अपने आप में विडंबना है। असलियत यह है कि अमेरिका मुख्य रूप से हथियार बेचने वाला देश है और इसके लिए वह अस्थिरता और टकराव को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि उसकी नीतियां दीर्घकालिक शांति और सहयोग की जगह संदेह और टकराव पैदा करती हैं।

- विभुक्ति बूपक्या, अक्षत खाचरोध उज्जैन

कुत्तों की हिंसक प्रकृति रोकने को भोजन का प्रबंध करें

देश भर में कुत्तों के काटने के आतंक से देश की अदालत द्वारा कुत्तों को एक प्रकार से केद में रखने का फरमान सुनाया था ! अदालत के फरमान से देश में कुत्ता प्रेमी लोगों ने देश की सबसे अदालत में इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर देशभर में प्रदर्शन करने लगे ! देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अततः कुतो के पक्ष में उनकी आज़ादी का फेसला सुनाकर कुता प्रेमियों को जश्न मनाने का मोका दिया ! बेशक पशु पक्षी प्रेमी होना कोई गुनाह नही नही हे और पशु प्रेमियों की हिफाजत करना हर मानव का धर्म भी हे ! लेकिन आज विडम्बना यह हे कि सोशल मीडिया पर या डिजिटल प्लेटफार्मो पर अपनी प्रसिद्ध बढ़ाने के लिए पशु प्रेमी होना या कुत्ता प्रेमीयो की तादाद लाखो में मिल जाएगी लेकिन हकीकत धरातल पर एक सेकड़ा भी पशु प्रेमी होना या कुत्ता प्रेमी लोगो का मिलना बेहद ही मुश्किल हे ! निसंदेह देशभर में सडको पर रहने वाले कुत्तों के खूंखार होने की प्रवृति बढती जा रही हे ! कुते ही नही सडको पर हर समय विचरण करने वाले अन्य गाय, बैल, सांड गधे आदि अन्य जानवर की भी प्रवृति हिंसक होती जा रही हे और यह मानवता के लिए दिनोंदिन घातक भी होते जा रहे हे ! पशु पक्षियों में आये दिन बढ़ती घातक हिंसक प्रवृत्ति पर सरकार, समाज और पशु पक्षी प्रेमियों को चिन्तन की जरूरत है।

- योगेश जोशी, बड़वाह

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

दैनिक जागरण
संयम ही विपत्ति में ढाल बनता है

स्थानीय निकायों पर निगाह

यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि आवारा कुत्तों की समस्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित अंतरिम फैसले के बाद केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर सक्रियता दिखाती। उसने सभी राज्यों को 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण का जो निर्देश दिया, वह समय की मांग है। केंद्र सरकार ने यह निर्देश देते हुए राज्यों को वित्तीय मदद देने का भी आश्वासन दिया है और हर माह आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट लेने की भी पहल की है। स्पष्ट है कि अब राज्य सरकारों को इस मामले में गंभीरता का परिचय देना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि स्थानीय निकायों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के मामले में स्थानीय निकाय एक बड़ी हद तक अक्षम और असफल ही साबित हुए हैं। इसी कारण इस समस्या ने इतना गंभीर रूप लिया। अपने देश में आवारा कुत्तों के काटने और लोगों के रैबीज से ग्रस्त होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष रैबीज से संक्रमित कुत्तों के काटने के कारण मरने वालों की संख्या 18 से 20 हजार के बीच है और स्पष्ट है कि यह सही संख्या नहीं है, क्योंकि न जाने कितने मामले दर्ज ही नहीं होते। क्या यह सामान्य बात है कि प्रतिवर्ष 18 से 20 हजार लोग रैबीज से ग्रस्त होकर मर जाएं? ध्यान रहे कि इनमें एक बड़ी संख्या बच्चों और किशोरों की होती है।

समझना कठिन है कि आवारा कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश पर कुछ कथित पशु प्रेमी लोग और संगठन असंतोष क्यों व्यक्त कर रहे हैं? असंतोष तो उन्हें व्यक्त करना चाहिए जो इससे चिंतित हैं कि क्या देश भर के नगर निकाय आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण कर पाएंगे? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वे आक्रामक और रैबीज ग्रस्त कुत्तों को आश्रयगृहों में रख पाएंगे? यह एक तथ्य है कि देश के महानगरों तक में पर्याप्त संख्या में आवारा कुत्तों के लिए आश्रयगृह नहीं हैं। यह ठीक है कि अधिकांश स्थानीय निकाय वित्तीय कठिनाइयों से दो चार हैं और संख्याबल के अभाव से भी ग्रस्त हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी समस्या उनकी ओर से अपने हिस्से की किसी भी जिम्मेदारी के निर्वहन में ढिलाई बरतना है। इसी कारण हमारे छोटे-बड़े शहर अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें से एक समस्या आवारा कुत्तों के आतंक की भी है। यदि राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को जवाबदेह नहीं बनाया तो भारत 2030 तक कुत्तों से होने वाले रैबीज के खात्मे के अपने लक्ष्य को पाने में नाकाम ही रहेगा।

अच्छा नहीं कचरा

स्वच्छ जलवायु के लिए जाने जाते हिमाचल प्रदेश के लिए कचरा बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। उत्तर भारत के प्राणवायु केंद्र इस पर्वतीय राज्य में सामाजिक, शासनिक और प्रशासनिक प्रवृत्ति यह हो गई है कि समस्या की ओर आंखें मूंद लें तो मानो वह हल हो गई। प्रदेश में गांवों, कस्बों और नगरों का तेजी से विकास हुआ है। इनकी सफाई के लिए स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी तय की गई है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में कचरा निष्पादन की उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं नालियां कचरे से भरी पड़ी हैं तो कई स्थानों से उठाकर अन्यत्र ढेर लगाए जा रहे हैं। धर्मशाला के प्रवेशद्वार पर तो कचरे का पहाड़ कई बार सुलगता देखा गया है। स्थिति यह है कि कचरे के ढेरों से वहां के लोगों का रहना दूभर हो गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ जिलों में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र न होने का कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि हर जिला मुख्यालय में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र क्यों स्थापित नहीं हैं। दो दिन पहले मंडी जिला के नेरचौक क्षेत्र में कूड़े के ढेरों से उठने वाली बदबू के कारण एक स्कूल के बच्चे बीमार हो गए थे। आशा है, सभी पक्ष अपना दायित्व समझते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की चिंता करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय हिमाचल प्रदेश की छवि से भी जुड़ा है और सुशासन से भी। खुले में कचरा जमा होने पर आसपास के लोगों को बहुत समस्या होती है। उससे उठती दुर्गंध से लोगों को सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में अच्छा होगा कि सरकार कूड़े की समस्या को गंभीरता से ले और उसका उचित निस्तारण करे।

अपशिष्ट प्रबंधन पर हाई कोर्ट के निर्देश से समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है

सुधार की दिशा में उठे कदम

जीएन वाजपेयी

जीएसटी में सुधारों का आर्थिक प्रभाव कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा

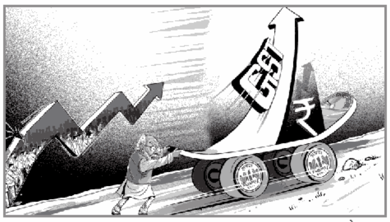

अवधेश राजपूत

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन की चर्चा अभी तक जारी है। लाल किले की प्राचीर से दिया गया उनका संबोधन ऊर्जावान, प्रेरक और आश्वस्तकारी था। व्यापक विषयों के समावेश वाले इस भाषण में भविष्य की झलक भी दिख रही थी। इस संबोधन में उस नेता की भावनाएं मुखर हो रही थीं, जिसने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं से ओतप्रोत किया है। राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाने वाले उनके संबोधन की गूंज पूंजी बाजार तक सुनाई दी। इससे सेंसेक्स में तेजी और रुपये की स्थिति में मजबूती का रुख दिखा। आर्थिक समृद्धि और किसी राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भू-राजनीतिक तथा ऊर्जा सुरक्षा के साथ गहराई से जुड़ा होता है। मोदी ने अपने सारगर्भित संबोधन में बताया कि ये तीनों सुरक्षा तत्व किस तरह उनके दृष्टिकोण में भारत के भविष्य का तानाबाना बुनेंगे।

आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में महान अर्थशास्त्री जान मेनार्ड कींस ने एनिमल स्पिरिट यानी उत्साही प्रवृत्ति की आवश्यकता रेखांकित की थी। इस उत्साही प्रवृत्ति को कारोबारी सुगमता और जीवन सुगमता से प्रोत्साहन मिलता है। इस दिशा में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधारों की घोषणा महत्वपूर्ण और दूरगामी असर करने वाली रही। जुलाई 2017 में तमाम जटिल करों और अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्र-एक कर जैसी संकल्पना के साथ जीएसटी अस्तित्व में आया। इसे 1991 के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार दिया गया। इसने कर राजस्व बढ़ाने के साथ अनुपालन को बेहतर बनाया। इसके चलते निवेश बढ़ा और एकीकृत बाजार के रूप में भारत का कायाकल्प हुआ। जीडीपी वृद्धि पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारों के बावजूद इसने संघीय सहमति का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि इसमें कायम कुछ विसंगतियां उद्यमों, राजस्व और विभिन्न हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल रही थीं। इसमें टैक्स ढांचे की जटिलता, नियमों और दरों में अक्सर होने वाले परिवर्तन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जुड़े मसले और कुछ मामलों में अनुपालन बोझ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अच्छी बात है कि इन विसंगतियों का संज्ञान लेकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने की पहल हुई है। जीएसटी सुधारों का प्रस्तावित उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना और इसे एक विश्वस्तरीय अप्रत्यक्ष कर संरचना में बदलना है। प्रस्तावित सुधारों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: दरों को तार्किक बनाना और घटाना, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन, अनुपालन बोझ को कम करना और विवादों का समाधान करना। उम्मीद है कि 12 प्रतिशत की 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत वाली श्रेणी में और 28 प्रतिशत वाली 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत वाली श्रेणी में स्थानांतरित हो जाएंगी। नई दरें न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे विकसित बाजारों के अनुरूप ही होंगी। इन देशों में जीएसटी दरें 5 से 15 प्रतिशत के बीच हैं।

दरों को तार्किक बनाने से विसंगतियों पर भी अंकुश लगेगा। इससे उद्योग की लागत में बढ़ोतरी, मूल्य श्रृंखला में विसंगतियां और इनपुट क्रेडिट का संचय होता रहा। वर्गीकरण की जटिलता को समाप्त करने से अनुपालन में सुधार होगा एवं कर संरचना और मजबूत बनेगी। आवश्यक और आकांक्षी वस्तुओं पर कर की दर में कमी आम आदमी, एमएसएमई, किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ ही खपत को बढ़ावा देगी और अंततः जीडीपी वृद्धि में योगदान करेगी। कुछ क्षेत्रों में इनपुट क्रेडिट की विसंगतियां जैसे कच्चे माल और तैयार माल के लिए अलग-अलग दरों को तार्किक बनाना एवं उनका स्पष्टीकरण भी स्थिति को सुधारेगा। प्रौद्योगिकी संचालित समाधान जैसे निर्बाध पंजीकरण, पूर्व में भरे हुए रिटर्न और स्वचालित रिफंड अनुपालन में आसानी प्रदान करेंगे और प्रशासन की लागत को काफी घटाने का काम करेंगे। त्वरित रिफंड कार्यशील पूंजी में वृद्धि करेगा, ब्याज लागत को कम करेगा और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।

जीएसटी के आठ वर्षों के दौरान कई विवाद भी सामने आए। खासतौर से वर्गीकरण को लेकर ऐसा कई बार दिखा। उन विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने से जटिलता, अनिश्चितता को कम किया जाएगा और भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुगम बनाने और भरोसा बढ़ाने में सहायक होगा।

विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने प्रस्तावित दरों में परिवर्तनों से राजस्व संग्रह पर प्रभावों का अपना आकलन दिया है। इस कड़ी में एचएसबीसी बैंक ने 1.43 लाख करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया है तो एसबीआइ के अनुसार यह 85,000 करोड़ रुपये है, जिसमें केवल 45000 करोड़ रुपये वर्तमान वर्ष के लिए है। एसबीआइ की ही रिपोर्ट में इससे खपत में 1.98 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है और आयकर दरों में कमी के साथ मिलकर इसे 5.31 लाख करोड़ रुपये आंका है, जो जीडीपी का 1.6 प्रतिशत तक हो सकता है। इसका दूसरा पहलू यही है कि खपत में वृद्धि कर राजस्व में वृद्धि करेगी और समय के साथ दरों में कमी और उनके तर्कसंगत के कारण संभावित अनुमानित क्षति की समय के साथ भरपाई होती जाएगी।

जीएसटी में सुधारों का आर्थिक प्रभाव 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, उद्यमों को औपचारिक स्वरूप अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अनुपालन में सुधार करेगा, कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएगा। इससे जहां महंगाई की स्थिति सुधरेगी, वहीं जीडीपी में 0.20 से 0.22 प्रतिशत का योगदान बढ़ेगा। हालांकि इस भली मंशा वाले सुधार की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर ही निर्भर होगी।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

श्रम बल में बढ़े महिलाओं की हिस्सेदारी

अनुरोध ललित जैन

भारत का आर्थिक भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि आधी आबादी की क्षमता को वह कितनी गंभीरता से लेता है

ट्रंप टैरिफ ने महिला कामगारों की बढ़ाई चुनौती। फाइल

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ। यह टैरिफ भारत से अमेरिका को होने वाले 40 अरब डालर के व्यापार को निशाना बनाता है। इससे देश की जीडीपी में लगभग एक प्रतिशत की कमी आ सकती है। यह टैरिफ कपड़ा और रत्न जैसे उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है, जहां उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। लगभग 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा और रत्न जैसे क्षेत्र 50 प्रतिशत तक के निर्यात में गिरावट का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और अफ्रीका, यूरोप जैसे क्षेत्रों में निर्यात विविधीकरण के कारण अमेरिकी टैरिफ की चुनौती का सामना करने में सक्षम दिख रहा, जबकि भारत इस मामले में असुरक्षित है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं-एक तो भारत का 18 प्रतिशत निर्यात अमेरिका पर निर्भर है और दूसरा, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पाद 30-35 प्रतिशत तक महंगे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। ऐसे संकट के समय में महात्मा गांधी के शब्द प्रासंगिक लगते हैं, "किसी राष्ट्र की ताकत उसकी महिलाओं में निहित होती है।" ऐसे में आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर हम भी इस चुनौती से पार पा सकते हैं।

भारत में महिला श्रम बल की बेहद कम भागीदारी है, जो 37 प्रतिशत से 41.7 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। जबकि वैश्विक औसत और चीन की दर लगभग 60 प्रतिशत है। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इस बात का प्रमाण हैं कि जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो समावेशी विकास संभव हो पाता है। जापान ने 'वुमेनामिक्स' रणनीति अपनाकर महिला भागीदारी को 74 प्रतिशत तक पहुंचाया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी महिलाओं की भागीदारी से मिली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस लैंगिक अंतर को समाप्त करने से भारत 2025 तक अपनी जीडीपी में 27 प्रतिशत यानी 770 अरब डालर की वृद्धि कर सकता है। 2047 तक यह आंकड़ा 14 लाख करोड़ डालर तक पहुंच सकता है, पर इसके रास्ते में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, नीतिगत निष्क्रियता और रोजगार के लिए प्रणालीगत बाधाएं आड़े आ सकती हैं। आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी और अब टैरिफ का खतरा-देश की आर्थिक क्षमता को और कमजोर कर सकता है।

भारत इस समय अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के शिखर पर है। यह एक ऐसा दौर है जब काम करने वाली आबादी आश्रितों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अवसर सीमित समय के लिए है और 2045 तक समाप्त हो जाएगा। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इसी अवसर का लाभ उठाकर विकसित हुए हैं। भारत को इस क्षणिक अवसर को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। इसका एकमात्र रास्ता महिलाओं को पूरी तरह से कार्यबल में शामिल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन यह ज्यादातर अवैतनिक और पारिवारिक कार्यों तक सीमित है, जिसकी उत्पादकता कम है। शहरी भारत में महिला श्रम बल भागीदारी स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता की कमी और अवैतनिक देखभाल कार्य का भारी बोझ महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों से दूर करता है।

आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी विकास पर नकारात्मक असर डाल रही है। इसे बदलना होगा। कर्नाटक की 'शक्ति' योजना, जो महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा प्रदान करती है, एक बेहतरीन उदाहरण है। 2023 में इसके लांच के बाद से महिला यात्रियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना ने महिलाओं की काम, शिक्षा और उद्यम के लिए गतिशीलता को बढ़ाया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इससे महिलाओं की नौकरी तक बेहतर पहुंच बनी है, पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हुई है और उनकी स्वायत्तता बढ़ी है। इसी तरह राजस्थान की 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' ने चार करोड़ से अधिक मानव-दिवस का काम सृजित किया है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। इसके तहत स्वच्छता, पौधरोपण और देखभाल जैसे कार्यों ने उन महिलाओं को भी कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है, जो पहले घरेलू जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाती थीं। 'अर्बन कंपनी' जैसे अग्रणी गिग प्लेटफार्म ने 45,000 से अधिक महिला सेवा प्रदाताओं को जोड़ा है, जो प्रतिमाह 18,000 से 25,000 रुपये तक कमाती हैं। इनको दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। यह दर्शाता है कि गिग कार्य माडल विशेष रूप से अर्ध-कुशल शहरी महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का माध्यम बन सकता है।

ट्रंप का टैरिफ एक चेतावनी है, लेकिन यह एक अवसर भी है। एक ऐसा अवसर जो हमें अपनी महिलाओं की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी आधी आबादी की क्षमता को कितनी गंभीरता से लेता है।

(लेखक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

कर्म

संसार में कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें नैतिक और अनैतिक कर्मों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनैतिक कर्म पाप और अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन अनैतिक कर्मों के भी दो प्रकार हैं- पहला, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को न निभाते हुए पाप कर्मों को मूकदर्शक बनकर देखना और दूसरा, अपने स्वार्थ या इंद्रिय पूर्ति के लिए दूसरों की संपत्ति या अधिकारों को छीनने के लिए शक्ति का प्रयोग करना।

जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कोई मनुष्य अपने कर्मों की विवेचना करता है। जब वह यह अनुभव करता है कि उसने स्वार्थ पूर्ति और इंद्रियों की तृप्ति के लिए पाप किया है, तो उसके अंदर अपराध बोध जागृत होता है। इसी अपराध बोध के साथ उसका अंत समय आ जाता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जीवन के आखिरी क्षणों में प्राणी की जो मनोदशा होती है, उसी के अनुसार उसे अच्छे या बुरे का अनुभव होता है और प्राणी को उसके अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है।

मनुष्य योनि को संसार में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि केवल इसी में प्राणी को विवेक प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए शुभ या अच्छे कर्म कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप वह भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जटायु है, जिसने पक्षी होते हुए भी सीताहरण जैसे पाप के विरुद्ध आवाज उठाई और रावण को रोकने के लिए युद्ध के लिए ललकारा, जिसमें उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके लिए भगवान श्रीराम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। वहीं द्रौपदी के चीरहरण जैसे पाप कर्म को मूकदर्शक बनकर देखने के कारण भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में छह महीने तक बाणों की शैया पर पड़े रहे। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए।

कर्नल शिवदानसिंह

लालच की बढ़ती मानसिकता

डा. मोनिका शर्मा

दहेज जैसी कुरीति को दूर करने के लिए कानून के साथ-साथ परिवार और समाज के दकियानूसी सोच का बदलना भी आवश्यक है

हाल में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला गया। आरोप है कि पति और परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर न केवल महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले भी कर दिया। घर में हो रही मारपीट और जिंदा जलाने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्पष्ट तौर पर बर्बरता देखी जा सकती है। इस भयावह घटना का सबसे व्यथित करने वाला पहलू यह भी है कि उसका बेटा ही कह रहा है कि पापा ने मां को लाइटर से जला डाला। वीडियो में वह मासूम बताता है कि पापा ने मम्मी को जलाया है।

असल में कुरीतियों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जीवनशैली में बदलाव मानसिकता बदलने की पुष्टि नहीं करता। न ही शिक्षा के आंकड़े भर संवेदनाओं और मानवीय समझ को पोसने का माध्यम बनते हैं। बीते दिनों तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एक युवती की आत्महत्या का मामला भी इन्हीं स्थितियों की बानगी बना। दुखद है कि अब न शादी के बाद साथ बिताया समय मायने रखता है और न ही दिया गया दहेज। कई परिवारों में यह लालच कभी खत्म ही नहीं होता। कहा जा रहा है कि शादी के मात्र दो महीने बाद आत्महत्या करने वाली तमिलनाडु की युवती के विवाह में लगभग 800 ग्राम सोना और 70 लाख की गाड़ी दी गई थी। बावजूद इसके ससुराल वालों द्वारा उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया। वहीं करीब नौ साल पहले गृहस्थी बसाने वाली नोएडा की इस महिला की शादी में भी महंगी कार समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था। बावजूद आरोप है कि सात साल के बच्चे के सामने ही मां को आग के हवाले कर दिया गया। विडंबना ही है कि लालच की इस मानसिकता के कारण आज भी कई युवतियों की शादी उनके लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाती है। बहुत सी महिलाएं जीवनभर प्रताड़ना सहती हैं। कुछ हिस्से जीवन का साथ छोड़ देने के हालात भी आ जाते हैं। चिंतनीय यह है कि ऊपरी तौर बदले सामाजिक-पारिवारिक परिवेश में स्थितियां और मुश्किल हो गई हैं। आज के बनावटी-दिखावटी परिवेश में तो विश्वास दिलाना भी मुश्किल हो गया है कि किसी को दहेज के शारीरिक-भावनात्मक प्रताड़ना दी जा रही है। सख्त कानून होने के बाद भी यह हिमाकत की जा रही है।

असल में केवल कानूनी स्तर पर दहेज समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। किसी भी कुरीति को दूर करने के लिए परिवार और समाज का दकियानूसी सोच का बदलना भी आवश्यक है। दहेज की समस्या भी किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षित महिलाओं को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। समग्र समाज की जागरूकता और संवेदनशीलता ही इससे निजात दिला सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आनलाइन मनी गेमिंग पर रोक

''एक बुरे धंधे पर लगाम'' शीर्षक से प्रकाशित संजय गुप्त का आलेख पढ़कर मन को संतोष हुआ। मोदी सरकार ने आनलाइन पैसों वाले गेम पर रोक लगाकर सचमुच जनता का बड़ा भला किया है। यह धंधा खासकर युवाओं और छोटे बच्चों तक को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। पढ़ाई-लिखाई और करियर बिगड़ने लगे थे, कई परिवार कर्ज में डूब गए और मानसिक तनाव बढ़ गया था। कई बच्चे तो चोरी-झपट तक करने लगे थे। यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि कालाधंधा बन चुका था। अब इस कानून से ऐसे धंधों पर लगाम लगेगी, मनी लांड्रिंग और आर्थिक नुकसान रुकेंगे और समाज में सुधार होगा। सच तो यह है कि इस बुराई पर बहुत पहले रोक लग जानी चाहिए थी, पर देर से ही सही, अब इसका अंत हुआ है। जरूरी है कि सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करे, ताकि कोई रास्ता बचकर फिर से यह धंधा न पनप पाए। यही जनता की सच्ची जीत होगी। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कंपनियां कोई चोर रास्ता खोजकर अपने बुरे धंधे चालू रखती हैं। अच्छा होता कि लेखक यह बताते कि कौशल वाले आनलाइन गेम को देश में कैसे बढ़ावा दिया जाए।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

130वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य राजनीति से अपराध और भ्रष्टाचार को दूर करना तथा शासन व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। विधेयक के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पांच साल या उससे अधिक सजायोग्य अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो वह स्वचालित रूप से अपने पद से हट जाएगा। सरकार इसे लोकतंत्र को ''जेल से शासन'' की स्थिति से मुक्त कराने वाला सुधार बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हुए 'सुपर इमरजेंसी' का नाम दे रहा है। इस संशोधन विधेयक का केंद्र बिंदु तीन संवैधानिक अनुच्छेदों-अनुच्छेद 75 (केंद्र में मंत्रिपरिषद), अनुच्छेद 164 (राज्यों में मंत्रिपरिषद) और अनुच्छेद 239एए (दिल्ली सरकार) में बदलाव है। प्रस्तावित प्रविधानों के अनुसार यदि कोई मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल (जैसा मामला हो) उसे पद से हटा देंगे। यह हटना स्वतः प्रभावी होगा। यानी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि रिहाई के बाद संबंधित व्यक्ति को पुनः मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि यह संशोधन राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों की नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और ऐसे नेताओं को शासन से दूर करेगा जो जेल में रहते हुए भी सत्ता पर काबिज रहते हैं। गृह मंत्री ने सदन में कहा कि ''जनता ने जिन नेताओं को सेवा के लिए चुना है, वे यदि जेल में हों तो शासन का अधिकार खो देते हैं।'' इस विधेयक को आगे की जांच और बहस के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है। यह विधेयक जेल से शासन की अवधारणा को खत्म करेगा और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को मजबूत बनाएगा।

रवि रंजन, नई दिल्ली

आवारा कुत्तों की समस्या

हमारे देश में आवारा कुत्तों की अनुमानित संख्या करोड़ों में है। हर वर्ष पूरी दुनिया में साठ हजार से ज्यादा लोगों की मौत रैबीज से होती है, जिनमें 36 फीसद भारत में होती है। यह आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। कुत्तों का बंध्याकरण एक आसान प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कुत्तों को रैबीज का टीका लगाना बेहद जटिल है। जब भी किसी कुत्ते को रैबीज का टीका दिया जाता है, तो 15 दिन के अंतराल में दो खुराक देनी पड़ती हैं। और क्योंकि यह एंटीबाडी 12 महीने तक शरीर में मौजूद रहती है, इसलिए उस कुत्ते को अगले साल फिर से टीका लगाना पड़ता है और यह टीकाकरण हर साल किया जाता है। यदि सही ढंग से कुत्तों का बंध्याकरण और रैबीज का टीका लगाना शुरू किया जा सके, तो निश्चित रूप से आवारा कुत्तों से होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।

रवि शंकर शर्मा, हल्द्वानी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPaperPaid1